हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

26 फरवरी, 2019

खण्ड–1, अंक–7

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 26 फरवरी, 2019 (द्वितीय बैठक)

	पृष्ठ संख्या
प्रशंसा प्रस्ताव	1
वर्ष 2019–20 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर	6
सदन की कार्यवाही में परिवर्तन	114
वर्ष 2019–20 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर	116
बैठक का समय बढ़ाना	170
वर्ष 2019–20 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर	170
बैठक का समय बढ़ाना	197
वर्ष 2019–20 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर	197
बैठक का समय बढ़ाना	219
वर्ष 2019–20 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर	220
बैठक का समय बढ़ाना	232

वर्ष 2019–20 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ) 232

वर्ष 2019–20 के लिए बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान 233

बैठक का समय बढ़ाना 244

वर्ष 2019–20 के लिए बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ) 245

बैठक का समय बढ़ाना 251

वर्ष 2019–20 के लिए बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ) 251

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 26 फरवरी, 2019 (द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 03:07 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

प्रशंसा प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्यमंत्री एक प्रस्ताव रखेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, एक बड़ी खुशी की बात है कि आज सुबह 3 बजकर 20 मिनट पर भारत की बहादुर फौजों ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादियों के ठिकानों पर बमबारमैंट करके 300 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है । हमारे देश में वर्ष 1947 से लेकर अब तक पुलवामा में हुए आक्रमण तक में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते वक्त हमेशा हमारी आखों में आंसू रहे हैं । स्पीकर सर, मैं राजगढ़ में हरि सिंह चौहान की शहादत पर भी उनके संस्कार पर गया था । उनके 11 महीने के बच्चे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी है ।

(इस समय सदन में भारत माता की जय और वन्दे मात्रम् के नारे लगाए गये ।)

स्पीकर सर, देश के प्रधान मंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी पुलवामा की घटना के बाद जहां पर भी बोले वह शहीदों को नमन करते हुए एक बात जरूर बोले हैं कि पुलवामा की घटना के बाद जो आग 130 करोड़ लोगों के दिलों में जल रही है वही आग मेरे दिल में भी धधक रही है । आज 130 करोड़ लोगों का पूरा हिन्दुस्तान भारत की फौजों की जय–जयकार कर रहा है, देश के प्रधान मंत्री की जय–जयकार कर रहा है । अपनी विधान सभा का सत्र भी चल रहा है इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सर्व सम्मति से कोई ऐसा प्रस्ताव पारित करें ताकि देश की भावनाओं के साथ यह महान सदन भी जुड़े । आज सभी राजनीतिक दलों के लोग यहां उपस्थित हैं । मेरा एक निवेदन है कि अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव यहां से पास होकर जाएगा तो उस प्रस्ताव पर हरियाणा और देश में अच्छा संज्ञान लिया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

> ''कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके पुलवामा में सी.आर.पी.एफ. के जवानों पर कायरतापूर्ण हमले का बदला लेकर सभी भारतवासियों को गौरवान्वित किया है । हम सब विधान सभा के सदस्य राजनीतिक बंदिशों से ऊपर उठकर एकजुट होकर आज के सर्जिकल स्ट्राइक का सर्वसम्मति से हार्दिक समर्थन करते हुए भारतीय वायु सेना के इस कदम की प्रशंसा करते हैं ।''

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> ''कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके पुलवामा में सी.आर.पी.एफ. के जवानों पर कायरतापूर्ण हमले का बदला लेकर सभी भारतवासियों को गौरवान्वित किया है । हम सब विधान सभा के सदस्य राजनीतिक बंदिशों से ऊपर उठकर एकजुट होकर आज के सर्जिकल स्ट्राइक का सर्वसम्मति से हार्दिक समर्थन करते हुए भारतीय वायु सेना के इस कदम की प्रशंसा करते हैं ।''

श्री कुलदीप शर्मा (गन्नौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार भारतीय सेना ने पाकिस्तान की टैरेटरी में जाकर सर्जिकल स्ट्राईक की है, समस्त राष्ट्र इससे गौरवान्वित हुआ है। हम राजनीतिक विचारधारा के अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो प्रश्न देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, उसमें हम देश की सुरक्षा के लिए सरकार के साथ खड़े रहना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश की एक राजनीतिक संस्कृति का मैं भी गवाह रहा हूँ तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी भी रहे है। जब वर्ष 1971 में वार पार्लियामैंट चल रही थी और पाकिस्तान के साथ आक्रमण हो रहा था तब माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कहा था कि यह इंदिरा नहीं–यह दुर्गा है और आज के वर्तमान संदर्भ में मैं भी उस परंपरा को दोहराना चाहता हूँ। चुनावी युद्ध में दो हाथ हो सकते हैं लेकिन देश के युद्ध में हम एक साथ खड़े रहेंगे। वास्तव में सर्जिकल स्ट्राईक की बहुत आवश्यकता थी। पुलवामा हमले के बाद पानी सिर से उपर गुजर रहा था। देश की सेनाओं का हौंसला बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन में रखा है, उसके साथ लब्बे–एक कहते हुए मैं भी देश की सेनाओं को बधाई देना चाहता हूँ। जिस मजबूती के साथ यह कदम उठाया गया है समय आने पर तथा जब तक देश की सीमायें शांत न हो जाये देश के अंदर आतंकवाद समाप्त न हो जाये तब तक इस तरह के और भी कदम बार–बार उठाये जा सकते हैं ताकि पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सीखाया जाये। जिस प्रकार सर्जीकल स्ट्राईक की चर्चा इस सदन में हो रही है उसी प्रकार एक समय था जब पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा था और देश की सीमाओं पर आक्रमण किया था तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमले का माकूल जवाब दिया और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए तथा बंगलादेश को एक अलग देश बना दिया। यह देश के इतिहास का हिस्सा है। आज फिर वही परिस्थिति है। मैं बड़ी मजबूती से तथा हमारी पार्टी भी राजनीतिक

विचारधारा को अलग रखते हुए पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री के और देश की सेनाओं के साथ खड़े हैं।

श्री जाकिर हुसैन(नूंह): अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय रामबिलास शर्मा जी ने आज सदन में सेनाओं का हौंसला बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं भी अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। आज इस बात की बहुत जरूरत है कि हम सब पार्टी स्तर की हर बात से उपर उठते हुए देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हमारे जिन जवानों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर किए और जो आज भी सीमाओं पर तथा देश के अंदर भारत की अखंडता व सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे रहे हैं, मैं इंडियन नैशनल लोकदल की तरफ से इन सबके प्रति खिराज–ए–अकीदत पेश करता हूँ। सदन में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पुरजोर समर्थन करती है और अपेक्षा करती है कि सदन में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया जाये। हमारे देश की परंपरा रही है कि चाहे हमारे वैचारिक मतभेद हो, चाहे राजनीतिक मतभेद हों लेकिन जब कभी भी देश पर कोई संकट आता है चाहे यह संकट अब आया है या चाहे पहले पुराने समय में कभी पहले आया हो तो देश के सभी लोगों ने उस संकट का बकायदा तौर पर मुकाबला करने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी कुलदीप शर्मा जी ने कहा कि जब 1971 की लड़ाई हुई थी तो स्वर्गीय इंदिरा जी को हमारे देश के बहुत बड़े नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुर्गा कहा था, वह इसलिए कहा था कि देश ने एकता के साथ प्रधानमंत्री जी का साथ दिया था और उन्होंने उस एकता के बल पर मजबूत होकर पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का काम किया था। आज जो एयर सर्जिकल स्ट्राईक हुई है यह सही वक्त पर उठाया गया एक सही कदम है और इस तरह के सख्त कदम आज के परिपेक्ष्य में उठाने की बहुत जरूरत थी ताकि पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर भविष्य में रोक लग सके और हमारे मासूमों का खून न बहे, इसलिए जो ताकतें देश का नुकसान कर रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए । माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में देश की एयरफॉर्स ने जो कदम उठाया है उसके लिए हम उसकी प्रशंसा करते हैं और इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि हरियाणा विधान सभा और पूरा देश उनके साथ खड़ा है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

> "कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके पुलवामा में सी.आर.पी.एफ. के जवानों पर कायरतापूर्ण हमले का बदला लेकर सभी भारतवासियों को गौरवान्वित किया है । हम सब विधान सभा के सदस्य राजनीतिक बंदिशों से ऊपर उठकर एकजुट होकर आज के सर्जिकल स्ट्राइक का सर्वसम्मति से हार्दिक समर्थन करते हुए भारतीय वायुसेना के इस कदम की प्रशंसा करते हैं ।"

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

वर्ष 2019–20 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर

श्री अध्यक्ष : अब वर्ष 2019–20 के बजट पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ होगा तथा डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जो हाउस एडजर्न होने से पहले बजट पर अपनी बात रख रहे थे, पुनः अपनी बात पूरी करेंगे ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान (बेरी) : थैंक यू स्पीकर सर । स्पीकर सर, जब मैंने बोलना शुरू किया था तो उस समय ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर मैडम चेयर पर आसीन थी । मेरे हिसाब से 13वीं विधान सभा का यह लास्ट सैशन है । 13वीं विधान सभा के अध्यक्ष की हैसियत से आपने जो फर्ज़ निभाया है और अध्यक्ष के पद का जिस तरह से निर्वहन किया है उसके बारे में अगर मैं न बताऊँ तो मैं अपने फर्ज़ से शायद कोताही करूंगा । इस सरकार में जितने सैशन हुए हैं उसमें आपने अपनी फिराकदिली, दरियादिली और शराफत दिखाई है और सभी पार्टियों को बराबर का अधिकार दिया, वजन दिया, बोलने का पूरा समय दिया । मैं यह भी जरूर मैंशन करूंगा कि आपने स्पीकर की चेयर की गरिमा को घटाने की बजाय बढ़ाने का काम किया है । Speaker Sir, I was on the legs. इस समय हाउस में कप्तान साहब नहीं हैं । मैं बजट एलोकेशन पर बोलना चाहता हूं । मेरा कहना है कि बजट का साइज बढ़ता जा रहा है और कई मेन हैड्स जैसे इरिगेशन, एजुकेशन, पावर, हैल्थ, ऐग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज, पुलिस, रूरल डिवैपमैंट, कोऑपरेशन में 5 सालों में बजट का ऐलोकेशन घटता जा रहा है । यह एक सीरियश मैटर है । ऐग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज में वर्ष 2016–16 में 12.3 परसैंट, वर्ष 2017–18 में 12.49 परसैंट, वर्ष 2018–19 में 12.22 परसैंट, वर्ष 2019–20 में 10.31 परसैंट बजट ऐलोकेट हुआ है । इसी तरह से हर हैड में बजट

का ऐलोकेशन डिक्रीज होता जा रहा है । आज किसान कर्ज के नीचे दबा हुआ है और मजबूर होकर आत्महत्या कर रहा है । किसानों की बेहतरी के लिए स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि किसानों की आय को दोगुनी करना चाहिए । इस बजट में सरकार ने ऐसा कोई भी स्टैप नहीं उठाया है । प्रदेश की 70–80 प्रतिशत जनसंख्या खेती–किसानी पर आधारित है । यह वर्ग प्रदेश और देश की आर्थिक रीड़ की हड्डी है । आज किसान सोया हुआ जरूर है लेकिन जिस दिन यह किसान कुम्भकरण की नींद से उठ गया उस दिन आसमान हिल जाएगा और धरती कांप उठेगी । यह कोई छोटी बात नहीं है । Speaker Sir, Government cannot make fool all the people all the time. स्पीकर सर, मैं बजट के ऐलोकेशन के बारे में बोल रहा था । इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदन में बैठे हुए हैं । स्पीकर सर, इस बजट के फसल बीमा योजना के हैड के बारे में मेरा कहना है कि इसके बारे में बहुत बड़ी–बड़ी बातें कही गई थी । बजट के फसल बीमा योजना के हैड में जो फैक्ट्स दिए गए हैं मैं उनसे डिफर करता हूं। जहां तक फसल बीमा योजना की बात है Insurance Companies reaped Rs. 15000 Crores profit but failed to pay Rs. 2800 Crores to farmers. इस बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सैकड़ों किसान इस तरह की समस्या लेकर मेरे पास आते हैं । कई किसानों का कहना है कि उनकी फसल का नुकसान होने के बाद उन्होंने डी.डी.ए. ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया था, उनकी बीमा की किस्त भी कटी हैं । इसके बाद जब डी.डी.ए. ने सर्वे कर लिया और असैसमैंट हो गई कि 70 परसैंट फसल का नुकसान हुआ है और उसके बाद भी उनको फसल का मुआवजा नहीं मिला । गांव डीघल का एक मनोज कुमार नाम का किसान है । उसकी फसल खराब होने के बाद उसने डिप्टी डायरैक्टर, एग्रीकल्चर (डी.डी.ए.) ऑफिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया, असैसमैंट हो गई कि उसकी 70 परसैंट फसल खराब हुई है और बैंक से फसल बीमे की किस्त भी कटी है । इसके बावजूद उसको फसल का मुआवजा नहीं मिला । स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उसको उसकी फसल का मुआवजा क्यों नहीं मिला ? उस किसान की बड़ी पैथेटिक कंडीशन है । अतः मैं इस हाउस के माध्यम से उस किसान की फरियाद माननीय कृषि मंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं । अब मैं हाउस में लोन के विषय पर बात करना चाहूंगा । हमारे प्रदेश पर लोन का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है । वर्ष 2013–14

में 71,000 करोड़ रूपये, वर्ष 2014–15 में 82,305 करोड़ रूपये, वर्ष 2015–16 में 1,14,048 करोड़ रूपये, वर्ष 2016–17 में 1,40,831 करोड़ रूपये और वर्ष 2019–20 में 1,98,064 करोड़ रूपये प्रदेश पर लोन की अदायगी है । वर्ष 2019–20 में प्रदेश पर लोन की अदायगी में 22 परसैंट इजाफा हुआ है । इसके अलावा हरियाणा विधान सभा की हिस्ट्री में यह पहली बार है जब बजट में डैब्ट का पेज नहीं दिया गया है। यह बहुत सीरियस मैटर है। जब सदन में श्री मनोहर लाल जैसे मुख्यमंत्री बैठे हों और बजट में इस प्रकार की चीटिंग की जाए तो यह अच्छा नहीं लगता। यह सभी मैम्बर्स के साथ चीटिंग है। स्पीकर सर, प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013–14 में इंट्रस्ट अमाउंट 5,849 करोड़ रूपये और प्रिंसिपल अमाउंट 5,877 करोड़ रूपये, वर्ष 2014–15 में इंट्रस्ट अमाउंट 7,195 करोड़ रूपये और प्रिंसिपल अमाउंट 10,646 करोड़ रूपये, वर्ष 2015–16 में इंट्रस्ट अमाउंट 8,563 करोड़ रूपये और प्रिंसिपल अमाउंट 10,035 करोड़ रूपये, वर्ष 2016–17 में इंट्रस्ट अमाउंट 9,616 करोड़ रूपये और प्रिंसिपल अमाउंट 2,680 करोड़ रूपये (कुल 15,896 करोड़ रूपये) की पेमेंट की थी । वर्ष 2017–18 में सरकार ने कुल 11,961 करोड़ रूपये की पेमेंट की थी । इस तरह से सरकार ने वर्ष 2017–18 में इंट्रस्ट और प्रिंसिपल के रूप में टोटल बजट के 20 परसैंट बजट की अदायगी की है । इसी तरह से वर्ष 2018–19 में प्रदेश सरकार का टोटल बजट का 23 परसैंट हिस्सा इंट्रस्ट और प्रिंसिपल के रूप में अदायगी में चला गया। वर्ष 2019–20 में प्रदेश सरकार ने इंट्रस्ट अमाउंट 16,632 करोड़ रूपये और प्रिंसिपल अमाउंट 20,257 करोड़ रूपये (कुल 36,889 करोड़ रूपये) की अदायगी की है जोकि कुल बजट का 28 परसैंट है। वर्ष 2019–20 का सरकार का जो प्लान बजट है जिससे प्रदेश का विकास होना है वह कुल 35,040 करोड़ रूपये का है। वर्ष 2019–20 में हम प्लान बजट से ज्यादा प्रदेश पर इंस्ट्रस्ट और प्रिंसिपल की राशि की अदायगी कर रहे हैं । मेरा प्रश्न है कि हमारा प्रदेश किस दिशा में जा रहा है ? इसको देखने से पता चलता है कि प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन कैसा है और यह प्रदेश के वित्त के कुप्रबंधन की तरफ इशारा करता है। प्रदेश सरकार की गलत नीतियों, अनुभवहीनता, समाज से वादाखिलाफी के कारण प्रदेश अंधेरे में और अलग दिशा में जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार वित्तीय प्रबंधन को ठीक करे। अगर आज कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह 1 लाख रूपये का कर्जा लेकर पैदा होता है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के खाते में 15–15

लाख रूपये देने का वायदा किया था परन्तु अभी तक वह वायदा पूरा नहीं किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री कर्ण देव कम्बोज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह बात किसी ने नहीं कही। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप वाईंड अप करें।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है। प्लीज, आप बैठ जाएं। आपको बोलने के लिए एक घंटे से भी ज्यादा समय दिया जा चुका है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय वित्त मंत्री जी भी बैठे हुए हैं और वित्त विभाग के अधिकारी भी बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बजट एट ए ग्लांस वर्ष 2018–19 और वर्ष 2019–20 में State Debt Liability to G.S.D.P. 2018-19 में अलग परसेंटेज है और वर्ष 2019–20 में वही परसेंटेज बजट एट ए ग्लांस डैफर कर रही है। इन दोनों बजट की परसेंटेज का फिगर्ज मिलना चाहिए था। इसमें कौन–सी परसेंटेज को ठीक माना जाए क्योंकि दोनों बजट वर्तमान सरकार द्वारा पेश किये गये हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा दिया है। मैंने वर्ष 2015–16 में बजट सैशन के दौरान बेरी हल्के की कुछ मांगे रखी थी। यह बहुत ही सीरियस मैटर है। माननीय मुख्य मंत्री जी का भी स्लोगन है कि 'सबका साथ, सबका विकास'।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, अभी दूसरे माननीय सदस्यों को भी बजट पर बोलना है। आप बजट पर केवल तीसरे ही माननीय सदस्य बोल रहे हैं। प्लीज आप बैठ जाएं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आप मेरा पिछला रिकार्ड निकलवाकर देख लें। मैं 8 मिनट से ज्यादा कभी नहीं बोला हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे बोलने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाए।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, 10 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि अभी दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलना है। प्लीज, आप जल्दी अपनी बात कम्पलीट करें।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, 'सबका साथ, सबका विकास' सरकार का बहुत ही अच्छा स्लोगन है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेरे बेरी हल्के में माननीय मुख्य मंत्री जी गये थे और उस दौरान उनको मांग पत्र भी दिया था। माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और बहुत ही काबिल मंत्री

हैं। माननीय मंत्री जी का सरकार में बड़ा रूतबा है और राजनीति के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा कद है। प्रदेश की जनता भी माननीय मंत्री जी की बात पर विश्वास करती है और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी मेरे हल्के में गये थे। मेरे बेरी हल्के के लिए बजट सैशन वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 और वर्ष 2018–19 में जो–जो मांगे रखी गयी थी वे मांगे अभी तक पूरी नहीं की गयी हैं। आज वर्ष 2019–20 का बजट भी पेश किया जा चुका है परन्तु इस बजट से पहले जो–जो मांगे रखी थी वे मांगे आज तक पूरी नहीं की गयी हैं। मेरे हल्के की मांगों पर सरकार द्वारा एक भी पैसा नहीं लगाया गया है। सरकार ने बेरी हल्के में गवर्नमैंट कॉलेज बनवाने की बात की है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके अतिरिक्त बेरी हल्के में एक पॉलटैक्निकल वूमन कॉलेज, बस स्टैंड ऑन झज्जर रोड, रोडवेज का सब डिपो, हुडा सैक्टर, बाई–पास, हर्बल पार्क छाजान पाने में, बैठान पाने में और चुलयान पाने में बनाया जाना था। इसके अतिरिक्त कम्युनिटी सैंटर, राउंड–एबाउट बनाये जाने थे, स्टार्टिंग ऑफ प्राईमरी स्कूल एट भागलपुर में बनाया जाना था। इसके अतिरिक्त कुछ रोडज बनाये जाने थे जिसमें बेरी–शेरिया रोड टू पुतलिया बाबा का मंदिर, छारा टू कुलताना, छारा टू रेवाड़ी खेड़ा (स्ट्रेट वे एलॉग विद ड्रेन), बेरी–दुबलधन रोड टू बाबा तूता का मंदिर, बहादुरगढ़ रोड टू माता देवी का मंदिर (छारा), मनाला पॉउंड टू शिव मंदिर (छारा) और बेरी दुजाना रोड टू निराचिया का मंदिर हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त इरिगेशन विभाग से संबंधित कुछ मांगे हैं जैसे एक्सटैंशन ऑफ रेवाड़ी खेड़ा माईनर अपटू कबलाना, छुडानी ड्रेन, बिशान माईनर, भंभेवा माईनर, ड्रेन फ्रॉम रोहड टू खरहड़, ड्रेनेज फॉर 250 एकड़ लैंड एट धौर, ब्रिज ओवर के.सी.बी. ड्रेन फॉर बापरोदा विलेज, डीघल ड्रेनेज फॉर विलेज फ्लड वॉटर हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप जो बातें कहना चाहते हैं वे रिटन में दे दे। आपकी बातों को सदन की कार्यवाही में शामिल कर लिया जाएगा।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं ये बातें रिटन में लिखकर दे दूंगा। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के के 80 प्रतिशत गांवों में एक भी ग्रान्ट नहीं दी गयी है। माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी कह रहे हैं कि उन्होंने सभी गांवों में ग्रान्ट्स दी हैं परन्तु मेरे हल्के के गांवों में ग्रान्ट्स नहीं दी गयी हैं और ग्रान्ट्स न मिलने के कारण सरपंच विकास कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, आप बैठ जाएं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन के दौरान मैंने लकड़िया गांव में मुरहा बफैलो फार्म बनाने की बात उठायी थी परन्तु सरकार द्वारा अभी तक मुरहा बफैलो फार्म नहीं बनवाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे बेरी हल्के के लकड़िया गांव में 35 वर्ष पुराना मुरहा बफैलो का फार्म था जो 8 एकड़ में बना हुआ था और वह फार्म डिमोलिस हो गया था और उसके स्थान पर लगभग 5–6 करोड़ रूपये की लागत से नयी बिल्डिंग बनवायी गयी है। सरकार ने वहां पर मुरहा बफैलो फार्म के स्थान पर एक पुलिस स्टेशन खोल दिया। अध्यक्ष महोदय, पहले लकड़िया गांव में मुरहा बफैलो का एक बहुत बड़ा सैंटर था और वहां पर इन्टर नेशनल लेवल की मार्केट थी तथा वहां पर हैलिकॉप्टर भी लैंड करते थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, प्लीज आप बैठ जाएं। आपकी बात कम्पलीट हो चुकी है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कदियानः अध्यक्ष महोदय, मेरी कुछ मांगे पब्लिक हैल्थ विभाग से भी संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त मेरे बेरी हल्के के सभी गांवों के हरिजनों को 100 यार्डस के प्लॉट्स दिये जाएं और एक रेलवे स्टेशन बनाने की डिमांड दुजाना–भंभेवा में है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आपने मेरी तारीफ की है। इसलिए मुझे भी आपको रोकना मुश्किल हो गया है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय जन स्वास्थ्य एंव अभियांत्रिकी मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे हल्के के गांवों में जितने भी पब्लिक हैल्थ विभाग के पानी के टैंक्स हैं, उनमें एक भी फिल्टर ठीक नहीं है। इसलिए उन फिल्टर्ज को ठीक करवाया जाए। इसके अतिरिक्त हैल्थ विभाग से संबंधित कुछ डिमांड्स हैं जिसमें जनरल हॉस्पिटल बेरी, कम्युनिटी हैल्थ सैंटर दुबलधन, कम्युनिटी हैल्थ सैंटर, छारा, प्राईमरी हैल्थ सैंटर, माजरा डी, प्राईमरी हैल्थ सैंटर, जहाजगढ़, प्राईमरी हैल्थ सैंटर, भंभेवा, प्राईमरी हैल्थ सैंटर, खरड़ में डाक्टर्ज और मेडिकल स्टॉफ की कमी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। मैंने कह दिया है कि आप अपनी बात रिटन में दे दें, उसको सदन की कार्यवाही में शामिल करवा दिया जाएगा। आपको बोलते हुए लगभग डेढ़ घंटा हो चुका है, प्लीज, आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य डॉ0 अभय सिंह यादव जी अपनी बात रखेंगे।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे बेरी हल्के के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप जो बातें कहना चाहते हैं वे रिटन में दें दे। आपकी बातों को सदन की कार्यवाही में शामिल कर लिया जाएगा।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार 'सबका साथ, सबका विकास,' की बजाय मेरे हल्के के साथ भेदभाव कर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप 50 मिनट पहले बोल चुके हैं और अब भी आपको बोलते हुए 30 मिनट का टाईम हो चुका है। अब अभय यादव जी बोलेंगे।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए 10 मिनट का टाईम दिया था परन्तु मुझे बोलते हुए अभी 2 ही मिनट ही हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है लेकिन माननीय सदस्य मेरा बोलने का समय बर्बाद कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। अभी दूसरे माननीय सदस्यों को भी अपनी बातें रखनी हैं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन यह है कि मुझे बोलने के लिए 5 मिनट का समय और दिया जाए। आप हमारी पार्टी के दूसरे माननीय सदस्यों का 5 मिनट का समय काट लें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने सबका साथ–सबका विकास के बजाय मेरे हल्के के साथ भेदभाव किया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, कृपया आप बैठ जाएं, आपका समय खत्म हो गया है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मुझे 5 मिनट का और समय दे दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन यह है कि सरकार का सबका साथ–सबका विकास का स्लोगन था, लेकिन मेरे बेरी हल्के के साथ भेद–भाव और डिस्क्रिमिनेशन यह हुआ है कि वहां पर सरकार ने अपनो का साथ, अपनो का विकास, किया है। जितने विधायक और मंत्री हैं, उनका सारा सौदा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है और इस तरह की एक कहावत भी है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने–अपने को दे। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि

The art and science of the administration is the equal and equitable distribution of natural resources among the masses. अध्यक्ष महोदय, यह फंडा डेमोक्रेसी का भी है और equal and equitable distribution का भी है और मैं बताना चाहूंगा कि इस फंडे की वायलेशन हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि यह इनकी सरकार का फंडा है। इनको पिछले 10 साल से यह फंडा याद नहीं आया। इनकी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मेरे हल्के में एक भी ईंट नहीं लगाई गई थी। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये एक मंत्री लैवल के आदमी होते हुए सिटिंग कमेन्ट्री कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जैसा कि यहां पर करप्शन की बात आई थी तो मैं बता देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में जो 183 देशों का सर्वे हुआ था, उसमें भारत का स्थान 179 से घटकर 81 हो गया है। इसके साथ ही साथ श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास जी और श्री उमेश अग्रवाल जी का भी बयान आया था कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पनप रहा है और श्री उमेश अग्रवाल जी ने ग्वाल पहाड़ी से संबंधित भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बिजली मीटर घोटाला, दो बार करनाल मे धान घोटाला, स्वर्ण जयंती समारोह घोटाला, गीता जयंती घोटाला, बायोमैट्रिक मशीन की खरीददारी में घोटाला, नगर–निगम, नगर–परिषद और कारपोरेशन में घोटाला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आउट–सोर्सिंग की भर्ती में भी घोटाला हुआ है, पार्कों का जो नवीनीकरण हो रहा है, उसमें भी जबरदस्त घोटाला हो रहा है। इसी तरह से राफेल विमान की खरीद में भी घोटाला हुआ है और अभी तक देश में लोकायुक्त की नियुक्ति भी नहीं हुई है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि शायद ये 2–जी स्पेक्ट्रम घोटाला भूल गए हैं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः आनरेबल स्पीकर सर, अगर हम इसके साथ–ही–साथ प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरे बेरी हल्के के बाजारों में व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और रोजाना लूट–डकैती, चैन स्नेचिंग, रेप,

मर्डर और फिरौतियों की घटनाओं से समाचार–पत्र भरे पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे बेरी हल्के में एक सुरेंद्र कुमार नाम का लड़का 5 लाख रुपए लेकर जा रहा था और उससे बदमाशों ने सारे पैसे छीन लिए और उसको चोट भी पहुंचा दी। उसके बाद वह लड़का एक महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा और अभी एक सप्ताह पहले ही उसकी मौत हो गई। अध्यक्ष महोदय, आज तक उसके हत्यारे को पकड़ा नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आपको आपकी मर्जी के हिसाब से बोलने का टाईम दे दिया गया था । प्लीज, अब आप बैठ जाये । (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत खुश नजर आ रहे हैं । मेरा आपसे एक निवेदन है कि जिस तरह से जींद उपचुनाव की जीत के बाद खुशियां मनाई जा रही हैं । सारे देश में पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से एक मांग आ रही है और विधान सभा से एक प्रस्ताव जाये कि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधान सभा चुनाव ई.वी.एम. (इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की बजाय बैलेट पेपर से हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये । अध्यक्ष महोदय, आज इस बारे में एक प्रस्ताव सदन में पास करके चुनाव आयोग को भेजने का कष्ट करें । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, ये ई.वी.एम. वाला सिस्टम किसकी सरकार में शुरू हुआ था। हमारी सरकार तो पहले भी ई.वी.एम. से चुनाव नहीं करवाना चाहती थी, यह सिस्टम कांग्रेस सरकार की ही देन है ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, जो वर्ल्ड में डिवैल्प्ड कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका और यूरोप में भी ई.वी.एम. मशीनों द्वारा नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आपने अपनी बात रख ली है इसलिए प्लीज आप बैठ जायें। आपको बोलने के लिए 5 मिनट से भी ज्यादा का समय दिया गया था । प्लीज, आप बैठ जायें । (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरे हल्के की कुछ डिमांड्स रह गई हैं। आपकी अनुमति हो तो मैं इनको सदन के पटल पर रख देता हूं। आप इन डिमांड्स को प्रोसिडिंग्स का पार्ट बनवा देना।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, कादियान साहब, आप इन डिमांड्स को सदन के पटल पर रख दें ।

***Dr. Raghuvir Singh Kadian :** Speaker Sir, I want to submit some indispensable demands of Beri Constituency to the Government for early action, which are as under:-

Beri Town:

1. Government College for Women.
2. Polytechnic Women College.
3. Bus Stand (outside near Mini Secretariat) on Beri-Jhajjar Road.
4. Sub-Depot of Haryana Roadways at Beri.
5. Huda Sector.
6. Bye pass.
7. Herbal Park in Chajjan Pana, Baithan Pana and Chulian Pana.
8. Community Centre.
9. Roundabout (Four).
10. Starting of Primary School at Bhagalpuri.

Roads:

Important roads whcih may be constructed as soon as possible:

1. Beri-Sheria road to Putlia Baba ka Mandir.
2. Chhara to Kultana.
3. Chhara to Rewari Khera (straightway alongwith Drain).
4. Beri-Dubaldhan road to Baba Tuta ka Mandir.
5. Bhadurgarh road to Mata Devi Ka Mandir (Chhara).
6. Manala Pond to Shiv Mandir (Chhara).
7. Beri-Dujana road to Nirachia ka Mandir.
8. From Matan Village to Chanderbhan Samadh (Freedom Fighter)

---

* चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त स्पीच को प्रोसिडिंग्स का पार्ट बनाया गया।

9. From Matan village to Dada Hikamwala Mandir (2 Kms.)

10. Majra (D) PWD road to Piliawala Pond.

11. Bye-Pass for Chhara Village on South side.

12. Bye-Pass for Dubaldhan on North side.

13. Bye-Pass for Matan village on Bhadurgarh-Beri Road.

14. Bye-Pass for Beri Town, Beri Kalanaur road to Beri-Jhajjar road.

Irrigation:

1. Extension of Rewari Khera Minor upto Kablana.

2. Chhudani drain (Kharman, Chhudani to KCB drain).

3. Bishan minor (allocation of time).

4. Bhambewa Minor (allocation of time).

5. Drainage (Bhambewa, Dimana Chuliana) to KCB drain.

6. Drain from Rohad to Kharhar.

7. Drainage for 250 acres land at Dhaur.

8. Drain for flood water village Dharana.

9. Bridge over KCB Drain for Bhaproda village.

10. Dighal Drainage for village flood water.

11. Dabodha Sub-Minor abandoned time 10 years water supply restored.

12. Drainage for Godhri and Safipur village.

13. Drainage from Majra (D), Siwana and Dubaldhan Ghikyan.

General:

1. Grants to each village.

2. Murrah Buffalo farm be started in Lakaria Village.

3. Grants for Chaupals.

4. 100 yards plots to Harizans in all villages of Beri Constituency.

5. Railway station Demand for Dujana, Bhambewa (Full-fill the criteria).

6. Road alongwith Railway line (West side) from Dujana to Bhambewa.

7. Bhambewa, Filling of low lying area Primary School.

8. Sheria, Filling of low lying area of High School.

Public Health:

1. Drinking water shortage in Bishan village be solved.

2. The filters of the water tank in every village of Beri Constituency be cleaned or replaced.

3. Drinking water shortage Beri Town be solved.

4. Shortage of pipes in every village of Beri Constituency.

Health

Shortage of Doctors and Medical staff to be fulfilled in the following villages:

1. General Hospital Beri.

2. Community Health Centre Dubaldhan.

3. Community Health Centre Dighal.

4. Community Health Centre Chhara.

5. Primary Health Centre Majra (D).

6. Primary Health Centre Barhana.

7. Primary Health Centre Jahajgarh.

8. Primary Health Centre Bhambewa.

9. Primary Health Centre Kharhar.

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं डॉक्टर कादियान जी का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम इन्होंने अपनी बात को कंक्लूड कर लिया ।

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यगण, अपनी–अपनी बातें थोड़े ही शब्दों में पूरा करने का प्रयास करें । अब डॉ. अभय सिंह यादव जी अपनी बात रखेंगे।

डॉ. अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी): अध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट अभिभाषण की बात है श्री असीम गोयल जी ने जो डाटा बताये हैं और डॉ. कादियान साहब ने जिस तरह से बात की है, उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि आंकड़ों में जाने की बजाये मैं कुछ और बातें कहूं । अध्यक्ष महोदय, बजट जो होता है वह सरकार का नीतियों और नियत का प्रतिबिम्ब होता है। सरकार तो लगातार चलने वाली एक सतत प्रकिया है लेकिन शासक बदलते रहते हैं। जब शासक बदलते हैं तो उसका माईंडसेट होता है, उससे सरकार की नीतियां और नियत दोनों निकलकर सामने आती हैं । अध्यक्ष महोदय, शासक अगर सरकारी साधनों का प्रयोग अपने हितों और अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए करता है तो उससे अनेक तरह की जैसे क्षेत्रवाद, वंशवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और बेईमानी बीमारियां पैदा होती हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सभी शक्तियां संविधान के अनुसार जब एक शासक को प्रदान की जाती हैं तो शासक उन शक्तियों का दुरूपयोग करता है तो ये सारी बीमारियां निकलकर सामने आती हैं । अध्यक्ष महोदय, अगर शासक संयम, दूरदर्शिता और बुद्धिमता से राज्य के संसाधनों का प्रयोग करता है तो राज्य को एक अलग दिशा मिलती है । हमारी सरकार ने प्रशासन को एक नई दिशा दी है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी प्रकिया शुरू की है कि जनभावना की जो जन समस्याएं थीं, उन सभी समस्याओं की एक–एक पहचान करके, उनको जड़ से निकालने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने वर्ष 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना शुरू किया था । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक लीक से हटकर काम किया है । अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि जब कोई शासक लीक से हटकर काम करता है तो स्थापित राजनीति कहलाती है । उसको स्थापित राजनीति के लोग कई तरह की परिभाषाएं देने लग जाते हैं, कोई अनुभवहीन बताता है, कोई कमजोर बताता है तो कोई नौसीखिया बताता है । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जनता की दृष्टि बड़ी गहरी होती है, बड़ी तीखी होती है और बड़ी पैनी होती है । जनता की दृष्टि बहुत सी चीजों को बड़ी नजदीकी से देखती है । उसके बाद उसके परिणाम भी आने शुरू हो जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, जब हम स्थापित राजनीति से कुछ हटकर काम करते हैं तो लोग हमें अनुभवहीन कहते हैं क्योंकि पहले वाले अनुभव शासक

को भ्रष्टाचार और बेईमानी का अनुभव होता है, तो वह शासक ऐसा अनुभवों का प्रयोग नहीं करता है । अध्यक्ष महोदय, जब किसी सरकार के पास संसाधन साथ होते हुए भी उन संसाधनों का जनहित के अलावा दूसरी तरह से दुरूपयोग न करे तो उसको लोग कमजोर कहने लग जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, जब जनता का मन बनता है तो जनता उस शासक को कसौटी पर परखती है और जब वह जनता की कसौटी पर खरा उतरता है तो अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है । अध्यक्ष महोदय, जब दूसरा शासक मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि वह क्या करें? अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आज हमारे हरियाणा प्रदेश में जो स्थिति और राजनीतिक हालात बने हुए हैं, उनको देखते हुए आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास कहने के लिए भी कुछ नहीं है। मन ही मन तो ये महसूस करते हैं कि हमारी सरकार सभी काम अच्छे कर रही है लेकिन लोगों के सामने जो ये दिखावा करते हैं और बातें करते हैं वे उन सबके मन की बातें नहीं होती हैं वह तो ये सिर्फ दिखाने और कहने के लिए ही करते हैं। मैं सरकार द्वारा किये गये कामों के बारे में बात करूंगा। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार आने से पहले किसान के नाम पर केवल खोखली और झूठी राजनीति हुई है। अभी डॉ. कादियान जी कह रहे थे कि हरियाणा का किसान कर्ज़ में डूबने के कारण आत्महत्या करने को विवश हो रहा है। मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि किसान केन्द्रित राजनीति हरियाणा बनने के बाद से पहली बार हमारी सरकार के समय में शुरू हुई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने पिछले समय जो विभिन्न फसलों के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये, वे अब तक के सर्वाधिक हैं। उसके बाद अब बाजरे का भाव 1100/– रूपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 1950/– रूपये प्रति क्विंटल हो गया। बाजरा उत्पादन करने वाले जो जिले हैं जैसे सिरसा, नारनौल, झज्जर, भिवानी इन इलाके के किसानों ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि कभी उनका बाजरा 2000/– रूपये क्विंटल के हिसाब से भी बिक सकता है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में कपास उत्पादक किसानों की कपास भी 6000/– रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी है। हमारी सरकार ने आते ही यह कहा था कि हम किसान की आमदनी को दुगुणा करने की कोशिश करेंगे। उस समय विपक्ष के माननीय साथियों द्वारा हमारी सरकार के इस कथन का मज़ाक उड़ाया जाता था। आज वास्तविकता यह है कि आज किसान की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारी सरकार के आने से पहले तो हालत यह

थी कि प्रदेश का किसान खेती करने से बचता था लेकिन अब ऐसा हो गया है कि किसान खेती करने की ओर अधिक से अधिक अग्रसर हो रहा है। इसी प्रकार किसान से रिलेटिड ही दूसरा मसला सिंचाई का है। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के सम्बन्ध में हरियाणा प्रदेश में दो तरह की दिक्कतें थी। प्रदेश के कुछ इलाकों में एक तरफ तो पानी की अधिकता के कारण जल भराव की समस्या थी व गीले रेगिस्तान का निर्माण हो रहा था और दूसरी तरफ हमारे भिवानी, महेन्द्रगढ़ और रेवाड़ी के इलाके थे जो कि भयंकर सूखे की मार से त्रस्त थे। हमारी सरकार ने सारी स्थिति का आकलन करने के बाद हमने इस समस्या का सर्वसम्मत समाधान निकाला। हमने किसी इलाके का पानी नहीं काटा बल्कि हमारी सरकार ने यमुना नदी का जो फालतू पानी था उसको लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम के माध्यम से उठाकर रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, नारनौल और भिवानी के इलाके में पहुंचाया। आज हमारे इन चारों जिलों में किसानों की फसलें लहलहा रही हैं। अगर विपक्षी पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को शक हो तो उसको इन चारों जिलों का एक चक्कर लगा लेना चाहिए उसका सारे का सारा शक दूर हो जायेगा क्योंकि इससे उसको पता चल जायेगा कि सरकार ने वहां पर क्या–क्या काम किये हैं। इन चारों जिलों में जमीन की एक क्यॉरी भी खाली नहीं है। वहां सारे के सारे इलाके में चना, गेहूं और सरसों की फसल लहलहा रही है। कपास की खेती के समय में बरसात के सीजन में पहली बार 112 दिन नहर चली है। हमारे क्षेत्र में बहुत पहले कपास की खेती हुआ करती थी लेकिन इस बार बहुत समय के बाद हमारे वहां पर कपास की खेती हुई है। वहां पर कपास की खेती से किसानों को 60,000/– रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से आमदनी हुई है। वहां पर जो छोटे–छोटे गांव हैं उनमें भी दो–दो व तीन–तीन करोड़ रूपये की कपास बिकी है। इस प्रकार से हमारे इलाके के किसानों की अर्थव्यवस्था करवट ले रही है। इसी प्रकार से सड़कों की बात है। हमारे सरकार ने आने के बाद भारत सरकार के सहयोग से पूरे हरियाणा प्रदेश में नेशनल हाईवेज़ का जाल बिछा दिया है। हरियाणा प्रदेश के लगभग हरेक हिस्से में कोई न कोई नेशनल हाईवे बन रहा है। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका हमारे रेवाड़ी और नारनौल को ही कहा जाता था। अब वहां पर नारनौल शहर के आस–पास से तीन नये नेशनल हाईवे बन रहे हैं। हाईवे नम्बर 148 बी नारनौल को कोटपुतली में राजस्थान से जोड़ रहा है, दूसरी तरफ हाईवे नम्बर 11 राजस्थान को रेवाड़ी से जोड़ रहा है। इसी प्रकार से एक नया ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे

बना है जो नारनौल से सीधा इस्माईलाबाद को जोड़ रहा है। उसकी लैंड एक्वीजिशन का काम कम्पलीट हो गया है और टैण्डरिंग की प्रोसैस शुरू हो गई है। हमें उम्मीद है कि इस हाईवे का काम भी जल्दी से जल्दी शुरू हो जायेगा। इसी प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश की सड़कों का रख रखाव भी बेहतर ढंग से हो रहा है। आज हमारे प्रदेश की सभी सड़कों की स्थिति इतनी अच्छी है जैसी कि पिछले 20–30 साल पहले कभी नहीं रही होगी। इसी प्रकार से हमारी सरकार द्वारा बिजली की व्यवस्था में सुधार किया गया है। हमारी सरकार द्वारा बिजली के बिल माफ करने के बजाये किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली के बिल के रेट्स कम करके उनको सीधा फायदा पहुंचाया जा रहा है। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि बातें करते समय और प्रचार करते समय कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है क्योंकि हमारे यहां प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में सभी को अपनी बात अपने हिसाब से कहने का अधिकार है लेकिन वास्तव में हर समस्या की जड़ में जाकर हरेक समस्या को सुलझाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार का यह काम काबिल–ए–तारीफ है। अभी माननीय सदस्य डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी कह रहे थे कि विभिन्न मदों में बजट एलोकेशन घट रही है। डॉ. साहब बड़े पड़े–लिखे आदमी हैं। वे परसैंटेज की बात कह रहे थे कि विभिन्न विभागों में परसैंटेज ऑफ एलोकेशन कम हो रही है। लेकिन जब एक बार बढ़ोतरी की जाती है तो अगली बार उसमें उतनी बढ़ोतरी नहीं होती है, कम ही होगी लेकिन बजट का टोटल अमाउंट हर साल बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, डॉ. कादियान कह रहे थे कि वित्त मंत्री जी के बजट के आंकड़ें गुमराह करने वाले हैं तो मैं कादियान साहब को कहना चाहता हूं कि इन्होंने भी आंकड़ों को घुमाफिराकर ही पेश किया है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, डॉ. अभय सिंह यादव जी ने कहा है कि मैंने आंकड़ों को घुमाफिराकर पेश किया है। अगर बजट ऐलोकेशन की परसैंटेज में डिक्रीज नहीं हुआ है तो मेरे खिलाफ सदन को गुमराह करने के लिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय कुल बजट 70,000/– करोड़ रुपये था । उस समय एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड सर्विसेज का बजट 8,000/– करोड़ रुपये का था। जब कुल बजट बढ़ कर 1 लाख करोड़ रुपये का हो गया तो एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड सर्विसेज का बजट 8500/– करोड़ रुपये हो गया और अब जब बजट 1,32,000/– करोड़ रुपये हो गया है तो

एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड सर्विसेज का बजट 9000/– करोड़ रुपये हो गया है। इस प्रकार से जहां तक अमाउंट की बात है तो अमाउंट तो बढ़ा है लेकिन कुल बजट के परसैंटेज के हिसाब से एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड सर्विसेज का बजट डिक्रीज हुआ है।

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, हम तो यही बात कह रहे हैं कि अमाउंट बढ़ा है और डॉ. कादियान ने उस बात को मान लिया है कि अमाउंट बढ़ा है। दूसरी बात यह है कि अगर हम इमरजैंसी को राजनीति का वाटरशैड मानें तो इमरजैंसी के बाद हरियाणा की राजनीति धीरे–धीरे राजघरानों, राजवंश और राजपरिवारों से बाहर निकल कर आ रही है। पहले हरियाणा में राजपरिवारों के नाम पर राज होता था लेकिन पहली बार किसी आम परिवार को, आम आदमी को स्टेट की लीडरशिप मिली है। जनता की जो तकलीफ होती है जब तक आप उसको अपने अन्दर महसूस न करो तब तक जनता की उस तकलीफ का समाधान नहीं निकलता है। एक आदमी जो पहले ही चांदी की चम्मच के साथ पहाड़ी की चोटी पर पैदा होता है उसको आम जनता की समस्याओं का कोई पता नहीं होता है। आम जनता के दर्द के बारे में तो वही व्यक्ति जान सकता है जो आम जनता के बीच रहा हो और जो आम जनता की तकलीफों से वाकिफ हो। मेरा अपना यह मानना है कि यह हमारे स्टेट का सौभाग्य है कि हरियाणा की राजनीति एक ऐसे तरीके से चल रही है जिसका एक मात्र मकसद जनकल्याण है। जो पॉलिसीज बनती हैं उनमें आम जनता के बारे में सोचा जाता है। किसी व्यक्ति विशेष, किसी क्षेत्र विशेष या किसी भी जाति–पाति या भाई भतीजावाद सबसे ऊपर उठ कर राजनीति हो रही है। मैं अपने विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि अच्छी बात की प्रशंसा करनी चाहिए। हमारे विपक्ष के साथियों की बाहर प्रशंसा न करने की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है लेकिन ये मन ही मन तो प्रशंसा अवश्य करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह (एस.सी.)(सढौरा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारे काबिल वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वह सराहनीय है। जब से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था में नये आयाम

स्थापित किये हैं। वर्ष 2013–14 में अर्थव्यवस्था में हमारा देश विश्व में 11वें पायदान पर था आज 2018–19 में 6वें पायदान पर आ गया है और 2030 तक यह विश्व में दूसरा पायदान हासिल करेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देकर समाज के सभी वर्गों के गरीबों को बराबरी का दर्जा दिया है। इसी प्रकार से जी.एस.टी. में बहुत सी वस्तुओं पर जो जी.एस.टी. की दर कम करके आम जनता को राहत दी है उससे यह हमारे विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की सराहना करता हूं। प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री जी ने जो वर्ष 2019–20 का जो बजट पेश किया है उसमें वर्ष 2019–20 के बजट में 1,32,165.99 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है । यह पिछले बजट से 14.73 प्रतिशत अधिक है जो एक अपने आप में सराहनीय है । आज हर सैक्टर में बजट को बढ़ाकर दिया गया है । एग्रीकल्चर सैक्टर में वर्ष 2018–19 में 3660 करोड़ रुपये का बजट था जिसको बढ़ाकर वर्ष 2019–20 में 3834 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है जिसमें 4.5 प्रतिशत की वृद्धि है । कॉपरेटिव में वर्ष 2018–19 में 807 करोड़ रुपये का बजट था जिसको बढ़ाकर वर्ष 2019–20 में 1396 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है जिसमें 74 प्रतिशत की वृद्धि है। राजस्व और आपदा प्रबंधन में वर्ष 2018–19 में 293 करोड़ रुपये का बजट था जिसको बढ़ाकर वर्ष 2019–20 में 1512.42 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है जिसमें 43.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । स्वास्थ्य जोकि प्रदेश का एक महत्वपूर्ण विभाग है उसमें भारत के प्रधान मंत्री जी ने सर्वे के मुताबिक यह योजना बनाई है कि एक व्यक्ति अपना 5 लाख रुपये तक का इलाज कहीं भी करवा सकता है। वह एक बहुत बड़ा कदम है । इसी तरह से हरियाणा प्रदेश में भी वर्ष 2018–19 में 4486 करोड़ रुपये का बजट था जिसको बढ़ाकर वर्ष 2019–20 में 5040.65 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है जिसमें लगभग सवा बारह प्रतिशत की वृद्धि है। जहां तक हायर एजुकेशन की बात करते हैं जहां से हमारा विकास शुरू होता है। उसके लिए वर्ष 2018–19 में 11,256 करोड़ रुपये बजट था जिसको बढ़ाकर वर्ष 2019–20 में 12,307.46 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है जिसमें 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । तकनीकी शिक्षा में जिससे हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके और बच्चे अच्छे पढ़–लिख सकें तथा आगे जाकर वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें । वर्ष 2018–19 में 465.70 करोड़ रुपये का बजट था जिसको बढ़ाकर वर्ष 2019–20 में 512.72 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है जिसमें 10.1 प्रतिशत

की वृद्धि हुई है। खेल और युवा मामले में जिसमें हमारी सरकार ने खिलाड़ियों को बहुत से इनाम भी दिए हैं और जिसमें हमारे प्रदेश के बच्चे एशियार्ड गेम्ज में अपने तमगे लेकर आए हैं। उसमें वर्ष 2018–19 में 131 करोड़ रुपये का बजट था जिसको बढ़ाकर वर्ष 2019–20 में 401.17 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है । जो बहुत ज्यादा है। इसी तरह से रोजगार के मामले में भी वर्ष 2018–19 में 241. 44 करोड़ रुपये का बजट था जिसको बढ़ाकर वर्ष 2019–20 में 365.20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है जिसमें 51.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसी तरह से इरिगेशन विभाग में जिसके बारे में आज तक यह हाहाकार मचती रही कि दक्षिण हरियाणा को पानी नहीं मिलता है । इस महान सदन में दक्षिण हरियाणा के माननीय विधायकों ने यह माना है कि उनके क्षेत्र में अन्तिम छोर तक पानी गया है। उसके लिए वर्ष 2018–19 में 3,130.63 करोड़ रुपये का बजट था जिसको बढ़ाकर वर्ष 2019–20 में 3,324.51 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है जिसमें 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जोकि यह दर्शाती है कि वित्त मंत्री जी ने बजट के हर पहलू पर हर विभाग के लिए अलग–अलग से बढ़ा कर बजट दिया है जो अपने आप में सराहनीय है । पब्लिक हैल्थ विभाग में जहां पीने के पानी की दिक्कतें थी उसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018–19 में 3590.47 करोड़ रुपये का बजट था जिसको बढ़ाकर वर्ष 2019–20 में 3605.32 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इसके साथ ही बिजली के मामले में जोकि विकास का अहम अंग है । जहां पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले कभी भी बिजली नहीं आती थी । अब हमारी सरकार ने प्रदेश के आधे गांवों में 24 घण्टे बिजली देने का काम, तारें बदलने, 33 के.वी. और 66 के.वी. लगाने का काम किया है जिसमें 12988.67 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान है जोकि बहुत बढ़िया है । इसके साथ ही आज अगर हम हरियाणा प्रदेश की सडकों की बात करें, चाहे वह नैशनल हाई–वे हैं, चाहे वह दूसरी सडकें है। आज साढ़े चार साल में पूरे हरियाणा में वह सारी सडकें चमचमाती हुई दिखाई दे रही हैं। यह नहीं है कि केवल रोहतक डिविजन में ही अच्छी सडकें हैं बल्कि हरियाणा के हर भाग में चाहे वह दक्षिणी क्षेत्र है, चाहे उत्तरी है, चाहे पश्चिमी क्षेत्र है, आज जो सड़कों का जाल बिछा है और जो सडकें बनी हैं वह अपने आप में बहुत बड़े विकास की धुरी है । उसके लिए वर्ष 2018 में 3169.70 करोड़ रुपये का बजट था जिसको बढ़ाकर वर्ष 2019–20 में 3626.21 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है जिसमें 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई

है। इसी तरह से शहरी निकाय विभाग में भी आज 3993.95 करोड़ रुपये का बजट है। चाहे सूचना व जनसंपर्क विभाग हो, सभी में हर चीज का ख्याल रखा जाता है। जहां तक नौकरी देने की बात है, आज हमारी सरकार ने निष्पक्ष और पारदर्शिता से 54 हजार के करीब गरीब बच्चों को जिनको यह भी पता नहीं था कि हमें नौकरी मिल जाएंगी, उनको नौकरी देने का काम किया है। उसके लिए हम सरकार की सराहना करते है तो इस प्रकार वित्त वर्ष 2018–2019 के बजट में सूचना एंव जनसंपर्क विभाग के लिए जहां 1364 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया था वही वर्ष 2019–20 के बजट में इसको 1873 करोड़ रूपये करने का काम हमारी सरकार ने किया है अर्थात पिछले बजट की अपेक्षा वर्तमान बजट में 37 परसेंट ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के लिए पिछली बार 6348.62 करोड़ रूपये का प्रावधान था लेकिन वर्तमान वित्त वर्ष में इसके लिए 7899.12 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है यानी 13.50 परसेंट के करीब इस मद पर वर्तमान बजट में वृद्धि की गई है। कुल मिलाकर यह एक सराहनीय बजट है जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री तथा हमारे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी बहुत–बहुत बधाई के पात्र है। स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया। धन्यवाद

श्री श्याम सिंह (रादौर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कल जो बजट सदन में पेश किया गया है इसकी चारों और भूरि–भूरि प्रशंसा की जा रही है। मैं एक किसान हूँ और किसान होने के नाते इस बजट में किसानों के हित के लिए जो बातें कही गई हैं उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से यह बजट तारीफ के योग्य है। भारत वर्ष एक कृषि प्रदान देश है यदि वातावरण, जलवायु या जमीन के हिसाब से हम दुनिया की 100 एकड़ अच्छी और उपजाऊ जमीन के बारे में बात करें तो पायेंगे कि हिंदुस्तान के पास पूरी दुनिया की 25 एकड़ अच्छी और उपजाऊ जमीन है और यही कारण है कि धीरे–धीरे हमारे देश के किसान की स्थिति में निरंतर बदलाव आता गया है। वर्ष 1964 में जब मैं मैट्रिक क्लास में था, उस समय गांव का किसान अपनी जमीन से साल भर में महज एक फसल लिया करता था। उसके पास पहले भदवाड़ होता था, उसके बाद लकड़ी या लोहे का हल आया, फिर बैलों की एक छोटी सी हीरो आई, बाद में मैसी फर्गुसन ट्रैक्टर आया, फिर गायटा आया, फिर फलसा आया और फिर एक छोटी सी मशीन जिसको घूघू कहते थे, वह आई

इनके काफी बाद जाकर कंबाईन आई। कहने का मतलब यह है कि किसान के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों में बड़ा भारी परिवर्तन आया लेकिन उसकी फसल के जो दाम जिस स्पीड से बढ़ने चाहिए थे, उस स्पीड से दाम नहीं बढ़े लेकिन जो दूसरी चीजें हैं उनके रेट समय–समय पर जरूर बढ़ते रहे। अगर कभी किसान ने कोशिश की कि उसकी फसलों के दाम बढ़ने चाहिए तो उस समय की जो भी सरकार थी वह किसान को यह कहकर चुप करा देती थी कि जो कृषि की फसल है वह एसेंशियल आईटम्ज में कवर होती है और खाने के काम आती है इसलिए इनका रेट हम नहीं बढ़ा सकते लेकिन बावजूद इसके किसान अपनी मेहनत के बलबूते देश के लोगों का पेट भरते रहे और गरीब होते चले गए और किसान की हालत माड़ी होती चली गई। आज हमारे विपक्ष के साथी किसान हित की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अच्छा यह होता अगर ये लोग अपनी–अपनी सरकार के शासनकाल में किसान के हितों का ध्यान रखते और जिस स्पीड से दूसरी चीजें के दाम बढ़े, उसी स्पीड से यदि किसान की फसलों के दाम बढ़ाने की तरफ ध्यान देते तो आज किसान की हालत इतनी दयनीय नहीं होती। मुझे याद है मैं वर्ष 1966 में हॉयर सैकेंडरी में हुआ करता था, उस समय जब गेहूं का रेट बढ़ा तो महज 50 पैसे प्रति क्विंटल बढ़ा था। यह ऑन रिकॉर्ड और बहुत ही शर्म की बात है कि महज 50 पैसे प्रति क्विंटल तत्कालीन सरकार ने किसान के गेहूं का रेट बढ़ाया। यदि कोई चाहे तो रिकॉर्ड निकालकर देख सकता है। परन्तु हमारी भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसान की फसलों के दाम इस प्रकार से देने का प्रावधान किया कि किसी भी सूरत में किसान को लॉस नहीं होना चाहिए। किसी एरिया की कोई भी फसल जिसकी किसान खेती करते हैं, उस फसल के दाम इस तरह से देने का काम किया कि किसी भी सूरत में किसान को लॉस नहीं होना चाहिए। चाहे कोई किसान बाजरे की खेती करे या चाहे फिर वह कपास की ही खेती क्यों न करे, उसको किसी भी सूरत में लॉस नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यदि

16.00 बजे

भारत वर्ष के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पता लगाएं कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो अपने राज्य में सभी वर्गों का ख्याल रखता है और सभी वर्गों का समान रूप से विकास करवाता है तो निश्चित तौर से उसमें हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का नाम सबसे ऊपर आता है। श्री मनोहर लाल जी ने पूरे प्रदेश में ईमानदारी से काम किया है। हरियाणा प्रदेश में काफी किसान आलू

की खेती करते हैं लेकिन इसमें किसानों को उचित रेट न मिलने की वजह से इतना घाटा उठाना पड़ता है कि उन्हें आलूओं को सड़कों पर फेंकना पड़ता है। 'भावांतर भरपाई योजना' जो हमारी सरकार ने शुरू की है वह बहुत ही बढ़िया योजना है। इस योजना के तहत किसानों को आलू पर 4 रुपये प्रति किलो का रेट दिया गया है। कभी–कभी आलू का रेट 2 रुपये प्रति किलो हो जाता था लेकिन जैसे ही किसान अपना आलू मण्डी में ले जाकर 'जे' फार्म कटवाता है वैसे ही उसके नुकसान की भरपाई हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, चाहे इस 'भावांतर भरपाई योजना' में प्याज, टमाटर या गोभी की भी फसल हो उसमें भी यह योजना लागू कर दी है। हमारी सरकार पशुओं की तरफ भी काफी ध्यान दे रही है। मुझे वह दिन भी याद है जब हम आपके साथ हैदराबाद में एक सैमिनार में गए थे। हमने वहां पर पशुओं के लिए जो चीज देखी थी वह बहुत ही बढ़िया थी। अध्यक्ष महोदय, हमने वहां देखा कि किसानों ने गांव के बाहर पंचायत जमीन में एक बहुत बड़ा बेड़ा पशुओं के लिए बना रखा है और उसकी चार दीवारी भी बना रखी है। उस गांव के जितने भी पशु पालक हैं उन सबके पशुओं को वहां इकट्ठा किया हुआ था। उस बाड़े में पशुओं के गोबर को भी एक जगह इकट्ठा किया जाता था। लोग गोबर लेने के लिए आते थे और गोबर को खाद बनाने के लिए ट्रकों में ले जाते थे, इससे किसानों को गोबर से भी आमदनी हो जाती थी। लगभग 60 किसानों का वह बाड़ा था, इसलिए हर किसान का लगभग 2 महीने के बाद उस बाड़े की पहरेदारी का समय आता था। उस बाड़े में डॉक्टर्ज, बिजली, पानी सारी सुविधाएं होती हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे अच्छा काम तो यह होता था कि गांव की सफाई रहती थी, जो स्वच्छ भारत मिशन को भी चरितार्थ करता है। इस तरह से गांव में गंदगी न होने की वजह से कोई भी मक्खी या मच्छर पैदा नहीं होते और गांव का सरपंच मक्खी या मच्छर के बारे में यह कहने लगा कि यदि गांव में से कोई भी व्यक्ति एक मक्खी या मच्छर लेकर आयेगा तो उसे 100 रुपये ईनाम दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरह का एक और अच्छा काम हमारी सरकार को करना चाहिए। हमारी सरकार ने गन्ना किसानों को देश में सबसे ज्यादा भाव दिया है। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज्यादा विकास के काम किए हैं। यदि किसी किसान का एक रुपया का भी नुकसान होता है तो उसका भी ख्याल सरकार को रखना चाहिए। अगर किसी किसान के खेत में पानी खड़ा है और उसकी वजह से उसकी फसल खराब हो रही है तो सरकार को उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

मेरे हल्के में एक किसान जिसका नाम श्री राम सिंह है, के खेत में पानी खड़ा था और उसकी फसल खराब हो रही थी तो मैंने जाकर उस किसान से पूछा कि क्या दिक्कत हो रही है? उस किसान ने कहा कि आस–पास के किसान पानी नहीं निकालने दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उसका समाधान करने के लिए उसके खेत में से अंडर ग्राउण्ड पाइप बिछाई गई और वह बरसाती नाला तक ले जाई गई। इससे उस किसान की समस्या का समाधान किया गया। इस प्रकार से किसी भी किसान की फसल पानी खड़ा होने के कारण खराब हो रही हो तो सरकार को उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। खेतों में आने–जाने के लिए छोटे रास्ते हैं, इस कारण से किसानों को अपने साधन खेतों में ले जाने के लिए काफी परेशानी होती है। हमने रादौर के अंदर अपने फंड में से रास्ते बनाए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र में गए थे और मुझसे कहने लगे कि आपके हल्के में क्या–क्या समस्याएं हैं तो मैंने अपनी इस समस्या का जिक्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रख दी और कहा कि हमारे क्षेत्र में 5 हजार एकड़ के रास्ते बकाया हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय यह आश्वासन दिया कि पूरे हरियाणा में किसानों के लिए रास्ते बनाए जायेंगे। यह बहुत ही अच्छी बात है, यदि 2,3 या 4 करम का रास्ता किसानों के लिए बना देते हैं तो किसानों को बहुत ज्यादा सुविधा हो जायेंगी। आज किसान तो यह कहता है कि हमें चाहे हमारे पैसों से ही बचा लो लेकिन हमें किसी भी तरह से बचा लो। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हमारी सरकार ने हर किसान की तरफ ध्यान दिया है। हमारी सरकार ने हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज बना दिया है। मैं तो यह कहता हूँ कि कॉलेज के साथ–साथ हर 20 किलोमीटर के दायरे में या हर ब्लॉक में एक पशुओं के लिए प्रयोगशाला खोली जाए ताकि उस प्रयोगशाला में पशुओं के खून, गोबर आदि का टैस्ट हो सके। जिससे पशुओं की बीमारियों का पता लगाया जा सके। (**इस समय सभापतियों की सूची में से श्री ज्ञान चंद गुप्ता पदासीन हुए**।) सभापति महोदय, हमारी सरकार ने नम्बरदारों का मानदेय 1500 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है। सरकार ने यह बहुत ही अच्छा काम किया है। प्रदेश में ई–सेवा केन्दों की स्थापना होने से बहुत बड़ी समस्या लोगों की हल हो गई है। पहले लोगों को रजिस्ट्री/राशन कार्ड/गिरदावरी आदि कामों के लिए यहां–वहां जाना पड़ता था और अब एक ही छत के नीचे लोगों के सब काम हो जायेंगे। हमारी सरकार ने बिजली के दामों में कटौती की है। जिसके बिल अभी तक पैंडिंग पड़े हुए हैं,

सरकार को उनको एक मौका और देना चाहिए क्योंकि किसानों के पास गन्ने की अदायगी अभी आई है और गेहूं की अदायगी आनी बाकी है। अगर सरकार किसानों को बिजली बिल भरने का एक मौका और देती है तो वह अपनी इस समस्या का समाधान कर सकता है। इसी तरह से सरकार को ट्रैक्टर के कर्ज के बारे में और पशुओं के कर्जे के बारे में कदम उठाना चाहिए। सभापति महोदय, सौर ऊर्जा के बारे में आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में सूर्य की बहुत तेज रोशनी रहती है, कई देशों में तो सूर्य की तेज रोशनी केवल 2 घंटे ही रहती है। हमें ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने चाहिए ताकि हम सौर ऊर्जा से अपने घरों में बिजली उपकरणों के साथ–साथ टयूबवैलों में भी सौर ऊर्जा से प्राप्त बिजली का इस्तेमाल कर सके।

सभापति महोदय : श्याम सिंह जी, अब आप वाईंड–अप कीजिए।

श्री श्याम सिंह : सभापति महोदय, हमारी सरकार हर क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रही है। सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री भगवान दास कबीर पंथी (अ.जा.) (नीलोखेड़ी) : सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सभापति महोदय, एक बेहतरीन बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत–बहुत बधाई देता हूँ। बजट में हर क्षेत्र जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़कें आदि व हर वर्ग मजदूर, व्यापारी, किसान, कर्मचारी आदि सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत सारे स्कूल्ज अपग्रेड किए हैं। लड़कियों के लिए अलग से कॉलेजिज खोले हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले वर्ष एक साथ 22 कॉलेजिज खोलने का उदघाटन किया था। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में वर्षों से एक कॉलेज खोलने की मांग चली आ रही थी लेकिन किसी भी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, केवल 20 वर्ष पहले कांग्रेस सरकार ने एक कॉलेज अढ़ाई एकड़ जमीन पर खोलने के लिए एक पत्थर जरूर लगाया था। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने ही हर क्षेत्र में कॉलेज बनाने का काम किया है और इस प्रकार से उस कॉलेज में पिछले वर्ष से क्लासिज़ भी शुरू हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निसिंग में भी एक कॉलेज की सौगात दी है और एक इंजीनियरिंग कॉलेज नीलोखेड़ी में खोला गया है। सभापति महोदय, मुझे आपके माध्यम से सदन को यह

बात बताते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले कई वर्षों से लम्बित मेरे क्षेत्र की डिमांड्स को पूरा किया है। इसके अतिरिक्त मैं कृषि के क्षेत्र की बात करूं तो सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया है उसमें चाहे फसलों के दाम बढ़ाने की बात हो या उनकी फसलों का एम.एस.पी. पर एक–एक दाना खरीदने की बात हो, हमारी सरकार ने ये सभी काम पूरे किये हैं। अनाज मंडियों में फसलों को बेचने के समय पर किसानों को बारदाना, लिफ्टिंग तथा किसी अन्य प्रकार की परेशानी न आए, उसका पूरा ध्यान रखा है। इसके लिए सरकार ने किसानों की फसलों के भाव में पिछले साल से 4.50 प्रतिशत की वृद्धि करके किसानों को तोहफा दिया है। इस साल भी मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों की जरूरतें पूरी होंगी। पहले की सरकारों के समय में सड़कों की हालत खराब हो चुकी थी परन्तु आज हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। इसके अतिरिक्त जो 5–6 करम के रास्ते थे जिनको बढ़वाने के लिए लोग वर्षों से इन्तजार कर रहे थे। लोग सोचते थे कि अगर ये रास्ते चौड़े कर दिये जाएंगे तो आने–जाने में काफी सुविधा होगी। हमारी सरकार ने इन रास्तों को चौड़ा किया है और कच्चे रास्तों को भी पक्का किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे रास्ते थे जहां से स्कूटर्ज व साईकिलों से जाना भी बन्द हो चुका था। अध्यक्ष महोदय, अगर आंकड़े निकालकर देंखे तो पता चलेगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की कोई भी ऐसी सड़क नहीं है, जहां पर काम न हुआ हो। मेरे विधान सभा क्षेत्र में हर सड़क को 12 फुट से 18 फुट चौड़ा किया है। इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई नये रास्ते भी बनाये गये हैं। सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए नये–नये स्टेडियम बनाये हैं। मेरे हल्के के जांबा, सिकरी, समाना बाहु तथा दूसरे गांवों में बच्चों के खेलने के लिए लगभग 6 स्टेडियम बनाये हैं ताकि बच्चे खेलों के माध्यम से भी आगे बढ़कर अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। सरकार ने मेरे विधान सभा हल्के में काफी विकास कार्य करवाएं हैं लेकिन अभी कुछ समस्याओं का समाधान करवाया जाना भी बाकी है। मेरा विधान सभा हल्का काफी वर्षों से शोषित रहा है। अभी कुछ दिन पहले सरकार द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत गांवों में सर्वे करवाये थे और प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत गांवों में मकान बनाकर देने की बात की

गयी थी परन्तु मेरे हल्के के कुछ लोगों के पास जमीन की रजिस्ट्री नहीं है, उनके पास असैसमेंट है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार ने अनुरोध है कि उन लोगों को असैसमेंट के आधार पर प्रधान मंत्री आवास योजना में शामिल किया जाए ताकि संबंधित लोगों का भी मकान बनवाया जा सके। इसके अतिरिक्त मेरी एक मांग यह है कि नीलोखेड़ी को सब डिविजन का दर्जा दिया जाए, यह जी.टी. रोड पर स्थित है और निशिंग में सब तहसील है, उसको तहसील का दर्जा दिया जाए। निशिंग की अनाज मंडी शहर के बीचों–बीच है और सरकार ने अभी करनाल से कैथल फोरलेन बनाने का काम शुरू किया है इसलिए वहां से बाई–पास निकाला जाए ताकि जाम व दुर्घटनाओं से छुटकारा मिल सके। सभापति महोदय, मैंने आपके माध्यम से सरकार के सामने मेरे हल्के की कुछ डिमांड्स रखी हैं, इनको पूरा करवाया जाए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का एक अच्छा बजट पेश करने के लिए धन्यवाद करता हूं।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल (जुलाना): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट पेश करते हुए आंकड़ों की बाजीगरी करके सरकार की सेहत अच्छी दिखाने की कोशिश की गयी है। अगर इस बजट को ध्यान से पढ़ा जाए तो हम इसको देशी भाषा में जलेबी कह सकते हैं। यह जलेबी भी गोहाना वाली जलेबी की तरह नहीं है बल्कि छोटी–छोटी जलेबियों का समूह है। प्रदेश सरकार द्वारा बहुत बड़ा बजट पेश किया गया है परन्तु इस बजट का 1/3 प्रतिशत ही बचेगा यानी 66 प्रतिशत बजट सैलरी, पैंशन और डैट की अदायगी पर खर्च किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए सरकार के पास सिर्फ 1/3 प्रतिशत बजट ही बचा है। अगर पूरे बजट का एस्टिमेट लगाएं तो सरकार के पास केवल 1/3 प्रतिशत बजट ही बचा है जिसको सरकार ने दावा किया है कि विकास की योजना पर खर्च किया जाएगा। सभापति महोदय, वर्ष 2015 में सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया था। इस श्वेत पत्र के जरिए वर्तमान सरकार ने पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2014 तक हरियाणा प्रदेश की जनता पर कर्जे की मार की और यह बात श्वेत पत्र का मुख्य हिस्सा थी। सभापति महोदय, हमें वर्तमान सरकार से यह आशा थी कि जो पिछली सरकार के समय 71 हजार करोड़ रुपए का हरियाणा की जनता के ऊपर कर्जा था, उसमें कमी लाएगी। लेकिन वर्तमान सरकार

ने तो सारे ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1 लाख 9 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्जा हरियाणा की जनता के ऊपर डाल दिया है और इस तरह से आज हरियाणा की जनता के ऊपर कुल 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का इतना बड़ा कर्ज का भार लाद दिया गया है। सभापति महोदय, अगर हम पूरे बजट का हिसाब लगाएं तो पाएंगे कि बजट एस्टिमेटस में 9 परसैंट फालतू है और जिसका पिछले साल से 4 परसैंट डैट में फालतू जा रहा है और 1 परसैंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फालतू जा रहा है। सभापति महोदय, इस तरह से वर्तमान सरकार के पास बजट एस्टिमेटस का केवल 4 परसेंट ही बचा है और सरकार को इस 4 परसैंट से ही आंकड़ों की बाजीगरी करते हुए सारी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करनी है। सभापति महोदय, मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार अपने दावे को कैसे पूरा कर सकेगी, क्योंकि सरकार की प्राप्तियां घट रही हैं। सभापति महोदय, अगर हम सरकार के पिछले बजट को देंखे तो पता चलेगा कि वर्ष 2018–19 के बजट में नॉन–टैक्स रेवेन्यू 9.81 परसेंट था, जो अब घटकर 7.51 परसेंट हो गया है। सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2018–19 में राज्य की जो अपनी प्राप्तियां 42.65 परसैंट थी, वह अब घटकर वर्ष 2019–20 में 38.67 परसैंट हो गयी हैं। इस तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू और प्राप्तियां कम होती जा रही हैं। हमें बजट एस्टिमेटस में पैसे बहुत दिखते हैं, लेकिन यह कटौती होती जा रही है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे और जैसा कि हमारे साथियों ने भी कहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्ष 2017–18 में बजट की राशि 12.49 परसैंट थी, वह घटकर 10.31 परसेंट हो गई है। इसी तरह से सोशल सर्विसेज में बजट एस्टिमेटस 7.46 परसैंट था, जो अब घटकर 7.5 परसैंट हो गया है। पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग में 3.31 परसैंट था जो अब घटकर 2.71 हो गयी है। ट्रांसपोर्ट में 6.23 परसैंट था, जो घटकर 4.12 परसैंट हो गया है। हैल्थ एण्ड फैमिली वेल्फेयर में वर्ष 2018–19 में 4.44 परसैंट थी, जो अब घटकर 3.80 पर आ गयी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार का जनरल सर्विसेज में बजट एस्टिमेटस बढ़ा है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज पहली बार श्री परमेंद्र सिंह ढुल जी बजट के ऊपर बोलते हुए आंकड़ों की बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, परमेंद्र सिंह ढुल जी, क्रिमिनल केसिज के एडवोकेट हैं और ये आज फाइनैंस जैसे विषय के ऊपर बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको आंकड़ों की एक लिस्ट सर्कुलेट हो गयी है। सभापति महोदय, मैं

आपके माध्यम से माननीय सदस्य ढुल साहब जी से कहना चाहूंगा कि मैं इनकी मद्द में ही खड़ा हुआ हूं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये यहां पर आज बीबीपुर का जिक्र नहीं कर रहे हैं, जबकि यह समय इनको अपनी गांव की समस्याओं के बारे में बोलने के लिए मिला है।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुलः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैं बीबीपुर की ही बात कर रहा हूं और पूरे सदन में मंत्री जी पर इल्जाम लगाता हूं कि इन्हें बीबीपुर में आमजन को फायदा पहुंचाने वाले जो काम करने चाहिए थे, वे भी नहीं किए, लेकिन बावजूद इसके हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सैशन में मैंने आपको तथा शिक्षा मंत्री जी को बीबीपुर के लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में लिखकर दिया था और इन्होंने आश्वासन दिया था कि वहां की समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा, लेकिन एक साल पूरा हो गया है और इन्होंने कुछ भी नहीं किया है।

श्री राम बिलास शर्माः सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि बीबीपुर गांव का स्कूल सबसे पहले हमने ही बनवाया था।

श्री परमेंद्र सिंह ढुलः सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो शिक्षा के ऊपर बजट रखा है, वह वर्ष 2017–18 में 14.24 परसैंट था, जो अब 19.20 परसैंट हो गया है। कई दिन पहले इस सदन में चर्चा चल रही थी और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी चर्चा की थी। पिछले साल सरकार ने 8228 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा का अनुमान लगाया था जो वास्तव में बढ़कर 8506 करोड़ रुपए के लगभग आया। इस बार भी सरकार ने 12022 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा का अनुमान लगाया है, मेरे ख्याल से जिस तरह से पिछले साल राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया था और वह बढ़ गया था, उसी तरह से इस बार भी राजस्व घाटा अनुमान से बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सभापति महोदय, इसी तरह से पिछले साल सरकार ने 17240 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया था, जो वास्तव में बढ़कर 20532 करोड़ रुपए आया। इस बार भी सरकार ने 22461.99 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया है, मेरे ख्याल से यह आंकड़ा 25000 करोड़ रुपए से भी ऊपर जाएगा। सभापति महोदय, यहां पर प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही थी कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय बहुत हो गई है। सभापति महोदय, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि मान लीजिए कि आपकी जेब में 100 रुपया है और मेरी जेब में 10 रुपया है और अगर हम

उसका एवरेज निकालेंगे तो वह 55 रुपए निकलेगा। इसलिए मेरा कहना है कि जब तक आप मेरी जेब में 45 रुपया नहीं डालेंगे, तब तक मुझे उसका क्या फायदा होगा। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हरियाणा के एक–तिहाई हिस्से के अंदर हो सकती है, बाकी के हिस्से में नहीं हो सकती है। सभापति महोदय, बजट में दर्शाई गई प्रति व्यक्ति आय में जब बढ़ोतरी होगी केवल तभी लोगों का भला हो सकेगा । शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2016 में संसेक्स के हिसाब से 18 से 23 साल के युवाओं की संख्या हरियाणा प्रदेश में 3185213 थी यदि इसका हिसाब लगाकर देखें तो प्रति बच्चे पर मात्र 6517 रुपये खर्च बैठता है। सभापति महोदय, सरकार इस बात का हिसाब लगा लें कि स्किल डिवैल्पमैंट मिशन के तहत कितने बच्चों को एजुकेशन दी है और कितनी एजुकेशन बढ़ाने का प्रयत्न किया है ? कई दिनों तक स्क्लि डिवैल्पमैंट मिशन की बड़ी चर्चाएं हुई और सरकार इसके माध्यम से 24,000 हजार बच्चों को शिक्षा दे चुकी है, मैंने इस बात का जिक्र पहले भी किया है। वर्ष 2016 के संसेक्स के हिसाब से हरियाणा प्रदेश में 14 वर्ष से 23 वर्ष के बच्चों की संख्या 5229000 से ऊपर है, उस हिसाब से देखें तो 0.47 प्रसेंट बच्चों को ही स्क्लि डिवैल्पमैंट मिशन के माध्यम से शिक्षा दी गई है। सभापति महोदय, सरकार ने स्क्लि डिवैल्पमैंट मिशन के तहत दावे बहुत किए थे कि हरियाणा प्रदेश में हम इस स्कीम के तहत 14 साल से लेकर 23 साल तक के बच्चों को एजुकेट कर देंगे लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस स्कीम के तहत 14 साल से 23 साल के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध नहीं करवा पाई है। सभापति महोदय, जहां तक हैल्थ की बात है तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हरियाणा प्रदेश से भी गरीब प्रदेश है जबकि वे हैल्थ पर प्रति व्यक्ति 5000 रुपये से ज्यादा खर्च करते हैं और हमारे यहां 1116 रुपये खर्च किया जाता है फिर भी सरकार दावा करती है कि हमारा हरियाणा प्रदेश हैल्थ में भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। सभापति महोदय, वर्ष 2019–20 का जो बजट है वह इन सभी दावों के हिसाब से खरा नहीं उतरता है । सभापति महोदय, जहां तक प्रधानमंत्री सम्मान निधि की बजट में घोषणा की गई और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी घोषणा की गई थी। इन घोषाणाओं का निश्चित तौर पर स्वागत होना चाहिए कि एक अच्छी शुरूआत तो कम से कम हुई और हमें लग रहा था और हम मानकर भी चल रहे थे परन्तु इसमें भी बड़ा ढ़िढ़ोरा पीटा जा रहा था कि किसानों को समान पेंशन देने का काम किया जायेगा। सभापति महोदय, मुझे लगा था कि किसान को एश्योर्ड इन्कम

दी जायेगी। यदि बीजेपी के मेरे साथी सदस्य देखना चाहते हैं तो https//www.gramsamvaad.com पर जायेंगे तो एक लम्बी लिस्ट मिलेगी। जिस तरह से अमेरिकन कंट्रीज़ और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में किसानों को एश्योर्ड इन्कम प्रति महीना दी जाती है । क्या आज एश्योर्ड इन्कम की जरूरत नहीं थी । सभापति महोदय, सरकार ने गैर कृषि क्षेत्र में महज 42 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि की है । क्या किसान को इसलिए सजा दी जाती है कि वह खेतों में अनाज पैदा करता है? किसान की अच्छी हालत तो आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देख सकते हैं जिसके बारे में नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला जी ने उदाहरण भी दिया था, कि वहां पर किसानों को जहां पहले 4 हजार रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से सरकार की तरफ से सहायता दी जाती थी आज वहीं सहायता 10000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से कर दी गई है सरकार को इससे सीखने की जरूरत है । सरकार हरियाणा प्रदेश में दावा करती है कि हम प्रति व्यक्ति आय में पूरे हिन्दुस्तान में सबसे आगे हैं, जैसा कि कर्मचारियों के लिए ''वेतन आयोग'' बना हुआ है इसी तरह से जब तक किसानों का ''वेतन आयोग'' नहीं बनाया जायेगा तब तक किसानों को सुरक्षा सहायता नहीं दे पायेंगे तो देश को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है । आज के दिन कृषि की हालत बहुत खराब है । वर्ष 2014–15 में –0.2 परसैंट एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई है, वर्ष 2015–16 में 0.7 प्रसेंट एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई है, वर्ष 2016–17 में बढ़कर 4.9 परसैंट एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई है और वर्ष 2017–18 में घटकर 2.1 परसैंट प्रसेंट एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई है । ये चिंतित करने वाले आंकड़े हैं । सभापति महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है हमारी आबादी का 63 प्रतिशत कृषि पर निर्भर करता है और हमारी राष्ट्रीय आय का एक तिहाई कृषि से आता है, जब तक कृषि क्षेत्र को उभारा नहीं जायेगा तब तक बात नहीं बनेगी । सभापति महोदय, मेरा सरकार से सुझाव है कि ''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'' में किसान का शेयर देखा जाये तो पूरे साल का 1200 रुपये प्रति एकड़ बैठता है । मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम और कुछ न देकर के जो किसान से शेयर ले रहे हैं, उस शेयर को और इस बजट में से जो भी सहायता हो सके वह किसान के खाते में डालने का काम किया जाये। सभापति महोदय, हम यह सोचेंगे कि प्रधानमंत्री जी को किसानों के प्रति हमदर्दी है।

सभापति महोदय : ढुल साहब, आपको बोलते हुए 10 मिनट हो गये हैं इसलिए आप बैठें । सभी विधायकों को तो 5–5 मिनट ही बोलने का समय दिया गया है ।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : सभापति महोदय, मैं अपने हल्के की बात करना चाहूंगा मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका नहीं मिला था इसलिए मेरा बोलने का राईट बनता है । मैं अपनी बात दो मिनट में ही समाप्त कर दूंगा । सभापति महोदय, मुझे वर्ष 2017 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जींद विधान सभा क्षेत्र में 9 सड़कें बनाने की मंजूरी का आश्वासन दिया था लेकिन इस बजट में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है । सभापति महोदय, सरकार ''सबका साथ सबका विकास'' करने की इच्छा रखती है । मैं वर्ष 2015 से लेकर हर विधान सभा सत्र में अपने हल्के के लिए लगातार उन्हीं कामों को बता रहा हूं लेकिन सरकार की रूचि होती तो इस नारे को पूरा करने का काम करती । सरकार की रूचि होती तो नवम्बर 2014 से प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ रुपये विकास के कार्य करवाने के लिए देती । इस प्रकार से अब तक यह राशि बढ़कर 20–25 करोड़ हो गई होती। मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा यही रकम सभी विधायकों को दे दी जाये जिससे कि हम अपने–अपने हल्के में इसी धनराशि से विकास कार्य करवा लें। अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि यह बजट हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए पूर्ण रूप से निराशाजनक है।

श्री सभापति : ढुल साहब, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए अब आप बैठ जायें।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : सभापति महोदय, मेरे हल्के की कुछ सड़कें हैं जिन्हें बनवाने की मेरी मांग है। अतः कृपया आप इनको भी प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनवा दें।

श्री सभापति : ठीक है, आप इन्हें लिखकर दे दीजिए उन्हें प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनवा दिया जाएगा।

***श्री परमेन्द्र सिंह ढुल :** सभापति महोदय, मैं अपने हल्के में निम्नलिखित सड़कें बनवाना चाहता हूं :–

1. भैरोखेड़ा से दिगारा 5 करम।
2. दिगारा से पड़ाना 5 करम।
3. निडाना से बिरोली 4 करम।
4. केन्द्र स्थापित करने की कृपा करें।
5. अरारफगढ़ से बिरोली 4 करम।

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनाया गया।**

6. रामगढ़ से दारी रामगढ़ 4 करम।
7. किलाजफगढ़ से देवरड़ 5 करम।
8. मालवी से झमोला 5 करम।
9. गतौली से रामकली 5 करम।
10. गतौली से करसौला 6 करम।
11. लिजवानाकला से लिरसाखेड़ी 5 करम।
12. लिजवानाकला से बुदाखेडा लाठर 5 करम।
13. लखमीरवाला से बराहखुद 5 करम।
14. आसन से मिड़ताना 5 करम।
15. खरकरामजी से मिड़ताना 5 करम।
16. खेड़ा बख्ता से करसौला 5 करम।
17. गढ़वाली से बुराडैहर 4 करम।
18. मालवी से पुठ्ठी 5 करम।
19. जुलाना हल्के के 20 गांवों में विभिन्न चौपालों के लिए 2.5 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी की गई है। उसे शीघ्र बनाया जाए। (गावों की लिस्ट मुख्यमंत्री जी को दी गई है।)
20. पढ़ासा सब माइनर की रीमोल्डिंग कराने बारे।
21. जे.डी.–3 की रीमोल्डिंग प्रौसेस जल्द कप्लीट की जाए।
22. करेला माइनर (नई) शीघ्र शुरू की जाए।

श्री ललित नागर (तिगांव) : सभापति महोदय जी, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए जो मौका दिया सर्वप्रथम तो मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, हमारे वित्त मंत्री जी ने काफी बड़ा बजट बहुत तेज गति से पढ़ा था। वर्तमान बजट लगभग 52 पेज की एक पत्रिका थी जिसमें 280 पैराग्राफ्स थे। वित्त मंत्री की बजट स्पीच को हमने बड़े गौर से सुना और पढ़ा। हमें पहले लग रहा था कि इस बार के बजट में हरियाणा प्रदेश के हरेक वर्ग के लिए बहुत कुछ मिलेगा और इस बजट से पूरे हरियाणा प्रदेश को बहुत फायदा होगा क्योंकि यह चुनावी बजट है और अक्सर चुनावी बजट में हर वर्ग को बहुत फायदा दिया जाता है लेकिन सच बात यह है कि जब हमने बजट को सुना और पढ़ा तो यह पाया कि उस बजट में प्रदेश के किसी भी वर्ग को कोई भी विशेष फायदा नहीं दिया गया है। प्रदेश का प्रत्येक वर्ग इस बजट से पूरी तरह से

निराश हुआ है। हर वर्ग को इस बजट से जो आशायें थी उनकी उन सभी आशाओं पर पूरी तरह से पानी फिर गया है। इस बजट में कोई भी नई योजना नहीं दी गई और न ही कोई नई परियोजना ही दी गई है। इस बजट में केवल और केवल सरकार द्वारा पिछले सवा चार साल में जो भी योजनायें बनाई गई थी उनका ही बखान किया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि किसानों के लिए उन्होंने अपने बजट में क्या दिया, मजदूरों के लिए क्या दिया, युवाओं के लिए क्या दिया और महिलाओं के लिए क्या दिया? हमने तो यही पाया है कि इस बजट में किसी भी वर्ग को कुछ भी नहीं दिया गया है। इस प्रकार से यह बिलकुल ही निराशाजनक बजट साबित हुआ है। मैं एक ही प्वायंट की बात करूंगा जोकि इस बजट के अंदर सबसे ज्यादा चिंताजनक है। वह प्वायंट है कर्ज। प्रदेश का कर्ज़ लगातार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2014–15 में जहां यह कर्ज़ 70 हजार करोड़ रूपये था। वर्तमान सरकार अक्तूबर, 2014 में आई। उसके बाद वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2017 में और वर्ष 2018 में इस सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किये गये। इन वर्षों के दौरान यह कर्ज़ लगातार बढ़ रहा है। आज हालात ये हो गये हैं कि आज यह कर्ज़ एक लाख 79 हजार 412 करोड़ रूपये हो गया है। इसी प्रकार से लगभग एक लाख 10 हजार करोड़ रूपये कर्ज़ पिछले चार वर्षों के दौरान इस सरकार ने बढ़ा दिया है। इससे यही जाहिर होता है कि वर्तमान सरकार पूरे हरियाणा प्रदेश को कर्ज़ में डूबोने जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश इसमें और डूबता चला जायेगा। इससे प्रदेश का प्रत्येक नागरिक परेशान होगा इसलिए यह चिंता का विषय है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए लेकिन सरकार ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को बुरी तरह से कर्ज़ में डूबोने का काम किया है। इसी प्रकार से राजस्व घाटे का प्वायंट आता है। जब यहां पर बजट को बड़े जोर–शोर से पेश किया गया है और मेजों को थपथपाया गया तो ऐसा लग रहा था कि यह बहुत ही अच्छा बजट साबित होगा लेकिन जब इस बजट को अंदर से बहुत गहराई से देखा गया तो यह पाया गया कि जहां वर्ष 2013–14 में राजस्व घाटा 3875 करोड़ रूपये था वो अब वर्ष 2018–19 में बढ़कर 12022 करोड़ रूपये हो गया है। इस प्रकार यह वर्तमान सरकार के शासनकाल के दौरान लगभग चार गुणा ज्यादा हो गया है। सभापति महोदय, जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारा

हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे प्रदेश की अधिकतर जनता कृषि पर निर्भर है। सभापति जी, जहां तक कृषि क्षेत्र की बात है तो वर्ष 2017–18 में कृषि क्षेत्र के लिए 3985 करोड़ रूपये खर्च करने के लिए रखे गए थे। जिसको वर्ष 2018–19 में बढ़ा कर 4054 करोड़ रुपये कर दिया गया था और अब वर्ष 2019–20 में 4250 करोड़ रुपये किया गया है लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कृर्षि के खर्च के लिए रखी गई इस राशि में से 1500 करोड़ रुपये किसान पैन्शन के निकाल लिये गये हैं जिससे यह राशि 2750 करोड़ रह गई है, उससे कैसे काम चलेगा? किसानों को वित्त मंत्री जी और बजट से बहुत उम्मीद थी। आज कृषि से संबंधित यंत्र, मशीनरीज और खाद पर यदि सरकार वैट खत्म कर दें तो उनके रेट्स नीचे आ जायें लेकिन उनकी तरफ बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह से पिछले 3–4 साल में सरकार द्वारा 3–4 बार वैट बढ़ाने का काम किया था जिसके कारण डीजल के रेट आसमान को छूने लगे हैं। कांग्रेस के समय में डीजल जहां 52 रुपये प्रति लीटर बिकता था वहीं आज 70–72 रुपये प्रति लीटर डीजल के दाम पहुंचाने का काम किया है।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो सब्सिडी की बात कह रहे हैं उसके बारे में मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। पहली बार हमारी मनोहर लाल जी की सरकार द्वारा ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों में चाहे रीपर है या बेलर है, सभी पर सब्सिडी दी जा रही है। हमारे कांग्रेस के साथी यह भी बता दें कि इनके शासनकाल में डीजल किस भाव बिक रहा था?

श्री ललित नागरः सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि डीजल से वैट कम किया जाना चाहिए जिससे किसानों को फायदा मिल सके। हाउस में सरकार के सभी एम.एल.एज और मंत्री बहुत तारीफ कर रहे थे कि यह बजट किसानों के फेवर का बजट है लेकिन मैं फरीदाबाद के किसानों के बारे में बात करना चाहता हूं। फरीदाबाद जिले में किसान बाजरा लेकर मंडियों में घूमते रहे लेकिन समय पर उनके बाजरे की खरीद नहीं हो सकी। कोई कहता कि तिगांव की मंडी में ले जाओ, कोई कहता कि बल्लभगढ़ की मंडी में ले जाओ, कोई कहता कि मोहना की मंडी में ले जाओ तथा कोई कहता कि फरीदाबाद की मंडी में ले जाओ कोई उनको यह कह देता था कि आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप अपनी संबंधित मंडी में जाइये। उनकी बहुत दुर्दशा हुई और हफ्ते–हफ्ते, 10–10 दिन तक उनके बाजरे की खरीद नहीं हुई और जब खरीद हुई तो वह बहुत कम रेट पर खरीदा गया।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो ये मेजें थपथपा कर कहते हैं कि हमने बाजरे का एक–एक दाना खरीदा है। बहुत से किसान परेशान हुये थे और बहुत से किसानों को उनके बाजरे का उचित रेट नहीं मिला। कांग्रेस के समय में जहां जीरी 4000, 4400 और 4800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिकती थी और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमने 1800, 2000 और 2200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव जीरी पिटती देखी है। जहां तक गन्ने की बात है तो मैं भी गन्ना पैदा करता हूं। समय पर गन्ना नहीं बिकता है, न ही तो पर्चियां मिलती हैं और न ही समय पर गन्ने का पैसा मिलता है। इसी प्रकार से जहां तक टमाटर, आलू और प्याज कितने ही किसानों को मंडियों के अन्दर और मंडियों से बाहर फेंकने पड़े और उनको उनकी सब्जियों का उचित रेट नहीं मिला। सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस बजट परिव्य में 37900 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय दिखाया गया है जबकि कहा यह गया है कि कुल बजट में से 46562 करोड़ रुपये प्रदेश में क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों के लिए हैं। 15 विकास योजनाएं आबंटित किये गये हैं जो चल रहे हैं अर्थात् नई योजनाओं के लिए नहीं पुरानी योजनाओं के लिए ही इस अमाउंट में देखते हैं तो 9000 करोड़ रुपये कम पड़ते हैं। इस प्रकार से पुरानी स्कीम्स कैसे पूरी होंगी और नई स्कीम्स कैसे चालू की जायेंगी ? इसी तरह से कुल बजट का 70 प्रतिशत हिस्सा कर्जों और पूंजीगत खर्च पर लग जाएगा तो फिर आगे बाकी का विकास कार्य कैसे चलेगा ? मैं एक बहुत काम की बात बताता हूं कि मंख्यमंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, और भी कई मंत्रियों ने पिछले साल बहुत ज्यादा एडवर्टाईजमैंट की थी, बड़े ढ़ोल बजाए थे कि हम विदेश से, कनाडा से, यू.के. से, अमेरिका से इन्वैस्टर्ज ला रहे हैं जो यहां कई लाख करोड़ रुपये इन्वैस्ट करेंगे । यहां बड़ी–बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी जिनमें बच्चों को नौकरियां मिलेंगी और उनसे हमारे देश को टैक्स मिलेगा । मैं आज पूछना चाहता हूं कि अब तक हमारे यहां कितने इन्वेस्टर्ज का इन्वेस्ट हुआ है, कितनी कम्पनियां लगाई गई हैं ? इसके साथ ही वित्त मंत्री जी यह भी बताने का काम करें कि जब वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बाहर गये थे और बाहर के लोग यहां आए थे, उनके ऊपर कितना खर्च हुआ है और वह खर्च किस अकाउंट से किया गया था ? इसके साथ ही यह भी बताने का काम करें कि जो एम.ओ.यू. हुए थे उनका क्या हुआ है ?

श्री सभापति : ललित जी, अब आप अपनी बात को खत्म कीजिए । आपको बोलते हुए ज्यादा समय हो गया है ।

श्री ललित नागर : सभापति महोदय, यह बड़े काम की बात है ।

श्री सभापति : ललित जी, यहां सभी सदस्य काम की ही बात कर रहे हैं बिना काम की बात कौन करता है ।

श्री ललित नागर : सभापति महोदय, गांव पल्ला से तिलपत के लिए एक 77 फुट चौड़ी रोड बनाई जा रही है । यह बड़ी अच्छी बात है कि आप वहां 77 फुट चौड़ी रोड बना रहे हैं लेकिन उस रोड के अन्दर इतना गलत काम किया जा रहा है कि जब मर्जी जहां घुमा दी जाती है । वहां पर सरकार को जो लोग अपने विरोधी लगते हैं उनके घर तोड़े जा रहे हैं । वहां पिक एण्ड चूज की नीति अपनाई जा रही है । वहां सैंकड़ों गरीब लोगों के घर गिराए जा रहे हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि ऐसा काम न करें कि आप रोड तो बनाएं लेकिन आप जो गरीब आदमियों के घरों को गिराने का काम कर रहे हैं वह न करें ।

श्री सभापति : ललित जी, अब आप वाईंड अप कीजिए ।

श्री ललित नागर : सभापति महोदय, मेरी दो–तीन बातें बहुत जरूरी हैं । मैं कॉलोनियों में विकास कार्यों के बारे में कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में इतनी कॉलोनियां बसी हुई हैं लेकिन उनमें कहीं भी विकास कार्य नहीं हुए हैं । मेरा निवेदन है कि उन कॉलोनियों में विकास कार्य करवाया जाए । इसी तरह से हमारे क्षेत्र में बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते हैं । अब पता नहीं मेरे तिगांव क्षेत्र में ही इतने ज्यादा क्यों आते हैं । बी.जे.पी. की सरकार तो यह कहती है कि हमने बिजली सस्ती कर दी है लेकिन मेरे क्षेत्र में एक गरीब आदमी का 50 हजार, 70 हजार, एक लाख और डेढ़ लाख रुपये तक के बिल आते हैं। क्या आपने बिजली के दो–दो रेट कर रखे हैं ? हमारे क्षेत्र में बिजली के बिल महंगे हैं और आपकी सरकार के सदस्यों के क्षेत्र में बिजली के बिल सस्ते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के बिजली के बिलों को भी ठीक किया जाए । (शोर एवं व्यवधान) सर, मेरा एक प्वाइंट रह गया है ।

श्री सभापति : ललित जी, अब आपके सारे प्वाइंट कवर हो गये हैं इसलिए आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणबीर सिंह गंगवा (नलवा): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया है । जहां तक बजट की बात है अभी मेरे से पहले भी तमाम सदस्यों ने यह बताने का काम किया है कि किस तरह से बजट में

राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है जो चिन्ता का विषय है । इस बार जो अनुमानित राजकोषीय घाटा है वह पिछले वर्ष से भी ज्यादा है । जैसे अभी बजट के अन्दर वित्त मंत्री महोदय ने बताया है कि कुल बजट का 26.12 प्रतिशत कृषि एवं संबंधित विभाग के ऊपर खर्च किया गया है लेकिन आज कृषि किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है इसलिए उनके ऊपर और ज्यादा ध्यान देने की बात है । जैसे चाहे बाजरे की बात है, चाहे वह सरसों की बात है । उसमें एम.एस.पी. बढ़ाया गया है । यह अच्छी बात है लेकिन जब तक किसान की खरीद पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं होगी तो फिर किसान को उसका पूरा फायदा कैसे मिलेगा क्योंकि चाहे वह बाजरा है, चाहे सरसों है उसको पूर्ण रूप से खरीदा नहीं गया है। आज किसान की हालत भी यह है कि हमारे क्षेत्र में खासकर हिसार, सिरसा व फतेहाबाद के अन्दर बहुत से किसान ढ़ाणियों के अन्दर रहते हैं । अगर किसानों की ढाणियों में लाईट नहीं होगी, गांवों–शहरों में लाईट नहीं होगी तो फिर किस प्रकार से किसानों के रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण हो सकेगा? आज वे किसान जो खेतों में ढाणियां बनाकर रहते हैं, अंदेरे में सोने को मजबूर हैं। महामहिम के अभिभाषण में तथा बजट में खेतों में ढाणियां बनाकर रहने वाले किसानों को लाईट मुहैया करवाने के प्रावधान का जिक्र होना चाहिए था ताकि ढ़ाणियों में रहने वाले किसानों के बच्चे भी पढ़ सकें। सभापति महोदय, बिना लाईट के किस प्रकार से डिजिटल इंडिया व अन्य दूसरी तमाम प्रकार की योजनाएं संभव हो सकेंगी? इसी तरीके से वर्तमान समय में रोजगार की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। महामहिम के अभिभाषण में तथा वित्त मंत्री महोदय ने बजट भाषण में कहा गया कि सरकार ने बिना पर्ची व बिना सिफारिश के नौकरियां देने का काम किया। यह बहुत अच्छी बात है लेकिन जो गौर करने लायक बात है वह यह है कि अभी ग्रुप डी के 18000 पदों के लिए 12 लाख बच्चों ने आवेदन किया। इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी बेराजगारों की संख्या हरियाणा प्रदेश में है। यह गौर करने लायक चीज है और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार से यह समस्या हल हो सकती है। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया चेयर पर आसीन हुई।)** उपाध्यक्ष महोदया, ग्रुप–डी की नौकरियों में एम.टैक., बी.टैक व टेक्निकल एजुकेटेड बच्चों ने आवेदन किया जिसका सीधा सा मतलब यह भी है कि वर्तमान सरकार में टैक्निकल एजुकेशन प्राप्त किए बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है यही कारण है कि वे ग्रुप–'डी' जैसी पोस्ट के प्रति मुखर हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदया, सब जानते हैं कि

हरियाणा प्रदेश के एन.सी.आर. में आने वाले एरियॉज जैसे गुरूग्राम, फरीदाबाद या अन्य दूसरी जगहों पर बहुत बड़ी संख्या में उद्योग लगे हुए हैं और यहां पर रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। यदि इन उद्योगों में हरियाणा प्रदेश के 50 प्रतिशत बच्चों को नौकरी मिलने का प्रावधान हो जाए तो हरियाणा प्रदेश की बेराजगारी की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। हम यह नहीं कहते कि जैसेकि कुछ महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि वहां पर केवल महाराष्ट्र के लोगों को ही रोजगार मिले, यह ठीक नहीं है क्योंकि दूसरे प्रदेशों के वे लोग जो काफी लंबे समय से हरियाणा प्रदेश में रहते आ रहे हैं, वे भी हरियाणा प्रदेश के ही वासी हैं। हमारा कहना सिर्फ यही है कि एन.सी.आर. में स्थित उद्योगों में हरियाणा प्रदेश के बच्चों को नौकरियों में 50 प्रतिशत नौकरी मिलने का प्रावधान हो और सरकार को इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने चाहिए। जहां तक सिंचाई की बात है, हमारे क्षेत्र में सिंचाई की बड़ी भारी दिक्कत और परेशानी है। सदन में बार–बार कहा गया कि दक्षिण हरियाणा में तो पूरा पानी चला गया है लेकिन मेरे क्षेत्र में ऐसा नहीं है। अभी पीछे कृषि मंत्री जी आंदोलन कर रहे किसानों को महीने में दो बार नहरी पानी देने का वायदा करके आए थे लेकिन आज भी यह पानी महीने में एक बार ही मिलता है जिसकी वजह से सिंचाई के कार्य में किसानों को बड़ी भारी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा कृषि मंत्री जी से निवेदन है इस दिशा में वे स्वयं ध्यान दे ताकि मेरे क्षेत्र के लोगों को सिंचाई के लिए पानी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त सरकार ने एस.वाई.एल. नहर के लिए 100 करोड़ रूपये रिजर्व तो रख लिए है लेकिन एस.वाई.एल. नहर बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आज केन्द्र में तथा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार है। एस.वाई.एल. नहर के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हरियाणा प्रदेश के हक में आ चुका है और कह दिया गया है कि नहर का निर्माण तुरंत हो जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा निवेदन है कि इस दिशा में भी सरकार को कदम उठाने की जरूरत है केवल पैसे रिजर्व रखने से कुछ नहीं होता। जब तक हरियाणा प्रदेश के किसानों के खेतों को पानी नहीं मिलेगा तब तक किसानों की समस्या हल नहीं हो सकेगी। उपाध्यक्ष महोदया, मेरे विधान सभा के गांव मंगाली में एक अस्थाई अनाज मंडी है जोकि कई सालों से बंद पड़ी है। अभी गेहूं का सीजन आने वाला है किसानों को अपनी फसल को हिसार शहर में स्थित अनाज मंडी में लाने के लिए शहर के बीचों बीच होकर गुजरना पड़ता है जिसकी

वजह से यहां पर जाम की समस्या बन जाती है और लोगों को बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अगर गांव मंगाली में स्थित अस्थाई अनाज मंडी को गेहूं के सीजन के दौरान खोल दिया जाये और गेहूं के सीजन में यहां पर गेहूं की खरीद शुरू कर दी जाये तो किसानों व आम जन को जाम की समस्या से मुक्ति मिल जायेगी। इसी तरीके से पिछली बार सरकार की तरफ से हमारे कैम रोड को फोर लाईन बनाने की बात कही गई थी लेकिन इस रोड पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है जबकि माननीय मंत्री जी द्वारा पूरे सदन में फोरलेन बनाने का आश्वासन दिया गया था। मिंगनीखेड़ा से मात्रश्याम गांव तक सड़क पर चलने के लिए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वह सड़क जल्दी से जल्दी बनाई जाए। इसी तरह से कैमरी रोड के साउथ बाइपास पर आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य चल रहा है पहले पानी ऊपर आने के कारण आर.यू.बी. का नोट फिज़िबल का प्रस्ताव पास हो कर आ गया था, इसलिए उस आर.ओ.बी. को जल्दी से जल्दी बनाया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक डिवैल्पमैंट की बात है, कांग्रेस सरकार में नगर निगम बने थे और जो शहर से बाहर कॉलोनियां और गांव का एरिया लगता था वह एरिया नगर निगम में शामिल कर लिया गया था। उन लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स भी लगना शुरू हो चुका था लेकिन नगर निगम के नाते जितनी डिवैल्पमैंट होनी चाहिए थी वहां पर नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदया : गंगवा जी, अब आप वाईंड–अप कीजिए।

श्री रणबीर गंगवा : उपाध्यक्ष महोदया, आज मेरे हल्के की कॉलोनिया चाहे वह कैमरी रोड या फिर आजाद नगर का एरिया हो उन कॉलोनियों की आज गांव से भी ज्यादा खराब हालत है। कई कॉलोनियों में तो अभी तक रोड बना ही नहीं है। सरकार को कोई स्पेशल पैकेज देकर क्योंकि वहां के लोग प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं, इसलिए वहां पर पक्की सड़कें और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। वहां के लोग यह कहने लगे कि हम शहर में जाकर तो बस गए हैं लेकिन वास्तव में हमें गांव जैसी सुविधा मिल रही हैं। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री कुलवन्त राम बाजीगर (अ.जा.) (गुहला) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है चाहे वह मजदूर हो, व्यापारी हो, किसान हो, कर्मचारी हो या किसान

आदि हो। हमारी सरकार जिस किसी भी तरीके से विकास के काम कर रही है उससे हरियाणा प्रदेश के सभी लोग खुश हैं। बिजली के क्षेत्र में हमारी सरकार ने लगभग 140 सब–स्टेशन बनाए हैं और इसके साथ–साथ बिजली के रेटों में भी कटौती की है। हमारी सरकार ने 'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना के माध्यम से बहुत सारे गांवों को 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। मेरा गुहला हल्का शुरू से पिछड़ापन का क्षेत्र रहा है। किसी भी सरकार ने इस क्षेत्र की सुध नहीं ली लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पिछड़ेपन के सिलसिले को दूर करने का काम शुरू हुआ। मेरे हल्के में 11 सब–स्टेशन बनाए गए हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत–बहुत बधाई देता हूँ। कृषि क्षेत्र की बात करूं तो हमारी सरकार ने नहरों में पानी पहुँचाया है और अन्तिम टेल तक पानी लेकर गई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 30 वर्षों से पानी की भारी समस्या रहती थी लेकिन आज हमारे क्षेत्र का जमींदार खुश है और श्री मनोहर लाल जी की सरकार का गुणगान कर रहा है। शिक्षा क्षेत्र की बात करूँ तो हमारी सरकार में बहुत सारे स्कूल्ज अपग्रेड हुए हैं। लगभग तीन दर्जन से भी ज्यादा लड़कियों के लिए कॉलेज बनाए हैं जिसमें से मेरे गुहला हल्के में भी एक लड़कियों के लिए कॉलेज बनाया गया है और लगभग 12 स्कूल्ज अपग्रेड किए गए हैं। आई.टी.आई. की बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। सड़कों के बारे में बात करूँ तो मेरे गुहला हल्के में पहले बहुत टूटी हुई सड़कें हुआ करती थी। पहले सड़कों पर गड्ढ़े नहीं थे बल्कि गड्ढ़ों में सड़क हुआ करती थी। हमारी सरकार आने के बाद सड़कों की मुरम्मत का कार्य, नई सड़कें व एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़कों का काम शुरू हुआ। यही नहीं सड़कों की चौड़ाई 12 फीट से 18 फीट करने का काम भी शुरू हुआ। उपाध्यक्ष महोदया, सड़कों के नाम पर हमारी सरकार का नाम पूरे हिन्दुस्तान में नाम लिया जाता है। जनस्वास्थ्य की बात करूँ तो पानी की निकासी के लिए और पानी की व्यवस्था के लिए मेरे हल्के को महानगरों जैसे सुविधा दी हुई है। मेरे हल्के के सिवानी में गलियों में पानी खड़ा होने के कारण लोग पैदल निकल नहीं सकते थे, इसलिए अपने साधनों के माध्यम गुजरते थे। अब वहां पर पानी की निकास होने के कारण लोग बहुत खुश हैं। स्वास्थ्य के बारे में बात करूँ तो हमारी सरकार ने सैंकड़ों पी.एच.सीज. का निर्माण करवाया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के अथक प्रयासों से ही हमारी सरकार गांव मनेठी, जिला रेवाड़ी में एम्स को लेकर आ रही है। मेरे गुहला हल्के के हरनौली गांव व आगोंध

गांव में पी.एच.सी. बनाई गई बल्कि इसके साथ–साथ इन पी.एच.सीज. में शवगृह और डॉक्टर्ज के लिए कमरों की भी व्यवस्था की गई है। इस प्रकार हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया सिस्टम कर दिया है । अगर खेल क्षेत्र की बात करें तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में 4–4 खेल स्टेडियम मंजूर हुए हैं। गांव बहूपुर और चीका में खेल स्टेडियम बन चुके हैं और ऊंदेल गांव में स्टेडियम बन रहा है। इस तरीके से खेल क्षेत्र में हमारे क्षेत्र को काफी आगे बढ़ाने का काम किया गया है। अगर माननीय मंत्री श्री नायब सैनी की बात करें जिनके पास लेबर एण्ड ऐम्पलॉयमैंट डिपार्टमैंट हैं, ने जरूरतमंदों की जरूरतों को समझते हुए गरीब महिलाओं को सिलाई मशीनें देने का निर्णय और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लड़कियों को 51 हजार रूपये की राशि देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह से अगर मैं माननीय मंत्री महोदया श्री कविता जैन को धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने हमारे निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों का सिंगापुर की तर्ज पर निर्माण करवाया है। मैं कहूंगा कि आज प्रदेश में इतना विकास हो रहा है कि विपक्ष के पास सदन में उठाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है । मैं हरियाणा प्रदेश में हो रहे विकास को एक शेर के माध्यम से बताना चाहूंगा –

विकास की असली उड़ान अभी बाकी है,
हमारे मंत्रियों के इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है,
अभी नापी है मुट्ठीभर जमीन इन्होंने,
सारा आसमान अभी बाकी है ।

मैं विपक्षी साथियों से कहूंगा कि इन्होंने राज़ को अपनी ताकत समझना शुरू कर दिया था। इन्हें ध्यान नहीं रहा कि यह तो जनता की दी हुई एक अमानत थी। मैं इसे भी एक शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा–

अमानत में ख्यानत तूने किया ताकत को जहां अपना समझा,
मनसद पर पहुंचकर भूल न जाइये ताकत तो एक अमानत है ।

आज ये लोग राज को तरस रहे हैं । बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने इतना कुछ कर दिया कि इन लोगों के पास बोलने के लिए कोई बात ही नहीं है । इनके विषय में मेरा कहना है कि इन्होंने राजनीति को व्यापार बना रखा था । अब अगर ये लोग व्यापार ही कर लें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि राजनीति में अब इनको कोई आगे नहीं आने देगा । मैं कहूंगा कि हमारी सरकार ने बिल्कुल अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति जैसे वाल्मीकि, बागड़ी, लौहार, सपेरे, बाजीगर, डूम आदि समाज के लिए डी.एन.टी. बोर्ड (National Commission for Denotified, Nomadic &

Semi-Nomadic Tribes) का निर्माण करवाया है जबकि इन समाजों के लोगों की पहले कहीं भी कोई पूछ नहीं थी । हमारी सरकार ने जिस परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है उन लोगों को सरकारी नौकरियों में अतिरिक्त 5 नंबर देकर उनका अच्छा ख्याल किया है । मेरा कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय भगवान का रूप हैं। ये हर व्यक्ति/समाज के भले के बारे में सोचते, समझते और विचार करते रहते हैं। ये कभी भी वोट की राजनीति नहीं करते हैं। इनका सिर्फ एक ही विचार रहता है कि समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। पिछली सरकारों में बिजली के बिलों के बारे में कहा जाता था कि हम इन्हें माफ कर देंगे। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि मैं सिस्टम ठीक करूंगा और लोगों को बिजली विभाग का कर्जदार ही नहीं बनने दूंगा । इस विचार से उन्होंने बिजली के रेट लगभग आधे कर दिए । पिछली सरकारों के समय लोग कहते थे कि बिजली का सिस्टम कभी ठीक नहीं हो सकता । जब हमारी सरकार ने बिजली के रेट आधे घटा दिए तो लोग काफी खुश और संतुष्ट हुए । पहले लोग बिजली के बिल से बचने के लिए कुंडियां लगाकर बिजली की चोरी करते थे । वे चोरी करते हुए पकड़े जाते थे और आये दिन जनप्रतिनिधियों के पास जाकर कहते कि हमें बचाइये, हम बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए । आज हरियाणा की जनता स्वयं मानती है कि हम जो बिजली का बिल कम करने के लिए कुंडिया लगाकर बिजली चोरी करते थे वह काम ठीक नहीं था । आज हर हरियाणावासी ईमानदारी से बिजली का बिल भरता है और उसे पूरी बिजली मिलती है । अब मैं आदरणीय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया है । आज प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि पहले जब प्रदेश का इतना बजट होता था तो वह कहां जाता था । पिछले साढ़े चार साल से पहले का अगर कोई भी अखबार उठाकर देख लें तो उसमें आये दिन होने वाले घोटालों की खबर छपी होती थी । मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में यह कह रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति पिछले साढ़े चार साल में हुए किसी भी घोटाले के बारे में बता दे और इस कोई ऐसा अखबार ला दे जिसमें समय से पहले घोटालों की खबर न हो तो मैं उसे ईनाम दूंगा । हमारी सरकार हर रोज़ नई योजना बनाती है जबकि पिछली सरकार में हर रोज घोटाले होते थे । अगर उस समय किसी ने कोई अच्छा काम किया होता तो आज ये लोग राज के लिए तड़प न रहे होते । उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि वे मेरे द्वारा दिये

गये व्यापार करने के सुझाव को मान लें तो बहुत ही अच्छी बात है। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए एक शेर कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं किः–

"आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं,

लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं।"

माननीय मुख्य मंत्री जी और सभी माननीय सदस्यों में खुदा का नूर है और सभी मिलकर समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय हिन्द।

श्रीमती गीता भुक्कल (एस.सी.) (झज्जर): उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे वर्ष 2019–20 के बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करती हूं। बजट के शुरू में ही माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि प्रजा के सुख में ही सरकार का सुख है, प्रजा के हित में ही सरकार का हित है। प्रजा का जो प्रिय है, वही सरकार का प्रिय है। यह बात बिल्कुल ठीक है और लोकतंत्र की परिभाषा भी यही है कि Government of the people, by the people, for the people. फिर क्या कारण है कि अगर सरकार और प्रजा में इतने अच्छे संबंध है तो प्रत्येक कर्मचारी संगठन सरकार के अगेंस्ट हैं, उसमें चाहे ए.एन.एम. वर्कर्ज हो, आंगनवाड़ी वर्कर्ज हों, चाहे सर्व कर्मचारी संघ हो, चाहे रोडवेज के कर्मचारी हों, चाहे टीचर्ज हों, चाहे गैस्ट टीचर्ज हों, चाहे जे.बी.टी. टीचर्ज हों और चाहे युवा या किसान हों, क्या कारण हैं कि आज सभी लोग सड़कों पर सरकार के अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं ?

श्री महीपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः महीपाल जी, आप पहले माननीय सदस्या की बात तो सुन लें, उसके बाद अपनी बात रख लें। अभी प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री महीपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः गीता जी, आप अपनी बात कन्टीन्यू रखें।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, जब हमारी पार्टी के माननीय सदस्य सदन में बोलते हैं तो सरकार के माननीय सदस्यों को तकलीफ होती है। मुझे इस बात की हैरानी है, जबकि लोकतंत्र में सरकार के साथ–साथ विपक्ष का भी उतना ही रोल होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि बजट में जो लिखा हुआ है, वह सत्य लिखा हुआ है। प्रदेश की जनता ने हमारे हक में वोट देने का फैसला किया है।

उपाध्यक्ष महोदयाः महीपाल जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, अभी कुछ दिन पहले पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के लिए आब्चुयरी भी हुई और सभी माननीय सदस्यों ने यूनानीमसली श्रद्धा के सुमन भी अर्पित किये। सदन में यह प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि पुलवामा और उसके बाद आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों के कारण सारा देश और सभी माननीय सदस्य बहुत ज्यादा दुखी है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। हम भारत सरकार को पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए अथॉराईज करते हैं। आज हमारी पार्टी भारत सरकार को बधाई भी देती है और मैं उन सभी जवानों को सैल्यूट करती हूं जिन जवानों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। खासतौर से हमारे एयर फोर्स के जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की है मैं उनको बहुत–बहुत बधाई देना चाहूंगी। हमारे देश के जवानों का हौसला अफजाई करना चाहेंगे जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और हमें जवानों को किसी राजनीतिक बंधन में न बांधकर उनका हौसला अफजाई करना चाहिए। जिन परिवारों के जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को सांत्वना देते हैं ताकि उनको भी हौसला मिले कि बहुत ही जल्द हमारे देश के जवानों ने शहीदों की शहादत का बदला लेने की बात की है। अभी मेरे बोलने से पहले सभी माननीय सदस्यों ने किसानों की चर्चा की है। मैं सबसे पहले महिला होने के नाते इम्पावरमैंट ऑफ वूमन की बात करूंगी और इम्पावरमैंट ऑफ वूमन की बात भी इसलिए करना चाहूंगी कि we are the 50 percent. We are the 50 percent of Human resource of the world. We are the 50 percent of human resource of the country and the State. तो क्या कारण हैं कि पहले केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इम्पावरमैंट ऑफ वूमन के लिए स्कीम्ज बनायी जाती थी परन्तु आज सरकार की पूरी ताकत इम्पावरमैंट ऑफ वूमन की

बजाय प्रोटैक्टशन ऑफ वूमन पर लग रही है। सरकार द्वारा बेटियों को बचाने की बात की जा रही है। आप बेटियों को कहां तक बचाएंगे ? सरकार को बेटियों को कोख से लेकर पैदा होने तक, पढ़ने, बढ़ने और वर्किंग स्थान तक बचाने के लिए अलग से पुलिस स्टेशन व थाने खोलने पड़ रहे हैं। क्या कारण है कि समाज में बेटियों के प्रति बदलाव आ रहा है ? इसकी क्या वजह है ? इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि जो इम्पावरमैंट ऑफ वूमन की बजाय प्रोटैक्टशन ऑफ वूमन की बात चल रही है, उसमें हमें सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। आज हमारी बेटियां एवरेस्ट पर फतह कर रही हैं, चांद को छू रही हैं, अंतरिक्ष में पहुंच चुकी हैं, ओलंपिक और कॉमनवैल्थ गेम्स में भी गोल्ड मैडल जीतकर ला रही हैं, परन्तु जब वह अपने हकों की बात करती हैं तो उन्हें वंचित कर दिया जाता है। मुझे इस बात से बड़ी हैरानी हुई कि हमारी माताएं व बहनों ने बताया कि जब वे रैलियों में काले दुपट्टे व साल पहनकर जाती हैं तो उन्हे राजनीतिक रैलियों में घूसने नहीं दिया जाता है। इसी तरह से जब हमारे पुरूष भाई भी काले स्वेटर व जैकेट पहनकर जाते हैं तो उनको भी राजनीतिक रैलियों में घूसने नहीं देते हैं। क्या कारण है कि सरकार को काले कपड़ों से भय है ? कल मैंने सदन में युवाओ की बात रखते हुए 'सक्षम युवा योजना' के बारे में भी बात की थी। मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी का आदर मान करती हूं और वे हमारे प्रदेश के मुखिया हैं। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि सरकार को युवाओं को रोजगार देना चाहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाल किले के प्राचीर से भी 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की बात करती है लेकिन

17:00 बजे

जब उनके हकों की बात आती है तो उन्हें केवल सास–बहु के मामलों में उलझाकर रखने की बात कही जाती है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं सरकार से यह कहना चाहूंगी कि आज हमारी यह जिम्मेवारी बनती है कि हम युवाओं को उनकी एजुकेशन के हिसाब से रोजगार दें।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी): उपाध्यक्ष महोदया, मेरा एक प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। अभी हमारे माननीय विधायिका श्रीमती गीता भुक्कल जी जो बातें कह रही हैं, उसके बारे में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इनके सामने पूरी बात विस्तार से बता दी है, लेकिन ये उनकी बातों को मान ही नहीं रही हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि सरकार ने जो एक ऐसी लोकप्रिय योजना चलाई है, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उदाहरण दिया था। सरकार ने जो योजना चलाई है,

उसके तहत हर युवा को 100 घंटे काम देना है, ताकि युवा घर पर फ्री न बैठे। हमारी सरकार युवाओं को एक तरह से सहयोग कर रही है न कि उनको रोजगार दे रही है। हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन्हें सारी बात बता दी है, लेकिन फिर भी यह बात माननीय सदस्या के समझ में नहीं आ रही है तो भला हम क्या कर सकते हैं ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इसमें एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सास–बहू के बारे में बातें कही हैं तो हो सकता है कि माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी के लिए सास–बहू का रिश्ता केवल लड़ाई–झगड़ा का हो, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि आज के समय में सास–बहू का जो रिश्ता होता है, वह मां और बेटी का होता है।

उपाध्यक्ष महोदयाः मैं बता देना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं को काम देने के लिए बात कर रहे थे।

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम माननीय सदस्या को यह भी बताना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की ढाई करोड़ जनता के मां और बाप की तरह हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वही रिश्ता हमारे प्रदेश के युवकों और युवाओं के साथ निभा रहे हैं।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, मैंने पहले ही कहा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की सोच का विरोध करते हैं, क्या ये महिलाओं को केवल सास–बहू के रिश्तों में ही उलझाकर रखेंगे। मैंने अभी कहा है कि हमारी बेटियां चांद और अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं और माननीय मंत्री जी को इस बात का ज्ञान नहीं है और वे कह रहे हैं कि युवाओं को हमारी सक्षम युवा योजना के तहत केवल 100 दिन का रोजगार देना है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि इन्होंने यह क्यों नहीं सुनिश्चित किया है कि किसी भी विभाग में युवा के क्वालिफिकेशन के मुताबिक ही रोजगार दिया जाए ?

उपाध्यक्ष महोदयाः गीता भुक्कल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सास–बहू का उदाहरण युवाओं को काम पर लगाने के लिए दिया था।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, मैंने कहा था कि we are the 50% human resource of the world. मैं पूछना चाहती हूं कि सरकार हमें सिर्फ झगड़े में उझाकर क्यों रखना चाहती है ? सरकार को उनको काम देना चाहिए।

श्री नायब सैनीः उपाध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहूंगा कि श्रीमती गीता भुक्कल जी का आज भी एक क्वैश्चन लगा हुआ था और उसके ऊपर भी इन्हें पूरी डिटेल के साथ जवाब दिया जा चुका है।

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने प्रदेश की आबादी के लिए क्या–क्या किया है, इन्हें उसके बारे में जानना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पांच साल पूरे नहीं हुए हैं और वर्ष 2014 के चुनाव के बाद सबसे पहले अगर इस देश के इतिहास में पैदा होने से पहले सारी आबादी की चिंता की है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्या को कहना चाहूंगी कि इनकी सरकार ने तो इस प्रदेश को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां पर हरियाणा को सबसे कम लिंगानुपात यानी सबसे कम बेटियों वाला प्रदेश कहां जाता था। इनकी सरकार ने तो अपने 10 साल के कार्यकाल में केवल जमीनें बेचने और जमीनों की दलाली करने का काम ही करती रही।

उपाध्यक्ष महोदयाः कविता जी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं और गीता जी को अपनी बात रखने दें।

श्रीमती कविता जैनः इनकी सरकार ने तो प्रदेश की महिलाओं को सबसे नीचे लाने का काम किया है ये आज किस मूंह से प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं की बात कर रहे हैं ?

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मैं आज बजट के ऊपर बोल रही हूं और मुझे बजट के ऊपर बोलने का पूरा अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदयाः गीता जी, आप अपनी बात रखें।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, मुझे सरकार से मेरे प्रश्नों के जवाब भी चाहिएं। आदरणीय हमारी बहन श्रीमती कविता जैन जी मंत्री हैं और मैं इनसे जवाब भी सूनना चाहूंगी। इन्होंने जो सैक्स रैश्यो बताई है, वह ठीक है और यह बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में सैक्स रैश्यो में सुधार हुआ है। मैं तो यहां पर महिलाओं की बात कर रही हूं, जो पुलिस स्टेशन, महिला विभाग या और भी दूसरे विभागों में एड–हॉक या कांट्रेक्ट पर लगी हुई हैं, वे सबसे लो–पेड है उनको सबसे कम तनख्वाह दी जाती है। अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो हमें बजट में इसका प्रावधान करना पड़ेगा कि उनकी सैफ्टी, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन

के साथ–साथ उनको इम्पावर्ड भी करना पड़ेगा, तभी हमारा देश और प्रदेश तरक्की करेगा।

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, मेरा एक प्वायंट ऑफ आर्डर है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहूंगी कि अभी इन्होंने जैसा कि कहा है कि हमारे विभाग में महिला कर्मचारियों को सबसे कम तनख्वाह दी जा रही है तो मैं इसके बारे में माननीय सदस्या को कहना चाहूंगी कि इन्होंने बहुत गलत स्टेटमैंट दी है।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह भी बताना चाहूंगी कि वूमन एण्ड चाइल्ड डेवल्पमैंट मिनिस्टर श्रीमती मेनका गांधी जी ने भी कहा था कि हमें ज्यादातर आंगनवाड़ी सैंटर्ज बंद कर देने चाहिए।

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, अभी हमारे माननीय सदस्या ने फ्लॉर ऑफ दि हाउस बहुत ही गलत स्टेटमैंट दी है कि हमारे विभागों में महिला कर्मचारियों को सबसे कम तनख्वाह दी जा रही है। उपाध्यक्ष महोदया, ये हाउस को मिसलीड और मिसगाइड कर रही हैं।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहूंगी कि ये मेरे सवालों का जवाब अपने रिप्लाई में बाद में दे दें।

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्या को कहना चाहूंगी कि ये मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है अगर मैं इनके सवालों का साथ–ही–साथ जवाब दे दूंगी तो इसमें क्या गलत है ? (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः कविता जी, कृपया आप एक बार गीता जी को अपनी बात पूरी करने दें, उसके बाद आप जवाब दे देना। (शोर एवं व्यवधान)

शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, क्या एक मंत्री प्वांयट ऑफ ऑर्डर पर खड़ा हो सकता है? माननीय मंत्री जी कौन से रूल के तहत प्वांयट ऑफ ऑर्डर ले रही हैं ? (विघ्न) प्वांयट ऑफ ऑर्डर तो विधायकों के लिए होता है । इसमें आप अपनी रूलिंग दीजिए । (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : करण दलाल जी, प्लीज आप बैठ जाये । माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहती हैं । (विघ्न)

श्रीमती कविता जैन : उपाध्यक्ष महोदया, अभी माननीय सदस्या ने कहा है कि महिला बाल विकास में महिला आंगनवाड़ी वर्कर्ज लगी हुईं हैं, पूरे देशभर में उनको सबसे कम तनख्वाह दी जा रही हैं । उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या की यह गलत स्टेटमैंट है । आज देशभर में आंगनवाड़ी वर्कर्ज को सबसे ज्यादा तनख्वाह अगर किसी स्टेट में दी जा रही है तो वह हरियाणा प्रदेश में दी जा रही है । (विघ्न)

श्रीमती गीता भुककल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह नहीं कह रही हूं कि हरियाणा प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर्ज को कम तनख्वाह दी जा रही हैं । मैं यह कहना चाहती हूं कि पूरे देशभर में विभागों में जो उनके जैसे इम्पलाईज़ हैं, उनसे हमारे यहां कम पेड हैं । मैं हरियाणा प्रदेश की बात ही नहीं कर रही हूं (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : गीता भुक्कल जी, प्लीज, आप बैठ जाये । (विघ्न)

श्रीमती कविता जैन : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगी कि हरियाणा प्रदेश में आंगवनवाड़ी कार्यकर्त्ता 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखती हैं, उनको 11429 रुपये प्रति माह मिलेंगे और जो आगंनवाड़ी कार्यकर्त्ता 10 वर्ष से कम अनुभव रखती हैं, उनको 10286 रुपये प्रति माह मिलेंगे । इसी तरह से मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता को पहले 4250 रुपये मिलते थे, आज उनको 10286 रुपये बढ़ाकर दिये जा रहे हैं और हैल्पर को 5715 रुपये दिये जा रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा सरकार ने पॉलिसी भी बनाई है कि जो हमारे प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्ज हैं, जो उनके 50 प्रतिशत सुपरवाईजर के पद होते हैं, वे उनकी प्रमोशन से भरे जायेंगे । जहां तक इन्श्योरेंस की बात है तो उसको भी बढ़ाने का काम किया गया है ।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने आपसे अनुरोध किया था । आप भी एक महिला होने के नाते उपाध्यक्ष के रूप में बैठी है, आज हमारी डिफैंस मिनिस्टिर भी, विदेश मंत्री भी और लोक सभा स्पीकर भी एक महिला हैं । क्या हम केवल और केवल सैक्स रेशों की बात ही करते रहेंगे ? क्यों हमें इम्पवारमैंट या अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? अगर हम विधान सभा में भी नहीं लड़ेगें तो फील्ड में कौन जीतने देगा और फील्ड से कौन निकलने देगा? I need your protection also. उपाध्यक्ष महोदया, मैं कुछ और मुद्दों पर चर्चा करना चाहती हूं। सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने यह कहा कि ''सबका साथ सबका विकास'' को लेकर खूब मेजें थपथपाई गईं । पहले फरीदाबाद के माननीय सदस्य बोले कि

खूब विकास हो गया है, फिर पंचकुला से श्री ज्ञान चन्द गुप्ता जी बोले कि खूब विकास हुआ, फिर श्री महीपाल ढांडा जी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोले और अभी श्री कुलवंत राम बाजीगर जी ने ''सबका साथ सबका विकास'' की बात कही। उपाध्यक्ष महोदया, क्या बात है ? मेरे झज्जर जिले में एक किलोमीटर सड़क भी नहीं बनी है और वहां के अस्पताल में केवल डायलिसिस की सुविधा दी जानी थी । हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी चार साल से कह रहे है कि डायलिसिस शुरू करवायेंगे लेकिन अभी तक नहीं हुआ? मेरे गांव मातनहेल में 50 बैडिड अस्पताल कब का तैयार हो चुका है और पी.एच.सी. में पुलिस की चौकी खोल दी उसका भी काम शुरू नहीं करवाया है? माननीय मुख्यमंत्री जी छूछकवास में कहकर गये थे कि महिलाओं के लिए कॉलेज बनवाया जायेगा, आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। छूछकवास बाई पास जहां हजारों एक्सीडेंट हो रहे हैं, मैंने उसके बारे में भी बार–बार कहा कि हैवी लोडिड ट्रक वहां से गुजरते है क्योंकि हमारा झाड़ली थर्मल पावर प्लांट, जे.के.एस. सुपर प्लांट, सी.एल.पी प्लांट और सुपर लक्ष्मी प्लांट से हैवी ट्रक आये दिन गुजरते रहते हैं । आज तक वहां पर बाईपास का निर्माण नहीं हुआ है । हमारे घरों के आगे से भी हैवी ट्रक गुजरते हैं, हमने इस बारे में एक बार नहीं बल्कि 50 बार कहा है । मैंने इस बारे में कॉलिंग अटैंशन मोशन भी दिया हुआ है लेकिन आज तक उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है । उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि स्टेट लैवल का स्पोर्टस स्टेडियम बनाने की बात कही थी लेकिन वहां पर एक भी ईंट लगाने का कार्य नहीं हुआ है तो ऐसे में ''सबका साथ सबका विकास'' कैसे हो गया? उपाध्यक्ष महोदया, आधे से ज्यादा विधायक तो बी.जे.पी. के नाराज बैठे हैं । श्रीमती बिमला चौधरी जी केवल स्कूल अपग्रेड कराने के लिए रोने तक को हो गई । उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे गांव मातनहेल में आये थे उन्होंने बहुत बड़ा जलसा निकाला था। सभी लोगों ने मुख्यमंत्री होने के नाते से स्वागत किया है और हमने भी इनका स्वागत किया । उपाध्यक्ष महोदया, वित्त मंत्री जी यहां सदन में उपस्थित नहीं हैं । मेरे गांव मातनहेल में सैनिकों को लेकर बहुत बड़ी–बड़ी चर्चाएं हुईं और बड़ी–बड़ी बातें हुई। सैनिक स्कूल के बारे में भी कहा गया, अच्छी बात है। हमारा सैनिकों का क्षेत्र है । मातनहेल के लोग सैनिक स्कूल की मांग करते–करते थक गये, आज तक वहां पर एक ईंट भी लगाने का काम नहीं किया गया और उसके लिए बजट में भी कोई प्रोविजन नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदया, किसका साथ

क्योंकि हमारा तो बिल्कुल भी साथ नहीं । हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदया : गीता जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए अब आप कृपया करके वाईंड–अप करें।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं एम्स के विषय पर बिलकुल भी कुछ नहीं कहना चाहूंगी। यह हमें मालूम है हमारा एम्स झज्जर में है और वह रहेगा भी। अगर वर्तमान सरकार इसे वहां पर बनायेगी तो ठीक नहीं तो हम आने वाले समय में अपनी सरकार के समय में इस काम को करेंगे। मैं मनरेगा की बात जरूर करना चाहूंगी। सक्षम युवाओं की जब हमने बात कही तो उस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि मनरेगा के हमारे यहां पर झज्जर जिले में जिसमें मातनहेल, साल्हावास, बेरी झज्जर ब्लॉक्स में तकरीबन 29000 मनरेगा के तहत अकुशल लोगों ने अपना जॉब कार्ड बनवाया हुआ है। इनमें से 15000 लोगों को आज तक किसी भी काम की पेमैंट नहीं हुई है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अगर 100 दिन का रोजगार दिया जाये तो उनको पेमैंट हो और अगर उनको 100 दिन का रोजगार सरकार सुनिश्चित नहीं करती है तो उनको भत्ता मिलना चाहिए जोकि अभी तक नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से सक्षम युवा रोजगार योजनाओं में भी भत्ता नहीं मिल रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो एक्सीडैंटल डैथ्स हैं इनका विषय बहुत ही गम्भीर है। हमारी तो यह कोशिश थी कि इस विषय पर एक कालिंग अटैंशन मोशन लाया जाये। हमारे प्रदेश में इस समय रोड सेफ्टी के विषय पर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। वर्ष 2018 में रोड सेफ्टी काउंसिंल बनी। सरकार को उसको जरूर एक्टिव करना चाहिए। आज ओवर स्पीड की वजह से, ओवर लोडिंग की वजह से और ड्रंक ड्राईविंग की वजह से हमारे प्रदेश में इस साल 5118 लोगों की मृत्यु हुई है, 11238 से ज्यादा एक्सीडैंट्स हुए हैं और इनमें 10020 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। सरकार को बजट में इस बात का प्रॉविजन करना पड़ेगा कि हम लोग सेफ्टी व सिक्युरिटी पर भी हम पूरा ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदया : गीता जी, आप जल्दी वाईंड–अप करें क्योंकि आपको बोलते हुए बहुत समय हो गया है और बाकी सदस्यों को भी अपनी बात कहनी है।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया जी, इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में गीता जयंती मनाई गई। यह बहुत ही अच्छी बात है। भगवान श्रीकृष्ण जी ने जो

गीता का संदेश दिया उसी को लेकर हम गीता जयंती मना रहे हैं। यह कोई पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तभी गीता जयंती मनाई जा रही है। मॉरिसस तक में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गीता जयंती मनाने का संदेश देकर आये यह बहुत ही अच्छी बात है लेकिन गीता के संदेश में जो भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है क्या सरकार के सभी लोग अपने जीवन में उसका पालन कर रहे हैं? इवैंट मैनेजमैंट पर करोड़ों रूपये खर्च किये जा रहे हैं। आज हमारे कर्मचारियों को सही समय पर सैलरी तो मिल नहीं रही है लेकिन इवैंट मैनेजमैंट पर करोड़ों रूपये खर्च किये जा रहे हैं। मैं यह बजट में ढूंढ रही थी कि गीता जयंती समारोह हो, सरस्वती समारोह हो या फिर हैपनिंग हरियाणा हो, इनके लिए बजट में कहीं भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदया जी, हमारे प्रदेश में कुछ समय पहले सरस्वती यात्रा निकली उससे सरस्वती का पानी तो नहीं आया लेकिन आज हमारे सरस्वती के मंदिर अर्थात् शिक्षा के मंदिर अनसेफ होते जा रहे हैं। मैं यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगी कि जिस समय हमारी सरकार थी उसके बाद सरकार बदली सभी साथियों ने कहा कि इन्होंने शिक्षा का भट्ठा बिठा दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगी कि यह मेरे पास सैंट्रल एडवाईजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की एक रिपोर्ट है जो उस समय टेबल्ड हुई। मैं उस समय इससे सम्बंधित सब–कमेटी की चेयरमैन थी। उस रिपोर्ट में राईट टू फ्री एण्ड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत मुफ्त में शिक्षा का प्रावधान था। फेल और पास करने की रिपोर्ट मेरे हस्ताक्षरों से आज से पांच साल पहले भारत सरकार में टेबल्ड हुई।

डॉ. पवन सैनी : उपाध्यक्ष महोदया जी, जो मैडम गीता जी कह रही हैं यह तो इन्होंने इनकी सरकार के जाते–जाते ही किया था वरना पांच साल में तो पूरे हरियाणा प्रदेश में शिक्षा का भट्ठा बिठा दिया था। अगर एक मार्च को भी कोई बच्चा स्कूल में दाखिला लेता था तो उसको भी ये 31 मार्च को पास कर देते थे। इनकी सरकार में इन्होंने स्कूल्ज़ का इतना बुरा हाल कर दिया था। आज हमारी सरकार के समय में बहुत से स्कूल्ज़ का रिजल्ट 70 परसैंट आया है और बहुत से स्कूल्ज़ ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट 100 परसैंट भी रहा है।

उपाध्यक्ष महोदया : गीता जी, आप कृपया करके एक मिनट में वाईंड–अप करें।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया जी, राईट टू एजुकेशन एक्ट में अमैंडमैंट लोक सभा में भी हो चुकी है और राज्य सभा में भी यह अमैंडमैंट हो चुकी है। यह

रिपोर्ट दोनों जगह टेबल्ड हुई है। राज्य सरकारों को कहा गया कि वे इस मामले में अपने हिसाब से निर्णय लें। यहां पर अभी शिक्षा मंत्री जी मौजूद नहीं हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि पांचवी क्लास और आठवीं क्लास की बोर्ड परीक्षायें कब यह सरकार शुरू करने का काम करेगी? सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बहुत से फैसले लिये गये। जो सरकार द्वारा किसान सम्मान पैंशन की बात की जा रही है हम इसका स्वागत करते हैं। हमारी सरकार के समय में हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट की मदद से हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में किसान मॉडल स्कूल्ज बनाने की बात कही थी। जिसके बावजूद हमने सात जिलों में किसान मॉडल स्कूल्ज़ शुरू भी कर दिये थे। पिछली बार जब मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न लगाया था तो उस समय सरकार ने कहा था कि उसने ये सभी किसान मॉडल स्कूल्ज़ बंद कर दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा कृषि मंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से भी यह अनुरोध है कि इन किसान मॉडल स्कूलों को दोबारा से शुरू किया जाये। मैं इस बारे में कहना चाहूंगी कि हमने जो 36 आरोही मॉडल स्कूल्स बनाये थे, करोड़ों रुपये की लागत से बिल्डिंग्स बनाई, हमारे नसीम अहमद भाई को वे नजर नहीं आई। हमने हर ब्लॉक में अरोही मॉडल स्कूल बनाने का काम किया था। उनके लिए टीचर्स की तथा प्रिंसिपल्स की नियुक्ति की जाये। ऐजूकेशन के मामले में हमने जो सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी महेन्द्रगढ़ में बनाई उसके बारे में पिछले दिनों अखबारों में यह छपा था कि उन्होंने यू.जी.सी. के नॉर्म्स को न मानते हुये भर्तियां निकाली हैं। वैसे वहां केवल 35 प्रतिशत फैकल्टी चल रही है और 60 प्रतिशत से ज्यादा हमारी यूनिवर्सिटीज में वैकेन्सीज खाली पड़ी हुई हैं। इस बारे में यू.जी.सी. का कहना यह है कि आप पूरी यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मानते हुये भर्ती करेंगे और उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान करेंगे लेकिन केवल हरियाणा सरकार द्वारा ही विभाग को एक यूनिट मानते हुये भर्तियां की गई हैं जिससे आरक्षित उम्मीदवारों को रिजर्वेशन का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो भी भर्तियां की जायें उनमें रिजर्वेशन को फोलो किया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, शिड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में यहां हाउस में सरकार की तरफ से बड़ी–बड़ी बातें कही गई हैं। मैं कहना चाहूंगी कि जब हमारी सरकार थी तो हमने शिड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन को बहुत ज्यादा पावर दे रखी थी लेकिन जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से उस कमीशन को ही भंग करने का काम किया है। आज सरकार का साढ़े चार साल का समय निकल

चुका है लेकिन आज तक शिड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन का गठन नहीं हो पाया है। इस प्रकार से एट्रोसीटीज के हितों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? सरकार की तरफ से क्राइम अगेंस्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स और क्राइम अगेंस्ट वूमन के जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें बहुत ज्यादा इनक्रीज हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, जब हमारी सरकार थी तो हमने अनुसूचित जाति, गरीबों और बी.पी.एल. को 100–100 गज के 3,84,000/– प्लाट आबंटित किये थे। हमने जब उनको पोजैशन दिया तो यह कहा था कि हम इनको ये प्लाट्स पूरी तरह से डिवैल्प करके देंगे। उनमें बिजली, पानी और गलियों की सभी सुविधायें उपलब्ध करवायेंगे लेकिन यह सरकार बनने के बाद वह स्कीम बंद कर दी गई है। किसी को एक प्लाट भी नहीं दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से पूछना चाहता हूं कि मिर्चपुर कांड के दलित पीड़ितों को आपने क्या दिया था? क्या उनको आपने डबल स्टोरी मकान बना कर दिये थे? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि ये तो भंग होने के बाद अनुसूचित जाति आयोग का भी गठन नहीं करवा पाये हैं, ये क्या दलितों की बातें करते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदीः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि हमने अनुसूचित जाति के लिए इतना किया है कि ये सोच भी नहीं सकती हैं। चार–चार महापुरूषों की जयन्ती को सरकारी घोषित करवाया है। मिर्चपुर कांड के पीड़ित तो गांव छोड़ कर जा रहे थे लेकिन हमने उनको गांव में ही बसाया है। ये किस मुंह से शिड्यूलड कास्ट्स की बातें करती हैं ? जब इनकी सरकार थी तब तो ये शिड्यूल्ड कास्ट के नाम पर अपना घर भरने में लगे रहे, उस समय इनको कुछ भी नजर नहीं आया। जब कुमारी शैलजा रो रही थी, राजपाल भूखड़ी रो रहा था और नरेश सेलवाल रो रहा था वह भी इनको नजर नहीं आया। अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष श्री अशोक तंवर की भी इन्होंने गर्दन तोड़ दी होती और आज ये शिड्यूल्ड कास्ट्स की बात करती हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने लगभग 5 साल होने वाले हैं। सबसे पहले आप अपनी सरकार के मंत्रियों को ट्रेनिंग दिलवाइये कि महिलाओं से किस शिष्टाचार से बात की जाती है। आज दलितों के

साथ कुम्भ स्नान किया जा रहा है, दलितों के पैर धोए जा रहे हैं इस तरह का नाटक दलितों के साथ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संवैधानिक अधिकार हैं जो भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत हमें दिये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदीः उपाध्यक्ष महोदया, आज सफाई कर्मचारियों का सम्मान हुआ है तो एक दलित महिला को यह नाटक लग रहा है, इनको दर्द है। इनको जलन इसलिए हो रही है कि वे बाल्मीकि समुदाय के लोग थे। इनको इसलिए दर्द है कि बाल्मीकियों के पैर क्यों धोए गये हैं, बाल्मीकि समाज के लोगों का सम्मान क्यों किया गया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, जिस प्रकार से मंत्री जी आपे से बाहर हो कर बोल रहे हैं । इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : उपाध्यक्ष महोदया, अगर इनमें नैतिकता थी तो इनको मिर्चपुर कांड पर रिजाईन देना चाहिए था, या जब गैस्ट टीचर्स के अन्दर रिजर्वेशन की बात आती थी तो उस पर इनको रिजाईन देना चाहिए था । आज ये नैतिकता की बात करते हैं ।(शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : मैडम गीता भुक्कल जी, आपका मैटर वाईंड अप हो चुका है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगी । यह पूरे स्टेट का विषय है । इस विषय पर मेरी चीफ सैक्रेटरी साहब से भी बात हुई है, मेरी कई ऑफिसर्ज से भी बात हुई है । जिला प्रशासन से भी बात हुई है कि डिजास्टर मैनेजमैंट के लिए हमारी जो नहरें हैं उनमें पिछले दिनों मेरे मातनहेल में बहुत सी जगहों पर लगातार काफी बच्चों की डूबने से मौत हुई है । जिसका हमारे पास कोई अलग से प्रावधान नहीं है इसलिए उसका प्रावधान किया जाए । एक यहां पौंड्ज अथोरिटी की बात की गई है कि पौंड्ज अथोरिटी का गठन किया गया है । मैं पूछना चाहती हूं कि जो हमारे जोहड़ हैं वह किसके अण्डर आते हैं और उन पर कौन पैसा खर्च करेगा ? क्योंकि मैंने तो चार साल पहले दो–तीन जोहड़ बताए थे कि उनको ठीक किया जाए । वह अभी तक ठीक नहीं हुए हैं । उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप मुझे प्रोटैक्ट नहीं कर पायी । आपने मुझे समय दिया

लेकिन उसके लिए सबको तकलीफ हुई है। मैं एक बात कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगी । बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें बहुत सशक्त किया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : उपाध्यक्ष महोदया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वालों ने अपने दलित प्रदेश अध्यक्ष को पीटा है । (शोर एवं व्यवधान) यह उनकी मीटिंग में नहीं जाते हैं । ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते हैं । (शोर एवं व्यवधान) इनको शर्म आनी चाहिए । ये लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर देश को लूट कर खा गये । बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को आप लोगों ने बेच दिया । (शोर एवं व्यवधान) आप लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को गिरवी रख दिया है । तुम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सबसे बड़े चोर हो । (शोर एवं व्यवधान) आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर डकैती करते हो । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : गीता जी, अब आप बैठिए ।

श्री हरविन्द्र कल्याण (घरौंडा): उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद । हमारे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी ने बड़ा शानदार बजट पेश किया है । उसमें बहुत से आंकड़ों के साथ सभी बातों की चर्चा हुई है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जहां किसानों सहित सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है । वहीं हरियाणा प्रदेश निरन्तर हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े उस बात का भी खास तौर से ख्याल रखा गया है । 'सबका साथ, सबका विकास' की निश्चित रूप से झलक इस बजट के अन्दर दिखाई देती है । उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा वर्ष 2030 में कैसा हो इस विजन को ध्यान में रखते हुए हरियाणा प्रदेश आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है । मैं खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्रीमान् नरेन्द्र मोदी जी की सोच है, चाहे वह किसानों की आय डबल करने की बात है या हर क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ना है वह काबिलेतारीफ है। जितनी भी योजनाएं केन्द्र से आई हैं लगभग उन सभी योजनाओं को लागू करने में सबसे पहले हरियाणा प्रदेश कामयाब रहा है । यह हमारी हरियाणा की सरकार की एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है जिसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है । उपाध्यक्ष महोदया, आज हमारे कांग्रेस के साथी सरकार की योजनाओं के

संबंध में संतुष्ट और असंतुष्ट होने की बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, यह तो इस प्रकार के लोग हैं जो सरकार की सबका साथ–सबका विकास जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं तक का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। यह लोग सरकार के हर उस अच्छे कदम का विरोध करते हैं जिससे हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ सकता है। यह लोग सरकार की हर बात का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, साढ़े चाल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले इन लोगों की सरकार हुआ करती थी और हम लोग टेलीविजन पर यह गाना सुना करते थे कि न.1 हरियाणा। इस तरह के गाने इन लोगों ने ही बनावाये थे। मैं घरौंडा विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। अगर मैं अपने घरौंडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की चार पांच बातें इनको बताऊं तो इनको समझ में आ जायेगा कि संतुष्ट क्या होता है और असंतुष्ट क्या होता है। आज थोड़ी–थोड़ी कमियों तक का यह लोग जिक्र करते हैं इनको मैं बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 40 साल पहले एक आई.टी.आई. बनाने की घोषणा हुई थी लेकिन कोई काम नहीं हुआ, वर्ष 2002 में पी.एच.सी. की मंजूरी हुई लेकिन कोई काम नहीं हुआ, लड़कियों का कॉलेज बनाने की कितने साल पहले से चर्चा चल रही है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, हर चुनाव से पहले बस स्टैंड बनाने का वायदा किया गया लेकिन कुछ नहीं हो पाया। यही नहीं हमारे यहां तो लड़कियों का स्कूल 22 साल तक डबल शिफ्ट में चला करता था। इसी प्रकार लड़कियों का कॉलेज और उसके साथ साथ जो हमारे यहां गवर्नमैंट कॉलेज है, यह भी पिछले 40 साल से बिना साईंस ब्लॉक के ही चलते रहे। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे घरौंडा विधान सभा क्षेत्र की सड़कें 10 फुट या 12 फूट की जर्जर हालत की हुआ करती थी। हमारे पुल बिल्कुल जर्जर हुआ करते थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम रायपुर जाटान है। जब मैं विधायक बनकर यहां पर गया तो एक बुजर्ग ने मेरा हाथ पकड़कर एक बात कही कि बेटा यह पुल देख रहे हो ना, हम बुग्गी लेकर इस पुल के उपर से जाते हैं पर हमें यकीन नहीं की हमारी बुग्गी इसी पुल के उपर से वापिस आ जायेगी। उपाध्यक्ष महोदया, यह नम्बर–1 हरियाणा की छाप का जिक्र मैं सदन को बता रहा हूँ। चाहे बस स्टैंड की बात हो या चाहे गांवों के विकास की बात हो हर क्षेत्र में प्रदेश का बहुत बुरा हाल था। आज यह लोग सदन में सब का साथ–सबका विकास जैसे योजनाओं का मजाक उड़ाने का काम करते है। उपाध्यक्ष महोदया, हमारा इलाका विकास के लिए तरसता था और विकास को महज रोहतक, झज्जर तथा हिसार

तक सीमित कर दिया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन काल में समान रूप से तथा मैरिट के आधार पर ऑनलाईन व्यवस्था को एडॉप्ट करते हुए युवाओं को नौकरियां देने का काम किया जा रहा है। अगर हम पिछले रिकॉर्ड को निकालकर देखें तो पायेंगे कि पिछली सरकारों के समय यदि 40 नौकरियों का रिजल्ट आता था तो उसमे ंसे 35 नौकरियां तो केवल 2–3 जिलों के युवाओं को ही मिला करती थी। उपाध्यक्ष महोदया, इस प्रकार की संकीर्ण सोच व कार्यशैली इन लोगों की हुआ करती थी लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में समान रूप से समान विकास किया जा रहा है। चाहे बिजली की बात हो, पानी की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, समाज कल्याण की बात हो, बेसिक इंफ्रॉस्ट्रक्चर की बात हो, व्यवस्था को ठीक करने की बात हो या मैरिट के आधार पर नौकरियां देने की बात हो हर क्षेत्र में पारदर्शिता बरतने का काम किया जा रहा है। आज ऐसे गरीब परिवारों के बच्चों को नौकरियां दी गई हैं जिन्होंने कभी सपने में भी नौकरी पाने का ख्वाब नहीं देखा था। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव मुंड़ीगढ़ी है। वहां से कुछ लोग मेरा मूंह मीठा करवाने के लिए आए। उन्होंने मुझे बताया कि आजादी के 70 साल के बाद पहली बार इस गांव में किसी युवा की सरकारी नौकरी लगी है और एक तरह से रिकॉर्ड टूटने का काम हुआ है। ऐसे ही मेरे एक विधान सभा क्षेत्र में संजय नगर है, यहां पर भी पहली बार किसी युवा को सरकारी नौकरी मिली है। उपाध्यक्ष महोदया, जब उन लोगों ने मुझे यह बात बताई तो मैंने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा कि तुम कहते हो कि आजादी के 70 साल बाद आज तुम्हारे गांव में पहली बार किसी युवा को सरकारी नौकरी मिलने से एक रिकॉर्ड टूटा है, मैंने उनको एक रिकॉर्ड की बात उनकी बात के जवाब के तौर पर बताई और वह यह थी कि यह भी प्रदेश में पहली बार हुआ है कि 54000 नौकरियां देने के बावजूद भी आप लोग चारों तरफ नज़र घूमा कर देख लो किसी एम.एल.ए. के परिवार से एक भी नौकरी लगी हो। उपाध्यक्ष महोदया, अगर किसी एम.एल.ए. के परिवार के सदस्य को नौकरी मिली है तो वह केवल गीता भुक्कल मैडम के परिवार के खाते में गई है लेकिन यह नौकरी भी योग्यता के आधार पर ही गई है।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, जैसाकि माननीय सदस्य कह रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह लगाया जाये कि किसी एम.एल.ए का बच्चा सक्षम व योग्य

नहीं है? सदन में हमारे बच्चों का जिक्र किया गया है। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का दम रखते है। क्या कल्याण जी समझते हैं कि मैं अपने बच्ची से रिजाईन करवाऊं। आप अपने बच्चों को शिक्षा दो किसने रोका है? आप लोगों को नौकरी लेने से किसने मना किया है? सरकार के विधायकों द्वारा सदन में मेरी बच्ची को नौकरी मिलने की बात इस तरह से की जा रही है जैसे मेरे परिवार ने कोई अपराध किया है। मेरे बच्ची ने मेहनत की है और उसी मेहनत की बदोलत नौकरी पाई है? यह लोग अपने बच्चों को पढ़ा ले इनको किसने रोका है? सदन में इस तरह से बात की जा रही है जैसे नौकरी लेकर हमारी बच्ची ने कोई अपराध किया है? हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। हमारे बच्चे मेहनती हैं। हमने उनको आगे बढ़ने की शिक्षा दी है।

श्री हरविन्द्र कल्याणः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या को मेरी बात को दिल पे नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैंने इनके परिवार के बारे में कोई गलत बात नहीं कही बल्कि मैं तो केवल मात्र व्यवस्था परिवर्तन की ही बात कह रहा हूँ और उसी व्यवस्था परिवर्तन के तहत पारदर्शिता बरतकर नौकरी देने का जो काम किया गया है, मैं केवल उसी की ही बात कह रहा हूँ और मैं माननीय सदस्या को बधाई देना चाहूंगा कि इनके बच्चों ने योग्यता के बल पर नौकरी पाने का काम किया है।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री(श्री नायब सैनी): उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या को समझना चाहिए कि सदन में केवल इस बात पर बल दिया जा रहा है कि पहले मेहनत करने वाले बच्चों को नज़रअंदाज कर दिया जाता था लेकिन आज जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वे आगे बढ़ते जा रहे हैं और सदन में यही बात कही गई कि गीता जी की बच्ची ने मेहनत के बल पर नौकरी पाई है जबकि पहले मेहनती युवाओं को उनका हक नहीं मिला करता था लेकिन आज मनोहर सरकार में युवाओं को उनका हक मिल रहा है।

डॉ0 पवन सैनी : उपाध्यक्ष महोदया, बहन गीता भुक्कल जी की बेटी बड़ी काबिले तारीफ है क्योंकि वह बेटी श्री मनोहर लाल जी की सरकार में नौकरी पर लगी है और बहन गीता जी कहना चाहती है कि वह अपने बल पर नौकरी लगी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। अच्छे संस्कार दिए हैं। हमने कोई अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं दी है। (शोर

एवं व्यवधान) हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : बहन गीता जी, आपकी लड़की काफी होशियार है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 पवन सैनी : अध्यक्ष महोदय, वह बेटी अपनी काबिलियत पर नौकरी लगी है, इसलिए बहन गीता भुक्कल को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री हरविन्द्र कल्याण : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस पुरानी व्यवस्था को बदला, जिसके कारण बेरोजगार युवा आगे बढ़े। हम बहन गीता जी की बेटी की योग्यता का भी सम्मान करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) बहन गीता भुक्कल जी का भी सम्मान करते हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार में बाकी भर्तियां मैरिट के आधार पर नहीं हुई? हमने अपने बच्चों को अच्छे ढंग से शिक्षा दिलवाई है। हमने अपने बच्चे कोई गुण्डे और बदमाश नहीं बनाएं हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात आपके माध्यम से सदन में बताना चाहती हूँ कि*** हमने अपने बच्चों को दूसरों की तरह गुण्डा बदमाश नहीं बनाया बल्कि हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। मेरा बेटा एल.एल.एम. कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : बहन गीता जी, कल्याण जी भी यही बातें कहना चाह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री हरविन्द्र कल्याण : उपाध्यक्ष महोदया, आज विषय यह नहीं है कि नौकरी किसको मिली। आज विषय यह है कि हमारी सरकार ने नई व्यवस्था कायम की है। पहले की सरकारों में पहले ही नौकरी पर लगने की लिस्ट आउट हो जाती थी कि फलां एम.एल.ए. के बेटे को या फिर फलां मंत्री के भतीजे को नौकरी मिलेगी। आज सवाल यह है कि हमारी सरकार ने एक नई व्यवस्था कायम की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ऐसी व्यवस्था बनी है कि योग्यता के आधार पर नौकरियां देने का काम शुरू हुआ है। नौकरियों में पारदर्शिता

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

लाकर हमारी सरकार ने व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदया, एक विषय यह आया था कि जहां सरकार में अच्छे–अच्छे कामों का जिक्र होता है तो फिर सड़कों पर इतने लोग क्यों हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन से इतना कहना चाहूँगा कि सड़कों पर आना उन लोगों का प्रायोजित भी हो सकता है। मगर पांच नगर निगम के चुनाव और जीन्द उप चुनाव यह कहीं भी प्रायोजित नहीं है। यह श्री मनोहर लाल जी के कामों की हकीकत है। यह आइना हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिखाया है। कांग्रेस पार्टी ने लम्बे समय से राज करते हुए हरियाणा की व्यवस्था को खराब करने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पं0 दीन दयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी निर्माणाधीन है, उसके लिए बजट में प्रावधान किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत–बहुत बधाई देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज हर क्षेत्र के लिए वित्तीय प्रबंधन करना और एक विजन के तहत हरियाणा को आगे ले जाने का काम कर रही है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ। (**इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए**।) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने एक विषय रखना चाहता हूँ कि करनाल का एरिया जी.टी. रोड और यमुनानगर के बीच का एरिया है। यमुनानगर के क्षेत्र में जितने भी डार्क जोन ब्लॉक हैं उनमें वॉटर लैवल में काफी अंतर है। कहीं युमनानगर के पास वॉटर लैवल ऊपर है और जी.टी. रोड की तरफ वॉटर लैवल नीचे है। पूरे डार्क जोन को अगर एक इकाई के तौर पर देखें तो लोगों को कनैक्शन मिलने में कठिनाई होती है। अध्यक्ष महोदय, यह रिव्यू होना चाहिए और केन्द्र सरकार को हमारी सरकार की तरफ से पत्र लिखना चाहिए कि डार्क जोन के लिए जहां पर वॉटर लैवल ऊपर व नीचे है उसके लिए एक सर्वे करवाया जाये ताकि भविष्य में किसानों को टयूबवैल आदि कनैक्शन लेने के लिए कोई दिक्कत न आए। अध्यक्ष महोदय, मैं बजट का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री तेजपाल सिंह तंवर : आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभासदों, आज हम 13वीं विधान सभा के 5वें बजट सत्र में उपस्थित हैं । स्पीकर साहब ने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया इसके लिए मैं उनका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । हमारे

वित्त मंत्री महोदय ने बहुत बढ़िया बजट पेश किया है । इसमें उन्होंने सभी चीजों का पूरा ख्याल रखा है । इस पर सदन में कुछ नोक–झोक भी हो रही है और कुछ सदस्य इस पर कटाक्ष भी कर रहे हैं । हमारा हरियाणा एक छोटा–सा प्रदेश है । मेरा विचार है कि अगर पिछली सरकारें थोड़ा–थोड़ा भी काम करती तो आज हमारा प्रदेश वाकई नंबर 1 होता । वैसे तो हरियाणा का नं. 1 होने का बहुत प्रचार किया गया लेकिन जब हमने सरकार में आने के बाद हरियाणा का हाल देखा तो पता चला कि हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में उस समय कोई विशेष काम नहीं हुआ था। (विघ्न) मेरे विपक्ष के भाइयों को मेरी इस बात से बुरा नहीं मानना चाहिए । हमने प्रदेश में जो काम किये हैं उनसे प्रदेश की जनता पूरी तरह खुश है । हमने सड़कों, यूनीवर्सिटीज, अंडरपासिज, ओवरब्रिजिज, ऐलिवेटिड पासिज, पुरानी हो चुकी तारों को बदलवाने, नये पावरहाउसिज बनवाने, मीठा पीने का पानी उपलब्ध करवाने इत्यादि का काम करवाया है । जहां पर खारा पानी था वहां हमने लोगों को पीने का मीठा पानी उपलब्ध करवाया है । हमारी सरकार ने मेरे स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम 23 गांवों में 68 करोड़ रूपये की लागत से पीने का पानी पहुंचाया है। हमारी सरकार ने हमारे मेवात जैसे पिछड़े क्षेत्र में भी पीने का मीठा पानी पहुंचाया है । हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय कम से कम 10 बार जा चुके हैं जबकि उनसे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने मेवात के लिए इतना समय नहीं दिया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज भी अपना पूरा फोकस मेवात क्षेत्र पर रखते हैं । इसके अतिरिक्त हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी मेवात के क्षेत्र को पिछड़ा जिला घोषित किया है। हमारे माननीय मंत्री महोदय और स्टील अथॉरिटी ने नूँह को गोद लिया है। हम इस बारे में कई बार मीटिंग करते हैं। हमारे माननीय सदस्य नसीब भाई और माननीय सदस्य जाकिर भाई भी बातें करते हैं कि पीछे जो सरकार थी उन्होंने हमारे इलाके में काम नहीं किया । मेरा कहना है कि हमारी सरकार और पिछली सरकार के कामों की अगर तुलना कर लें तो सच पता चल जाता है । सदन में माननीय सदस्य करण सिंह दलाल और कांग्रेस के अन्य साथी भी बैठे हैं जो काफी समय से सरकारों में रहे हैं । हमारी सरकार के बारे में कुछ बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन पता नहीं क्यों विपक्ष को उनसे तकलीफ होती है ? मेरा कहना है कि उनको अपनी बात करनी चाहिए । अगर हमारी सरकार में कोई कमी है तो उनको गिनवाना चाहिए और अच्छे कामों को अच्छा भी कहना चाहिए । पिछली सरकारों में जो काम हुए हैं वे सबके सामने हैं । सदन में

पुराने और धुरंधर साथी बैठे हुए हैं । हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा । सदन में लिखा भी हुआ है कि जो भी झूठ बोलेगा या गलत बोलेगा उसको पाप लगेगा । जब विधान सभा का निर्माण हुआ तो उस समय ये बातें यहां पर अंकित करने वाला कोई उच्च कोटि का बुद्धिजीवी ही रहा होगा और उसने ये बातें सोच–समझकर ही लिखी हैं । हमारी सरकार ने प्रदेश के किसान वर्ग का काफी ख्याल रखा है । हमारे इलाके में बाजरे की काफी ज्यादा खेती होती है । पहले बाजरा 700–800 रूपये प्रति क्विंटल के भाव से बिकता था लेकिन हमारी सरकार ने एक झटके में बाजरे का मूल्य 1950 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया । आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि किसानों की फसल कम से कम दोगुने भाव पर बिकनी चाहिए और एक एकड़ में 1–2 लाख रूपये तक की आमदनी होनी चाहिए । हमारी सरकार किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए इस दिशा में काम भी कर रही है और किसानों के लिए हर पहलू पर विचार–विमर्श किया जा रहा है । पिछली सरकारों ने किसानों के नाम पर सरकारें तो बनाई थी लेकिन उनके लिए काम नहीं किया था । कुछ लोगों ने सिर्फ झूठ बोलकर 50 सालों तक हरियाणा में हुकूमत की है । हमारी सरकार से पहले की सरकारों में कुछ लोग ऐसे थे जो विकास को पसंद नहीं करते थे । उनकी सोच थी कि सिर्फ झूठ बोलो और राज करो । अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी की सोच है कि प्रदेश में विकास होना चाहिए और लोगों को हर तकलीफ से मुक्त करवाया जाना चाहिए, उसमें चाहे प्रदेश में पानी की दिक्कत हो, चाहे स्कूल खोलने की बात हो, चाहे बेटियों की सुरक्षा की बात हो, चाहे कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे यातायात के साधनों की बात हो या रोड्ज बनाने की बात हो। ये सभी चीजें हमारे प्रदेश के सभी विभागों के माननीय मंत्री पूरी कर रहे हैं। हमारी प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है। सभी माननीय मंत्री अपने–अपने विभागों में पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। जहां तक बजट की बात है तो प्रदेश सरकार ने बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाकर बजट पेश किया है। विपक्ष के माननीय सदस्यों की चिन्ता है कि बजट बढाने से प्रदेश के ऊपर कर्जे का बोझ भी बढ़ जाएगा। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि अगर कर्जा लिया जाएगा तो मेहनत करके भरा भी जाएगा। बस में लिखा हुआ होता है कि सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करेगी। अगर सरकार कोई गलती करेगी तो उसे सरकार ही सुधारेगी। इसलिए विपक्ष के माननीय सदस्यों को चिन्ता नहीं करनी चाहिए। सरकार ने यह बजट

प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए बढ़ाया है और सरकार प्रदेश में विकास कार्यों पर भी खर्च करेगी। सरकार ने जिस–जिस क्षेत्र में जितना बजट दिया है, सरकार उस बजट का प्रबन्ध भी करेगी। इसके लिए सरकार कहीं से भी पैसों का प्रबन्ध करेगी। सरकार ने जो बजट पेश किया है उसको 100 फीसदी पूरा किया जाएगा। माननीय मुख्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी का नारा है कि प्रदेश को विकास करके चमकाना है और प्रदेश में किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के कुछ छोटे–छोटे काम पैंडिंग रह गये हैं, उनको पूरा करवाया जाए। माननीय शिक्षा मंत्री जी इस समय सदन में नहीं बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के कुछ स्कूल्ज अपग्रेड हो चुके हैं और कुछ स्कूल्ज अपग्रेड होने वाले हैं। हमारे जिले में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजिज भी बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में दो मेडिकल कॉलेज बनाये गये हैं जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रत्येक जिले में एक–एक मेडिकल कॉलेज बनवाने की बात ही कही थी। हमारे क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य करवाये गये हैं। मेरी एक मांग यह है कि मेरे तावडू क्षेत्र को गुरूग्राम जिले में शामिल कर दिया जाए। मेरी यह बहुत पुरानी मांग है, इसलिए इस मांग को पूरा कर दिया जाए। हमारे प्रदेश के माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं और सभी माननीय सदस्य भी बैठे हुए हैं। मेरा माननीय सदस्य श्री जाकिर हुसैन जी से भी अनुरोध हे कि वे भी इस मामले में मेरा समर्थन करें। गुरूग्राम जिले में तावडू को शामिल करने की मांग बहुत पुरानी है, इसको पूरा किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर विपक्ष के माननीय सदस्य बात को शांति से सुन लें तो 2 मिनट में ही बात पूरी हो जाती है।

श्री श्याम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे रादौर हल्के में बहुत विकास हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे हल्के के किसानों पर दर्ज केस वापिस लिए जाए।

श्री नसीम अहमद (फिरोजपुर झिरका): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे हरियाणा प्रदेश के इस बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अगर बजट में आंकड़ों की बात करें तो वे चीजें मेरी समझ में नहीं आयी, लेकिन मैंने 2– 4 मोटी–मोटी बातें समझी हैं जिनमें से एक बात तो यह है कि

हरियाणा प्रदेश का कर्जा बढ़ा है। आज हमारे प्रदेश पर 1 लाख 80 हजार करोड़ रूपये का कर्जा है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जब वर्ष 2005 तक इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी तब हरियाणा प्रदेश पर 23,000 करोड़ रूपये का कर्जा था।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने की बात की गयी है जिसमें कहा गया है कि हरियाणा प्रदेश के 56,000 नौजवानों को रोजगार दिया गया है। मैंने जब आंकड़े देखे तो मेरी समझ में नहीं आया कि 56,000 नौकरियाँ कहां पर दी गयी हैं ? हरियाणा प्रदेश के सभी विभागों की कुल सरकारी नौकरियाँ 3,41,775 हैं और अगर वर्ष 2005 तक की बात करें तो उस समय प्रदेश में कुल 3,20,515 नौकरियाँ थी। पिछले 15 सालों में केवल 21,000 नौकरियाँ बढ़ी हैं परन्तु सरकार कह रही है कि उन्होंने 56,000 सरकारी नौकरियाँ दी हैं।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कुछ कर्मचारी रिटायर भी हो जाते हैं।

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि सरकार नयी पोस्ट्स क्रिएट क्यों नहीं कर रही है ? आज प्रत्येक महकमें में स्टॉफ की कमी है। हैल्थ विभाग में भी स्टॉफ की कमी है।

श्री नायब सैनीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनको इस बात का पता नहीं लग रहा है कि ये नौकरियां कहां पर दी गयी हैं ? इस जानकारी के लिए माननीय सदस्य मुझसे अलग से आकर मिल लें तो मैं उनको बता दूंगा कि संबंधित बच्चों ने किन–किन विभागों में ज्वाईन किया है। माननीय सदस्य को प्रत्येक बच्चे का ज्वाईनिंग लैटर दिखा दूंगा जिससे पता चल जाएगा कि सरकार द्वारा कितनी नौकरियाँ दी गयी हैं।

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मेरी बात को तो सुन लें। सरकार कह रही है कि उन्होंने 56,000 युवाओं को नौकरियाँ दी हैं।

श्री अध्यक्षः नसीम जी, माननीय मंत्री जी आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं।

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी का राज था और वे भी कई लाख नौकरियाँ देने की बात कह रहे हैं। सरकार जो कर्मचारी

रिटायर्ड हो रहे हैं सरकार उन्हीं कर्मचारियों के अगेंस्ट भर्ती कर रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार नयी वैकेन्सीज क्रिएट करे तो इस तरह के कार्य से हमारे युवाओं को और ज्यादा रोजगार मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अब तक पिछले 15 साल में केवल 21 हजार ही नई भर्तियां हुई हैं। (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नसीम अहमद जी हमारे बड़े ही काबिल साथी हैं और मैं इनकी बातों को दुरुस्त कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 56 हजार नई नौकरियां दी हैं, जबकि इससे पहले की सरकार के अपने 10 साल के कार्यकाल में केवल 18 हजार ही सरकारी नौकरियां दी गई थीं। उससे पहले चौटाला साहब की सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 5500 सरकारी नौकरियां दी गई थीं। अभी हमारी सरकार ने 56 हजार नौकरियां दी हैं और आने वाले तीन–चार महीने में 17 हजार और नौकरियां देने जा रही है। अगर हम नई सरकारी नौकरी देने की तुलना पिछली दो सरकारों से करें तो पाएंगे कि पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 9 हजार सरकारी नौकरियां दी गई थीं, जिससे पांच गुना ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाली हमारी सरकार इस साल हो जाएगी और अगर हम चौटाला साहब के 5 साल के कार्यकाल में जो 5500 सरकारी नौकरियां दी गई थीं, उससे तुलना करें तो उससे लगभग 12.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाली हमारी सरकार इस साल हो जाएगी। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि हमने पिछले साढ़े चार साल में जितनी नई सरकारी नौकरियों की पोस्टें सैंक्शन की है, उतनी पोस्टें पिछले 15 सालों में सैंक्शन नहीं हुई थीं। मैं इसका आंकड़ा भी माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री नसीम अहमदः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही जानना चाह रहा था कि आज के समय में हरियाणा के बहुत सारे विभागों में जो वैकेंसिज खाली पड़ी हुई हैं, जिनमें खासकर एक हैल्थ डिपार्टमैंट भी है। हमारे मेवात जिले के अंदर हैल्थ डिपार्टमैंट में जितनी डॉक्टरों की पोस्ट सैंक्शन हैं, उसका 10 परसेंट भी पोस्ट्स भरी हुई नहीं है। अगर मैं एजुकेशन डिपार्टमैंट की बात करूं तो मैं बताना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा में एजुकेशन डिपार्टमैंट में 28 हजार सरकारी नौकरियों की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, वहीं मेवात जिले के अंदर सरकार ने एजुकेशन डिपार्टमैंट में 1700 पोस्टें सैंक्शन कर रखी है और उसमें 700 के लगभग पोस्टें भरी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री

जी से कहना चाहूंगा कि जब सरकार प्रदेश में इतनी नौकरियां दे रही हैं तो उसे नई नौकरियां भी देनी चाहिए, ताकि सरकारी विभागों में स्टाफ की जो कमी है, वे पूरी हो सकें। आज के समय में कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, जहां पर स्टाफ की कमी न हो। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल जब माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था तो उस बजट में उन्होंने मेवात के अंदर रेल चलाने की व्यवस्था की थी। उस बजट में उन्होंने यह भी जिक्र किया था कि हम मेवात के अंदर रेल चलाने के लिए फिजीबिलिटी चेक करवा रहे हैं और हम वहां पर जल्दी से जल्दी रेल चलाने की व्यवस्था करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार के पिछले बजट का 121 नम्बर पैरा था जिसमें कहा गया था दिल्ली, सोहना, नूंह, फिरोजपुर–झिरका और अलवर की रेलवे स्लाइडिंग परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है। सर, इस बार भी बजट में सरकार ने उसकी व्यवहार्यता जांच करने का ही जिक्र कर रही है। अध्यक्ष महादेय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ये कब तक मेवात में रेलवे लाइन चलाने के लिए व्यवहार्यता की ही जांच करते रहेंगे ? सरकार तो पिछले एक साल से कह कर रही है कि वह उसकी व्यवहार्यता की जांच कर रही है। सन् 1971 से लेकर आज तक हर सरकार के शासनकाल में इसके लिए अपने–अपने स्तर से वायदा किया गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने मेवात में रेलवे लाइन शुरू करने के लिए व्यवहार्यता की तो जांच करवा ही है, अब ये जल्दी से जल्दी उसके लिए बजट का आबंटन करें और केन्द्र सरकार से इसके लिए जल्दी से जल्दी आदेश लें ताकि वहां पर जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेवात की बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि कल आपने भी मुझे कहा था कि मैं भी मेवात के लिए वही कैसेट चलाऊंगा जो मेवात की पहले से चलती रही है। स्पीकर सर, यह हमारी मजबूरी है, अगर हम मेवात के लिए वह कैसेट न चलाएं तो हमारे मुद्दे तो दबे के दबे रह जाएंगे। हम तो पिछले कई सालों से उन्हीं मुद्दों को उठाते आ रहे हैं, क्योंकि यह हमारी मजबूरी है। अगर सरकार हमारे उन मुद्दों को खत्म ही कर देगी तो हम मुद्दे क्यों उठाएंगे। स्पीकर सर, हमारे यहां पर रेलवे लाइन की बहुत ही पुरानी डिमांड है। स्पीकर सर, जैसा कि आज क्वैश्चन आवर में भी मेवात के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूवल का एक मुद्दा आया था। अध्यक्ष महोदय, हमारे मेवात के 35 हजार युवक जो रोजगार के नाम पर ड्राइविंग करते हैं उन बेरोजगार युवकों के

लिए यह बहुत ही जरूरी है और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और उन लोगों को इसमें कुछ सहूलियतें दी जानी चाहिए। स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री श्री नरबीर सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे फिरोजपुर–झिरका से बिवान का बड़ा ही खूबसूरत रोड बनवाया, लेकिन मैं उनका ज्यादा धन्यवाद और फूल–मालाओं से स्वागत उस दिन करूंगा जिस दिन वे हमारे फिरोजपुर–झिरका का जो नैशनल हाईवे नम्बर 248–A है, उसको फोर–लेन बनवा देंगे। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि इस खूनी रोड पर रोज हमारे बच्चे और नौजवानों की मौत हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये उसको फोर–लेन बनाने का जल्दी से जल्दी कार्य करें, जिससे मेवात के लोगों का भला हो सके। अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी की हमारी बहुत पुरानी मांग है । माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर यूनिवर्सिटी बनाने का प्रावधान हो तो आज ही इसकी घोषणा कर दें । जब वित्त मंत्री जी बजट पर जवाब दें तो इस विषय पर भी अपनी टिप्पणी देने की कृपा करें। आज मेवात के विद्यार्थी पढ़ने के लिए बहुत जागरूक हो चुके हैं। अब मेवात बदल रहा है और इस बदलाव का श्रेय यदि आप ले लेंगे तो आपको इसका पुण्य भी मिलेगा । हमारे यहां जनरल अस्पताल माढ़ी खेड़ा और मैडिकल कॉलेज, नलहड़ में स्टॉफ की बेहद कमी है । इन दोनों अस्पतालों में आउट–सोर्सिज के द्वारा भर्ती की गई है । वहां के लोकल ठेकदारों को जो ठेका दे रखा था उसमें उन्होंने बहुत धांधली की हुई है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पिछले साल भी एक कम्पनी का ठेकेदार मजदूरों के पैसे लेकर भाग गया था और सरकार को उसके 20 लाख रुपये रोकने पड़े थे, यह सब रिकॉर्ड की बातें हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि उसकी जांच करवाई जाए और इस तरीके के ठेकेदारों को ठेका न दिया जाए जो पैसे लेकर के भर्तियां करते हैं और हमारे बेरोजगार नौजवानों के साथ छल करते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पहली बार ऐसा बजट पेश किया गया है जिसमें हमारे मेवात डिवैल्पमैंट अथॉरिटी का जिक्र तक नहीं किया गया है और इस बजट में ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं रखा गया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना ? अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि एम.डी.बी. पर विशेष ध्यान दिया जाये, जिस तरीके से सरकार के बनते ही कई बार मीटिंग की गई । हमें यह बात बड़ी अच्छी लगी कि उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी,

माननीय वित्त मंत्री जी और मंत्रिमंडल के अन्य माननीय मंत्री जी बैठकर के मीटिंग लेते थे लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यदि उसकी मीटिंग करते रहेंगे तो कुछ अधिकारी सीरियस होकर के काम भी करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नसीम जी, अब आप वाईंड अप कर लीजिए क्योंकि आपको बोलते हुए 10 मिनट हो गये हैं ।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी बोलना शुरू भी नहीं किया है। जहां तक नहरी पानी की बात है तो हमारे फिरोजपुर झिरका में 10 प्रतिशत ऐसा क्षेत्र है जिसमें नहर के माध्यम से पानी सिंचाई के लिए आता है। अध्यक्ष महोदय, अगर आज आप वहां जाकर के देखोगे तो आपको एक बूंद भी पानी की नहीं मिलेगी। फिरोजपुर झिरका में नहरों की कई टेल हैं, आज तक उन टेलों में एक बूंद भी पानी की नहीं गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि पंचायत विभाग में बहुत गड़बड़ी चल रही है और वहां जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको सख्त हिदायत दी जाये ताकि वे ठीक काम कर सकें क्योंकि वहां के अधिकारियों ने अपने ठेकेदार बैठा रखे हैं । अध्यक्ष महोदय, अगर कोई व्यक्ति अपने काम के लिए जाता है तो वे अधिकारी अपने ठेकेदारों से काम करवाते हैं और उनसे मनमर्जी के पैसे भी दिलवाते हैं और काम भी अच्छा नहीं करते हैं । अध्यक्ष महोदय, मुझे हैदाराबाद में आयोजित सेमिनार में विधान सभा कमेटी की तरफ से जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मुझे वहां का सिस्टम बहुत अच्छा लगा था । वहां पूरे हिन्दुस्तान की अलग–अलग विधान सभाओं के विधायकगण सेमिनार में उपस्थित हुये थे । आपकी चेयरमैनशिप में वहां सेमिनार भी हुआ था जिसमें श्री श्याम सिंह राणा जी और श्री ज्ञान चन्द गुप्ता जी भी उपस्थित थे। वहां के माननीय पंचायत मंत्री जी उपस्थित थे। मैं इस महान सदन में सेमिनार की कुछ झलकियों के बारे में बताना चाहूंगा। वहां जो मनरेगा का सिस्टम है। उसको देखकर के हम सभी बहुत प्रभावित हुये थे। वहां की कमेटी ने हमें तेलंगाना का इब्राहिमपुर नाम का एक आदर्श गांव दिखाया था, उस गांव में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत बहुत काम करवाये गये हैं। जैसा कि श्याम सिंह राणा जी कह रहे थे कि वहां पर मॉस्कीटो फ्री नालियां, उनमें किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं, अच्छे सौलर सिस्टम और गायों व भैंसों के लिए अलग सिस्टम बना रखे थे । अध्यक्ष महोदय, वे काम वाकई में देखने

लायक थे । उन लोगों को मनरेगा के तहत कृषि क्षेत्र में विकास करने के लिए सब्सिडी भी मिलती है, जिससे कि वहां अधिक से अधिक लोग प्रोत्साहित हो सकें । अध्यक्ष महोदय, उन्होंने वहां के कब्रिस्तानों में इतनी अच्छी शैड बना रखी थी जैसा कि पीछे सदन में बात चल रही थी कि बड़ा मन करता है कि कोई आदमी यह सोचे कि मैं मर जाऊं तो कितना अच्छा कब्रिस्तान मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं देखी । अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय पंचायत मंत्री जी से अनुरोध है कि हरियाणा प्रदेश के लिए भी ऐसी पॉलिसी और मनरेगा का प्रावधान करने का काम करें। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य है कि हरियाणा प्रदेश की जनता को और हरियाणा की पंचायतों को मनरेगा के बारे में सही मायनों में मालूम नहीं है इसलिए मनरेगा को प्रत्येक गांव में प्रमोट करना चाहिए। मनरेगा बहुत बड़ी स्कीम है। आज मनरेगा हिन्दुस्तान के ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए और रूरल अर्बन डिवैल्पमैंट के लिए लाईफ लाईन है। इसको सूचारू रूप से लागू करवाने के लिए गांवों की पंचायतों को निर्देश दिया जाये कि ज्यादा से ज्यादा काम करवाये जायें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 45 हजार की आबादी के एरिया पर जो पी.एच.सी. बनी हुई है, उनमें एक भी डॉक्टर नहीं है । वहां सिर्फ एक लैडी नर्स की ड्यूटी लगा रखी है । यदि अचानक रात के समय में डिलीवरी से रिलेटिड कोई केस आ जाये तो वहां ऐसी कोई सहूलियत नहीं है, जिससे आसानी से डिलीवरी करवाई जा सके। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर डॉक्टरों की पोस्टिंग जल्दी से जल्दी करने का काम करें। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में हरियाणा रोडवेज़ की बसों की बड़ी भारी कमी है। हमारे क्षेत्र में पहले फिरोजपुर झिरका में हरियाणा रोडवेज़ का सब–डिपो हुआ करता था जोकि 1982 से चल रहा था लेकिन पिछली सरकार में उसको वहां से शिफ्ट कर दिया गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि फिरोजपुर झिरका में फिर से हरियाणा रोडवेज़ का सब–डिपो बनाने की कृपा करें ताकि हमारे वहां पर जिन लोगों की उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रिश्तेदारियां हैं उनको वहां पर आने–जाने में आसानी हो सके। स्पीकर सर, मैं एक बार आपका फिर से धन्यवाद करता हूं और सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि उसका जाने का समय नज़दीक है इसलिए अब तो वह मेवात के लोगों के लिए कुछ अच्छे काम कर जाये जिससे मेवात के लोग इस सरकार को सदा याद रखें। आने वाले समय में यही सरकार सत्तासीन होती है या नहीं होती

है यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है इसलिए सरकार को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए।

सदन की कार्यवाही में परिवर्तन

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : आदरणीय अध्यक्ष जी, बजट पर आपने बहुत अच्छी चर्चा करवाई है और मुझे लगता है कि काफी सदस्यों ने आज बजट पर चर्चा में हिस्सा भी लिया है। मेरा निवेदन है कि अभी भी कुछ सदस्य बचे हैं जो हमारे सीनियर साथी हैं हम बजट पर उनकी टिप्पणी भी सुनना चाहते हैं। अगर आप अनुमति दें तो आज आप डिमाण्डज़ पास करवा करके उसके बाद जब सभी माननीय सदस्य बजट पर बोल लें तो उसके बाद मैं कल डिटेल में रिप्लाई दे दूं । इस प्रकार से मैं सदन के माध्यम से आपकी अनुमति चाहता हूं कि डिमाण्डज़ आज आप पास करवा लें। उसके बाद कल मैं अपनी डिटेल्ड रिप्लाई कर दूंगा।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : स्पीकर सर, इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि वित्त मंत्री महोदय के रिप्लाई से पहले डिमाण्डज़ को पास नहीं किया जा सकता।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, ढुल साहब जो कह रहे हैं मैं यह समझता हूं कि वो एप्रोप्रिएशन बिल होते हैं जिनको वित्त मंत्री के जवाब के बाद ही पास करवाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है ढुल जी, कल एप्रोप्रिएशन बिल्ज़ पर चर्चा करवा ली जायेगी और डिमाण्डज़ को आज पास करवा लेते हैं।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : स्पीकर सर, जैसा आप कह रहे हैं अगर आप करना चाहें तो वह तो आप करके ही रहेंगे लेकिन इसको रूल्ज़, रेगूलेशंज और परम्परायें कहीं भी अलाऊ नहीं करती। इस तथ्य को आप अवश्य ध्यान में रख लेना।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, आप इस सम्बन्ध में रूल्ज़ रेगूलेशन को ध्यान में रखते हुए निर्णय कर दें।

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, जब सभी माननीय सदस्यगण बजट पर होने वाली चर्चा में भाग ले लेंगे उसके बाद डिमाण्डज़ को आज पास करवाया जा सकता है और कल एप्रोप्रिएशन बिल्ज़ पर चर्चा करवाई जा सकती है।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : ठीक है स्पीकर सर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो आज ही वर्ष 2019–2020 के लिए बजट अनुमानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान आज ही करवा लिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बजट पर अनुमानों की मांगों को आज ही सदन में पास करवा लिया जाये।

श्री जाकिर हुसैन : स्पीकर सर, मेरी इस सम्बन्ध में एक सबमिशन है कि हम जो सदस्य ऐसे रह रहे हैं जो अभी तक बजट पर नहीं बोलें हैं उनको कल सुबह बजट पर बोलने का मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है जाकिर जी, जो सदस्य बजट पर बोलने से रह गए हैं उनको कल बिल्ज़ पर बोलने का मौका दे दिया जायेगा।

वर्ष 2019–2020 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर

श्री कुलवंत राम बाजीगर : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अभी जब मैं बाहर पानी पीने गया हुआ था, उस समय बहन गीता भुक्कल जी ने यह कहा था कि *** मेरा यह कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है इसलिए इसको हाउस की प्रोसीडिंग्स में से निकलवाया जाये। ऐसा कोई भी मामला नहीं है। एक से डेढ़ महीना पहले कोई गाड़ी पीछे करने वाली बात थी। उस समय मैंने अपने बेटे से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भाई से भी मिल लेता हूं। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि इस मामले को हाउस की कार्यवाही से निकलवाया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है कुलवंत जी, इस सम्बन्ध में जो भी चर्चा हाउस की कार्यवाही में दर्ज़ हुई होगी उसको हाउस की कार्यवाही से निकलवा दिया जायेगा। जो भी इस बारे में चर्चा की गई है उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये। अब आप कृपया बैठ जायें और श्री केहर सिंह रावत जी को अपनी बात कहने दें।

श्री कुलवंत राम बाजीगर : धन्यवाद सर।

18:00 बजे

श्री केहर सिंह (हथीन): अध्यक्ष महोदय, बजट में सिंचाई के बारे में काफी प्रावधान रखा गया है लेकिन हथीन विधान सभा क्षेत्र और पलवल जिले की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जो आगरा कैनाल से निकलती हैं उनको पक्का करवाने का प्रावधान पिछले बजट में रखा गया था लेकिन उनको पक्का नहीं किया गया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आगरा कैनाल से निकलने वाली हथीन डिस्ट्रीब्यूटरी, होडल डिस्ट्रीब्यूटरी और हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी

.....

***चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।**

और उसकी माइनरों को भी पक्का किया जाये। सरकार की तरफ से दावा किया गया कि हमने 1300 टेलों तक पानी पहुंचाया है लेकिन मेरे पलवल जिले और हथीन विधान सभा क्षेत्र की तकरीबन समस्त ऐसी माइनरें हैं जहां टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। उसके लिए मेरा एक सुझाव भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि गौछी ड्रेन में पम्प सैट लगा कर उटावड़ डिस्ट्रीब्यूटरी और हथीन डिस्ट्रीब्यूटरी के माध्यम से पानी दिया जाये ताकि अंतिम खेत तक पानी पहुंच सके। जहां तक सेम की समस्या का सवाल है तो जुलाना हल्के में, रोहतक जिले में और झज्जर जिले में सेम की समस्या से पीड़ित किसानों के लिए काफी योजनाएं बनाई गई हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी और पड़ोसी मेरा हल्का नूंह है, उसमें भी 20 हजार एकड़ जमीन ऐसी है जहां पिछले 20 साल से किसान सेम की समस्या से पीड़ित हैं। मेरा निवेदन है कि उसके लिए भी कोई न कोई प्रावधान किया जाये ताकि सेम की समस्या से पीड़ित किसानों को इस समस्या से निजात मिल सके। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पेयजल व्यवस्था की बात है तो स्वयं मेरा गांव ऐसा है जो 10 साल से खारे पानी को पीता है और बहन बेटियां दो किलोमीटर दूर से सिर पर मटके से पानी लाती हैं। बार–बार हमने इस सदन में यह आवाज उठाई है। जब मैं पहली बार चुन कर आया था तब भी मैंने प्रश्न उठाया था और आज भी यह समस्या बरकरार है। इसलिए मेरा पब्लिक हैल्थ मंत्री से निवेदन है कि मेरे गांव में जल्दी से जल्दी पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाये ताकि पानी की किल्लत दूर हो सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015 में माननीय मुख्यमंत्री हथीन कस्बे में गये थे और उन्होंने हथीन के बाईपास के लिए घोषणा की थी। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने लडमाकी माइनर बनाने की भी घोषणा की थी लेकिन आज तक न माइनर बनी और न ही हमारा हथीन का बाईपास बना है। मेरा माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध है कि पलवल से हथीन के लिए जो सड़क जाती है वह जर्जर अवस्था में है इसलिए उसकी स्पेशल रिपेयर की जाये। हमारी मार्केट कमेटी की भी कुछ सड़कें हैं जिनमें जयन्ती मोड़ हथीन से लेकर कौंडल मानसिंह चौराहे तक, नांगल जाट से लेकर अंधौड़ तक और मंडकौला से लेकर स्यारौली गांव तक सड़कें टूटी हुई हैं इसलिए उनकी यथाशीघ्र स्पेशल रिपेयर करवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने घोषणा की थी कि पूर्व सरपंच, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष, पूर्व मेयर और पूर्व जिला परिषद् के चेयरमैन की हम पैन्शन

बनायेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि मैंने बजट पढ़ा है लेकिन उसमें कहीं भी पूर्व सरपंच, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष, पूर्व मेयर और पूर्व जिला परिषद् के चेयरमैन की पैन्शन का कहीं कोई विवरण नहीं दिया गया है इसलिए उनको पैन्शन देने की व्यवस्था की जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरे गांवों नांगल जाट, अंधोप, मानपुर, मंडकौला और मडनाका में सरकारी स्कूलों में बच्चों की बहुत अधिक संख्या है लेकिन उनको अपग्रेड नहीं किया जा रहा है। मेरे गांव नांगल जाट और मानपुर की बेटियों को तो तीन–तीन किलोमीटर चलकर बहीन के स्कूल में पढ़ने जाना पड़ता है। जब सरकार बजट में शिक्षा पर इतना पैसा खर्च कर रही है तो नांगल जाट और मानपुर के हाई स्कूलों को सीनियर सैकेंडरी में अपग्रेड किया जाये। मानपुर गांव और बहीन गांव के बीच में दाऊजी महाराज का छठ का मन्दिर पड़ता है, वहां पंचायत जमीन देने के लिए भी तैयार है। इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र में 40 गांव ऐसे हैं जहां पर एक लड़कियों का कॉलेज बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है जिससे उच्च शिक्षा लेने के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस महान सदन में निवेदन करता हूं कि जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वह बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वह कानून व्यवस्था की समस्या हो इन सारी समस्याओं की जड़ इस देश और प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या है। जो निरन्तर जनसंख्या बढ़ रही है उसको देखते हुये मेरा इस महान सदन से एक निवेदन है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक बिल लाया जाना चाहिए तथा पास करके केन्द्र सरकार के पास भेजना चाहिए कि हमें जनसंख्या पर नियन्त्रण करना चाहिए ताकि भविष्य में जो संकट पैदा होने वाला है उससे बचा जा सके। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार भी चाहिए। बढ़ती जनसंख्या के कारण न हमारे पास रोजगार होंगे और न ही इतनी जनसंख्या के लिए हम खाद्य आपूर्ति कर पायेंगे। इसी कारण से आये दिन एक्सीडैंट्स होते हैं और इसी कारण से आये दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण बिल इस सदन के द्वारा पास करके केन्द्र सरकार को भेजना चाहिए। आपने पहले भी बहुत सारे बिल पास किये हैं, आपने गौमाता के लिए भी संरक्षण बिल इस सदन में पास किया था और यदि आप यह जनसंख्या नियंत्रण बिल आप पास करोगे तो निश्चित रुप से देश में बदलाव आयेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री बलकौर सिंह (एस.सी.) (कालांवाली): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का जो समय दिया है उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद । सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें हरियाणा के लोगों के लिए बहुत कुछ करने के लिए रखा गया है लेकिन अभी उसमें बहुत कुछ बाकी है । सरकार ने अपने बजट में प्रावधान किया है कि सरकार हर खेत को पानी देने का काम करेगी । मेरा हल्का कालांवाली सारा ही खेती पर निर्भर है । हमारे हल्के में न तो कोई बड़ा उद्योग है और न ही कोई हायर एजुकेशन का हब है । हमारे वहां के 99 प्रतिशत लोग खेती–बाड़ी पर निर्भर हैं । मेरे हल्के के 95 प्रतिशत एरिया में पानी बहुत खारा है जोकि फसलों के लिए बहुत नुकसानदायक है जिससे पैदावार बहुत कम होती है । हमारे हल्के में नहरी पानी भी बहुत कम है जोकि पीने के लिए भी पूरा नहीं होता है इसलिए जो घग्गर नदी है वह मेरे हल्के के लिए एक वरदान है क्योंकि इसका पानी हमारे किसानों को काफी मात्रा में खेती की सिंचाई के लिए मिल सकता है । घग्गर नदी में से सरकार ने कई चैनल भी निकाले हैं । जैसे रत्ताखेड़ा चैनल है उससे हमारे 20–25 गांवों को पानी मिलता है । एक मंगाला चैनल है जिससे 25 किलोमीटर तक 20 गांवों को पानी मिलता है । इसी तरह से एक एन.जी.सी. चैनल है उससे हमारे 20 गांवों को पानी मिलता है । उसी तरह से एक एस.जी.सी. चैनल है जो घग्गर नदी से निकलता है, वह भी तकरीबन हमारे 25 गांवों को पानी देता है। एक नाई वाला चैनल है जोकि घग्गर नदी से निकलता है उससे भी हमारे काफी गांवों को पानी मिलता है । एक जी.वी.एस.एम. चैनल है इससे भी लगभग हमारे 10 गांवों को पानी मिलता है । यह सारे चैनल रानियां, ऐलनाबाद, डबवाली हल्कों से निकलते हैं लेकिन मेरे हल्के के अन्दर कोई भी चैनल नहीं हैं । मेरे हल्के कालांवाली के अन्दर गांव रंगा लहंगे वाला से तकरीबन 5 किलोमीटर से घग्गर नदी शुरू हो जाती है। जब इस नदी के अन्दर पानी आता है और उसका पानी दूसरे हल्कों के अन्दर जाता है और जब मेरे हल्के के किसान इसको देखते हैं तो वह कहते हैं कि घग्गर नदी का पानी हमारे हल्के के खेतों को भी मिलना चाहिए। मेरे हल्के के किसी भी गांव के अन्दर कोई भी चैनल न निकलने से हमारे हल्के के किसान बहुत निराश होते हैं इसलिए अगर सरकार मेरे हल्के कालांवाली के गांव रंगा लहंगे वाला से भी एक चैनल निकलवा दें जोकि घग्गर नदी से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है तो हमारे हल्के के किसानों को भी पानी मिल सकता है। जैसे कुरनाली, फगु, थराज, पक्का सीधा, कमाल, बडागुड़ा, दादू, खतरावां,

सुखचैन, भादड़ा, लकड़ावाली, गदरानां, तारूवाना, त्रिलोकेवाला, सूबा खेड़ा, सिंधपुरा और कालांवाली आदि गांवों को एक नया चैनल दिया जाए तो इन गांवों के किसानों के खेतों को भी पानी मिल सकता है और उससे सभी किसान खुश हो सकते हैं । हमारे किसानों को नहर का बढ़िया पानी नहीं मिलता है । इस चैनल से हमारे किसानों को बढ़िया पानी मिल सकता है । इससे लोगों का रोजगार भी चल सकता है । अतः मेरा निवेदन है कि घग्गर नदी से गांव रंगा लहंगे वाला से एक नया चैनल जरूर निकाला जाए क्योंकि उससे हमारे हल्के के 20–25 गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकता है । मेरा हल्का कालांवाली जोकि एक पंजाबी एरिया है । जैसे सरकार का नारा है कि 'सबका साथ, सबका विकास,' तो उस नारे को संभव करते हुए मेरे हल्के से भी एक नया चैनल निकाला जाए क्योंकि बाकी हल्कों से भी चैनल निकाले गये हैं । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि किसानों को पानी देने के लिए मेरे हल्के से भी वह चैनल निकाला जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के अन्दर कैंसर और हेपेटाईटिस की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार को कोई इन्तजाम करने की जरूरत है। कालांवाली के अन्दर सरकार ने हमारे अस्पताल को पी.एच.सी. से अपग्रेड करके सी.एच.सी. बना दिया है लेकिन अभी तक उसके अन्दर कोई भी डॉक्टर नहीं है । वहां जो दो डॉक्टर डैपुटेशन पर आए हैं वह उस अस्पताल को समय नहीं देते हैं। उस अस्पताल के अन्दर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसमें कोई भी लैब नहीं है । इस वजह से जिस अस्पताल को पी.एच.सी. से सी.एच.सी. बनाया था वह अब एक डिस्पैंसरी बनकर रह गया है । जो सब डिवीजन पिछली सरकार ने बनाया था वह भी एक प्राइवेट जगह पर चल रहा है। हालांकि सरकार ने सब डिवीजन के लिए जगह चिन्हित कर रखी है इसलिए मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि चिन्हित की गई जगह पर सब डिवीजन की बिल्डिंग बनाकर चालू की जाये और साथ ही चिन्हित जगह पर एक ज्यूडिशियल कांपलैक्स भी बनाया जाये। इसी तरह मेरे शहर कालांवाली में तीन–चार अवैध कालोनियां का भी एक विषय है। इसके बारे में मैं पहले भी सदन में आवाज उठा चुका हूँ। इन अवैध कॉलोनियों के बाशिंदों ने एम.सी. चुनाव में वोट भी दिया है परन्तु बावजूद इसके इन लोगों को आज भी मूलभूत सुविधायें नहीं मिल पाई हैं। न यहां पर सीवरेज की सुविधा है, न पीने का पानी हैं और न सड़कें बनाई गई हैं। जब इन अवैध कॉलोनियां के निवासी अपनी मांग उठाते हैं तो इनकी मांगों को यह कहकर नकार

दिया जाता है कि तुम तो अवैध कालोनियों के निवासी हो तुम्हें अपनी मांगे मांगने का कोई अधिकार नहीं है, तो इस परिपेक्ष्य में मैं सरकार से मांग करूंगा कि इन अवैध कालोनियों को जल्द से जल्द वैध करने व यहां के आमजन को मूलभूत सुविधायें व सहूलियतें देने का काम सरकार की तरफ से किया जाये। जहां तक बिजली की समस्या की बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र मे स्थित ढाणियों में बिजली की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। एक एक ढ़ाणी में महज 10 से 15 घर रहते हैं परन्तु बावजूद इसके ढ़ाणियों में बिजली नहीं दी जा रही है। ढ़ाणियों में रहने वाले लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई व दूसरे कामों के लिए बिजली की बहुत जरूरत है इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में आने वाली ढ़ाणियों में बिजली पहुंचाने का काम किया जाये। यही नहीं मेरे हल्के के 5–6 गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक फसल बीमा राशि नहीं दी गई है जबकि गांव कालांवाली, रोहड्यावाली, मोजूखेड़ा, सूबाखेड़ा व गांव भीमा में फसल बीमा राशि मिल चुकी है। अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करूंगा कि यह फसल बीमा राशि जल्द से जल्द देने का काम किया जाये। इस तरह एक अन्य समस्या की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। वर्ष 2017 में कालांवाली हलके के देशुमलकाना गांव में 80 एकड़ जमीन में खड़ी गेहूं की फसल आग में जलकर स्वाहा हो गई थी जिसके लिए सरकार ने 12000 रूपये प्रति एकड़ मुआवजे की अनाउंसमेंट की थी लेकिन अफसोस इस बात का है कि यह मुआवजा आज तक भी नहीं दिया गया है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि अनाउंस किया गया मुआवजा जल्द से जल्द देने का काम किया जाये। जहां तक सफाई की व्यवस्था है हमारे शहर कालांवाली में सफाई की बहुत लचर व्यवस्था है। कारण यह है कि हुडा ने नगरपालिका को सफाई व्यवस्था का काम तो दिया है लेकिन सफाई कर्मचारियों को हुडा की तरफ से कोई पैसा नहीं दिया जाता जिसके कारण नगरपालिका में थोड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी रखे जाते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि ज्यादा सफाई कर्मचारियों का प्रबंध करके यहां पर सफाई की बेहतर प्रबंधन किया जाये। मैंने आज सदन के माध्यम से अपने हलके की महत्वपूर्ण समस्याओं को रखा है, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इन समस्याओं के निवारण के लिए बजट में पूरा प्रावधान किया जाये। धन्यवाद

श्री कुलदीप शर्मा (गन्नौर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जब भी बजट प्रस्तुत होता है

तो हरियाणा प्रदेश की जनता और हरियाणा का हर वर्ग, इन सबका ध्यान हरियाणा सरकार और हरियाणा विधान सभा की ओर जाता है। बड़ी आशाओं से इस चुनावी वर्ष में हरियाणा की जनता और हरियाणा का हर एक वर्ग इस चुनावी वर्ष में बजट रूपी पिटारे की ओर देख रहा था। कर्मचारी अपने नजरिये से देख रहे थे, किसान अपने नजरिये से देख रहे थे, गरीब, शोषित वर्ग तथा व्यापारी अपने नज़रिये से देख रहे थे अर्थात सबका अपना–अपना नज़रिया या सबकी अपनी–अपनी एक्सपैक्टेशंज थी कि चार साल तक तो इस सरकार ने कुछ किया नहीं और शायद पाचवें साल में जब यह चुनावी वर्ष आया है तो शायद वोटों का पटोरा बांधने का लिए कुछ न कुछ हरियाणा के लोगों का ध्यान रखा जायेगा लेकिन खबर गर्म थी कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे–देखने हम भी पहुंचे पर तमाशा न हुआ। अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि बजट में किसी भी सैक्शन के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया है और न ही बजट में कोई नई स्कीम्स की घोषणा हुई है। सिर्फ पुरानी स्कीम्स की दोबारा से घोषणा हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, जो बजट में स्कीम्स के लिए पैसा रखा गया है वह पुरानी स्कीम्स को पूरा करने के लिए ही खर्च हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूँ कि नई योजनाओं पर बजट के माध्यम से कोई खर्च नहीं हो पायेगा। भाजपा सरकार ने हरियाणा प्रदेश की जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ा दिया है और कर्जा अपनी सीमाएं लांघ गया है। जो कोर सैक्टर्ज हैं जैसे बिजली का है, कृषि का है, सिंचाई का है और जन स्वास्थ्य का है, इन सैक्टर्ज के विभागों में खर्च की कटौती की गई है यानी इन विभागों का बजट एलोकेशन कम हुआ है। जब इन कोर सैक्टर्ज में यह परिस्थिति है तो मैं नहीं समझता कि सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी ? सरकार ने डैफिसिट भी बढ़ा दिया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की बजट के बारे में एक नीति रहती है और विपक्ष का आंकलन अपनी तरह से होता है। लेकिन जिन पॉसिबिलिटीज को एक विजन के साथ सरकार एक्सप्लोर कर सकती थी वह काम नहीं हुआ है। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं सदन में हुई हैं कि हमारी भाजपा सरकार ने ऐसा किया है और पिछली सरकारों ने वैसा किया था। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 60–70 वर्ष के इतिहास की बात करने लग जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह देश वर्ष 1947 में आजाद हुआ था। उस समय न तो स्कूल्ज थे, न ही सड़कें थी, न ही परिवहन के साधन थे और न ही आधी आबादी को पेट भरने के लिए रोटी थी। अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी ने काफी तरक्की की है। सरकारें आई और चली गईं लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी रही है।

अध्यक्ष महोदय, यह कह देना कि पीछे कुछ भी विकास नहीं हुआ और सब कुछ हमने 5 वर्ष के कार्यकाल में किया है, यह अनुचित है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह कहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है और हम उनके काम को और आगे बढ़ाऐंगे। इस प्रकार की कोई भी संस्कृति सदन में नहीं बनती है। आज परिस्थिति यह है कि सदन का अधिक से अधिक समय आरोप–प्रत्यारोप और आक्रोश में ही बीत जाता है। अध्यक्ष महोदय, आज इस बात का कोई जिक्र नहीं किया जाता है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे या हमारा हरियाणा कैसे आगे बढ़ेगा या फिर किस प्रकार से समाज के हर वर्ग का विकास होगा? अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से मैं विधायक चुनकर आता हूँ वह क्षेत्र एन.सी.आर. में आता है। दिल्ली से चलने के बाद गन्नौर पहला छोटा सा क्षेत्र है जो जी.टी. रोड पर आता है। इस क्षेत्र में विकास और इकोनॉमी में डिवैल्पमैंट की अनंत संभावनाएं हैं। हरियाणा प्रदेश का गुरूग्राम और फरीदाबाद जिले तो आगे बढ़ गए हैं लेकिन बाकि क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। इस प्रकार से आज हमारी सरकार का पूरा ध्यान इस तरफ होना चाहिए ताकि दिल्ली के साथ जो सबसे नजदीक का एरिया है वह डिवैल्पमैंट का हिस्सा बन सके। अध्यक्ष महोदय, गन्नौर के अंदर इंटरनैशनल हॉर्टिकल्चर फ्रूट एंड वैजिटेबल मार्किट बननी थी। वर्ष 2013–14 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो श्री राहुल गांधी जी ने इस मार्किट का शिलान्यास किया था। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा के हर सत्र में मैंने इस मण्डी के बारे में प्रश्न उठाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से मिला भी था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप क्रॉप डायवर्सी फिकेशन की बात करते हैं या फिर कैश क्रॉप की बात करते हैं। मेरा निवेदन है कि दिल्ली की मण्डी में जो हमारी सब्जियां बिकने के लिए जा रही हैं उसका व्यापार गन्नौर मण्डी के माध्यम से होना चाहिए। दिल्ली की मण्डी 40 एकड़ में बनी हुई है और गन्नौर एन.सी.आर. का ऐसा क्षेत्र है जहां पर 537 एकड़ जमीन किसी भी सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई लैंड पूल है। भाजपा सरकार द्वारा गन्नौर में ऐग्री सम्मिट का आयोजन किया गया था और उस ऐग्री सम्मिट में मैं भी गया था। उस ऐग्री सम्मिट पर करोड़ों रुपये सरकार ने खर्च किए थे और नई टैक्नॉलोजी को बताने के लिए किसानों को बसों के माध्यम से बुलाया गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से पूछना चाहता हूँ कि जिस मण्डी में सरकार का यह कार्यक्रम हो रहा था, क्या सरकार ने उस मण्डी की

डिवैल्पमैंट के लिए कोई कदम उठाया है? उस प्रोजैक्ट का अनावरण हुए 5 साल हो चुके हैं । वह प्रोजैक्ट उस इलाके के किसानों के चेहरे पर खुशहाली ला सकता था, एग्रो इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता था और उस इलाके में कैश क्रॉप्स की संस्कृति को बढ़ा सकता था लेकिन सरकार ने उस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया । यह शायद इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वहां का प्रतिनिधित्व विपक्ष का एक विधायक कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर 'सबका साथ सबका विकास' वाली बात कहाँ रह गई ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि सरकार को देखना चाहिए कि हम गन्नौर की उस मण्डी की अनन्त संभावनाओं और उस क्षेत्र के विकास के लिए किस तरह से नीति–निर्धारण कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं हाउस में एन.एच.–1 के पार्ट पानीपत–दिल्ली की चर्चा करना चाहूंगा । पानीपत–दिल्ली तक जाने में इतना ही समय लगता है जितना चंडीगढ़–पानीपत तक लगता है जबकि पानीपत–दिल्ली की दूरी चंडीगढ़–पानीपत की दूरी की सिर्फ 50 प्रतिशत है । पानीपत से दिल्ली तक पहुंचने में 3–4 घंटे लगते हैं । वहां पर रास्ते में कई जगह ट्रैफिक जाम रहता है । यह एन.एच.ए.आई. का प्रोजैक्ट है । इसके बावजूद पिछले 8 महीने से इस प्रोजैक्ट पर कोई भी काम नहीं हो रहा है । वह प्रोजैक्ट जहां का तहां पड़ा हुआ है । वहां पर आये दिन एक्सीडैंट्स होते हैं । उस हाइवे का 10 लेनिंग का कार्य प्रायरिटी पर होना चाहिए था क्योंकि वहां से रोज़ लाखों लोग देश की राजधानी दिल्ली आते और जाते हैं । वहां पर सरकार ने 3–3 टोल प्लाजा तो स्थापित कर दिए लेकिन उस हाइवे का काम जहां था वहीं रूका हुआ है । उसका काम ज़रा भी आगे नहीं बढ़ रहा है । अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार एन.एच.ए.आई. से सम्पर्क करके दिल्ली–पानीपत हाइवे के 10 लेनिंग के कार्य को प्रायरिटी पर ले और उस काम में तत्काल प्रभाव से तेजी लाकर उसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करे । अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र गन्नौर के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है । गन्नौर में एक रेल कोच फैक्ट्री लगनी थी । इस फैक्ट्री को लगवाने के बारे में सरकार ने बड़ा ढ़ोल पीटा था, बड़े–बड़े पोस्टर्स और बैनर्स लगवाए गए थे लेकिन अब गन्नौर में रेल कोच फैक्ट्री की बजाय रेल कोच रिपेयर वर्कशॉप लगाई जा रही है । इससे गन्नौर के निवासियों को जो हताशा हुई है उससे मैं यही कहूंगा – 'खोदा पहाड़ और निकला चूहा।' यह युनिट उम्मीद से इतनी छोटी है कि हम इसके बारे में कहेंगे कि यह चूहा भी मरा हुआ और सड़ा हुआ है । कहां तो गन्नौर में पंजाब के कपूरथला की

तरह रेल कोच फैक्ट्री लगती जिसमें 20 हजार ऐम्पलॉइज की ऐम्पलॉयमैंट अपोरच्युनिटी बनती और कहां अब रेल कोच रिपेयर वर्कशॉप बननी प्रस्तावित है जिसमें सिर्फ 250–300 ऐम्पलॉयज की ऐम्पलॉयमैंट अपोरच्युनिटी बनेगी । अतः यह मेरे इलाके के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हिसार में एयरपोर्ट बनाने के विषय पर बात की गई थी । मेरा प्रश्न है कि क्या उस एयरपोर्ट के बनने के बाद आज तक वहां पर एक सिंगल फ्लाइट भी लैण्ड हुई है ? कहा जा रहा था कि हिसार में इंटरनैशनल लैवल का एयरपोर्ट बनेगा और वहां पर बड़ी–बड़ी फ्लाइट्स लैण्ड होंगी । मैंने 2 दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि वहां पर आज तक एक सिंगल फ्लाइट भी लैंड नहीं हुई है । अध्यक्ष महोदय, करनाल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्वाचन क्षेत्र है । इसके बारे में कहा गया था कि यहां पर भी एयरपोर्ट बनेगा और इसकी स्ट्रिप एक्सटैंड होगी लेकिन आज तक यह बात धरातल पर नहीं आई और वहां पर एयरपोर्ट नहीं बनाया गया । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आप प्लीज, वाइंड अप कर लीजिए ।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । मैं सिर्फ 5 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर लूंगा । अध्यक्ष महोदय, करनाल को सी.एम. सिटी कहा जा रहा है । दुख है कि ऐसा होते हुए भी वहां पर विकास का कोई खास काम नहीं हुआ । वहां पर 1–2 सड़कें तो अवश्य बनी हैं लेकिन करनाल विधान सभा क्षेत्र से प्रदेश का चीफ मिनिस्टर होने के नाते वहां के लोग करनाल का जैसा विकास चाह रहे थे वैसा वहां का विकास नहीं हुआ । इसके अलावा मेरे निर्वाचन क्षेत्र के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है । अर्बन लोकल बोडीज मिनिस्टर द्वारा सोनीपत शहर का सारा म्युनिसिपल वेस्ट उठवाकर गन्नौर की सीमा में डलवाया जा रहा है । इससे वहां के ऐवायर्नमैंट में बड़ा फर्क आ रहा है । वहां के 10–15 गांवों के लोगों के मन में टीस है कि सोनीपत शहर का सारा वेस्ट हमारी सीमा में क्यों डाला जा रहा है ? यह तथ्य है कि उस वेस्ट को कहीं न कहीं तो डालना ही था लेकिन उसे एक पोलिसी बनाकर डाला जाना चाहिए था । ऐसा नहीं होना चाहिए था कि वहां पर बगैर प्लानिंग के गंदगी के भंडार लगा दिए जाएं । इस वेस्ट के डाले जाने से वहां का ऐसा आलम है कि जब हम वहां के बाइपास से गुजरते हैं तो इतनी बदबू आती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है । वहां पर जब तेज हवा चलती है तो आसपास के अनेकों गांवों के लोगों को बदबू आती

है। हमने इसका प्रोटैस्ट भी किया था । माननीय अर्बन लोकल बोडीज मिनिस्टर जिस प्रकार से सोनीपत शहर का सारा वेस्ट गन्नौर की सीमा में डलवा रही हैं यह बिल्कुल गलत है । इस काम को तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए क्योंकि इसका इन्वायर्नमैंट पर भी बुरा असर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के के आहुलाना गांव के लिए एक पी.एच.सी. मंजूर की गयी थी लेकिन अभी तक उसकी बिल्डिंग नहीं बनायी गयी है। यह पी.एच.सी. हमारी सरकार के कार्यकाल के आखिरी साल में मंजूर हुई थी। मैंने इस बारे में पिछले सैशन के दौरान भी माननीय मंत्री जी से जवाब मांगा था और उन्होंने कहा था कि इस बिल्डिंग के लिए लगभग 3 करोड़ रूपये मंजूर किये जा चुके हैं परन्तु आज तक पी.एच.सी. की बिल्डिंग बनाने के लिए एक भी पैसा नहीं लगा है और डिस्पैंसरी में ही वह पी.एच.सी. चल रही है। आज पी.एच.सी. की घोषणा हुए 5 साल बीत चुके हैं। गांव की पंचायत ने रेजोलूशन पास करके पी. एच.सी. बनाने के लिए जमीन दी हुई है लेकिन सरकार ने पी.एच.सी. का निर्माण करवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। हमारा क्षेत्र नेशनल कैपिटल रिजन में पड़ता है और वहां पर अपराध बहुत बढ़ गया है। हमारे क्षेत्र में लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति खराब है। प्रदेश सरकार कह रही है कि बहुत थाने खोले गये हैं, पिंक थाने खोल दिये हैं, स्टॉफ के लिए नयी–नयी गाड़ियां खरीदी गयी हैं, संचार व्यवस्था ठीक हो गयी है तो फिर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं ? एक शायर ने कहा है कि "ये अंधेर है या अंधेरा है, चिराग जल रहे हैं और रोशनी नहीं होती।" सरकार द्वारा सब कुछ खरीदा जा रहा है और सब कुछ लिया जा रहा है लेकिन जमीनी धरातल पर प्रगति को नापा जाए तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने दिशाहीन और मायोपिक विजन का बजट बनाया है। मैं इस बजट पर अपनी असहमति प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र के लोगों की 2 सड़कें बनाने की मांग उठाना चाहूंगा जिसमें एक सड़क तो खुबड़ू से एम.पी. माजरा तक जाती है। यह सड़क जितनी हमारी सरकार के समय में बनायी गयी थी वही पर रूकी हुई है क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ने इस सड़क को पूरा करने के लिए आगे कोई काम नहीं किया है। दूसरी सेखपुरा से अगवान तक की सड़क का निर्माण करवाया जाए। इन सड़कों के अलावा हमारी सरकार के समय में मेरे हल्के की सभी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करवा दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इन दोनों

सड़कों का जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाए। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री घनश्याम दास (यमुनानगर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रदेश को नयी दिशा और दशा देने वाला बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट प्रदेश कितना आगे बढा है और कितनी उन्नति की है, उन सभी बातों का स्पष्ट उल्लेख है। उदाहरण के रूप में गन्ने का मूल्य 340/– रूपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। इस प्रकार सरकार ने निश्चित रूप से गन्ने का समर्थन मूल्य 10 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर एक संदेश देने का प्रयास किया है कि माननीय प्रधान मंत्री जी की योजना के अनुसार किसानों की कृषि आय वर्ष 2022 तक दोगुनी हो जाए, यह उस दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। इसके साथ ही साथ माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके कृषि उपज के मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया अपनायी है। इससे निश्चित रूप से किसान लाभान्वित होंगे और यह वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की तरफ बढ़ाया हुआ एक सफल प्रयास है। इसके अतिरिक्त माननीय प्रधान मंत्री जी ने 'किसान सम्मान निधि' के माध्यम से 5 एकड़ जमीन तक के किसानों को वर्ष में 6,000 रूपये की राशि देने का प्रावधान रखा है जिसके लिए बजट में 75,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से हमारी प्रदेश सरकार ने भी माननीय मुख्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 1500 करोड़ रूपये की राशि बजट में रखी है। यह एक बहुत ही सहराहनीय कदम है और समाज का प्रत्येक वर्ग निश्चित रूप से इस स्कीम से लाभान्वित होगा। इसके साथ ही साथ हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर जिले के आसपास के क्षेत्रों में पॉपलर की खेती बहुतायत में होती है क्योंकि किसान अपने खेतों में पॉपलर और सफेदा लगाते हैं। कांग्रेस सरकार के समय पॉपलर और सफेदे का रेट लगभग 400 रूपये प्रति क्विंटल था। कांग्रेस सरकार के समय में इस उद्योग को लगाने के लिए नये लाईसेंसिज देने की कोई नीति नहीं थी और ब्लैक में ही लाईसैंस दिये जाते थे। हमारी सरकार ने नये लाईसेंसिज देने की नीति बनायी है और इस नीति के तहत जो भी पात्र व्यक्ति लाईसेंस लेने के लिए एप्लाई करेगा, उसी को लाईसेंसिज दिये जाएंगे। इस नीति के कारण बहुत ज्यादा संख्या में यमुनानगर और आसपास के

क्षेत्रों में उद्योग लगे। इसी नीति के परिणामस्वरूप आज किसानों को 800 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पॉपलर और सफेदे के दाम मिल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाए, उतनी कम है। हमारी सरकार ने सारे प्रदेश में समान रूप से विकास, समान विकास–समान रोजगार और सबका साथ–सबका विकास की नीति पर काम करते हुए एक नये आयाम स्थापित किये हैं और आज हम हरियाणा में कहीं भी चले जाते हैं तो वहां पर सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है, सफाई व्यवस्था में दिन–प्रतिदिन सुधार हो रहा है और अनेकों वर्षों से जो कॉलोनियां अवैध रूप से बनी हुई थीं, उनको वैध करने का काम भी हमारी वर्तमान सरकार ने किया है। सारे हरियाणा में उन वैध कॉलोनियों के विकास के लिए लगभग 1 हजार करोड़ रुपए का बजट हमारी सरकार ने दिया है और इस तरह से सरकार के द्वारा यह निश्चित ही एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके साथ ही साथ मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा समय–समय पर गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़क को बनाया जाता है, परंतु अब खेतों के रास्ते भी ईंट और खड़ौंजा लगाकर उनको सड़क से जोड़ने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। ये सभी काम इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी सरकार हर तरह से प्रयास करेगी कि किसानों का भला हो, गांव का विकास हो, गांव में सुधार हो। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने पौंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा बनाकर गांव के जो तालाब हैं, उनके भी स्वरूप को सुधारने के लिए, उनके क्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए और उनको प्रदूषण मुक्त करने के लिए यह योजना बनाई है और यह सरकार का निश्चय ही प्रशंसनीय कदम है। इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने किसान सम्मान निधि की चर्चा की थी कि हर एक कदम सरकार के द्वारा ऐसा उठाया जा रहा है कि हम वर्ष 2022 तक किसान की आय को दोगुना कर सकें। जिस प्रकार हरियाणा में भावांतर–भरपाई योजना शुरू की गई है, वह एक नया प्रयोग है। इस योजना से किसान को कम से कम लागत मूल्य मिल जाएगी और उनको लाभ मिल जाएगा, जिससे उनको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। किसान के ऊपर हमेशा जो खतरा रहता था और उसको यह अंदेशा रहता था कि उसको उसकी उपज का ठीक मूल्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारी सरकार ने भावांतर–भरपाई योजना के तहत किसानों के उस डर दूर करने का सफल प्रयास किया है। जैसा कि यहां पर डायवर्सिफिकेशन यानी फसलों की विविधीकरण की बात हुई थी तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने हरियाणा में एक बागवानी विश्वविद्यालय बनाया है।

जिससे किसान केवल गेहूं और धान के चक्कर में नहीं रहेगा, बल्कि वह उसके चक्कर से बाहर निकल जाएगा। सरकार ने इस तरह की जो योजना बनाई है, उससे निश्चित रूप से और विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि किसान धान और गेहूं के चक्कर से निकलकर फसल विविधीकरण का लाभ उठाते हुए प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की यह भी योजना है कि हरियाणा के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि यमुनानगर जिले में अभी तक मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति नहीं मिली है, इसलिए वे जल्दी से जल्दी यमुनानगर जिले में भी एक मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान करें, जिससे निश्चित रूप से उस क्षेत्र के सामान्य–से–सामान्य व्यक्ति को लाभ हो। अभी हमारे साथ महिपाल जी बैठे हुए हैं और वे कह रहे हैं कि पानीपत में भी एक मेडिकल कॉलेज खोला जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में वेस्ट मैनेजमैंट की बहुत बड़ी समस्या विशेष रूप से है, इसके लिए सरकार उचित व्यवस्था करने की ओर अग्रसर भी है और कई स्थानों पर किया भी है और इसके लिए क्लस्टर योजना भी बनाई गई है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वातावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार वेस्ट मैनेजमैंट की एक अच्छी योजना जल्दी से जल्दी सारे प्रदेश में शुरू करे। इसके साथ ही साथ मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो वर्तमान बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, वह इस प्रदेश की जनता को एक नई दिशा देगा और प्रदेश विकास की ओर अग्रसर होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कथन है, हरियाणा एक–हरियाणवी एक, समान विकास–समान रोजगार। इस कथन को पूरा करने के लिए ये बजट निश्चित रूप से राह को आसान करेगा । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री ओम प्रकाश यादव (नारनौल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट सत्र में बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । आज से ठीक चार साल पहले हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित हुआ। सरकार ने अपनी तरफ से वचनबद्धता दिखाई थी कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के मंत्र पर कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक संकल्प लिया था कि ''सबका साथ सबका विकास'' के नारे को मानकर हम आगे बढ़ेंगे । हमारी सरकार ने इस मूल भावना को समझते हुए सबसे पहले इस बात की

प्राथमिकता देने का प्रयास किया । अगर इस देश के किसान का उद्धार हो, इस देश में किसान और किसान से जुड़े हुए तबके का उद्धार हो, चूंकि इस देश के किसान और किसानियत से जुड़ी हुई 60 प्रतिशत आबादी से देश का बहुत जल्दी सुधार हो सकता है । अध्यक्ष महोदय, उस मूलभूत भावना को समझते हुए किसानों के लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना'' के तहत 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि वाले छोटे किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6000 रुपये का एलान किया है । आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस महान सदन में किसानों के लिए और ऐसी योजना हरियाणा प्रदेश की तरफ से जोड़ने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, जब हम इस सदन में इस तरह की चर्चा करते हैं तो विपक्ष के माननीय सदस्यों को यह बात अच्छी नहीं लगती है और वे किसी न किसी बात पर टोका टिप्पणी और उल्टी टिप्पणी करने का प्रयास करते हैं तथा वे छोटी–छोटी बातों की मांग करते हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारी समझ में यह नहीं आता कि इन लोगों ने लगातार 10 साल तक हरियाणा प्रदेश में शासन किया, कोई भी माननीय सदस्य अपने गांव में जोहड़ के लिए नाली तक नहीं लगवा पाया, कोई अपनी सड़क नहीं बनवा पाया। अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व स्पीकर साहब कह रहे थे कि 70 साल में विकास बहुत हुआ है । हम मानते हैं कि विकास तो हुआ है । मान लो एक 1 रुपये का विकास होना चाहिए था उसमें से चार आने ही विकास कार्यों में लगाये हैं, 75 प्रतिशत पैसा कहां चला गया? हमारी सरकार जब से बनी है तब से इस बीमारी को दूर करने का काम किया है। हमारी सरकार ने यदि एक 1 रुपये का विकास कार्य किसी योजना पर लगाने का या ऐसा प्लान बनाने के लिए किया है तो उन विकास कार्यों में 100 प्रतिशत ही पैसा खर्चा किया गया है। ऐसा नहीं है कि उसमें से दो पैसे भी कम हो गये हों । अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकारों में और वर्तमान सरकार के काम करने के तरीके में यही अंतर है । चाहे केन्द्र में माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार हो और चाहे हरियाणा प्रदेश में माननीय श्री मनोहर लाल जी की सरकार हो। अध्यक्ष महोदय, हमारे किसानों को चिंता मुक्त करने के लिए कृषि के क्षेत्र में एक ''भावान्तर भरपाई योजना'' लागू की गई है। इस योजना के शुरू होने से किसान को यह चिंता नहीं रहेगी कि फसल का भाव अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा और फसल की लागत का मूल्य मिलेगा या नहीं? हमारे किसानों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि किसान के लिए इतनी सुन्दर ''भावांतर

भरपाई योजना'' लागू की है। यह योजना किसान के कल्याण के लिए उसके हौंसले के लिए और किसान को निश्चिंत करने के लिए शुरूआत की गई है। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के रास्ते में हमारी सरकार ने कहा है कि किसानों को उसकी लागत का डेढ़ गुणा मूल्य मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने सभी जींसों के भाव बढ़ाकर किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुणा मुनाफा देने का काम किया है। बाजरे जैसी फसल की लोग खेती करना पसंद नहीं करते। हमारा क्षेत्र शुष्क है इसलिए हमारे वहां के किसानों को मज़बूरीवश बाजरे की फसल की खेती करनी पड़ती है। हमारी सरकार द्वारा बाजरे के भाव को 800–900 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1950/– रूपये प्रति क्विंटल किया है। यह विशेषकर हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। हमारी सरकार का यह स्पष्ट विजन है कि जब तक किसान का जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो सकता तब तक वह सुदृढ़ नहीं होगा और जब तक देश–प्रदेश का किसान सुदृढ़ नहीं होगा तब तक प्रदेश भी देश–सुदृढ़ नहीं हो सकता। हमारी सरकार आने के बाद जब–जब प्राकृतिक आपदा से प्रदेश के किसानों की फसल बर्बाद हुई। उस खराब हुई फसल का अधिकतम मुआवज़ा देने का काम किया गया। हमारे से पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा प्राकृतिक आपदओं से किसानों की बर्बाद हुई फसलों के कहीं 4/– रूपये तो कहीं पर 5/– रूपये के चैक दिये जाते थे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और अपनी पूरी सरकार का धन्यवाद करता हूं। मैं अपने विपक्ष के भी सभी साथियों से यह अनुरोध करता हूं कि वे भी इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करें। हमारी सरकार ने प्रदेश के गरीब आदमी के उत्थान के लिए एक से बढ़कर एक बहुत सी योजनायें चलाई हैं। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत में पांच लाख रूपये तक का गरीब आदमी का इलाज मुफ्त होने लग रहा है। क्या कोई गरीब आदमी सोच सकता था कि इतनी आबादी के देश में, जिसका दुनिया में आबादी के हिसाब से दूसरा नम्बर है, इस प्रकार के इलाज की सुविधा भी उसको मिल सकती है? कम आबादी वाले देशों में तो ऐसी स्कीम चल सकती है, 1–2 कम आबादी वाले देशों में इस प्रकार की स्कीम चल भी रही है लेकिन इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश में इस प्रकार की स्कीम चलाना अपने आप में एक चमत्कार है। हमारी सरकार ने गरीब आदमी के लिए इस प्रकार की स्कीम बनाकर उसके जीवन का पूर्ण रूप से कायाकल्प करने का काम किया है। हाउस के अंदर तो विपक्ष द्वारा

हरेक प्रकार की टिप्पणियां सरकार के कामकाज पर होती ही रहती हैं लेकिन विपक्ष के माननीय सदस्य कभी भी इस बात का जिक्र नहीं करते कि इनकी सरकार के समय में कुकिंग गैस की उपलब्धता का क्या हाल था? उस समय लोग तीन–तीन दिन तक गैस के खाली सिलैण्डर अपने सिर पर रखकर घूमते थे। उस समय न तो कहीं बाहर से ही कुकिंग गैस मंगवाई गई और न ही अपने प्रदेश में ही कुकिंग गैस के प्रोडक्शन का कोई इंतजाम किया गया। इसके विपरीत हमारी सरकार के समय में लोगों को कुकिंग गैस के सिलैण्डर की एडवांस में होम डिलीवरी हो रही है। यह फर्क इसलिए उजागर हो रहा है क्योंकि हमारी सरकार पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी की नीतियों पर चल रही है। हमारी सरकार की नीति अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की है। हमारी सरकार की योजनाओं का केन्द्र बिन्दु मुख्य रूप से वह व्यक्ति होता है जो किसी भी प्रकार की सफलता से वंचित है। हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को पूरी कोशिश के साथ आगे लाया जाये। हमारी सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों के मामले में भी पूर्ण रूप से पारदर्शिता का परिचय दिया गया है। पूर्ववर्ती सरकार में भाई–भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, पैसावाद इत्यादि वादों से सरकारी नौकरियां मिलती थी। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सरकार के समय में सरकारी नौकरियों के मामले में किस प्रकार से इंसाफ हुआ है यह हम सभी के सामने है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी भाई–भतीजावाद, बिना किसी क्षेत्रवाद, बिना किसी पैसावाद के सरकारी नौकरियां दी हैं। यही पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी का सपना था कि गरीब से गरीब व्यक्ति को जब तक समाज में ऊपर उठने का समान अवसर न मिले तब तक किसी भी प्रकार का विकास कोई मायने नहीं रखता है। हमारी सरकार गरीब के हित के ये सभी कार्य बिना किसी भी प्रकार भेदभाव के कर रही है। हमारी सरकार ने ही कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतनमान दिया। इसी प्रकार से केन्द्र सरकार द्वारा सैनिक भाईयों के लिए वन–रैंक, वन–पैंशन योजना लागू की। पिछले 70 सालों से बिजली की जिन तारों को नहीं बदला गया था हमारी सरकार ने उन तारों को भी बदला है। हमारी सरकार के आने के बाद बिजली के क्षेत्र में भी बहुत से अभूतपूर्व सुधार हुए हैं जिनसे प्रदेश में बिजली की उपलब्धता निरंतर बढ़ती जा रही है। गांवों में उन पुरानी तारों की जगह केबल लगाई जा रही हैं। यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारी सरकार ने बिजली के बिल आधे कर दिये और बिजली की

सप्लाई डबल कर दी है। पहले वाली सरकारों के समय में तो यह होता था कि बिजली 2 से 3 घंटे आती थी और बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते थे। पिछली सरकारों के समय में अगर किसी के घर के ऊपर से हाई वोल्टेज़ पॉवर लाईन्ज़ जा रही होती थी उनको घर के मालिक द्वारा अपने खर्च पर ही बदलवाया जा सकता था लेकिन हमारी सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर इन हाई वोल्टेज़ लाईन्ज़ को चेंज किया जा रहा है। यह भी प्रदेश के लोगों के लिए एक चमत्कार है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार से इन सभी बातों के साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई। अगर तबादला नीति की बात की जाये तो तबादलों को ऑनलाइन करके इतना पारदर्शी बनाया गया है कि 50 हजार शिक्षकों के तबादले एक ही बटन से कर दिये गये। इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। अभी पीछे जब हम राजस्थान चुनाव में गये थे तो वहां पर भी शिक्षक हरियाणा की तबादला नीति की प्रशंसा कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ बातें मेरे विधान सभा क्षेत्र की भी करना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र को पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता था और आज तक भी कहा जाता है। यह बात सही है कि हम पिछड़े भी रहे हैं क्योंकि पिछली सरकारों ने हमारे साथ भेदभाव किया और हमें कुछ नहीं दिया, और कोई माने या न माने लेकिन हम यह मानते हैं कि इस सरकार ने हमारा पिछड़ापन दूर कर दिया, हम अब पिछड़े हुये नहीं रहे हैं। आज जो इलाके हमसे आगे हैं आने वाले समय में हम न केवल उनकी बराबरी करेंगे बल्कि उनसे भी आगे जायेंगे। यह केवल माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की नीतियों से हुआ है। इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया बल्कि हर क्षेत्र में हमारी सहायता की है। अगर मैं उन बातों का एक–एक का जिक्र करूं तो उनमें सबसे पहले हमें मेडिकल कॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। हमें इलाज के लिए डेढ़–डेढ़ सौ किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं बार–बार इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आज सदन में कहा गया कि 500 करोड़ रुपये की लागत से महेन्द्रगढ़ के लिए मेडिकल कॉलेज बनवाया जायेगा लेकिन यह 2 साल की टाईम लिमिट में पूरा करवाने के लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिले को एक लॉजिस्टिक हब की सौगात भी प्रदान की है। इसके साथ–साथ हमारे जिले को एक आई.एम.टी. भी प्रदान किया है जिससे बेरोजगारी दूर होगी और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लॉजिस्टिक हब

और आई.एम.टी. देकर हमारे जिले को धन्य कर दिया। जिस महेन्द्रगढ़ जिले को सारा हरियाणा बैकवर्ड कहता था ये दोनों काम होने के बाद मैं समझता हूं कि हम बैकवर्ड नहीं रहेंगे। पिछली सरकार की कार्यशैली की वजह से हमें बैकवर्ड कहा जाता था। पिछली सरकारों में हमें न तो पानी मिला, न कोई मेडिकल कॉलेज मिला, न आई.एम.टी. मिली और न ही कोई बड़ी इंडस्ट्री मिली जिससे रोजगार मिल सके। हमारे जिले में सबसे मूलभूत आवश्यकता पानी की थी। इस सरकार ने बनते ही 143 करोड़ रुपये की लागत से लिफ्ट इरीगेशन योजना को चुस्त–दुरूस्त किया, सारे पम्प हाउस बदले गये और हमारी नहरों की टेल्स तक पानी पहुंचाया, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। इसके लिए मैं माननीय कृषि मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 143 करोड़ रुपये की योजना देकर बड़ी दरियादिली का परिचय दिया है जिसकी वजह से हमारे महेन्द्रगढ़ जिले में नहर का पानी पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इस बजट में उल्लेख है कि हमारी सरकार लखवार और किशाऊ डैम पर भी बहुत तेजी से काम करने जा रही है। हमें उम्मीद है कि उस पर तेजी से काम होगा तो जो सरप्लस पानी आयेगा उसमें हमारे जिले का भी हिस्सा होगा तथा जो पानी की कमी हमें महसूस होती है उसकी भी पूर्ति होगी। इसी प्रकार से एक बहुत बड़ी परियोजना जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते थे, हमारे एरिया में आई है। हमारे रेवाड़ी जिले के मनेठी में एम्स की स्थापना की जा रही है। इससे न केवल हमारे इलाके को बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश और राजस्थान को भी इसका लाभ होगा। इसके लिए मैं बार–बार माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। सुबह भाई जाकिर हुसैन जी कह रहे थे कि हमारे एम.पी. साहब राव इन्द्रजीत जी का पता नहीं कहां रहते हैं । मैं भाई जाकिर हुसैन जी को बताना चाहता हूं कि हमारे एम.पी. साहब इस प्रकार की एम्स जैसे इंस्टीच्यूट लाने के लिए दिल्ली की पार्लियामैंट में मेहनत करते हैं । एम.पीज. का काम गांव की गलियों में घूमने का नहीं होता है । एम.पीज. का काम तो इस तरह के इंस्टीच्यूट लाने का है । अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय जाकिर जी कुछ पूछना ही चाहते हैं तो उन्हें आदरणीय मनोहर लाल जी से पूछना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे एम.पी. साहब ने जिनका नाम जाकिर जी ले रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर एम्स को रेवाड़ी में लाने में सहयोग किया है ।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, जिन एम.पी. साहब का मैंने जिक्र किया है, के बारे में माननीय सदस्य एक बात बता दें कि वह कांग्रेस सरकार में केन्द्रीय मंत्री थे या नहीं थे ?

श्री ओम प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, राव इन्द्रजीत जी केन्द्रीय मंत्री थे या नहीं थे, इसका प्रस्तुत संदर्भ से कोई लेना देना नहीं है । प्रदेश में सरकारें आती जाती रहती हैं । कभी इनकी सरकार सत्ता में थी, कभी किसी और की सरकार सत्ता में थी । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार सत्ता में थी तब इन लोगों ने एस.वाई.एल. नहर के लिए क्या काम करके दिखाया था ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ओमप्रकाश जी, आप अपनी बात को खत्म कीजिए ।

श्री ओम प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. नहर का पानी दक्षिण हरियाणा के साथ–साथ जाकिर भाई के एरिया को भी मिलना है लेकिन इनकी सरकार ने अत्यंत महत्व के इस विषय पर कोई पग नहीं उठाये ।

श्री जाकिर हुसैन : ओम प्रकाश जी, आप सरकारों की बात मत करो । सरकारों की बात तो मुख्यमंत्री जी और विपक्ष के नेता कर लेंगे ।

श्री ओम प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं एम्स के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का व सरकार का धन्यवाद करता हूं क्योंकि एम्स एक तरफ और बाकी चीजें दूसरी तरफ । मुख्यमंत्री जी आपने हरियाणा को एम्स देकर बहुत बड़ा काम किया है । इस प्रदेश में 10–10, 15–15 साल राज करने वाले लोग आज सदन में छोटे–छोटे जोहड़ों के लिए कहते हैं । आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमें इतना दिया है कि आने वाले 10 सालों तक हम आपसे इस तरह की कोई छोटी–मोटी चीज नहीं मांगेंगे । अगर आप हमें खुद कुछ दोगे तो आपका भला लेकिन हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे । आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्री विक्रम सिंह यादव (कोसली): अध्यक्ष महोदय, कल वित्त मंत्री जी ने हरियाणा के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री जी की रहनुमाई में हरियाणा के विकास के लिए जो इतना बड़ा बजट पेश किया है उसके लिए मैं ही नहीं हरियाणा की जनता वाह् वाही कर रही है । आज जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हरियाणा के अन्दर पिछले 10 साल में जो कॉलेज नहीं खुले थे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर हल्के में 20 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज खोलने का काम किया है । उनमें से

मेरे हल्के के जाटसाना गांव में भी एक गवर्नमैंट कॉलेज खोला गया है । जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं । अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, जिसके बारे में हमारे साथी ओम प्रकाश जी भी बात कर रहे थे क्योंकि इनके जिले में तो एक मैडिकल कॉलेज भी खुल गया है । माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय केन्दीय मंत्री जी के सहयोग से हरियाणा में जो एम्स इंस्टीच्यूट आया है उसके लिए मेरे जिले के मनेठी गांव में जगह का चुनाव किया गया है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तय दिल से धन्यवाद करता हूं । इसी के साथ एम्स ही नहीं मैं माननीय मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे विधान सभा कोसली में एक नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी ही नहीं दी बल्कि उसका शिलान्यास कर दिया है और बजट भी दे दिया है । उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं । इसी के साथ जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में पिछली सरकार के समय रोड्ज की जो स्थिति हुआ करती थी, उसके बारे में हर आदमी जानता है। हमारे विपक्ष के साथी भी जानते है कि इनकी सरकार के समय इन पुराने रोड्ज की मरम्मत तक करने का काम नहीं किया जाता था। अध्यक्ष महोदय, कोसली विधान सभा क्षेत्र में मार्किट बोर्ड के अधीन आने वाले रोड्ज तथा पी.डब्ल्यू.डी.(बी.एंड.आर.) के अधीन आने वाले रोड्ज को भारतीय जनता पार्टी के महज 4 साल के शासन काल में हमारे माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और राव नरवीर जी ने बनवाने का काम किया है जबकि पिछले 10 साल में यह रोड्ज नहीं बनाये जा सके थे। इसके लिए मैं धनखड साहब, राव नरवीर जी तथा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यही नहीं लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर जी ने दिल खोलकर हमारे हल्के में नई रोड्ज को भी मंजूरी देने का काम किया है और जल्द ही यह रोड्ज बनकर तैयार भी हो गए हैं जिसके लिए मैं लोक निर्माण मंत्री जी का दिल की गहराईयों से बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। जहां तक परिवहन की बात है, मैं बताना चाहूंगा कि जिला रेवाड़ी में शहर के बीच एक बस डिपों हुआ करता था जिसको शहर से बाहर करने के लिए लोगों ने पिछली सरकार के समय आवाज उठाई लेकिन बावजूद इसके, इस बस डिपों को शहर से बाहर निकालने का काम पिछली कांग्रेस सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल में नहीं कर सकी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही सबसे पहले रिवाड़ी के बस डिपो को

शहर से बाहर करने की घोषणा करने का काम किया था। आज कोसली में सब–बस डिपों का काम आरम्भ हो चुका है जिसके लिए मैं माननीय परिवहन मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जहां तक पीने के पानी की बात है, इस दिशा में हमारे क्षेत्र को अब तक पिछड़ा कहा जाता रहा क्योंकि हमारे क्षेत्र में पानी बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मेरे क्षेत्र की आखिरी टेल तक पानी पहुंचाया गया है और इस कार्य ने पूरे दक्षिणी हरियाणा के जिलों के लिए एक मिसाल कायम कर दी है जो निश्चित तौर से सरकार की उत्कृष्ठ महत्वकांक्षा का ही एक परिणाम है जिसकी वजह से आज दक्षिण हरियाणा की नहरों में आखिरी टेल तक पानी पहुंच गया है और यही कारण है कि आज मेरे क्षेत्र को पानी के मामले में पिछड़ा नहीं कहा जा रहा है। जहां तक सबका साथ–सबका विकास की बात है, आज पूरे प्रदेश में समान विकास की अवधारणा को हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपनाने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश का चाहे कोई भी हल्का हो, सत्ता पक्ष के विधायक का हल्का हो या विपक्ष के विधायक का हलका हो, सब जगह समान रूप से विकास करवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभी सदन में हमारे साथी कुलदीप जी नहीं हैं। वे जिस प्रकार से लय में बोल रहे थे, उस लय में वे भी इस बात को मान रहे थे कि विकास की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश में पिछले 10 साल में जो काम नहीं किए गए थे, वे सभी काम भारतीय जनता पार्टी के पिछले 4 साल के शासन काल में पूरे किए गए। कहने का भाव यह है कि पूरा विपक्ष भी इस बात को मानता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में समान रूप से विकास के काम हुए है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से गीता जी को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में हमारे यहां कृष्ण नगर जिसको लूला अहीर के नाम से जाना जाता था, एक रीजनल सैंटर बनाने की घोषणा की गई थी **ले**किन आगे कुछ नहीं हुआ परन्तु माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की रहनुमाई में वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही इस रीजनल सैंटर को आरम्भ कर दिया और यही कारण है कि आज हम उस अवस्था में आ गए है कि 2 तारीख को इस रीजनल सैंटर की बिल्डिंग का उद्घाटन होने जा रहा है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। जहां कभी एक कॉलेज तक नहीं खोला जा सका वहां बी.जे.पी. के पिछले साढ़े चार साल के कार्यकाल में दो शिक्षण

संस्थायें अर्थात रीजनल सैंटर लूला अहीर और जाटूसाना गवर्नमैंट कॉलेज अस्तित्व में आ गए। आज जिस प्रकार से मैं अपने विपक्ष के सीनियर साथियों की बातों को सुनता हूँ तो एक बात मेरे जहन में आती है कि निःसंदेह विपक्ष का काम आलोचना करने का होता है परन्तु बावजूद इसके जायज बात को मानने से उन्हें संकोच नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी के शासन काल में हरियाणा प्रदेश में धरातल पर काम हुआ है केवल कागजों में काम हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। चाहे नर्सिंग कालेज की बात हो, चाहे सब डिपो कोसली की बात हो, चाहे रोड्ज बनाने की बात हो, चाहे मार्केटिंग बोर्ड या पी.डब्ल्यू.डी (बी.एंड.आर.) के रोड्ज की बात हो, आज तक के हरियाणा के 50 साल के इतिहास में किसी सरकार के महज चार साल की कार्यकाल के अन्दर इतने नये रोड्स किसी भी सरकार में नहीं बने हैं,

19.00 बजे

चाहे इस बात का रिकॉर्ड भी निकाल कर देख ले। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं पानी के बारे में बात करूँ तो हम पहले यह देखते थे कि गांव के अंदर पेयजल की भारी समस्या रहती थी लेकिन जब से डॉ0 बनवारी लाल ने यह विभाग संभाला है तब से रेवाड़ी के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर पीने के पानी की कोई भी समस्या नहीं रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से एक मांग चलती आ रही थी कि लुहाना गांव और बेरली गांव में पी.एच.सी. बनाई जाये और मंदोला गांव और लुहाना गांव में कॉलेज बनाया जाये। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे क्षेत्र की ये जो मांगें हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरी करें। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, उन सभी घोषणाओं को सरकार जल्दी से जल्दी पूरा करे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : सभी सदस्यगण, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल चुके हैं लेकिन अब दोबारा से बजट पर भी बोलना चाहते हैं, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि सिर्फ 4–5 मिनट में ही अपनी बात को समाप्त कर दें ताकि सभी माननीय सदस्यों को बजट पर भी बोलने का समय मिल सके।

श्री जाकिर हुसैन (नूंह) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए, मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब भी माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता था उसमें मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड और मेवात के विकास

के लिए अलग से जिक्र हुआ करता था। बजट में भी इस बात का जिक्र हुआ करता था। लेकिन इस बार के माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में तथा इस बार के बजट में भी मेवात के बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया गया है। जबकि हमें पूरी उम्मीद थी कि मेवात क्षेत्र के विकास के विषय को लेकर माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में तथा बजट में तरजीह दी जायेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 115 Aspirational Districts का नाम लिया था और उसमें मेवात का भी नाम आता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य के केन्द्रीय मंत्री चौधरी चौ0 बीरेन्द्र सिंह को Aspirational Districts का कन्वीनर बनाया गया है और फाइनैंस सचिव भी हमारे हैं। इस प्रकार से हमें पूरी उम्मीद थी कि जब फाइनैंस मिनिस्ट्री से बजट आयेगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को अपनाते हुए और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो फोकस मेवात पर कर रखा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे मेवात क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रकार की डिवैल्पमैंट स्कीम्स का बजट में उल्लेख होगा और अलग से रेफरैंस होगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि बजट में मेवात के लिए कोई अलग से रेफरैंस नहीं है। इस बात से से हमारे क्षेत्र के लोगों को काफी मायूसी हुई है। 'We For Development' कार्यक्रम माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा शुरू किया गया था और उस कार्यक्रम में मैं भी गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम के चीफ गैस्ट थे। उन्होंने बहुत फोकस किया था कि इन जिलों को विकास के मामले में आगे रखा जायेगा ताकि ये जिले पिछड़े न रहे। अध्यक्ष महोदय, इन बातों का बजट में कोई जिक्र नहीं है। 3 सितम्बर, 2015, 23 अक्तूबर, 2017, 6 मार्च, 2018 और 11 सितम्बर, 2018 को बार–बार मेवात फीडर कैनाल के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय सिंचाई मंत्री महोदय ने यह बात कही थी कि इसको मंजूर करके बना दिया जाएगा । वर्ष 2016–17 की गवर्नमैंट ऐश्योरेंसिज कमेटी की सदन में पेश की गई 46वीं रिपोर्ट के पेज नं. 173 पर यह आश्वासन अंकित है । इस बजट में मेवात फीडर कैनाल बनाने का कोई जिक्र नहीं है । बड़ी हैरानी की बात है कि बजट में मेवात के बारे में सिर्फ यही लिखा है कि the Government has announced the Mewat Water Supply Channel to meet the drinking water needs of Mewat area. वाटर सप्लाई पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट का एक सब्जैक्ट है लेकिन उसको भी ऐक्वायर में डाल दिया गया । इरीगेशन डिपार्टमैंट ने इसकी पी.पी.आर. मंजूर की हुई है और डी.पी.आर. अभी

पैंडिंग है। गुड़गांव कैनाल वर्ष 1959 की बनी हुई है उसका भी बजट में कोई हवाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्होंने 300 क्यूसिक पानी की क्षमता की पाइपलाइन डालने के लिए शिलान्यास पत्थर लगाने की 25 जनवरी तिथि निर्धारित की थी। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की बात का आदर करते हुए मेवात के लिए बजट में तरमीन करके इसका प्रावधान करें। मेरा कहना है कि यह माननीय प्रधानमंत्री की बात की इज्जत रखने का इशू है न कि हमारा इज्जत रखने का कोई इशू है। इसी तरह से होर्टिकल्चर के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि हर जिले में एक 'सैंटर फॉर एक्सीलैंस' स्थापित किया जाना है। अतः इसे जिला नूंह में भी अवश्य स्थापित किया जाए। इसके अलावा मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि दिल्ली के आसपास नूंह जिले में कहीं पर सब्जियों की बिक्री के लिए एक इंटरनैशनल मार्केट बनाई जाए जो राजस्थान तक के एरिया को फीड कर सके। इसी तरह से स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के संबंध में मेरा कहना है कि नूंह के एक गांव शाहपुर नंगली ने अपनी बेशकीमती जमीन स्टेडियम बनाने के लिए कई सालों से दी हुई है। मेवात में कोई भी स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है । अतः मेरा अनुरोध है कि उसका काम शुरू किया जाए । अगर मैं इम्पलॉयमैंट पर बात करूं तो आई.एम.टी. रोजकामेव में इंडस्ट्रीज एरिया स्थापित करने के लिए बहुत दिनों से जमीन ऐक्वायर की हुई है। मेरा आग्रह है कि उसे जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए और जिन 9 गांवों की जमीन ऐक्वायर हुई है उनके बच्चों को प्रेफ्रैंस देकर नौकरियां दी जाएं। इसके अलावा मेरा कहना है कि उन लोगों के साथ बहुत ज्यादती हुई है, इसलिए उनको जमीन का मुआवजा बढ़ाकर दिया जाए। सरकार ने अभी ग्रुप–डी की साढ़े 18 हजार पोस्ट्स की भर्ती कंप्लीट की है। मेरा कहना है कि इससे पिछले 10–10 सालों से जो लोग सरकार में माली, रसोइये आदि के तौर पर काम कर रहे थे वे बेरोजगार हो गए हैं । अतः सरकार को उनके लिए भी इम्पलॉयमैंट का कुछ प्रबंध करना चाहिए । इसी के साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय 17.09.2017 को 2 दिन के प्रवास पर नूंह में गए थे । उन्होंने वहां पर एक दिव्यांग बच्चे शौकीन को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था । मेरे पास इसकी तस्वीर और खबर भी है । अतः मेरा आग्रह है कि वह एक गरीब घर का बच्चा है और नौकरी न मिलने से वह बहुत मायूस है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जाकिर जी, आपके 5 मिनट पूरे हो चुके हैं ।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नसीब भाई ने रेल, सड़क, ड्राइविंग लाइसैंस आदि मुद्दों पर बात की है । अतः सरकार द्वारा इन पर गौर किया जाना चाहिए । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जाकिर जी, ये सारी बातें हो चुकी हैं । अब आप कोई नई बात बताइये ।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन एवं भत्ते देने पर अपनी पीठ बहुत थपथपाई है । मेरा कहना है कि हरियाणा के कर्मचारियों को आज तक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एच.आर.ए. नहीं दिया गया है । इससे वे बड़े मायूस हैं । अतः सरकार को कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एच.आर.ए. देना चाहिए । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जाकिर जी, आपने स्वयं अपने लिए 5 मिनट निर्धारित किये थे । अब वे पूरे हो चुके हैं ।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, नूंह में कोई हुडा का सैक्टर विकसित नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त मैं फौजियों की कैंटीन के बारे में बात करना चाहूंगा । बजट में फौजियों का जिक्र भी किया गया है । अध्यक्ष महोदय, हमारे मेवात जिले के बहुत से जवान फौज में भर्ती हैं और कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं परन्तु हमारे जिले में फौजियों के लिए कोई सी.एस.डी. कैंटीन नहीं बनायी गयी है। इसलिए उनको सी.एस.डी. से सामान खरीदने के लिए गुरूग्राम जिले में जाना पड़ता है जिससे उनको स्वयं और आश्रितों को आने–जाने में असुविधा होती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि नूंह में एक सी.एस.डी. कैंटीन का निर्माण करवाया जाए।

श्री अध्यक्षः जाकिर जी, आपकी बात पूरी हो गयी है। प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वे मेवात फीडर कैनाल का पत्थर रखवा कर काम शुरू करवा दें।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः करण सिंह जी, माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं इसलिए आपको बाद में बोलने के लिए मौका दे दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री जाकिर हुसैन जी और विशेष तौर पर मेवात जिले के माननीय सदस्यों और सदन के दूसरे सभी माननीय सदस्यों को भी बताना चाहूंगा कि पूरे देश के 100 एसपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में मेवात जिला भी शामिल था। सरकार का मेवात जिले पर विशेष ध्यान है और इस जिले की डिवलेपमैंट के लिए सभी विभाग कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक महीने इन सभी 100 डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग बनायी जाती है। यह रैंकिंग पांच क्षेत्रों के आधार पर बनायी जाती है जिसमें एजूकेशन, हैल्थ, एग्रीकल्चर, फाईनैंशियल इन्कलूजन और बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को शामिल किया गया है। मुझे कल ही एक समाचार मिला है कि जनवरी के महीने की जो रैंकिंग आयी है उसमें पूरे देश के इन 100 जिलों में 5 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में तो मेवात जिला फर्स्ट आया है, दूसरे क्षेत्र में सैकिण्ड और तीसरे क्षेत्र में थर्ड आया है। इसके अतिरिक्त दो क्षेत्रों में इम्प्रूवमैंट करना बाकी है। पूरे देश के 100 जिलों में ऑवर आल रैंकिंग में मेवात जिला फर्स्ट आया है और यह रैंकिंग हर महीने में बनायी जाती है। नीति आयोग ने घोषणा की है कि जिस महीने में जो भी जिला फर्स्ट आएगा, उसको 10 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जाएगा। इसलिए मेवात जिले को नीति आयोग से 10 करोड़ रूपये का अनुदान मिलेगा।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। मेवात जिले के माननीय सदस्य और सभी लोग भी पीछे रहकर खुश नहीं है।

श्री अध्यक्षः मेवात जिले के सभी माननीय सदस्यों को माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। यह मेवात जिले को फर्स्ट पॉजीशन पर लाने वाली सरकार है।

श्री जाकिर हुसैन: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो घोषणाएं की हैं अगर वे सभी पूरी हो जाएं तो हम पूरे इंडिया में ही फर्स्ट आ जाएंगे। मेवात जिले के लिए सरकार की जो पूर्व योजनाएं हैं, वे सिरे चढ़ाई जाएं।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल): स्पीकर सर, मेरी आपसे यह रिकवेस्ट है कि मैंने बजट पर बोलने के लिए आंकड़े इकट्ठे किये हैं इसलिए मेरे ऊपर टाईम की बंदिश न लगायी जाए। हालांकि मैं जल्दी ही अपनी बात कम्पलीट कर दूंगा।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी के लिए कहना चाहूंगा कि it is a contradictory situtation of

Hon'ble M.L.A. One side he accepts the Budget and other side he is making cut of 50 rupees only. माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी 1 लाख 32 हजार करोड़ रूपये के बजट को तो स्वीकृत करते हैं परन्तु बोलने के लिए 50 रूपये का कट लगाकर स्वीकार करते हैं।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, इस बात में भी एक राज है। पिछले दिनों हमारे माननीय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी ने बजट में एप्रोप्रिएशन बिल पर सिर्फ 1 ही रूपया मांगा था। मैं कम से कम 50 रूपये की तो मांग कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पिछले दिनों सरकार ने डिमोनिटाईजेशन किया था जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाने से सभी क्षेत्रों के लोगों को चौतरफा नुकसान हुआ था। अभी एक सप्ताह पहले भारत सरकार ने The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019 लोक सभा में पेश किया था और यह बिल लोक सभा में पास भी हो गया था लेकिन राज्य सभा में पास नहीं करवाया जा सका। जब लोक सभा साईन डाई हो रही थी तो उसके पहले दिन एक और काला कानून बना दिया गया। इस एक्ट में 1–2 बातें तो अच्छी हैं। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में जो लॉटरी के स्कैम हुए और चिट फंड घोटाला हुए थे, उनको रोकने की बात तो ठीक है। हमें इस बात पर कोई एतराज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने कम्पनीज एक्ट में भी बदलाव किया है।

श्री अध्यक्षः करण सिंह जी, आप जो बात कह रहे हैं, वह बजट का विषय नहीं है।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। माननीय सदस्य बजट के प्रावधानों के ऊपर बोलने के लिए खड़े हुए हैं और हम उनके सुझाव, उनकी टिप्पणियों और उनकी आलोचना को सुनना चाहते हैं, लेकिन यह अपनी बात प्रारंभ कर रहे हैं कि लोक सभा में क्या हो रहा है और केन्द्र सरकार कोई आर्डिनेंस ला रही है। इन सारी बातों का इस बजट से कोई संबंध नहीं है, इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप माननीय सदस्य को बताएं कि ये बजट के ऊपर ही बोलें। हम वास्तव में इनकी बात को सुनना चाहते हैं।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैं जो बातें कह रहा हूं, वह हरियाणा प्रदेश के ऊपर भी लागू है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान गरीब छात्रों का होने जा रहा है।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि जो केन्द्रीय कानून होगा वह हरियाणा पर लागू हो सकता है, परंतु उसका इस बजट से कोई संबंध नहीं है, इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन है कि ये आज इस बजट के ऊपर ही बोले।

श्री अध्यक्षः करण जी, आप बजट के ऊपर ही बोलें।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर मैं इस बात को इस सदन में नहीं कह सकता हूं तो मैं इसे बाद में अखबारों में दे दूंगा।

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही कमाल की बात है कि यहां पर सी.एल.पी. लीडर अपनी बात अखबारों की खबर से शुरू करती है और करण दलाल जी भी अखबारों की बातें कर रहे हैं, इसलिए मेरा करण दलाल जी से कहना है कि ये उनकी कॉपी क्यों कर रहे हैं, ये तो खुद ओरिजनल है।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन्होंने बजट में वर्ष 2019–20 का फिस्कल डेफिसिट 2.9 परसैंट दर्शाया है और यह जो 2.9 परसैंट फिस्कल डेफिसिट है वह नेशनल एवरेज के मुकाबले में बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। इसमें मेरा सुझाव यह है कि सरकार को इस फिस्कल डेफिसिट को या तो 3.5 परसैंट पर ले जाना पड़ेगा, वरना सरकार ने बजट में हर विभाग के जो कार्यक्रम बनाए हैं, वे पूरे नहीं हो पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जो आउट–स्टैंडिंग फिस्कल डेफिसिट हैं, वह वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 तक विद उदय 2.9 परसैंट है और विद–आउट उदय 2.6 परसैंट है। जो आउट–स्टैंडिंग लाइबिलिटीज हैं, वह विद उदय 20.9 परसैंट और विद–आउट उदय 19.6 परसैंट है। अध्यक्ष महोदय, ये सारे आंकड़े इतनी बदहाल स्थिति में हैं कि सरकार विभाग की स्कीम्ज को पूरा नहीं कर पाएगी। इसके साथ–ही–साथ मंत्री जी ने बजट में एग्रीकल्चर के लिए 4.4 परसैंट बजट का प्रावधान किया है, जबकि 27 स्टेट्स में इसका एवरेज 6.4 परसैंट है। अगर माननीय मंत्री जी मुझ से डाटा मांगना चाहते हैं तो मैं इनको इसका डाटा भी दे सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं एजुकेशन की बात करना चाहूंगा कि मंत्री जी ने बजट में एजुकेशन के लिए 13.9 परसैंट का प्रावधान किया है, जबकि 27 स्टेट्स में इसका एवरेज 15.9 परसैंट है। अध्यक्ष महोदय, आज हम कहते हैं कि हरियाणा बहुत

तरक्की कर रहा है और उसके पास शिक्षा के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम देश के एवरेज राज्यों से पीछे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हरियाणा इस देश के अंदर कोई मायने नहीं रखता। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हैल्थ भी किसी देश या प्रदेश के लिए सबसे जरूरी कम्पोनैंट होता है और अगर हमें किसी देश या प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो हमें 2 इशूज स्वास्थ्य और शिक्षा पर विचार जरूर करना होगा। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बजट में हैल्थ के लिए 4.5 परसैंट का प्रावधान किया है, जबकि 27 स्टेट्स का बजट एवरेज 5.2 परसैंट है। मैं पिछले साल का भी डाटा बता देना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने पिछले सालों में बजट में हैल्थ के लिए कितने परसैंट का प्रावधान किया था। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हैल्थ के लिए वर्ष 2017–18 के बजट में 3.9 परसैंट, वर्ष 2018–19 के बजट में 4.7 परसैंट और 2019–20 के बजट में 4.5 परसैंट रखा है। इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर हम हैल्थ में भी इस देश के एवरेज राज्यों से भी पीछे हैं तो हरियाणा के बारे में यह कहा जाता सकता है कि हरियाणा के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सबसे भयंकर स्थिति एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी. और माइनोरिटी की है। The state has allocated 0.5% of it's total budget towards the welfare of SC, ST & BC and Minorities. Sir, This is lower than the allocations of 26 other States of this Country. मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो एस.सी./एस.टी. और ओ.बी.सी. के गरीब लोग हैं, उनकी भलाई के लिए बजट में केवल 0.5 परसैंट ही क्यों रखा गया है ? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इनको इसके ऊपर फिर से विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार इन गरीब लोगों को इस तरह से इग्नोर करेगी तो यह बहुत ही गलत बात है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं pendency of cases in Distirct and Subordinate Courts as on 14th January, 2019 के बारे में बताना चाहूंगा कि हरियाणा में सिविल केसिज की संख्या 282613 यानि 38.21 परसैंट और क्रिमिनल केसिज़ की संख्या 457106 हैं जोकि काफी खतरनाक है, इसकी प्रतिशतताः 60.79 बनती है। हम सबोर्डिनेट कोर्टस और सिविल कोर्टस में इतना पैसा देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे इतने क्रिमिनल और सिविल केसिज़ पैंडिंग पड़े हुए हैं, यह बहुत ही हैरानी की बात है वकील तारीख पर तारीख लगाते जाते हैं और इससे आम आदमी दुःखी होता रहता है । अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थितियां ऐसी हो गईं हैं, जिसके

कारण से न तो सड़कों पर चलने की जगह बची है और न ही अदालतों में बैठने के लिए जगह बची है। मेरा तो यही कहना है कि इस बारे में भी सरकार को अच्छी तरह से गौर करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी बहुत सारे केसिज़ पैंडिंग पड़े हुए हैं, उन केसिज़ के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे भी चाहे इनका कोई न कोई समाधान करवाये क्योंकि इसमें भी हमारी पोजिशन अच्छी नहीं है। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सिविल के 166111 केसिज़ पैंडिंग पड़े हुए है जोकि परसैंटेज़ के हिसाब से देखें तो पूरे रेस्ट ऑफ दी स्टेट के हिसाब से यानि प्रतिशतताः 44.74 बनती है और क्रिमिनल के 131085 केसिज़ पैंडिंग पड़े हुए हैं । यदि इस बात की तरफ गौर किया जाये तो यह बहुत सीरियस बात है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस और प्रोसिक्यूशन विभाग जिस तरह से मुकदमों को अदालत में बनाकर भेजते हैं उससे लोगों के केसिज़ का डिस्पोज़ल होना मुश्किल है। यदि उनके फैसले ही नहीं होंगे तो न्याय प्रणाली किस काम आयेगी? इस पर भी चिंता करने की जरूरत है । अध्यक्ष महोदय, जहां तक फारेस्ट कवर की बात है तो आज के दिन पर्यावरण काफी बिगड़ा हुआ है। हरियाणा प्रदेश के किसी भी शहर का पोल्यूशन लैवल देखेंगे तो वह अनहैल्दी ही दिखाया जाता है । अध्यक्ष महोदय, आज हम फारेस्ट कवर ठीक नहीं कर पायेंगे तो हमारे बाल बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य जो बिगड़ रहे हैं, उनको कैसे ठीक किया जायेगा? वर्ष 2017 का जो फौरेस्ट कवर है वह 0.06 परसैंट है और यदि मैं दूसरी स्टेट के फौरेस्ट कवर के बारे में जिक्र करूं तो बिहार प्रदेश में यह 30 परसैंट है और केरला में भी यह 30 परसैंट है, तमिलनाडु में 14.5 परसैंट है और वेस्ट बंगाल में 35 परसैंट फौरेस्ट कवर आता है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के फौरेस्ट कवर को ठीक करना इसलिए जरूरी है कि इसके बिना हम लोगों के स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पायेंगे । इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश का जो ग्राउंड वाटर डिवैल्पमैंट एंड कवरेज ऑफ इरीगेशन है वह 127 परसैंट है और इरीगेटिड एरिया 88.3 परसैंट है । अध्यक्ष महोदय, यदि हम हरियाणा प्रदेश का पंजाब प्रदेश के साथ इस बारे में कम्पेयर करके देखें तो ग्राउंड वाटर डिवैल्पमैंट एंड कवरेज ऑफ इरीगेशन 170 परसैंट है और इरीगेटिड एरिया 99.1 परसैंट है । अध्यक्ष महोदय, यदि हम पड़ोसी प्रदेशों में होने वाली अच्छी बातों का मुकाबला नहीं करेंगे तो फिर हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने में बड़ी भारी दिक्कतों

का सामना करना पड़ सकता है । अध्यक्ष महोदय, अब मैं हरियाणा में वर्ष 2017 में जो रोड एक्सीडेंट्स, fatalities and injuries हुई, उनके बारे में बताना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : करण दलाल जी, आप वाईंड अप कर लीजिए ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं वहीं बातें बता रहा हूं जो इन लोगों को कहीं नहीं मिलेगी और यदि इन बातों पर गौर नहीं किया जायेगा तो हरियाणा प्रदेश का भला नहीं होगा। मैं यहां पर कोई फालतू की बात नहीं कर रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, रोड एक्सीडेंट्स के मामले में हरियाणा में 11258 केसिज़ वर्ष 2017 में रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं । Road accidents per lac population 40, fatalities 5120 और इसी तरीके से 10339 केसिज़ इंजरी के हैं, इसके बावजूद जो इतने एक्सीडैंट छोटे से प्रदेश में हो रहे हैं, यह सोचने वाली बात है । हमारी किस तरह की रोड सैफ्टी है? हरियाणा प्रदेश में एक्सीडेंट्स से आये दिन नौजवानों की मौतें होती रहती हैं। हम इस तरह के हालातों को अपने हल्कों में भी देखते रहते हैं। स्पीकर सर, प्रदेश में आये दिन एक्सीडैंट्स से इतनी बड़ी संख्या में लोग घायल होते हैं कि उनके इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भी कम पड़ते हैं। स्पीकर सर, जहां तक ड्राईविंग लाईसैंस की बात है इस बारे में मेरा यह कहना है कि हरियाणा प्रदेश में ड्राईविंग लाईसैंस को इशू करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। मेरा यह कहना है कि ड्राईविंग लाईसैंस बनाने से पहले लाईसैंसधारक का ड्राईविंग का टैस्ट लिया जाये और इसी के साथ उसका पूरा मैडीकल चैक–अप भी होना चाहिए। आजकल तो एम.एल.ए. और मंत्री लोगों की सिफारिशों से ड्राईविंग लाईसैंसिज़ बनाये जाते हैं। हमारे जैसों के फोन जाते हैं और किसी का भी ड्राईविंग लाईसैंस बन जाता है जोकि नहीं होना चाहिए। जो इस प्रकार से जो ड्राईविंग लाईसैंस बनते हैं वे भी एक्सीडैंट्स की एक मुख्य वजह होते हैं इसलिए मेरा कहना है कि ड्राईविंग लाईसैंस बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से दुरूस्त किया जाये। अब मैं कंविक्शन रेट के बारे में बताना चाहूंगा जो कि आज के परिपेक्ष्य में बहुत ही इम्पोर्टैंट है। इंडियन पैनल कोड के तहत हरियाणा का कंविक्शन रेट 26.9 परसैंट है और स्पैशल एण्ड लोकल लॉज का 712.7 परसैंट है जबकि तमिलनाडु में यह 90 परसैंट है एवं उत्तराखण्ड में 85 परसैंट है। मेरा यह कहना है कि कैप्टन अभिमन्यु जी को अपने डिपार्टमैंट को यह बताना होगा कि अगर हमारी कंविक्शन ही नहीं है तो फिर कोई भी कानून क्या करेगा और फिर किस प्रकार से इस तरह से समाज में होने वाले अपराधों को रोका जा सकेगा। इसी

प्रकार से मैं एक और सीरियस बात यहां पर करना चाहता हूं। जो जी.एस.टी. का कानून देश में लागू हुआ है इसमें Central transfers as a percentage of total revenue हरियाणा को 21 परसैंट मिलता है और State on GST revenue as a percentage of total revenue यानि जो भारत सरकार के पूल में जाता है वह 31 परसैंट है। इस प्रकार से हरियाणा में अगर हम 31 परसैंट कमाकर भारत सरकार को दे रहे हैं और फिर वहां से 21 परसैंट हरियाणा को मिल रहा है तो फिर जी.एस.टी. का कानून बनने से हरियाणा स्टेट को क्या फायदा हुआ? इसकी भरपाई के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री जी की केन्द्र सरकार के मंत्रियों या उच्चाधिकारियों के साथ मीटिंग होती है तो उस समय इस बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि यह एक बहुत ही ज्यादा सीरियस मुद्दा है। आज हम यहां पर अपनी छोटी–मोटी मांगों को मनवाने के लिए केन्द्र सरकार और केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों के चक्कर काटते रहें हैं जबकि हमारे खून पसीने की कमाई का बहुत सारा पैसा दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। राज्य सरकार को किसी न किसी तरीके से केन्द्र सरकार से इस नुक्सान की भरपाई का इंतजाम करवाना चाहिए।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध है कि जो प्वायंट उन्होंने अभी–अभी बताया है वे उसे कृपया करके दोबारा बतायेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें कुछ त्रुटि है।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं इस प्वायंट को दोबारा दोहरा देता हूं। जो प्वायंट मैंने बताया उसका हैडिंग यह है– Implementation of GST is expected to reduce the autonomy of the States on their revenue. वर्ष 2018–19 के दौरान के ये पूरे स्टेट्स के डाटाज़ हैं। इसमें यह बताया गया है कि किस स्टेट ने सैंट्रल पूल में जी.एस.टी. का कितना पैसा दिया और फिर कितना पैसा सैंट्रल पूल से स्टेट्स को वापिस मिला। वित्त मंत्री जी ने हरियाणा के पोर्शन को रिपीट करने के लिए कहा है इसलिए मैं उसे रिपीट कर देता हूं। इसमें यह लिखा है कि Central transfers as a percentage of total revenue हरियाणा को 21 परसैंट मिला है और State on GST revenue as a percentage of total revenue यानि जो भारत सरकार से जी.एस.टी. के तहत गया है वह 31 परसैंट है।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय स्पीकर सर, मेरा इस बारे में यह कहना है कि माननीय सदस्य का यह प्वायंट बजट से अलग है लेकिन फिर भी मैं इसको

एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आदरणीय सदस्य ने यह प्वायंट उठाया है कि जी.एस.टी. आने के बाद केन्द्र और राज्य का आपस का जो हिस्सा है उसमें उनको यह लगता है कि वह राज्यों के हितों के विपरीत जायेगा। मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि माननीय सदस्य जो भी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं वह ठीक नहीं है। जी.एस.टी. के लिए कॉस्टीच्युशनल प्रॉविजन के तहत पूरे देश के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के प्रतिनिधियों को मिलाकर के एक जी.एस.टी. काउंसिल का गठन किया गया है जोकि एक कॉस्टीच्युशनल बॉडी है। इस काउंसिल ने पूरी असैसमैंट करके जो केन्द्र और राज्य के जी.एस.टी. के रेवेन्यू के शेयरिंग का जो 50–50 परसैंट का फार्मूला तैयार किया यह भी इस आधार पर तय किया था कि इसमें पहले जो रेवेन्यू आ रहा था वह पहले केन्द्र को ज्यादा जाता था और जी.एस.टी. आने के बाद आज जो रेवेन्यू आयेगा वह राज्यों को ज्यादा आयेगा। इसमें केन्द्र ने अपने शेयर का भी कुछ सैक्रीफाईस किया था। इस जी.एस.टी. काउंसिल में सभी राज्यों और सभी यूनियन टेरीटरीज़ के लोग आज भी हैं। दूसरी बात यह है कि केन्द्र में वर्तमान सरकार द्वारा नीति आयोग बनाने के बाद सैन्ट्रल टैक्सिज की डिवोल्यूशन का नया फार्मूला बनाया गया है। पहले जहां सैन्ट्रल टैक्सिज की डिवोल्यूशन के तहत राज्यों को 32 प्रतिशत मिलता था वहीं अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उसको बढ़ा कर 42 प्रतिशत कर दिया है। मुझे लगता है कि दलाल साहब जो जानकारी दे रहे हैं वह ठीक नहीं है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाये?

आवाजेंः ठीक है, जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2019–2020 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, ह्यूमन डिवैल्पमैंट पर दिल्ली सबसे ज्यादा 40 प्रतिशत खर्च करता है जबकि हरियाणा ह्यूमन डिवैल्पमैंट पर 23 प्रतिशत खर्च करता है। दिल्ली हमसे छोटा है और हमारी आमदनी और बजट भी उनसे अधिक है फिर भी वह इस मामले में हमसे ज्यादा खर्च करते हैं। तेलंगाना जैसा राज्य भी

इकॉनोमिक एण्ड इनफ्रास्ट्रक्चर पर 63 प्रतिशत खर्च करता है जबकि हरियाणा 34 प्रतिशत खर्च करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पास इनफ्रास्ट्रक्चर ही उपलब्ध नहीं होगा तो हरियाणा दूसरे राज्यों का मुकाबला किस प्रकार से कर पायेगा? जो राज्य कल ही बने हैं और उनके पास बहुत ज्यादा साधन भी उपलब्ध नहीं हैं वे इकॉनोमिक डिवैल्पमैंट और इनफ्रास्ट्रक्चर पर 63 प्रतिशत खर्च करते हैं और हम इतना कम पैसा खर्च करते हैं। जो अनस्पैंट बजट है, जो बजट खर्च नहीं कर पाये हैं उसमें हरियाणा –8 प्रतिशत पर आता है।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि ये आंकड़े कौन से साल के बता रहे हैं?

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े वर्ष 2011–17 के बीच के हैं।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, आज हमने वर्ष 2018–19 के रिवाइज्ड बजट ऐस्टीमेट्स प्रस्तुत किये हैं और वर्ष 2019–20 के बजट ऐस्टीमेट्स प्रस्तुत किये हैं और माननीय सदस्य अपने समय के आंकड़े बता रहे हैं। वर्ष 2011–17 में अधिकांश हिस्सा इन्हीं की सरकार के समय का है क्योंकि वर्ष 2014 तक इनकी सरकार रही थी। हम बड़े आदरपूर्वक इनकी बात सुनना चाहते हैं लेकिन ये सही जानकारी सदन के सामने रखें।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आप जल्दी से वाइंडअप कीजिए।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अगर रिवैन्यू कलैक्शन की बात की जाये तो उसमें हम –12 प्रतिशत पर आते हैं। इसमें यह भी देखना होगा कि रिवैन्यू कलैक्शन में हम इतने क्यों पिछड़ रहे हैं ? अगर माननीय वित्त मंत्री जी ये कागज लेना चाहें तो मैं ये उनको दे सकता हूं। अंत में मैं पीने के पानी पर अपनी बात रखना चाहता हूं। पंजाब में पीने के पानी पर इतना ध्यान दिया गया है कि सरकार ने घर–घर में आर.ओ. लगवाने का संकल्प लिया है जबकि हरियाणा में पीने के पानी की स्थिति बहुत खराब है। खास तौर से मेवात, पलवल, फरीदाबाद तथा गुरूग्राम में अंडर ग्राउंड वाटर ब्रैकिस है और आर्सेनिलिक वाटर पूरे हरियाणा में फैल रहा है क्योंकि धान की खेती हो रही है। आज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की पूरे देश और हमारे प्रदेश को भी जरूरत है। बहुत अच्छा होता अगर सरकार किसानों को और अधिक पैसा देकर धान की खेती को बंद करवा देती। अब हमें धान की खेती को बंद करने बारे विचार करना चाहिए क्योंकि रोजाना रिपोर्ट्स आ

रही हैं कि अपना इंडो जेनेटिक बेसिन ट्रिमर हो रहा है। अंडर ग्राउंड वाटर की भी स्थिति दिन–प्रतिदिन बहुत खतरनाक होती जा रही है और उसके लिए धान की खेती बहुत बड़ा कारण है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि किसानों को जो पैसा सरकार की तरफ से दिया गया है वह और ज्यादा दिया जाता लेकिन सरकार की तरफ से स्कीम यह बनाई जानी चाहिए थी कि जो किसान धान की खेती की जगह मक्का की खेती करेंगे सरकार उनको प्रोत्साहन राशि देगी। इससे हमारा पर्यावरण भी ठीक होता और धान की खेती पर सिंचाई में जो बिजली खर्च होती है वह भी बचती। मक्का से तेल भी निकलता है, खाने की भी बहुत सारी चीजें बनती हैं और पर्यावरण भी अच्छा होता है। अगर ऐसी स्कीम लाई जाती तो हरियाणा के किसानों का भी भला हो जाता और धान की खेती के कारण हरियाणा प्रदेश पर बिजली और पानी का अतिरिक्त भार पड़ता है उससे भी राहत मिल सकती थी। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट में ए.डी.ओ. के पद खाली पड़े हुये हैं क्योंकि अभी तक उनके सर्विस रूल्ज नहीं बने हैं। यदि सर्विस रूल्ज ही नहीं होंगे तो रिक्रुटमैंट कैसे होगी? जब विभाग के सर्विस रूल्ज बन जायेंगे तभी भर्ती का प्रोसैस शुरू होगा। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ने यह कहा है कि किसानों को लोन देने से पहले किसानों से पोस्ट डेटिड चैक लिया जाये ताकि अगर कोई किसान समय पर पैसा नहीं लौटाता है तो उनके खिलाफ कोर्ट में केस डाल कर उनको जेल में डालने का इंतजाम किया जाये। मेरा निवेदन है कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के अधिकारियों से बात करके इस सिस्टम को तुरन्त बन्द करवाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, आपकी बात खत्म हो गई है । प्लीज अब आप बैठ जाइये ।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया (फतेहाबाद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद । वैसे तो एक कहावत है कि 'पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं ।' जब महामहिम का अभिभाषण पढ़ा गया तो उसी समय पता लग गया था कि बजट कैसा आएगा । बजट में कैप्टन साहब ने शब्दों के माया जाल में सबको जिस तरह से गुमराह किया है उसमें मैं तो यह सोच रहा था कि फौजी आदमी है वह बजट में ऐसे शब्दों का मायाजाल नहीं करेगा । फिर मुझे याद आया कि एक हमारे चाचा का लड़का है जिसको हम लाड–प्यार में थानेदार कहते हैं लेकिन वह थानेदार लग नहीं रहा है ।

उसी तरह से कभी आप भी कैप्टन साहब को प्यार में तो कैप्टन नहीं कहते हैं क्योंकि फौजी आदमी ऐसे शब्दों का मायाजाल नहीं करता है । बजट पेश होने के बाद काफी लोगों ने अपनी–अपनी प्रतिक्रिया दी है । शर्मा जी तो बहुत व्यायामी प्रवृति के आदमी हैं इन्होंने तो उनकी बहुत तारीफ की थी ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : बलवान जी, मैं खाली फौजी ही नहीं था । मैं एक कमांडो भी था ।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : सर, कमांडों ऐसे शब्दों का मायाजाल नहीं करता है । कैप्टन साहब, इसलिए थोड़ा सा शक हो रहा था । मैंने सोचा कि जिस तरह से हम अपने भाई को थानेदार कहते थे कभी ऐसे ही आपको भी कैप्टन साहब कहते हों । अध्यक्ष महोदय, भिन्न–भिन्न मंत्रियों ने बजट पर अपनी–अपनी प्रतिक्रिया दी है । शर्मा जी बहुत व्यायामी प्रवृति के आदमी हैं इन्होंने तो उनकी बहुत तारीफ की थी लेकिन धनखड़ साहब ने बजट पर बड़ी स्टीक प्रतिक्रिया दी थी । एक पत्रकार उनके घर जाकर कहने लगा कि आप बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए । वह कहने लगे कि आप मेरी गाय देखिए यह 18 लिटर दूध देती है । पत्रकार कहने लगा कि मैं बजट पर प्रतिक्रिया लेने आया हूं । मंत्री जी कहने लगे कि मेरी जन रसोई देखिए यहां पर आम जनता खाना खाती है और मैं भी यहीं खाना खाता हूं । वह कहने लगा कि आप बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैंने आपकी बाईट भेजनी है । मंत्री जी कहने लगे कि आप अमर नाथ जाओ वहां अमर नाथ से आगे भूस्खलन बहुत होता है । वहां पर लिखा हुआ है कि प्रक्रति पर गुस्सा मत करिए सबकी अपनी–अपनी भूमिकाएं हैं तो मुझे यह प्रतिक्रिया ठीक लगी । अध्यक्ष महोदय, अगर बजट के अन्दर तीन बातें ठीक कर ली जाएं तो ठीक रहेगा । उसमें वितीय राजकोषीय घाटा ठीक कर लिया जाए और एक पूंजीगत निवेश को बढ़ा लिया जाए । जैसे कहा जाता है कि हम राजकोषीय घाटे के लिए एक अध्यादेश लाएंगे और हम हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व विधेयक के नाम से एक विधेयक ला रहे हैं । इस उपाय से सरकार अगले पांच वर्षों में राजस्व घाटे को शून्य पर लाने के लिए आशान्वित हैं । कैप्टन साहब, पहले ही यह सभी राजकीय कोष मानक पूरी तरह से 14वें वित्त आयोग और एफ.आर.–बी.एम. अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं में है । इसलिए इसके लिए कोई नया बिल लाने की जरूरत नहीं है । अगर आपकी नीति और नीयत ठीक है तो वैसे ही इस घाटे को कम किया जा सकता है। आप इस घाटे को ठीक कीजिए । यह घाटा

दिन–प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है । इसी तरह से आप शब्दों के मायाजाल में कहते हैं कि राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत सीमाओं के अन्दर है लेकिन यह 3 प्रतिशत से ज्यादा है । आपने इस घाटे को अपने शब्दों में गुमराह किया है । इसी तरह से पूंजीगत व्यय से सम्पत्ति अर्जित होती है । सारे विकास कार्य इसी से होते हैं इसलिए इसके अन्दर ज्यादा से ज्यादा पूंजीगत व्यय होना चाहिए । कैप्टन साहब, कह रहे हैं कि हम वर्ष 2018–19 में 35.40 हजार करोड़ रुपये बढ़ाने में सक्षम हुए हैं और इस बार वर्ष 2019–20 में यह 37.924 करोड़ रुपये बढ़ाने की सम्भावना है । जोकि थोड़ा बढ़ाया गया है इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सरकार की प्राथमिकता न शिक्षा है, न कृषि है, न हैल्थ है । सभी विभागों में इन्होंने कटौती करने का काम किया है । अब शर्मा जी की तो शिक्षा के मामले में बड़ाई करनी पड़ती है जबकि इनको भी शिक्षा के क्षेत्र में बजट कम दिया गया है । मैं आपके माध्यम से शर्मा जी को बताना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग में 40 हजार पद रिक्त पड़े हुए हैं उनको भरने का कोई प्रावधान नहीं है । पिछली बार शिक्षा के क्षेत्र में 12.96 करोड़ रुपये बजट था जिसको अबकी बार घटा कर 11.61 करोड़ रुपये कर दिया गया है । हैल्थ सभी मूलभूत सुविधाओं में सबसे ज्यादा जरूरी है लेकिन कैप्टन साहब ने हैल्थ को भी नहीं छोड़ा उसके लिए विज साहब इनको सबके सामने कहेंगे या बाद में कहेंगे । वैसे वह कह देते हैं क्योंकि वह ठीक आदमी हैं । पिछली बार हैल्थ के क्षेत्र में 4.14 करोड़ रुपये बजट था जिसको अबकी बार घटा कर 3.81 कर दिया है । जबकि हमारे यहां डॉक्टर्ज की बड़ी भारी कमी है । मेरे क्षेत्र भूना में 35 हजार से ऊपर की आबादी है । वहां पर मुख्यमंत्री जी की बुआ जी भी रहती है । मुख्यमंत्री जी रिश्तेदारी में ज्यादा विश्वास रखते हैं और वहां पर मुख्यमंत्री जी ने एक–दो बार नाईट स्टे भी किया है । इसी तरह से गांव भट्टू में हमारा सिविल होस्पीटल एक नर्स के भरोसे चलता है और भूना में एक डॉक्टर एम.बी.बी.एस. एनेस्थीसिया है और एक नर्स है । वहां पर भी स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए लेकिन कैप्टन साहब यदि हैल्थ के बजट में कुछ कटौती कर रहे हैं तो यह कैसे होगा ? इसी तरह से ट्रांसपोर्ट का है । सरकारी बसों में हमारी बहन–बेटियां सफर करती हैं तो वह अपने आप को सुरक्षित समझती हैं क्योंकि ड्राईवर–कंडैक्टर का करैक्टर लाईसैंस होता है, लेकिन अब इस विभाग को जो प्राईवेट करने की कोशिश की जा रही है वह नहीं होनी चाहिए । मुख्यमंत्री जी को इस विभाग को प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए । इसमें

अपने–अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर के रेट देकर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं । सरकार को ऐसा न करके सरकारी बसों की तरफ ध्यान देना चाहिए । ज्यादा से जयादा बसें खरीदनी चाहिए । सरकार बसें खरीदने के नाम पर कह रही है कि हम प्रयासरत हैं । वह प्रयासरत साढ़े चार साल में तो पूरे हुए नहीं अब 6 महीने में हो जाएं तो अच्छी बात है । इसी तरह पिछली बार के वर्ष 2018–19 के बजट में संशोधित अनुमानित लागत के लिए 70 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था जिसको अब घटकार 48 करोड़ रूपये कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में धनखड़ साहब से पूछा तथा कैप्टन साहब से भी पूछा कि यह कैसे संभव हुआ, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने का काम नहीं किया। इसी प्रकार मैंने सदन में अपने क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट हैडक्वॉर्टर पर नैशनल पोस्ट ग्रेजुएट कालेज बनाये जाने का प्रश्न लगाया था, पिछले सैशन में भी मैंने प्रश्न किया था और माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा इसके लिए हामी भरी गई थी। इस सत्र में भी उसी सेम प्रश्न का जवाब देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि भोढ़िया में कॉलेज शुरू कर दिया है और एम.ए. की क्लासिज शुरू कर दी गई हैं। वास्तव में यह एडिड कालेज है जिसको एम.एम. कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यहां पर बी.ए. में एडमिशन के लिए 12 हजार रूपये फीस लगती है जबकि सरकारी कॉलेज में यही एडमिशन फीस 3000 रूपये लगती है। मेरे प्रश्न को शायद मंत्री जी समझ नहीं पाये हैं अतः मैं पुन उनसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट हैडक्वॉर्टर पर एक नैशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोला जाये। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि इनके क्षेत्र भूना में सब सुविधाओं से युक्त एक बड़ा कॉलेज बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरियाः अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल डिस्ट्रिक्ट हैडक्वॉर्टर पर कॉलेज खोलने की बात कर रहा हूँ परन्तु अफसोस इस बात का है कि मेरे क्षेत्र के भोढ़िया व भूना की बात तो कर ली जाती है लेकिन मेरे फतेहाबाद जिले का नाम लेना तक किसी को गुरेज नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा जी फतेहाबाद का नाम लेने से बच रहे हैं इसी प्रकार कैप्टन साहब के बजट में एक बार भी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम तक नहीं लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, फतेहाबाद की जमीन बहुत ही उपजाऊ और कृषि योग्य भूमि है। यहां पर इतना अच्छा नैशनल हाइवे बन गया है कि हम अढ़ाई घंटे में दिल्ली जा सकते हैं। जिस

प्रकार से अभी दलाल साहब धान और कनक के फसल चक्र को अपनाने की बात कह रहे थे, उस परिपेक्ष्य में मैं सदन में कहना चाहूंगा कि अगर मेरे क्षेत्र में बागवानी जैसे फूल या सब्जी से संबंधित कोई रिसर्च सैंटर खुल जाता है तो यहां के लोगों को इसका बहुत फायदा होगा क्योंकि नैशनल हाईवे का प्रयोग करके वह सब्जी–फल–फूल व अन्य दूसरी चीजों को दिल्ली तक ले जाने में सक्षम हो सकेंगे जिससे उनकी आय दोगुना हो जायेगी। जहां तक भूना शुगर मिल की बात है, पुरानी सरकारों की बुरी नीयत की वजह से यह शुगर मिल बंद हो चुका है और जिसके लिए हमारे किसान धरना भी दे चुके हैं। फतेहाबाद, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का जिला भी है, अतः इस परिपेक्ष्य में मैं निवेदन करता हूँ कि सरकार को इस शुगर मिल को टेक ओवर करके, एजेंसी के माध्यम से इस शुगर मिल को दोबारा से चालू करवाने का काम करना चाहिए। इसी प्रकार सेमग्रस्त क्षेत्र के लिए सरकार की तरफ से कोई मास्टर प्लॉन बनाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से बार–बार कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा 24 फूट की खालों को 40 फूट की पक्की खालों में तब्दील किया जा रहा है। पिछले 6 महीने से इस तरह की बात सुनने को मिल रही है जबकि धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा निवेदन है कि इसकी स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है और यह किसानों की बड़ी जरूरी मांग भी है। जहां तक गऊंशालाओं की बात है, गौ– भक्त होने की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। माननीय हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रति गाँय को 15 रूपये डाइट दी जाये जिसके खिलाफ हुड्डा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का काम किया था और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि कोई राज्य गऊं के लिए डाइट निर्धारित करने के लिए बाध्य नहीं है। कोई भी प्रदेश गऊं डाइट देने या न देने के लिए स्वतंत्र है तो इस संबंध में मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि प्रति गऊं डाइट को 15 रूपये की बजाय 25 रूपये करने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, हम भागवत कथा सुनने के लिए कहां–कहां नहीं जाते और वहां जाकर 11000, 21000 तथा 51000 तक का दान कर देते है। आज गौंशालाओं की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है अगर इस तरह के दान गौंशालों के दिए जाए तो गौशालाएं आर्थिक तौर पर मजबूत हो जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, बड़ी अफसोस की बात है कि गौ–भक्त होने के तमाम प्रकार दावे किए जाते है, गांयों के संरक्षण के लिए तमाम प्रकार के गीत अलापे जा रहे है लेकिन जब इनके लिए कुछ देने का वक्त आता है तो खाली जेब दिखाने का काम किया जाता है। अध्यक्ष महोदय,

मेरा निवेदन है कि सरकार को इस दिशा में कड़ा संज्ञान लेते हुए काम करने की जरूरत है। धन्यवाद।

श्री उदय भान(एस.सी.)(होडल) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहूंगा। सदन में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी तथा शिक्षा मंत्री जी उपस्थित हैं, उनको याद होगा कि मैंने गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुए बताया था और आज फिर उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी की एक घोषणा न. 10 है जिसको 5 अप्रैल, 2016 को जब नितिन गड़करी जी के.एम.पी. का उद्घाटन करने आये थे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि हसनपुर–यमुना पुल बनवाया जायेगा। यही नहीं 9 अक्टूबर, 2016 को मुख्यमंत्री जी ने हसनपुर पहुंचकर फिर इस घोषणा को रिपीट करते हुए कहा था कि वे फाइल चलाकर आये हैं और जल्द ही हसनपुर में यमुना पुल बनाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इस पुल के लिए 3 बार लोगों ने आमरण अनशन किया है। अभी 15 दिन पहले ही यह आमरण अनशन खत्म हुआ है। हसनपुर में यमुना पुल बनाने की बहुत आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस संबंध में दो बार घोषणा भी कर आये हैं और इस घोषणा को आने वाली 5 अप्रैल की तारीख को तीन साल हो जायेगे लेकिन अभी तक इस पुल को बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि शीघ्र ही इसके ऊपर संज्ञान ले। अध्यक्ष महोदय, हसनपुर में गर्ल्स कॉलेज खोलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा नं0 15177 की थी लेकिन हसनपुर में जमीन न होने के कारण माननीय शिक्षा मंत्री जी ने तिगोड़ में कॉलेज खोलने की बात की थी। यह बात मैं दावे के साथ सदन में कह रहा हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि एक सप्ताह के अंदर तिगोड़ में गर्ल्स कॉलेज खोलने की शुरूआत कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, हम फरीदाबाद, पलवल और मेवात के विधायकगण के.जी.पी. ऐक्सप्रेस–वे पर एंट्री और एग्ज़िट प्वायंट के लिए माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी से मिले थे, वहां पर हसनपुर और यमुना पुल का भी जिक्र हुआ था लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ और न ही हमें यह पता है कि यह काम कब तक शुरू होगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा भवन, नई दिल्ली भी हम साथ में थे और मेरे साथ श्री जाकिर हुसैन जी व श्री दीपक मंगला जी भी थे, वहां माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि उदय भान जी जिस कॉलेज का जिक्र आपने किया था उसका काम एक सप्ताह में शुरू हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा

बार–बार आश्वासन देने के बाद भी आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई भी गर्ल्स कॉलेज नहीं है। पिंगोड़ से जो सरकार की 20 किलोमीटर के दायरे वाली कॉलेज की पॉलिसी है उसके मुताबिक कोई भी कॉलेज नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दे रखा है इसलिए इन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मार्केटिंग बोर्ड जो माननीय कृषि मंत्री जी के विभाग से संबंधित है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक बात कहना चाहता हूँ कि एक आर.ओ.बी. बालनी खेड़ा से हसनपुर बनना है और उस आर.ओ.बी. के कारण सारा का सारा ट्रैफिक मीतरौल से दीघोट वाली रोड पर हसनपुर जाने के लिए डायवर्ट हो गया है। मीतरौल से दीघोट तक रोड एच.एस.ए. एम.बी. के अंडर आती है। एच.एस.ए.एम.बी. की हालत यह है कि जितनी भी हमारी 5–6 रोड हैं वे सारी की सारी खस्ता हालत में हैं। एच.एस.ए.एम.बी. के रोड बनाने की क्वालिटी खराब है लेकिन पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क बनाने की क्वालिटी कुछ ठीक है। अध्यक्ष महोदय, विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रपोज़ल बनाकर सरकार को भेजा भी हुआ है, इसलिए मीतरौल से दीघोट रोड तुरंत बनाने की आवश्यकता है। तूमसरा से गुघराना होते हुए शोलाका और रेलवे स्टेशन तक वही स्थिति है। पिंगोड़ से कामरका का रोड पी.डब्ल्यू.डी. के अंडर है और कामरका से मीरपुर कौशली और घासेड़ा तक का रोड एच.एस.ए.एम.बी. के अंडर है। अध्यक्ष महोदय, एच.एस.ए.एम.बी. के रोड तो बिल्कुल खस्ता हालत में है और पी.डब्ल्यू.डी. के भी रोड संतोषजनक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह पूरा रोड पी.डब्ल्यू.डी. विभाग को ट्रांसफर करके बनाना चाहिए या फिर एच.एस.ए.एम.बी. दोबारा से रोड को बनाए क्योंकि इस रोड की हालत काफी खस्ता हालत में है। अध्यक्ष महोदय, गुलाबद से बछीपुरा रोड की भी यही हालत है। हसनपुर बाइपास जो सतुआगढ़ी से माहौली तक रोड जाता है उसकी भी यही हालत है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र होडल और हसनपुर में बिजली की हालत काफी खराब है। बिजली का लोड की वजह से अघोषित कट लगते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव भी है और इस बारे में एक प्रपोज़ल भी आई हुई है कि जो मीरपुर कुराली में 220 के.वी.ए. का सब–स्टेशन बन रहा है उसमें एक पच्चीस बाई तीस एम.वी.ए. का अलग से ट्रांसफार्मर और होडल में 66 के.वी.ए. का जो सब–स्टेशन है उसमें साढ़े बारह बाई सोलह एम.वी.ए. का अलग से ट्रांसफार्मर रखने से होडल और हसनपुर में बिजली की स्थिति सुधर सकती है। इसके अतिरिक्त दो गांवों गढ़ी पट्टी और बेड़ा पट्टी को

वर्ष 2015 से नगर परिषद, होडल में शामिल किया गया है । इससे पहले ये दोनों गांव ग्राम पंचायत थे । खेद है कि आज भी इन गांवों में गांवों जैसी ही सुविधा है। इनमें आज भी गांवों के हिसाब से बिजली दी जाती है । नगर परिषद के गांवों में बिजली, पानी, सीवर आदि की जो व्यवस्था होती है वह इन गांवो में नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : उदय भान जी, अब आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, अब मैं माननीय कृषि मंत्री जी से सिंचाई विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। हम यह बात हर सैशन में उठाते हैं कि हमारे इलाके में दिल्ली का प्रदूषित पानी आ रहा है। दिल्ली के 32 नाले यमुना नदी में गिरते हैं। उन नालों में सीवर का पानी, इंडस्ट्रीज का कैमिकलयुक्त पानी और बदबूदार गंदा पानी होता है। गुड़गांव कैनाल और आगरा कैनाल के माध्यम से यह पानी हमारे इलाके के अंडरग्राउंड वाटर को खराब कर रहा है। उस पानी के प्रयोग करने से लोगों में हड्डी रोग, पीलिया, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं । अतः वहां के पानी को ठीक करने के लिए सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए । सरकार को या तो दिल्ली सरकार को बाध्य करना चाहिए कि वह गंदे पानी को ट्रीट करके यमुना नदी में डाले या फिर गुड़गांव कैनाल और आगरा कैनाल में ट्रीटमैंट प्लांट लगाकर पानी की क्वालिटी को सुधारना चाहिए । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : उदय भान जी, आपको बोलते हुए काफी ज्यादा समय हो गया है । अतः अब आप वाइंड अप कर लीजिए ।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, हमारे हथीन रजबाहे से डारका माइनर और होडल रजबाहे से डकोरा माइनर एवं विजयगढ़ माइनर निकलती हैं । इनमें से किसी भी माइनर में टेल की बात तो दूर इनके हैड पर भी पानी नहीं है । अतः मेरा अनुरोध है कि इनमें पानी की व्यवस्था को सुधारा जाए । आपने मुझे बोलने के समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को एक जानकारी देना चाहूंगा । माननीय सदस्य करण सिंह दलाल जी ने जिस समय मुझसे यह जानकारी मांगी थी उस समय मेरे पास ऑथैंटिक जानकारी नहीं थी । मैं इस सदन को जानकारी दे रहा हूं कि हरियाणा में वर्ष 1966 में फौरेस्ट कवर 3.53 परसैंट था जो आज 26.02.2019 तक बढ़कर 6.79 परसैंट हो गया है ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है यह उसके मुकाबले में कम ही है ।

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, यह आंकड़ा कम हो सकता है लेकिन आपने ज्यादा ही कम बता दिया था ।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री कैप्टन साहब द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए ऐतिहासिक बजट पेश करने पर उन्हें बधाई देता हूं क्योंकि इस बजट में हर वर्ग के साथ धोखा किया गया है, हर वर्ग को परेशान किया गया है । यह एक ऐसा बजट है जिससे किसी भी वर्ग को राहत नहीं मिली है। मेरे विचार से ऐसा ऐतिहासिक बजट शायद हरियाणा में पहली बार पेश किया गया है । मैं अब हरियाणा के कर्मचारियों का जिक्र करना चाहूंगा जो इस बजट से काफी उम्मीद लगाए बैठे थे। उन्हें उम्मीद थी कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और सभी कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान दिया जाएगा। हरियाणा में डी.सी. रेट, आउटसॉर्स बेस पर काम करने वाले और सफाई करने वाले कर्मचारियों को उम्मीद थी उनको नियमित किया जाएगा । इस बजट में ऐसा कुछ नहीं किया गया । भाजपा के मैनीफैस्टो में उनको नियमित करने का वायदा किया गया था लेकिन वे कर्मचारी आज तक नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जगबीर सिंह जी, आप प्लीज, अपनी स्पीच शॉर्ट कर लीजिए ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एजुकेशन और हैल्थ सैक्टर में हरियाणा प्रदेश की स्थिति काफी खराब है । मेरा कहना है कि पिछले साढ़े चार साल के कार्यकाल में कोई किसी एक भी जिले का नाम बता दे जिसके किसी भी सरकारी स्कूल में सरकार ने टीचर्स की संख्या पूरी हो । मेरा कहना है कि आज के दिन 22 जिलों में से एक भी जिले में ऐसा नहीं है । इसी तरह से कोई 22 जिलों में से एक जिला बता दें जिसके सरकारी अस्पतालों में डॉक्ट्र्स की संख्या पूरी हो । यह सरकार अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में दोनों बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाई । इस तरह से यह सरकार लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाई । ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जो किसी भी स्टेट की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है । अगर मैं बी.पी.एस. महिला मैडिकल कॉलेज की बात करूं तो वहां पर इतना बुरा हाल है कि वहां पर इलाज के लिए समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं । वह मैडिकल कॉलेज अब एक रैफरल

सैंटर बनकर रह गया है । वहां पर आने वाले 80 परसैंट पेशेंट्स को पी.जी.आई., रोहतक रैफर किया जाता है । अधिकतर पेशेंट्स जब तक अपने घर से बी.पी.एस. महिला मैडिकल कॉलेज जाते हैं और फिर वहां से रैफर होकर पी.जी.आई., रोहतक पहुंचते हैं तब तक उनकी मौत हो चुकी होती है । इसके अलावा उस मैडिकल कॉलेज में जो टैक्नीकल स्टाफ है वह नियमित नहीं है । वह टैक्नीकल स्टाफ आउटसॉर्स पर काम कर रहा है । आउटसॉर्स के कर्मचारी से टैक्नीकल काम करवाना परमिशीबल नहीं है । उनको समय पर तनख्वाह नहीं दी जाती । मेरा कहना है कि जब बी.पी.एस. महिला मैडिकल कॉलेज का यह हाल है तो फिर प्रदेश के 22 जिलों में अन्य मैडिकल कॉलेज बनाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब तक सभी हॉस्पिटल्ज में पूरे डाक्टर्ज न हों तो यह तो सिर्फ डैथ ट्रैप ही होगा क्योंकि अगर हॉस्पिटल्ज में डाक्टर्ज ही नहीं हैं तो उन हॉस्टिल्ज में जाना तो अपनी मौत को बुलावा देना है। सरकार पिछले साढ़े 4 सालों से अधूरे काम करती आ रही है। सरकार ने आज तक कोई पूरा कार्य नहीं किया है उसमें चाहे आदर्श ग्राम योजना हो, स्वर्ण जंयती मनाने की बात हो या उदय योजना की बात हो। पिछली बार के बजट में उदय योजना के लिए 1500 करोड़ रूपये का प्रावधान था परन्तु उस राशि में से एक करोड़ रूपये भी खर्च नहीं हुए। सरकार को उन पैसों के बारे में भी बताना चाहिए। इस प्रकार से कागजों में योजनाएं बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। इस बजट में भी काफी योजनाएं बनायी गयी हैं परन्तु प्रैक्टिली कुछ भी नहीं है। सरकार ने जो प्लॉन का बजट रखा है उससे पिछली योजनाएं भी पूरी नहीं हो सकती तो अगली योजनाओं पर किस प्रकार से कार्य किया जाएगा ? इसलिए सरकार द्वारा सपने क्यों दिखाए जा रहे हैं ? सरकार ने कितनी स्मार्ट सिटीज बनायी हैं और कितने गांवों में वाई–फाई लगवाये हैं ? सरकार द्वारा प्रत्येक बजट में इस प्रकार की योजनाएं बनायी जाती हैं परन्तु उन योजनाओं पर काम कुछ नहीं होता है। हमारी सरकार के समय में IIIT किलोहडद में बनाने की घोषणा की गयी थी परन्तु वर्तमान सरकार द्वारा उसकी नींव भी नहीं भरी गयी है। सरकार ने इसको बनाने के लिए पिछले बजट में 128 करोड़ रूपये का प्रावधान किया था परन्तु इस बजट में उन पैसों को नामंजूर कर दिया गया है। यह सरकार का काम करने का तरीका है। सरकार कहती है कि प्रदेश को खुले से शौच मुक्त कर दिया है, आवारा पशुओं से फ्री कर दिया और स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मेरे पास दिसम्बर महीने की अखबारों की रिपोर्ट है जिसमें सभी क्षेत्रों का

बुरा हाल बताया गया है। सरकार द्वारा गरीब लोगों को घर देने की बात की गयी थी। आज तक प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 2500 घर बनाये गये हैं परन्तु सरकार द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत एक भी मकान एलॉट नहीं किया गया है। सरकार ने एक भी गरीब आदमी को मकान नही दिया है। इसके अलावा सरकार हर साल बजट में बागवानी का रकबा बढ़ाने की बात करती है परन्तु अभी तक बागवानी के रकबे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने की बात की जाती है परन्तु गांवों में दिन में डेढ घंटे ही बिजली आती है और रात के समय सिर्फ 5 घंटे ही बिजली आती है। सरकार ने जिन गांवों को 'हमारा गांव, जगमग गांव' योजना में शामिल कर रखा है उन गांवों में भी बिजली का बुरा हाल है। सरकार एस.वाई.एल. का पानी लाने की बात करती है और उसके लिए बजट भी रखा जाता है लेकिन हांसी–बुटाना ब्रांच के लिए कोई योजना नहीं है। इस ब्रांच के लिए सरकार द्वारा बजट रखना चाहिए क्योंकि यह ब्रांच पानी के सम्मान बंटवारे के लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के की बहुत सी दूसरी बाते भी बताना चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः जगबीर जी, प्लीज आप बैठ जाएं। आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा 'मनोहर ज्योति योजना' चलायी गयी है परन्तु इस योजना पर भी कोई काम नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अभी तो बहुत सी योजनाओं के बारे में भी बताना बाकी है।

श्री अध्यक्षः जगबीर जी, आपकी बातें तो बाकी हैं परन्तु टाईम की समस्या है। अभी दूसरे माननीय सदस्यों को भी बजट पर बोलना है।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं कोई नयी मांग नहीं रख रहा हूं। पिछली सरकार के समय में IIIT किलोहडद में बनाने की घोषणा की गयी थी, लाठ गांव में आई.एम.टी. बनायी जाए और गोहाना में वेस्टर्न बाई पास बनाया जाए। इन सभी कार्यों को पूरा कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त सरपंचों को विकास कार्य करवाने के लिए 2–2 करोड़ दिये जाएं तथा शहरों को 10–10 करोड़ रूपये दिये जाएं। इसके अतिरिक्त मेरी कोई नयी डिमांड नहीं है। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः जगबीर जी, आपकी बात कम्पलीट हो चुकी है। आप रिटन में दे दें, मैं आपकी बातों को सदन की कार्यवाही में शामिल करवा दूंगा। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में अंडर ग्राउंड वाटर खराब हो गया है जिसके कारण पीने के लिए भी पानी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मलिक जी, आप लिखकर दे दें मैं आपकी बातें सदन की कार्यवाही में शामिल करवा दूंगा।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मेरे गोहाना हल्के को जिला बनवाने के लिए तो सरकार ने मना कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जगबीर जी, आपको बोलते हुए बहुत समय हो चुका है। प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जगबीर जी, आप लिखकर दे दें। मैं आपकी बातों को सदन की कार्यवाही में शामिल करवा दूंगा। प्लीज, आप बैठ जाएं। जय प्रकाश जी आप जल्दी अपनी बात कम्पलीट करें।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरे गोहाना हल्के की कुछ बातें कहने से रह गयी हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इनको मैं सदन के पटल पर रख देता हूं। आप इनको प्रोसिडिंग्ज का पार्ट बनवा देना।

श्री अध्यक्षः ठीक है। मलिक जी, आप इनको सदन के पटल पर रख दें।

***श्री जगबीर सिंह मलिकः** अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की निम्नलिखित मांगों पर भी ध्यान दिया जाए।

गोहाना हल्के की मांगे

1. मेरे गोहाना हल्के को जिला बनाया जाए।
2. मेरे गोहाना हल्के का पश्चिमी बाईपास बनवाया जाए, जो पानीपत रोड वाया जीन्द रोड से रोहतक रोड को जोड़े।
3. मेरे गोहाना हल्के में बरोदा रोड पर आर0ओ0बी0 बनवाया जाए।
4. मेरे गोहाना हल्के के लाठ गांव में आई0एम0टी0 स्थापित की जाए।

.....

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त स्पीच को प्रोसिडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

5. मेरे गोहाना हल्के में टूरिस्ट्स कॉम्पलैक्स स्थापित किया जाए।

6. मेरे गोहाना हल्के के भठगांव व मोहाना गांवों में आई0टी0आई0 बनवाई जाएं।

7. मेरे गोहाना हल्के के किलोहडद गांव में आई.आई.आई.टी. की बिल्डिंग के लिए बजट दिया जाए।

8. मेरे गोहाना हल्के के सभी गांवों में लोहे के खंभो की जगह पर सीमेंट के खंभे लगाए जाएं।

9. मेरे गोहाना हल्के में लड़कियों के लिए कॉलेज बनवाया जाए।

जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग

1. मेरे हल्के के गामडी गांव में आधे गांव में पीने का पानी नहीं है। इसलिए वहां पर पानी की व्यवस्था करवायी जाए।

2. मेरे हल्के के तिहाड मलिक गांव में पीने का पानी नहीं है क्योंकि डिग्गी में पानी नहीं आता। इसलिए वहां पर पानी की व्यवस्था करवायी जाए।

3. मेरे हल्के के गुहणा गांव में नये टयूबवैल से गांव तक पानी की लाईन डलवायी जाए।

4. मेरे हल्के के महलाना गांव में टयूबवैल का पानी खराब है जिसके कारण पीने के पानी की समस्या पैदा हो गयी है, वहां पर पानी की व्यवस्था करवायी जाए।

5. मेरे हल्के के बडवासनी गांव के स्कूल में पीने का पानी नहीं है। इसलिए वहां पर पानी की व्यवस्था करवायी जाए।

6. मेरे हल्के के पिनाना गांव में पीने के पानी की समस्या है, वहां पर पानी की व्यवस्था करवायी जाए।

7. मेरे हल्के के जौली गांव में नये टयूबवैल्ज लगवाये जाएं।

पॉवर विभाग

1. मेरे हल्के के मोहाना गांव की झीमर बस्ती में खभें व केबल लगवाये जाएं।

2. मेरे हल्के के सलीमपुर टाली गांव में बिजली की लाईन मकानों के ऊपर से गुजर रही है, उस बिजली की लाईन को मकानों के ऊपर से हटवाया जाए।

3. मेरे हल्के के भठगांव गांव में लोहे के 50 पोल हैं, उनको बदलवाया जाए।

4. मेरे हल्के के महलाना गांव में बिजली के तार जर्जर हालत में हैं, उनको बदला जाए।

5. मेरे हल्के के चिटाना गांव में बिजली के तार जर्जर हालत में हैं, उनको बदला जाए।

6. मेरे हल्के के माहरा गांव में लोहे के खंभे हैं, उनको बदला जाए।

7. मेरे हल्के के पिनाना गांव में हरिजन बस्ती के ऊपर से एच.टी. लाईन गुजरती है, उस एच.टी. लाईन को हटवाया जाए।

8. मेरे हल्के के भटाना जाफराबाद गांव में लोहे के पोल लगे हुए हैं व बिजली के तार भी जर्जर हालत में हैं। इसलिए लोहे के पोल व बिजली के तार बदले जाएं।

नहर विभाग

1. मेरे हल्के के कैलाना खास गांव में रामगढ़ माईनर में पानी नहीं आ रहा है। इसलिए वहां पर पानी की व्यवस्था करवायी जाए।

2. मेरे हल्के के लाठ गांव में बी.एस.बी. नहर से पुरानी लाठ माईनर तक सोनीपत रोड के साथ–साथ रजबाहा मंजूर किया जाए। इसके अतिरिक्त वहां पर वॉटर लेवल ऊपर है। इसलिए वहां पर खारे पानी की निकासी ड्रेन में करने के लिए सरकारी टयूबवैल लगाया जाए।

3. मेरे हल्के के कासण्डा गांव के नहरी खालों को रिपेयर किया जाए।

4. मेरे हल्के के कासण्डी गांव के रजबाहा नं0 9 पर पुल बनवाया जाए।

5. मेरे हल्के के दोदवा से बोहला भैंसवाल डिस्ट्रीब्यूट्री पर पुल का निर्माण करवाया जाए।

6. मेरे हल्के के बीधल –जौली गांवों वाले रास्ते के रजबाहे पर बने पुल को चौड़ा करवाया जाए।

7. मेरे हल्के की गुहना माईनर में पानी नहीं आता है। इसलिए इस गुहना माईनर के लिए पानी की व्यवस्था करवायी जाए।

8 मेरे हल्के की नैना तातारनुर– मोहाना माईनर starting point में कच्ची है, इसको पक्का करवाया जाए।

9. मेरे हल्के के लुहारी टिब्बा गांव में बाढ़ के पानी की निकासी के लिए सरकारी टयूबवैल लगावाये जाएं।

10. मेरे हल्के के भठगांव– भदाना माईनर में टेल पर पानी नहीं पहुंचता है। इसलिए वहां पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था करवायी जाए।

11. मेरे हल्के की तिहाड कलां माईनर और भदाना माईनर में पानी नहीं आता है। इसलिए इन माईनर्ज के लिए पानी की व्यवस्था करवायी जाए।

12. मेरे हल्के की बागडू– भदाना माईनर पर मोगा नं0 1000/आर पर खाल टूटा हुआ है, इस खाल को 4 से 9 इंच चौड़ा करवाया जाए।

लोक निर्माण विभाग

1. मेरे हल्के के भटगांव धर्मशाला से खेडी दहिया वाया हसनपुर तिहाड कलां सड़क का निर्माण करवाया जाए।

2. मेरे हल्के के खानपुर कलां – शामडी– गुण्डलाना वाली सड़क को गांव के बाहर से बनवाया जाए।

3. मेरे हल्के के खेडी दमकन से जौली गांव तक सड़क बनवायी जाए।

4. मेरे हल्के के कासण्डी से शामडी गांव तक सड़क का निर्माण करवाया जाए।

5. मेरे हल्के के सलीमपुर माजरा– सोनीपत से फरमाना सड़क की मरम्मत करवायी जाए, यह सड़क बिल्कुल टूट चुकी है।

6. मेरे हल्के के सलीमपुर ट्राली से चटिया देवा गांव तक सड़क का निर्माण करवाया जाए।

7. मेरे हल्के के भठगांव– सोनीपत महलाना फरमाणा रोड की मरम्मत करवायी जाए।

8. मेरे हल्के के तिहाड खुर्द से तिहाड कलां तक सड़क मरम्मत करवायी जाए।

9. मेरे हल्के के बडवासनी से बुवाना नहर के साथ वाली सड़क की मरम्मत करवायी जाए, यह सड़क बिल्कुल टूट चुकी है।

10. मेरे हल्के के हुल्लाहेडी से रतनगढ़ माजरा गांव तक सड़क निर्माण करवाया जाए।

11. मेरे हल्के के माहरा से शहजादपुर गांव तक सड़क निर्माण करवाया जाए।

12. मेरे हल्के के जाजी से भठगांव तक सड़क निर्माण करवाया जाए।

13. मेरे हल्के के चिटाना से हुल्लाहेडी गांव तक सड़क निर्माण करवाया जाए।

14. मेरे हल्के के लुहारी टिब्बा से जाजी गांव तक सड़क का निर्माण करवाया जाए।

15. सोनीपत– जीन्द रेलवे लाईन पर जो रेलवे स्टेशन गांव से दुर स्थित है, उन सभी रेलवे स्टेशंज से गांवों तक सड़क निर्माण करवाया जाए।

16. सोनीपत– जीन्द रेलवे लाईन पर बने सभी अंडर ब्रिज से पानी की निकासी करवाई जाए और उनके ऊपर शैड लगवाई जाए ताकि इनमें पानी न भर सके।

शिक्षा विभाग

1. मेरे हल्के के चिटाना गांव के स्कूल को 10वीं से 12वीं में अपग्रेड किया जाए।

2. मेरे हल्के के भठगांव गांव में लड़कियों का कॉलेज बनवाया जाए।

स्वास्थ्य विभाग

1. मेरे हल्के के ककाना गांव में डिस्पैन्शरी बनवायी जाए।

2. मेरे हल्के के सिटावली गांव में आयुर्वेदिक डिस्पैन्शरी बनवायी जाए।

3. जौली– सब हैल्थ सेंटर का निर्माण करवाने बारे।

पशुपालन विभाग

1. मेरे हल्के के ककाना गांव में पशु अस्पताल बनवाया जाए।

2. मेरे हल्के के रोलद लतीफपुर गांव में पशु अस्पताल में स्टॉफ नहीं है, वहां पर स्टॉफ की नियुक्ति की जाए।

3. मेरे हल्के के बीधल गांव में पशु अस्पताल बनवाया जाए।

4. मेरे हल्के के करेवडी गांव में पशु अस्पताल बनवाया जाए।

5. मेरे हल्के के चिटाना गांव में पशु अस्पताल बनवाया जाए।

6. मेरे हल्के के जाजी गांव में पशु अस्पताल बनवाया जाए।

पंचायत विभाग

1. मेरे हल्के के खन्दराई गांव में गन्दे पानी की निकासी नहीं है। इसलिए वहां पर गन्दे पानी की निकासी का प्रबन्ध करवाया जाए।

2. मेरे हल्के के वजीरपुरा गांव की चौपाल का अधूरा कार्य पूरा करवाया जाए और इस गांव में गलियों की हालत खराब है, उनको दोबारा बनवाया जाए। इसके अतिरिक्त फिरनी की पैमाईश का कार्य पूरा करवाया जाए व गलियों को पक्की पक्का करवाया जाए।

3 मेरे हल्के के कैलाना खास गांव की गलियां टूटी हुई हैं, उनको दोबारा से बनवाया जाए।

4 मेरे हल्के के सैनीपुरा गांव में गन्दे पानी की निकासी नहीं हो रही है, इसलिए वहां पर गन्दे पानी की निकासी के लिए नाला बनवाया जाए।

5 मेरे हल्के के गामडी गांव की फिरनी अधूरी पड़ी है, उसको पूरा करवाया जाए। इसके अतिरिक्त गांव की कच्ची गलियों को पक्का बनवाया जाए।

6 मेरे हल्के के लाठ गांव के माजरे वाले रास्ते से बली वाले रास्ते तक फिरनी बनवायी जाए।

7 मेरे हल्के के दुभेटा गांव में गज्जूवाला तालाब की चार दिवारी का निर्माण करवाया जाए।

8 मेरे हल्के के कासण्डा गांव की छोटी चौपाल अधूरी पड़ी है, उसको पूरा करवाया जाए।

9 मेरे हल्के के जौली गांव के गर्ल्ज स्कूल से खानपुर रोड़ तक फिरनी बनवायी जाए। इसके अतिरिक्त जौली गांव के सरगथल वाले रास्ते पर तालाब की चार दिवारी सड़क के साथ–साथ बनवायी जाए।

10 मेरे हल्के के माजरी गांव के प्राईमरी स्कूल में गन्दे पानी की निकासी नहीं हो रही है। इसलिए वहां पर गन्दे पानी की निकासी करवाने का प्रबन्ध किया जाए।

11 मेरे हल्के के नैना तातारपुर गांव की फिरनी अधूरी है, उसको पूरा करवाया जाए।

12 मेरे हल्के के लुहारी टिब्बा गांव के तालाब की चार दिवारी व घाट निर्माण करवाया जाए।

13 मेरे हल्के के गढ़ी हकीकत से भठगांव गांव की तरफ फिरनी वाला रास्ता अधूरा है। इसको पूरा करवाया जाए।

14 मेरे हल्के के करेवडी गांव में चौक का लेवल नीचे है। इसलिए चौक का निर्माण करवाया जाए। इसके अतिरिक्त चौक के नाले की सफाई करवायी जाए।

15 मेरे हल्के के बडवासनी गांव में खेल स्टेडियम्ज मंजूर हो चुका है परन्तु निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसलिए वहां पर निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए।

16 मेरे हल्के के माहरा गांव के स्कूल तक रास्ता चौड़ा करवाया जाए।

17 मेरे हल्के के जाजी गांव के गन्दे पानी की निकासी नहीं हो रही है। इसलिए वहां पर गन्दे पानी की निकासी शुरू करवायी जाए।

खेल एवं युवा मामले विभाग

मेरे हल्के के मोहाना, सलारपुर माजरा, बडवासनी, गुहणा, बादशाहपुर माच्छरी, गामडी, दुभेटा, मोई व भादी गांवों में खेल स्टेडियम्ज का निर्माण करवाया जाए और जो खेल स्टेडियम्ज अधूरे हैं, उनका निर्माण कार्य पूरा करवाया जाए तथा उनमें कोच भी नियुक्त किये जाएं।

फिरनी

मेरे गोहाना हल्के के कई गांवों की फिरनी अधूरी पड़ी हैं जिनमें सरकार का काफी पैसा लगा हुआ है। इसलिए निम्नलिखित गांवों की फिरनी पूरी करवायी जाएंः– खंदराई, हसनगढ़, वजीरपुरा, गामडी, कासण्डा, ककाना भादरी, जौली, लुहारी टिब्बा, नैना तातारपुर, माजरा, बादशाहपुर माच्छरी, तिहाड खुर्द, महलाना, हुल्लाहेडी व खानपुर कलां।

चौपाल

मेरे गोहाना हल्के के जिन गांवों की चौपाल अधूरी पड़ी हैं, उनका निर्माण कार्य पूरा करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त मेरे गोहाना हल्के के मोहाना गांव को ब्लॉक का दर्जा दिया जाए ताकि आसपास के गांव के लोगों को सुविधाएं मिल सकें।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 लाख 32 हजार करोड़ रूपये का बजट पेश किया है यह बहुत अच्छा बजट बनाया। इसमें 4–5 बाते हैं। भारत सरकार द्वारा कुछ एरियाज को डार्क जोन क्षेत्र घोषित किया गया था।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजेंः ठीक है, सर।

श्री अध्यक्षः हाउस का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2019–2020 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर

श्री जय प्रकाश (कलायत): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजौंद ब्लॉक के गांवों को डार्क जोन घोषित किया हुआ है और डार्क जोन में नये ट्यूबवैल्ज के लिए बिजली के कनैक्शंज नहीं लगाये जा सकते। पिछले साल सरकार द्वारा फैसला लिया गया था कि जो ट्यूबवैल्ज लगे हुए हैं, उनका बिजली का लोड बढ़ाया जाएगा लेकिन आज एक वर्ष बीत जाने के बाद भी संबंधित ट्यूबवैल्ज का लोड नहीं बढ़ाया गया है और लोड न बढ़ाने के कारण लोगों को मजबूरन बिजली की चोरी करनी पड़ती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे हल्के के डार्क जोन क्षेत्र का लोड बढ़ाया जाए। दूसरी बात यह है कि हम विधान सभा के सभी माननीय सदस्य और अधिकारी/कर्मचारी एक ही छत के नीचे बैठकर काम करते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 लाख 32 हजार करोड़ रूपये का बजट पेश करके

20:00 बजे

पंजाब सरकार के बजट से मुकाबला कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पंजाब के विधान सभा के कर्मचारियों की तनख्वाह हमारे विधान सभा के कर्मचारियों से ज्यादा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा विधान सभा के कर्मचारियों को पंजाब विधान सभा के कर्मचारियों के बराबर तनख्वाह दी जाए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे विधान सभा में जो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, उनकी भी कोई प्रमोशन नहीं हो रही है और उनके साथ भी ज्यादती की जा रही है। यहां पर हमारे कई साथियों ने बिजली के बारे में बात कही है कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार पिछले 2 सालों से कह रही है कि वह चौसाला गांव में एक पावर हाउस बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो चौसाला गांव है वह धान का इलाका है और जब वहां पर धान की बिजाई और रोपाई का काम शुरू होता है तो वहां पर बिजली का कट लगाया जाता है, इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर एक पावर हाउस बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जखोली गांव में पंचायत ने आई.टी.आई. कॉलेज बनाने के लिए जमीन दी हुई है और जब नरबीर सिंह जी मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि अगर जमीन हमें मिल जाएगी तो हम वहां पर आई.टी.आई. कॉलेज बना देंगे, लेकिन पिछले तीन सालों से बजट में जखोली गांव में आई.टी.आई. कॉलेज खोलने का कोई प्रॉविजन नहीं रखा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर कर्मचारियों की भी बात कही गई है तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने ग्रुप–डी के कर्मचारियों को रखा है, यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैट्रिक और 10+2 पास वाले छात्रों के साथ ज्यादती की गई है और वे कह रहे हैं कि हम दोबारा मैट्रिक और 10+2 पास वाले छात्रों को भर्ती करवा देंगे। अगर उनकी भर्ती नहीं की गई तो नौजवानों में बड़ा रोष पैदा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आई.टी.आई. कॉलेजों में पिछले 8, 9 और 10 सालों से जो कर्मचारी इंस्ट्रक्टर के पद पर लगे हुए हैं, जो वर्तमान सरकार और कांग्रेस की सरकार में मैरिट के आधार पर लगे थे। अब उनको हटाने के लिए नोटिस दे दिया गया है। मेरे कहने का मतलब है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनको हटाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनको न हटाया जाए और उनकी जो भी योग्यता है, उसके आधार पर उनको पक्का किया जाए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना

चाहूंगा कि पिछले दिनों जो रोडवेज की हड़ताल हुई थी, उसमें रोडवेज के कई कर्मचारियों को हटा दिया गया था। वे बेचारे हमारे घरों के सामने हड़ताल पर बैठ जाते हैं और यह कहते हैं कि हमें सरकार ने पहले यह कहकर रखा था कि सरकार उनको पक्का करेगी और दूसरे कर्मचारियों से लड़ाई करवा दी और जिस दिन स्ट्राइक टूटी उनकी छुट्टी कर दी गई। दो सड़कों की घोषणा श्री नरबीर सिंह जी और कृषि मंत्री जी ने की थी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक सड़क सुजुम्म्मा से लाम्बाखेड़ी है, जिसके लिए मुख्यममंत्री जी ने घोषणा की थी, उसे बनाया जाएगा। लेकिन उसे न तो नरबीर सिंह जी बनवा रहे हैं और न ही कृषि मंत्री जी बनवा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सुजुम्मा से लाम्बाखेड़ी और कुराड से सिनद की सड़क जल्द से जल्द बनाई जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में बस यही एक बात कहना चाहूंगा कि आज हमारे जो एड्होक के टीचर हैं। उनकी सर्विस सिक्योरिटी के बारे में मैंने एक अखबार में पढ़ा था, उसको भी किल कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार अगर लोगों को नौकरी दे रही है तो हम सरकार का स्वागत करते हैं, लेकिन जो कर्मचारी पिछले 8, 9 और 10 वर्षों से पी.डब्ल्यू.डी., पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमैंट जैसे विभागों में सर्विस कर रहे थे, उनको सरकार ने हटा दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको दोबारा से सर्विस पर रखा जाए। वरना, सरकार के द्वारा 56 हजार नई नौकरियां देने का कोई फायदा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदंय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसलिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।

डॉ. पवन सैनी (लाडवा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सरकार का भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस विधान सभा को आप के जैसा अध्यक्ष दिया है। अध्यक्ष महोदय, आपने हर प्रकार से इस विधान सभा की गरिमा बढ़ाई है। अध्यक्ष महोदय, एक विधान सभा के अध्यक्ष की कैसी भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका को आपने यहां पर पेश करके एक मिसाल कायम की है। अध्यक्ष महोदय, हमने चांद में दाग सुना है, लेकिन मैं यह दावे के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे विधान सभा के अध्यक्ष में किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा प्रदेश के वित्त

मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी ने हवन–यज्ञ करके जो मनोहर बजट पेश किया है, उसकी केवल इस सदन के हमारे 30–35 माननीय सदस्यों को छोड़कर पूरे हरियाणा की जनता प्रशंसा कर रही है। इस सदन के हमारे जो 30–35 सदस्य हैं वे भी रात को इस बजट की प्रशंसा करते हैं। मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इनका नार्को टेस्ट किया जाएगा तो ये उसमें भी इस बजट की प्रशंसा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है, इसलिए मैं बजट के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के लाडवा में बहुत बड़ी जाम की समस्या रहती है, अगर आपको लगता है तो बेशक आप पता करवा सकते हैं । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका सर्वे करवाया है इसलिए जल्दी से जल्दी बाईपास शुरू करवाने का काम करे । मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरस्वती नदी और राक्षी नदी आती हैं । मैंने इन दोनों नदियों के बारे में पिछले बजट सत्र में सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि सरस्वती नदी में निरन्तर पानी का प्रवाह चलाने का काम किया जाये। इसके अलावा सोमनदी पर डैम बनाकर उसमें पानी चलाने का काम जल्दी से जल्दी शुरू करें और राक्षी नदी में भी जल प्रवाह के लिए बुबका हैड पर गेट लगाकर पानी छोड़ने का काम करें । अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सत्र के दौरान इसे मंजूर कर लिया गया था और वहां पर भी काम शुरू करवाने का काम करें । मेरे विधान सभा क्षेत्र में आलू व टमाटर की खेती बहुत होती है। यदि वहां पर इन फसलों से संबंधित प्रोसेसिंग यूनिट्स लग जाएं तो वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार के भी अवसर मिल सकते हैं। मेरा इस बारे में सरकार से निवेदन है कि इन फसलों पर आधारित प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने का काम करें। मेरे मथाना गांव में यू.एच.बी.वी.एन. (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम) का उपमंडल ऑपरेशन बनाने के लिए बिजली मंत्री जी ने पिछले बजट सत्र में मंजूर किया था इसलिए मथाना गांव में एक नया सब डिवीजन बनाने का काम करें क्योंकि पिपली में यू.एच. बी.वी.एन. का बहुत बड़ा सब डिवीजन है । अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ट्रॉमा सैंटर बनाने के लिए मंजूरी दी थी कि खानपुर कोलियां में प्राईमरी हैल्थ सैंटर में ट्रॉमा सैंटर जल्दी से शुरू करवाने का काम करे । गांव बिहोली में रोडवेज ड्राईविंग स्कूल के लिए हमारी पंचायत ने जमीन से रिलेटिड पूरे प्रोसैस को कंपलीट कर लिया गया है इसलिए रोडवेज ड्राईविंग स्कूल शुरू करवाने का काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी की सीएम अनाउंसमैंट में वेटरिनरी पॉली क्लीनिक बनाने का विचार किया गया था । इसकी भी प्रक्रिया फाईल से रिलेटिड कंपलीट

हो चुकी है, इसको भी शुरू करवाने का काम करे । अध्यक्ष महोदय, गावं रामसरण माजरा बावैन में शिक्षा मंत्री ने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बनाने की घोषणा की थी, इसकी फाईल का काम चल रहा है इसलिए गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज को बनाने का भी काम करें । मैं उम्मीद करता हूं कि वर्ष 2019–20 के बजट सत्र से ही गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की शुरूआत हो जायेगी । अध्यक्ष महोदय, मेरे लाडवा विधान सभा क्षेत्र को डार्कजोन घोषित किया गया है और डार्कजोन होने के कारण से किसानों को टयूबवैलों के लिए बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं । इस बात को लेकर वहां के किसान बहुत परेशान है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालकर लाडवा के किसानों को टयूबवैलों के लिए बिजली कनेक्शन देने का काम करें । अध्यक्ष महोदय, अम्बाला पुलिस रेंज में स्ट्रैंथ बहुत कम है लेकिन गुरूग्राम और रोहतक पुलिस रेंज की स्ट्रैंथ अधिक है । मान लो वहां का कांस्टेबल और अम्बाला का कांस्टेबल दोनों एक ही बैच के हैं । अम्बाला रेंज के कांस्टेबल की हवलदार तक की प्रमोशन नहीं होती है और गुरूग्राम और रोहतक रेंज के कांस्टेबल की एस.आई और ए.एस.आई. तक की प्रमोशन हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, आपका यमुनानगर क्षेत्र भी अम्बाला रेंज में आता है इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि इसकी सट्रैंथ बढ़ाने का काम करें । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अभी तक कांस्टेबल्ज की सैलरी में कोई इजाफा नहीं किया है लेकिन सरकार ने जिस तरह से होम गार्ड्ज और आंगनवाड़ी वर्कर्ज की सैलरी बढ़ाने का काम किया है उसी तरह से हमारे कांस्टेबल्ज़ की भी सैलरी बढ़ाने का काम करे । मैंने मिलिट्री अस्पताल बनाने के लिए भी डिमांड की थी, जैसे मिलिट्री वालों को मिलिट्री अस्पताल में सुविधाएं दी जाती हैं वैसे ही पुलिस वालों को भी पुलिस अस्पताल में सुविधाएं दी जानी चाहिए । यदि पुलिस अस्पताल नहीं बना सकते तो कम से कम एक पुलिस वार्ड के नाम से डिस्ट्रिक्ट सिविल अस्पताल बनाने का काम करें । इससे हमारे पुलिस कर्मचारियों को लाभ मिलेगा । इसी प्रकार जैसाकि सबको पता है कि एम.आई.टी.सी. बंद करके इसके कर्मचारियों को इरीगेशन डिपार्टमैंट में मर्ज कर दिया गया था, यह मर्ज हुए कर्मचारी जे.ई. या बड़े अधिकारी बनकर रिटायर हो चुके हैं लेकिन बावजूद इसके यह लोग अपनी पुरानी सैलरी और सर्विस बैनीफिट्स से वंचित ही रहे, इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उनको पूर्व की सर्विस के सभी सभी बैनीफिट्स देने का काम किया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक चौक है जिसके पास एक गवर्नमेंट स्कूल है उसकी

बिल्डिंग शिफ्ट होनी चाहिए उसकी फाईल प्रोसैस में है। वहां बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बनाने का काम करें । अध्यक्ष महोदय, लाडवा क्षेत्र राजा अजीत सिंह की नगरी के नाम से विख्यात है तो वहां पर राजा अजीत सिंह के नाम से स्मारक बनाने का काम करें । हमारे कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिक्षक/पैंशनर्ज़ जो रिटायर हो चुके हैं । मैं बताना चाहूंगा कि हमारा हरियाणा प्रदेश देश का पहला ऐसा प्रदेश है, जिसमें कर्मचारियों को सातवें पे कमीशन की सिफारिशों का लाभ दिया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिक्षक/पेंशनर्ज़ को भी सातवें पे कमीशन का लाभ देकर, आज तक जो उनका एरियर बनता है वह भी देने का काम करें । अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आचार्य को एम.ए. के इक्विलैंट और शास्त्री को बी.ए. के इक्विलैंट करने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, इसमें सीधी भर्ती के कारण उनकी पदोन्नति में दिक्कत आती है इसलिए इस प्रक्रिया में जो विसंगति है, उसको दुरूस्त करने का काम किया जाए । अध्यक्ष महोदय, हमारे जो पाल समाज से सम्बन्ध रखते हैं, उनको हरियाणा सरकार अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग में जो डी.सी. रेट पर कर्मचारी लगे हुए हैं, वे कर्मचारी आपके पास और हमारे पास हर रोज चक्कर काटते हैं । बिजली विभाग में मैन पावर कम होने के कारण ''म्हारा गांव जगमग गांव'' योजना को हर गावं तक इम्पलीमैंट करने में देरी हो रही है इसको जल्दी से जल्दी दुरूस्त करने का काम करें । अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने गेस्ट टीचर को दोबारा से रिइनस्टेट किया है । मैं कहना चाहता हूं कि गेस्ट टीचर की सैलरी तो अवश्य ही बढ़ाने का काम किया है लेकिन उनको पक्का करने का काम भी करें इसके साथ ही साथ हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल के जिन जवानों को इनैलो की सरकार ने नौकरी से निकाला था हमारी सरकार ने उनको ढूंढ–ढूंढ़ कर एस.पी.ओ. लगाया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ मेरा यह भी कहना है कि इनकी सैलरी को भी बढ़ाया जाये और उनको भी पक्का करने का कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाला जाये। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने जो नई भर्ती की है उन कर्मचारियों का हाउस रैंट बहुत कम है। इस भर्ती में जिन कर्मचारियों ने चण्ड़ीगढ़ में ड्यूटी ज्वाईन की है उनको यहां पर 6000/– रूपये में किराये पर कमरा मिल रहा है। उनकी सैलरी इस समय 20,000/– रूपये है। इस प्रकार से उसकी सैलरी का

अधिकतम हिस्सा मकान किराये में ही चला जाता है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि नवनियुक्त जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनका हाउस रैंट तीन से चार हजार रूपये करने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, जो कम्प्युटर टीचर्ज़ थे उनके साथ भी पिछली सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया था। हमारी सरकार ने लगभग 65 करोड़ रूपये की व्यवस्था करके कम्प्युटर टीचर्ज़ की लम्बे समय से रूकी हुई सैलरी 25,000/– रूपये प्रति महीने के हिसाब से दी। मेरा यह कहना है कि इन कम्प्युटर टीचर्ज़ की सैलरी को भी बढ़ाया जाये और उनको भी पक्का करने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकाला जाये।

श्री अध्यक्ष : पवन जी, अब आप बैठिए क्योंकि आपका समय समाप्त हो गया है।

डॉ. पवन सैनी : अध्यक्ष महोदय, मेरी कुछ बातें अभी कहने से रह गयी हैं इसलिए मेरा आप से नम्र निवेदन है कि मेरी इन बातों को सदन की कार्यवाही में जोड़ने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप लिखकर दें दीजिए उन्हें सदन की कार्यवाही में शामिल कर लिया जाएगा।

***डॉ. पवन सैनी :** स्पीकर सर, मेरी निम्नलिखित डिमाण्ड्ज़ को विधान सभा की कार्यवाही में शामिल करवाने की कृपा करें :–

1. लाडवा नगर में बाई–पास का सर्वे हो चुका है उसे बनवान की कृपा करें।

2. सरस्वती नदी पर पिछले विधान सभा के सत्र में इस नदी पर डैम बनाकर निरन्तर जल प्रवाह करने को मंजूरी दी थी। कृपया इसे जल्दी पूरा किया जाए।

3. राक्षी नदी में भी बुबका हैड पर गेट लगाकर जल प्रवाह करने को मंजूरी पिछले सत्र में सरकार ने दी थी। कृपया इसे जल्दी शुरु किया जाए।

4. लाडवा क्षेत्र में आलू व टमाटर की फसल बहुत होती है, इसलिए सरकार इस क्षेत्र में इन फसलों पर आधारित प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की कृपा करें।

5. मेरे विधान सभा क्षेत्र में बरोट रोड अथवा इन्द्री रोड पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की कृपा करें।

6. गावं मथान में U.H.B.V.N. का उपमण्डल बनाने की कृपा करें क्योंकि पिपली उपमण्डल बहुत बड़ा उपमण्डल बन गया जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जिसको सत्र में माननीय मंत्री ने स्वीकृति दी थी।

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनाया गया।**

7. प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र खानपुर कोलियां में ट्रामासेंटर को माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, ने मंजूर किया था। कृपया इसे शीघ्र बनाने की कृपा करें।

8. गांव बिहोली में रोडवेज ड्राइविंग स्कूल बनाने के गां की तरफ से सभी आवश्यकताएं अथाव कागजात विभाग को दिए हुये हैं, इसे शीघ्र बनवाएं।

9. वैटरनरी पॉली कलीनिक गांव बिहोली में मुख्यमंत्री घोषणा है, कृपया इसे शीघ्र बनवाने की कृपा करें।

10. राजकीय महिला महाविद्यालय गांव रामशरण माजरा, बाबैन में जो माननीय शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा द्वारा घोषणा की गई थी, उसकी फाइल विभाग के पास है, कृपया इसे शीघ्र बनवाया जाए, जिससे आगामी सत्र में महाविद्यालय प्रारम्भ हो सकें।

11. हरियाणा पुलिस की अम्बाला रेजं की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएं, जबकि रोहतक, गुरूग्राम रेज की स्ट्रेन्थ ज्यादा है। जिसके कारण अम्बाला रेंज के बैच के सिपाही दूसरी रेंज को सिपाही जल्दी पदोन्नत हो जाता है।

12. पुलिस कर्मचारियों का Salary Structure बढ़ाया जाए एवं जिला नागारिक हस्पताल में पुलिस बार्ड बनाया जाए।

13. लाडवा नगर जो कि राजा अजीत सिंह की रियासत थी कृपया इस नगर में इनके नाम से स्मारक बनाया जाए।

14. M.I.T.C. विभाग के बन्द होने पर जो कर्मचारी दूसरे विभाग में समायोजित किए थे उनको Service Benefit नहीं दिए गये, कृपया ये दिया जाए।

15. कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के सेवानिवृत कर्मचारियों को 7th पे कमीशन अनुसार एरियर दिया जाए।

16. आर्चाय को एम. ए., शास्त्री को बी.ए. कर्मचारियों को पदोन्नति में व इन्हें सीधा भर्ती में शामिल किया जाए।

17. हरियाणा सरकार पाल समाज को अनुसुचित जाति में शामिल करने की कृपा करे।

18. हरियाणा सरकार से प्रार्थना है कि गेस्ट टीचर को पक्का करने की कृपा करें।

19. हरियाणा सरकार से निवेदन कम्पयुटर टीचर की सैलरी बढ़ाने की कृपा करें। इन्हें पक्का किया जाए।

20. औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान जो हरियाणा पुलिस में एस.पी.ओ. के पद पर लगाए गए है। इनकी सैलरी बढ़ाई जाए।

21. हरियाणा सरकार द्वारा नवनियुक्त जो भी कर्मचारी होता है अथवा व्यक्ति जब भर्ती होता है तो उसका हाउस रेंट बहुत ही कम है, कृपया नवनियुक्त कर्मचारियों का हाउस रेंट कम से कम 3000 से 4000 किया जाए। धन्यवाद,

श्री ज्ञान चंद गुप्ता (पंचकुला) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद एवं बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं सर्वप्रथम आदरणीय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने कल सदन में ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह बजट हरियाणा के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री जी द्वारा जो 1,32,1656.99 करोड़ रूपये का जो बजट पेश किया गया मैं समझता हूं कि वह एक ऐतिहासिक बजट है जिसके अंदर हरियाणा प्रदेश के सभी वर्गों का ख्याल माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रखा गया है। चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह कर्मचारी हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह मजदूर हो, युवा हो या महिला हो, इन सभी को वित्त मंत्री जी ने कुछ न कुछ दिया है। जिस तरीके से सभी डिपार्टमैंट्स के बजट के अंदर इंक्रीज किया गया है। हैल्थ डिपार्टमैंट के अंदर 12 परसैंट बजट इंक्रीज हुआ है, टैक्नीकल एजुकेशन के अंदर 10 परसैंट बजट इंक्रीज हुआ है, हॉयर एजुकेशन के अंदर 17 परसैंट बजट इंक्रीज हुआ है, एलीमैंट्री एजुकेशन के अंदर 9 परसैंट बजट इंक्रीज हुआ है और इसी प्रकार से स्पोर्टस डिपार्टमैंट के अंदर 14 परसैंट बजट इंक्रीज हुआ है और टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट के अंदर 37.4 परसैंट बजट इंक्रीज हुआ है। इस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी ने सभी डिपार्टमैंट्स को अधिक से अधिक बजट दिया है ताकि आने वाले वर्ष के अंदर सभी डिपार्टमैंट्स और भी ज्यादा अच्छे ढ़ंग से काम कर सकें और अच्छी फैसिलिटीज़ प्रदेश की जनता को मिल सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां पर वर्ष 2019–20 का बजट प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष जी, जो 1500 करोड़ रूपया किसानों की पैंशन के लिए केन्द्रीय बजट में रखा गया था आज माननीय प्रधान मंत्री जी उसके आबंटन की प्रक्रिया की शुरूआत करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के गन्ना किसानों को 340/– रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का पूरे देश में सबसे ज्यादा भाव दिया है। यह हमारी सरकार के लिए किसानों के हित में किया गया बहुत बड़ा कार्य है। प्रधानमंत्री जी द्वारा भी फसल बीमा योजना, आयुष्मान योजना, पण्डित दीन दयाल पशुधन योजना और प्रधानमंत्री

किसान सम्मान निधि इत्यादि बहुत सी योजनाओं का एलान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है उनको 6000 रूपये वार्षिक की दर से पैंशन दी जायेगी। यह ऐतिहासिक योजना सर्वप्रथम हमारी सरकार लेकर आई है। मैं समझता हूं कि इस योजना से किसान के साथ ही साथ सभी वर्गों का फायदा होने वाला है। इसी प्रकार से केन्द्रीय बजट में माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा आय कर की सीमा को पांच लाख रूपये तक बढ़ाया गया है। मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री और आदरणीय केन्द्रीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। जो आय कर की सीमा बढ़ाई गई है उससे हर वर्ग और विशेषकर कर्मचारी वर्ग को उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसी प्रकार से जब अपने देश के अंदर जी.एस.टी. लागू किया गया था उस समय बहुत सारे लोगों द्वारा बहुत सारे भ्रम पैदा करने का काम किया गया था लेकिन जी.एस.टी. के अंदर पिछले एक साल के दौरान जितने सुधार किये गये हैं और जिस प्रकार से टैक्स के रेट्स को कम किया गया है उससे आज प्रत्येक व्यापारी यह महसूस करता है कि ईमानदारी से काम करने के लिए और ईमानदारी से व्यापार करने के लिए जी.एस.टी. से बढ़कर कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से ईज़ ऑफ डूईंग बिजनैस के अंदर हमारा प्रदेश आज 14वें स्थान से तीसरे स्थान पर आया है। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की व्यापारी वर्ग के लिए बनाई गई हितकारी नीतियों के कारण ही प्रदेश में व्यापारियों को व्यापार करने के लिए अनुकूल माहौल प्राप्त हुआ है। छोटे स्तर के जो रोजगार हैं जिनमें दस्तकार तथा शिल्पकार हैं उनको 20 किलोवाट तक बी. खण्डों के लोगों को 2 रुपये प्रति किलोवाट तथा ए.बी. खण्डों के लोगों को 10 किलोवाट तक कनैक्टिड भार पर 2 रुपये प्रति किलोवाट की जो सब्सिडी दी गई उससे उनको बहुत लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से आदरणीय वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री जी ने इंडस्ट्रीज के लिए जो कलस्टर स्कीम चालू की है उसके लागू होने से भी इंडस्ट्रीज में एक नया रिवोल्यूशन आयेगा। पंचकुला के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो सौगातें दी हैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। पंचकुला का सिविल हॉस्पिटल नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एण्ड हैल्थकेयर प्रोवाइड्र्स द्वारा मान्यता प्राप्त है और वह पूरे देश में नम्बर 1 पर आया है। इसी प्रकार से पंचकुला में सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क की घोषणा की गई है। 24x7 इमरजैंसी सर्विसिज के लिए स्टाफ पुलिस कंट्रोल रूम का कार्यालय पंचकुला

में बनने जा रहा है। इसी प्रकार से मोरनी में जो हर्बल पार्क की स्थापना का जिक्र बजट में किया गया है उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। पंचकुला से यमुनानगर तक फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य करवाया गया है जो कि 15–20 साल से पैंडिंग पड़ी योजना थी जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का आभार प्रकट करता हूं। केन्द्र सरकार की तरफ से पंचकुला में जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का शिलान्यास किया गया है उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने बजट में वित्तीय अनियमितताओं को कंट्रोल करने के लिए विभागों में जो ऑडिट का प्रावधान किया है उससे वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम लगेगी तथा विभागों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। इससे रेवेन्यू जनरेट करने में मदद मिलेगी। इससे पहले भी जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वह फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉसिबिलिटी तय करने से हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए भी कुछ करने की जरूरत है। उसके लिए कोई न कोई कमेटी बनाई जाये ताकि वर्किंग में पारदर्शिता आ सके और सरकार का जनता को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का वायदा पूरा हो सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास (रिवाड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात एक कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं।

चन्द्रमास्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय का करूं मैं दिल से सत्कार,
गरिमामयी इस महान सदन को नमन करूं मैं बारम्बार,
2019–20 का बजट पेश हुआ धमाकेदार।
हरियाणा एक हरियाणवी एक, जय हो मनोहर सरकार।

हम सबसे पहले पुलवामा के शहीदों को शीश झुकाते हैं,
कुटुम्बी रोये, जनता रोई, गुस्से में नैन भर आते हैं।
देश दुखी नम हैं आंखें, जीया भर–भर आता है,
ये कैसा धोखा हुआ जब सिंह का शिकार, श्यार कर जाता है,
राष्ट्राध्यक्ष ने पहली बार मर्दानी भाषा बोली है।

सेना को छूट दे दी सभी बंदिशें खोली हैं,

डरने की कोई बात नहीं खूब चलाओ गोली है,

मोदी जी की जय बोलो, मर्दानी भाषा बोली है।

पाकिस्तान को सबक सिखाने गडकरी ने जड़ा हथोड़ा है,

अब उसकी कमर तोड़ने को पानी का रुख मोड़ा है।

अब धारा 370 का भी निकलेगा कोई उपाय,

फिर सारा कलेश कट जायेगा, चिन्ता कोई रहेगी नाय,

पुनः नमन शहीदों को, जिन्होंने शहादत झेली है,

मोदी जी की जय बोलो मर्दानी भाषा बोली है।

गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 50 हजार नौकरियों की एक पोटली खोली है । मोदी जी की जय बोलो, मर्दानी भाषा बोली है ।

चौधरी मित्र सैन के लाल, बजट में किया कमाल ।
सभी वर्गों का रखा ख्याल, अब ऐसी मची धमाल ।
हरियाणा होगा मालामाल । हरियाणा होगा मालामाल ।
वीर सैनिक, अर्थ शास्त्री ने 1 लाख 32 हजार करोड़ का बजट बनाया है ।
कल्याणकारी, विकासोनुमुखी प्रस्ताव फरमाया है।
तूं भी सैनिक, मैं भी सैनिक हम दोनों हमजोली हैं ।
मोदी जी की जय बोलो, मर्दानी भाषा बोली है ।

ओ.पी. धनखड़ जी, तेरी लगन बड़ी उत्साही है।
किसानों की आमदनी दो गुणी बढ़ जा, इसी योजना बनाई है ।
बागवानी, गो संवर्धन ए–2 दूध की महता बताई है ।
अन्न दाता, उर्जा दाता, जोखिम फ्री नीति बनाई है ।
मोदी जी की जय बोलो, मर्दानी भाषा बोली है ।

सहकारिता विच मनीष ग्रोवर दा, परचम फहराया है ।
बजट विच 74 प्रतिशत दी बढ़ोतरी, नाल 1396 करोड़ फरमाया है ।

ऐसी लागी लगन, अनिल विज रहते मग्न,
वह तो स्वास्थ्य सुधार में ऐसे लगे,
63 हस्पताल दिए, 125 सामुहिक केन्द्र मिले,
वह आयुष सुविधा भी बढ़ाने लगे।
मनोहर दयालू बड़ा, दिया एम्स खुलवा,
वह तो मनेठी(रेवाड़ी) को चमकाने लगे,
बाढ़सा में एम्स कैंसर की भी शुरूआत हो ली है ।
मोदी जी की जय बोलो, मर्दानी भाषा बोली है ।

मुख्यमंत्री जी ने सबको साथ लिया, समान विकास किया ।
वह तो नौकरियों में धूम मचाने लगे,
मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, नहरों जीर्णोधार किया,
वर्षों बाद टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया ।

अब जनता की बारी है, तेरा उपकार चुकाएगी,
पुनः केन्द्र व हरियाणा में बी.जे.पी. को लाएगी ।
फसल मुआवजा दिया खूब, सेवा की हद हो ली है ।
मोदी जी की जय बोलो, मर्दानी भाषा बोली है ।

धाकड़ नेता राम बिलास शर्मा ने शिक्षा का स्तर बढ़ाया है ।
विश्व विद्यालय, महा विद्यालय खुलवा कर बढ़िया नाम कमाया है ।
शिक्षा में प्रति स्पर्धा का बीज बोकर उज्ज्वल भविष्य दिखाया है ।
भारत विश्व गुरू बने, ऐसा परचम फहराया है ।
खेल खिलाड़ी पदक पा रहे हैं, शिखर छूने का मन चाहा है।
अब शिक्षा में 12,307 करोड़ रुपये की पोटली खोली है ।
मोदी जी की जय बोलो, मर्दानी भाषा बोली है ।

लाडले भाई नरबीर सिंह ने चमत्कार दिखलाया है ।
गुणवता पर सडक बना, बढ़िया नाम कमाया है ।
आर.ओ.बी. तथा आर.यू.बी. का खूब निर्माण कराया है,
सडक बन रही जल्दी–जल्दी फर–फर, फरा फर,
मंजिल पर अब पहुंचे गाड़ी।
सर, सर, सर, सरा, सर, सर, सर,
कैप्टन अभिमन्यु ने बजट बढ़ा कर, भर दई इसकी झोली है ।
मोदी जी की जय बोलो, मर्दानी भाषा बोली है ।

कृष्ण जी की बजे बंसरी और ताल सुना दे न्यारी है,

परिवहन सेवा में, अब सुधार निरंतर जारी है।

कविता जैन और विपुल गोयल ने विकास की गंगा टोह ली है,

और मोदी जी की जय बोलो, मर्दानी भाषा बोली है।।

अध्यक्ष महोदय, जहां मोदी जी पहले 56 इंच की छाती बताते थे, आज के पाकिस्तान पर हमले के बाद उनकी छाती 65 इंच की हो गई है।

नायब सैनी, कर्णदेव, बेदी और बनवारी की टोली है,

और मोदी जी की जय बोलो, मर्दानी भाषा बोली है।

सभासदों का ध्यान धरूं और शीश नवां प्रणाम करूं,

विपक्षी का भी सत्कार करूं–सुझाव की राह टोह ली है।।

और मोदी जी की जय बोलो मर्दानी भाषा बोली है।।।

अजे भी बजट बनाना है–अब सबको हलको में जाना है,

और मोदी जी की जय बोलो–मिलके उन्हें जिताना है।

यह खुशी की हंसी ठिठोली है–मोदी जी की जय बोलो, मर्दानी भाषा बोली है।।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हलके की कुछ मांगों की चर्चा करना चाहूंगा जो इस प्रकार है। रेवाड़ी और धारूहेड़ा में नए बस स्टैंड का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाये। रेवाड़ी में पांच एकड़ में स्थित ब्वॉज कॉलेज के लिए 10 एकड़ जमीन देने का काम किया जाये। रेवाड़ी में जिला लाईब्रेरी बनाई जाये ताकि बच्चे यहां पर बैठकर अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकें। धारूहेड़ा को जल्द से जल्द ब्लॉक बनाया जाये जिसके लिए गांव मसानी में भवन उपलब्ध है। अच्छी हैल्थ भी लोगों के लिए बहुत जरूरी है अतः निवेदन है कि रेवाड़ी में 300 बैड क्षमता का हस्पताल बनाया जाये जिसके लिए 27 एकड़ भूमि उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त धारूहेड़ा में भी 50 बैड का हस्पताल बनाया जाये ताकि हमारे लोगों को समय पर इलाज सुलभ हो सके। अध्यक्ष महोदय, गर्मियों में रेवाड़ी में पीने के पानी की समस्या हो जाती है जिसके कारण वहां टैंकरों के द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है, इस समस्या के निदान के लिए गांव गोकलगढ़ की पंचायत अपनी जमीन देने के लिए तैयार है अतः वहां पर पानी स्टोरेज टैंक बनाने की व्यवस्था की जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके धन्यवाद करता हूँ और बजट का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्षः कुलवंत जी आपको पहले भी बोलने का मौका दिया गया था, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं अतः एक मिनट में अपनी बात रखिए।

श्री कुलवंत राम बाजीगरः अध्यक्ष महोदय, मैं व्हाट्स–अप देख रहा था जिसमें एक विडियो आया है जिसको बजट–2019 के संदर्भ में कैप्टन साहब के फोटो के साथ एक गाना दिखाया जा रहा है जिसके लफ्ज इस प्रकार है कि इस गंगा सी गवर्नमैंट के हृद्य से गुण गाउं मैं। इसी गाने से ओत प्रोत होकर मेरा भी मन है कि मैं भी गवर्नमैंट रूपी बहती गंगा के जल से अपने क्षेत्र के लिए एक बाल्टी जल की भर लूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के सीवन गांव की पंचायत अपनी पंचायती जीमन देने के लिए तैयार है अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि यहां पर जल्द से जल्द एक मैडिकल कॉलेज खोला जाये तथा गुहला चीका में एक बस डिपो बनाया जाये। धन्यवाद।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अगर सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 20 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए?

आवाजेंः ठीक है, जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, सदन का समय 20 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2019–20 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री जी वर्ष 2019–20 के बजट अनुमानों पर हुई चर्चा का उत्तर देंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, आपने सदन में बजट प्रस्तुत करने के बाद सभी माननीय सदस्यों के माध्यम से बजट के अनुमानों पर बहुत बढ़िया चर्चा करवाई हैं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का चाहे वे इस समय सदन में उपस्थित भी न हों उन्होंने बजट के प्रस्तावों पर टीका–टिप्पणी, सराहना और आलोचना भी की है। माननीय सदस्यों ने बजट को पढ़कर और समझ कर अपने सुझाव भी दिए हैं, हिदायत भी दी हैं, समझाने की भी कोशिश की हैं और कुछ माननीय सदस्यों ने भविष्य को लेकर अच्छे सुझाव भी दिए हैं, इस प्रकार से मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बजट के प्रस्तावों पर चर्चा के साथ–साथ अपने क्षेत्र की मांगों और समस्याओं या फिर अन्य विषयों से संबंधित बातें रखी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूँ कि जितने भी तमाम सुझाव और मांगें बजट को लेकर सदन के पटल पर आई हैं सरकार उन सभी बातों को संबंधित विभाग में भेजने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे आग्रह किया था कि आज डिमाण्ड्स के ऊपर चर्चा होकर वोटिंग की जाए, इस बात को आपने स्वीकार किया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बजट के ऊपर चर्चा बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं ज्यादा लम्बी चर्चा न करते हुए संक्षेप में जो मुख्य बिन्दु सदन के पटल पर आए हैं, आपकी अनुमति से केवल उन्हीं बातों का जवाब देना उचित समझता हूँ। माननीय सदस्यों ने मोटे तौर पर जो चिंता व्यक्त की है उसी का मैं पिछले 2–3 सालों से जवाब भी देता आ रहा हूँ, इसलिए माननीय सदस्यगण मेरे पिछले उत्तर को भी जरा देखे लें तो वही बातें निकल कर सामने आयेंगी। अध्यक्ष

महोदय, लेकिन जिन बातों का उत्तर रह गया है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि डॉ0 कादियान जी ने कहा था कि कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, कैग की रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है और प्रिंसिपल फाइनैंस एकाउण्ट्स की रिपोर्ट है वह तैयार हो गई है और सदन के पटल पर भी रख दी गई है। जैसे ही कैग की रिपोर्ट तैयार हो जायेगी वैसे ही वह रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रख दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, एक मुख्य चिंता माननीय सदस्यों की कर्जा को लेकर थी। पहली बात तो यह है कि हरियाणा प्रदेश का जो वित्तीय प्रबंधन का मॉडल है उसकी सराहना आज भी देश में हो रही है और उसे आदर्श माना जाता है। उसका कारण यह है कि एफ.आर.बी. एम. नॉर्म्ज में डैब्ट जी.एस.डी.पी. की रेशों में 25 प्रतिशत होना चाहिए था, हम उसकी मर्यादा में है और अच्छी स्थिति में है। फिस्कल डैफिसिट जो 3 प्रतिशत जी. एस.डी.पी. का होना चाहिए था, उससे कम ही है। अर्थात् उसकी मर्यादा में और अच्छी स्थिति में है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल ने भी इस बारे में चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि फिस्कल डैफिसिट 2.9 प्रतिशत है और यह आगे और निकल जायेगा, इसलिए यह बड़ी खतरनाक स्थिति में है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को भरोसा दिलाता हूँ कि इस प्रकार की नौबत नहीं आयेगी और यह भी खुशी की बात है कि हमारे अपने सवा चार साल के कार्यकाल में उदय का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसके अनुसार 26 हजार करोड़ रुपये का कर्जा सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है। यह बहुत ही साहसिक फैसला माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, जिस साल हमने यह फैसला किया था अगर सदन इसकी कल्पना करे और देखे कि हम जो सालाना कर्जा लेते हैं वह लगभग 16 हजार करोड़ रुपये का था लेकिन 26 हजार करोड़ रुपये का कर्जा अपने ऊपर लेने का मतलब डेढ़ साल से ज्यादा पीरियड का अतिरिक्त कर्जा लेना है। यह बहुत ही साहसिक फैसला लिया गया था। अध्यक्ष महोदय, इस अतिरिक्त कर्ज का परिणाम यह हुआ कि जो हमारे ऊपर महँगा कर्जा था उसको सस्ता कर्जा में बदल दिया गया। जो कर्जा बिजली कम्पनियों के ऊपर था, वह कर्जा उन कम्पनियों से उतार दिया गया। बिजली कम्पनियों पर जो सालाना ब्याज का खर्चा था वह उनके खाते से हट गया। सरकार के खाते में जो ब्याज आया वह पहले से कम आया। अध्यक्ष महोदय, उदय का बिजली कम्पनियों पर यह असर हुआ कि चारों बिजली कम्पनियां प्रॉफिट में

आई। इसके परिणाम से जब बिजली कम्पनियों की कीमत कम हुई तो हम रेगुलेटरी कमीशन में यह प्रस्ताव लेकर गए और उस घटी हुई कीमत का हवाला देकर आए। इस तरह से आम उपभोक्ताओं को जो बिजली की दरे पहले लगती थी उसको कम करवाने में कामयाबी हासिल की। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हरियाणा के इतिहास में पहली बार बिजली के दामों में कटौती हुई है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) यह सब हमारी सरकार में संभव हो पाया है । हमें एक सीमा मिली थी और कहा गया था कि 'उदय' को आप एफ.आर.बी.एम. के दायरे में रहकर लागू करेंगे और एक सीमा के बाद मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे । आज मैं खुशी से कह सकता हूं कि वर्ष 2019–20 के बजट प्रावधानों में हम 'उदय' को ऑब्जर्व करने के बाद भी फिस्कल डैफीसिट और डैट टू जी.एस.टी.पी. के रेश्यो की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं । हम उसकी सीमा में आ गये हैं । माननीय सदस्य करण सिंह दलाल जी ने कहा था कि 22 परसैंट डैट टू जी.एस.टी.पी. होना बड़ा खतरनाक है । मैं बताना चाहूंगा कि हम अब भी डैट टू जी.एस.टी.पी. 25 परसैंट की निर्धारित मर्यादा में हैं । इसको समझाने के लिए मैं अपने पड़ोसी राज्य पंजाब का उदाहरण दूंगा और यह उदाहरण सिर्फ एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से दिया जाएगा न कि किसी तरह की हीन भावना से । उनका डैट टू जी.एस.टी.पी. 42 परसैंट है और हमारा डैट टू जी.एस.टी.पी. 22 परसैंट है । हमारे प्रदेश की एक जिम्मेदार राज्य की पहचान है और हम उसे कायम रखे हुए हैं । जो फिस्कल डैफीसिट है यह 'उदय' के बाद और 'उदय' के बिना भी दोनों में जो वर्ष 2014–15 के बाद वर्ष 2015–16 में लिया उसमें वह 6.48 परसैंट तक चला गया था । भारत सरकार ने हमें उसकी इजाज़त दे दी थी । आज 'उदय' के इम्पैक्ट के बाद भी फिस्कल डैफीसिट जो हमने इस बार के बजट्री ऐस्टीमेट्स में दिया है वह घटकर 2.86 परसैंट पर आ गया है । अगर 'उदय' का इम्पैक्ट नहीं होता तो वह 2.95 परसैंट होता । मैं बताना चाहता हूं कि यह 26 हजार करोड़ रूपये का कर्ज हमारी सरकार ने नहीं लिया है बल्कि हमने इसमें 1 रूपये का भी कर्ज नहीं लिया है । यह कर्ज पिछली सरकार हम पर छोड़कर गई थी और मुझे हैरानी होती है कि हम यह बात पिछले 3 साल से कहते आ रहे हैं । इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों में इतना आत्मिक बल नहीं है, क्रेज ऑफ कन्विक्शन नहीं है कि वे कह सकें कि यह 26 हजार करोड़ रूपये का कर्ज हमारे समय का है और हम इस आंकड़े के बाद के कर्ज से आपकी तुलना करेंगे । यह बात आज तक इन्होंने नहीं कही है । अगर

इस कर्ज के बारे में ये बाहर मीडिया में कहें तो हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन ये लोग इस बात को हाउस में भी दोहराते रहते हैं । इनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए और मैं इतने बड़े नेताओं से इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूं कि वे अपने समय के लिए हुए कर्ज को स्वीकार करें । इन्होंने आज भी सदन में कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश का कर्ज दोगुना कर दिया है । मैं इनको आइना दिखाने के लिए एक उदाहरण देता हूं । हमने बजट के पेज नं. 12 पर 'बजट एट ए ग्लांस' पर एक चार्ट दिया हुआ है । इनके समय में डैट लायबिलिटी साल–दर–साल बढ़ती थी । वर्ष 2013–14 में कर्ज लेने की सालाना वृद्धि दर 19 परसैंट थी । अगर हम 'उदय' को छोड़ दें और इनकी सरकार के समय के लिए हुए कर्ज को उसमें जोड़ लें तो इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा कि वह कितनी थी । अब हमने इसको घटाकर 15.1 परसैंट तक लाने का काम किया है । चार्ट के माध्यम से ये स्वयं आइना देख सकते हैं कि किसने अच्छे तरीके से और जिम्मेवारी से काम किया है । हमने इसमें किसी एक साल का नहीं अपितु पांचों सालों का रिकॉर्ड दिया है । अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने एक और चार्ट दिया है जिसमें अंकित है कि पहले कर्जा लेने का क्या तरीका रहा और उसका कैसे इस्तेमाल होता रहा । वर्ष 2013–14 में जो कर्ज लिया गया था उसका कैपिटल एक्सपैंडीचर 48.9 परसैंट था और वर्ष 2014–15 में लिए हुए कर्ज का कैपिटल एक्सपैंडीचर 42.9 परसैंट था । यानि कि वर्ष 2014–15 में जो कर्ज लिया उसमें से निर्माण में (कैपिटल एक्सपैंडीचर में) जो खर्च किया वह 50 परसैंट से भी कम था । यानि कि पिछली सरकारें कर्ज को किन्हीं और चीजों में इस्तेमाल करती थी । वे उसका इस्तेमाल निर्माण में (कैपिटल एक्सपैंडीचर में) नहीं करते थे। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017–18 में जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका रिवाईज्ड एस्टिमेट और वर्ष 2018–19 के रिवाईज्ड एस्टिमेट में जितना कर्ज लिया गया है, उसका 101.6 प्रतिशत कैपिटल एक्सपैंडिचर में खर्चा किया है। यह बात उस कर्जे की तुलना में बतायी गयी है। यह 'उदय' का इम्पैक्ट है कि अगर पिछली सरकार के समय लिए हुए कर्जे का इम्पैक्ट नहीं होता तो आज वर्ष 2019–20 का 22.9 प्रतिशत और वर्ष 2018–19 का 22.2 प्रतिशत प्रोजैक्शन से घटकर 18.50 प्रतिशत और 19.50 प्रतिशत ही होता। इससे आदर्श स्थिति देश में शायद ही किसी दूसरे स्टेट में मिलेगी। डैट और फिस्कल डेफिसिट पर इतना कहना ही पर्याप्त होगा। माननीय सदस्यों के द्वारा एक चिन्ता की गयी है कि सरकार ने कृषि क्षेत्र में पैसा घटा दिया

है। मैं इसको थोड़ा–सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर एलाईड सैक्टर में टोटल एलोकेशन 4.47 प्रतिशत बढ़ती दिखाई देती है। इसमें आप देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर के कम्पोनैंट को घटाया है क्योंकि पिछले साल हॉर्टिकल्चर सैक्टर का जो कम्पोनैंट दिया था उसमें सैंट्रल योजनाओं के साथ कुछ पैसों का प्रॉवीजन किया था परन्तु केन्द्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में धन नहीं आने की वजह से योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो सका। इसलिए हमने योजना को रि–कलिब्रेशन किया है कि इस बार कितने पैसों की आवश्यकता है ? सरकार ने आवश्यकतानुसार पैसों को एकारडिंगली रि–एडजैस्ट किया है। मैं बताना चाहूंगा कि कॉ–आपरेशन सैक्टर में 74 प्रतिशत बजट इन्क्रीज किया है और 1396.21 करोड़ रूपये कॉ–आपरेशन सैक्टर में दिया है। इस अमाउंट का मेजर पोरशन शुगर मिल और शुगर केन फार्मर्ज को दिया गया है। इसके लिए एस.ए.पी. और एफ.आर.पी का डिफरैंस प्लान किया है, यह पैसा फार्मर्ज के लिए और एग्रीकल्चर एलाईड सैक्टर के लिए दिया जा रहा है। इसमें 74 प्रतिशत का इन्क्रीज है। पॉवर सैक्टर में जो आर.ई. सब्सिडी देते थे, उसमें से भी 6878.40 करोड़ रूपये की राशि कृषि के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस प्रकार से कृषि की कुल वृद्धि दर इन तीनों क्षेत्रों की अमाउंट को मिलाकर 11.37 प्रतिशत हो जाती है। हमने 1500 करोड़ रूपये का प्रावधान अलग से किया है। इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि प्रधान मंत्री 'कृषि समृद्ध योजना' की तर्ज पर लाभार्थियों को हरियाणा सरकार की तरफ से 6,000 रूपये के हिसाब से सालाना किसानों को दिये जाएंगे। इन 1500 करोड़ रूपये में से चाहे 800–900–1000 करोड़ रूपये या उससे अधिक ही खर्च होंगे, इससे कम पैसे खर्च नहीं होंगे। वह पैसा भी फार्मर्ज को एग्रीकल्चर और एलाईड सैक्टर के लिए दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, एग्रीकल्चर एलाईड सैक्टर और इन 4 चीजों को मिलाकर जो टोटल रेशो बनता है, उसको मुझे कल काउंट करने का मौका मिलता है तो मैं काउंट करके भी बताता। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि सरकार ने एलोकेशन को बढ़ाया है और किसी भी सूरत में घटाने का सवाल ही नहीं उठता। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि पिछली सरकारों के समय में क्या–क्या किया गया और परसेंटेज क्या थी ? यह लम्बी बात हो जाएगी। अध्यक्ष जी, केवल एलोकेशन बताने के लिए जो मेजर डिपार्टमैंट्स की चिन्ता की गयी है उसमें एजूकेशन डिपार्टमैंट के बारे में चिन्ता की गयी है कि एजूकेशन का बजट घटा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वर्ष 2013–14 के बजट में जी.डी.

पी. का (जिसको जी.एस.डी.पी. कहते हैं) 1.95 प्रतिशत एजूकेशन के लिए खर्च किया गया था। आज हमने लगातार हर साल उससे कहीं ज्यादा बढ़ाकर बजट रखा है और इस साल के बजट में जी.डी.पी. का 2.04 प्रतिशत एजूकेशन के लिए खर्च किया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर इरीगेशन व पब्लिक हैल्थ और हैल्थ सैक्टर की बात करूं तो वर्ष 2013–14 में हैल्थ सैक्टर के बजट का टोटल शेयर 3. 21 प्रतिशत था, हैल्थ सैक्टर का बजट वर्ष 2018–19 और वर्ष 2019–20 के दोनों वर्षों का 3.73 प्रतिशत और 3.81 प्रतिशत है, जो कि पिछली सरकारों के समय से अधिक है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हैल्थ सैक्टर का वर्ष 2018–2019 का कितना बजट है ?

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हैल्थ सैक्टर का वर्ष 2018– 2019 का रिवाईज्ड एस्टिमेट 3.73 प्रतिशत है और वर्ष 2019–20 में 3.81 प्रतिशत है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह बजट घटने का सवाल ही नहीं है बल्कि हमने परसेंटेज में भी इम्प्रूव किया है। माननीय सदस्य बजट के बारे में सपैसिफिक सवाल पूछेंगे तो मुझे उनके सवालों का जवाब देकर बड़ी खुशी होगी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम रेवेन्यू डेफिसिट को पिछले समय से लगातार रिवर्सल के ट्रेंड में लेकर आये हुए हैं और हमने इस साल भी प्रोजेक्शन की है कि हम रेवेन्यू डेफिसिट को 0.73 परसैंट तक लाने का प्रयास करेंगे। इफैक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को हमने वर्ष 2019–20 के लिए टारगेट किया है और जो रेवेन्यू डेफिसिट वर्ष 2014–15 में 1.90 परसैंट था, उसको हमने वर्ष 2018–19 में 1.20 परसैंट रेवेन्यू डेफिसिट पर लाकर खड़ा किया है और एक इफैक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एक पैरामीटर है जो ज्यादा बेहतर पैरामीटर है, उसको हमने 0.53 परसैंट पर लेकर आने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से कुल मिलाकर हर फिस्कल पैरामीटर पर हरियाणा की जो वित्तीय स्थिति है, वह कहीं ज्यादा अच्छी और बेहतर है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के साथियों का और अधिक समय न लेते हुए, मैंने केवल मोटी–मोटी बातों का ही जवाब देने की कोशिश की है। मैं आप सभी लोगों को यह भरोसा दिलाते हुए कहना चाहूंगा कि जिस किसी भी प्रकार से सरकार के काम के लिए जो भी आवश्यक काम हुआ, हमने उसे किया है। आज हमारे हरियाणा सरकार के अंदर कर्मचारियों को जो सैलरी और पेंशन दी जाती है, जो वर्ष 2013–14 और वर्ष 2014–15 में 15,400

करोड़ रुपए सालाना थी, वह अब 30,900 करोड़ रुपए यानी डबल हो गई है। जो पहले कर्मचारियों को 1000 रुपए पेंशन दी जाती थी, उसे 2000 रुपए कर दी गई है यानी डबल कर दी गई है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सांतवे वेतन आयोग का असर तो सैलरी और पेंशन पर पड़ ही गया है। किसान वर्ग, दस्तकार वर्ग और शिल्पकार वर्ग के लिए हर प्रकार के समाज कल्याण, लोक कल्याण और जन कल्याण के लिए जो भी आवश्यकता हुई है, उसके लिए हरियाणा की जनता ने अपने खजाने में खूब कांन्ट्रिब्यूट किया और इसके लिए मैं हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और सदन के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं और इसके साथ ही साथ मैं डिप्टी स्पीकर मैडम का भी आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही साथ में इस सदन के पटल पर रिकॉर्ड के लिए लाना चाहूंगा कि ये बजट केवल वित्त मंत्री ने नहीं बनाया है, बल्कि इस बजट को बनाने में सभी विभागों के मंत्रियों ने अपने–अपने स्तर पर अपनी–अपनी भूमिका निभाई है। इस बजट को बनाने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों ने रात–दिन कार्य किया। मैं इस सदन से उन सभी अधिकारियों के लिए शाबाशी चाहूंगा, जिन्होंने इस बजट को बनाने में रात–दिन अपनी भूमिका निभाने का काम किया है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस बजट को बनाने में महिला कर्मचारियों ने 12:00, 1:00 और 2:00 बजे रात तक बैठकर इस बजट को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। (मेजें थप–थपाई गईं) अध्यक्ष महोदय, मैं आप सभी को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ रहा है तो इसके बावजूद सरकार के ऊपर कर्ज का बोझ क्यों बढ़ रहा है ?

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम माननीय सदस्य डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान जी को बताना चाहूंगा कि फिस्कल डेफिसिट 3 परसैंट की जी.एस.टी.पी. की मर्यादा में रखना जरूरी है। अगर मैं इनको आंकड़ों में लेकर जाऊं तो बताना चाहूंगा कि इस साल हमने लगभग 20,000 करोड़ रुपए पिछले लोन और ब्याज को चुकाने में लगाया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं अभी आंकड़ा अच्छी तरह से ढूंढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमने इस साल लगभग साढ़े 13,000 करोड़ रुपए पिछली सरकारों का लिया कर्जा चुकाने का काम किया है।(मेजें थप–थपाई गईं) और उसके ऊपर लगभग 6,700 करोड़ रुपए

का ब्याज की जो लाइबिलिटी है, जिसमें 'उदय' भी शामिल है, हमने उसको चुकाने का काम किया है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इनकी सरकार ने वर्ष 2018–19 में इंट्रेस्ट अमाउंट 11,961 करोड़ रुपए और प्रिंसिपल अमाउंट 6,938 करोड़ रुपए की पेमेंट की थी। इस तरह से सरकार ने टोटल कर्जे की पेमेंट 18,299 करोड़ रुपए ही की है।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि मेरे पास अभी वह कागज नहीं है, ज्यों ही वह कागज मेरे पास आएगा मैं इनको सारी डिटेल बता दूंगा।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे पास वह कागज है और मैं इनको वह कागज देना चाहूंगा।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमने वर्ष 2018–19 के अंदर रि–पेमेंट ऑफ पब्लिक डेट 17,596.31 करोड़ रुपए का पे किया था और इंट्रेस्ट 13,846.56 करोड़ रुपए का पे किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि यह जो 17,596.31 करोड़ रुपए डेट की पेमेंट है, यह हमारी सरकार के समय का लिया हुआ कर्जा नहीं है, बल्कि यह वह कर्जा है, जिसे हमने चुकाने का काम किया है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए?

आवाजें : ठीक है, जी ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2019–2020 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डॉ. कादियान जी का सवाल है कि फिस्कल डैफिसिट पर जब आप चैक रख रहे हो तो कर्जा क्यों बढ़ रहा है ? कर्जा तो एक डिवैल्पमैंट इकॉनोमी का एक मूल सिद्धांत है । अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग यहां पर बैठे हैं । हम लोगों ने किसी स्कूल में पढ़ाई की होगी, किसी कॉलेज में पढ़ाई की होगी, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की होगी, किसी अस्पताल में

इलाज करवाया होगा, किसी सड़क पर पैदल या गाड़ी लेकर चले होंगे, किसी पुल से होकर गुजरे होंगे या हम लोगों ने किसी बस या ट्रेन की सुविधा इस्तेमाल की होंगी, अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों का एक ही मतलब बनता है कि हमारे पूर्वजों ने पहले कर्जा लेकर ही हमारे लिए ये सारी सुविधाएं बनाईं और इन सभी सुविधाओं का लाभ लेकर हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है। जिसके परिणाम में हम पूर्वजों के लिए हुए कर्जे को चुका पाने में सफल भी हो रहे हैं और तभी यह सारा सोशल इकॉनामिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है । अध्यक्ष महोदय, मर्यादा यह कहती है कि किसी व्यक्ति को लोन इतना लेना चाहिए कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां उस कर्ज को चुका देने में सक्षम हो इसलिए सीलिंग रखी जाती है कि इससे ज्यादा लोन न लिया जाये । हम जो अतिरिक्त कार्य करते हैं जिसके लिए कर्जा लेना होता है उसके कारण से फिसकल डेफिसिट होता है । अध्यक्ष महोदय, जो जी.एस. डी.पी. वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 में मिली थी तथा जो आज की यानि वर्ष 2019–20 की जी.एस.डी.पी. प्रोजैक्ट्ड है, वह लगभग प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद दुगुनी है, जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और उसी कारण से ही हमारी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ी है । खर्चा बढ़ने के कारण कर्ज लेने की आवयकता भी बढ़ी है । अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता यह है कि जब भविष्य की पीढ़ियां लोन लेती हैं तो वे तय शुदा मर्यादा में रहकर ही लोन लें । हरियाणा प्रदेश आज जिस मुकाम पर खड़ा है, उस मुकाम से हरियाणा प्रदेश और आगे बढ़ने का काम करेगा।

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2019–20 में जो बजट पेश किया है, उसमें 16632 करोड़ रुपये इन्ट्रस्ट पेमैंट हैं और 20257 करोड़ रुपये प्रिंसीपल पेमैंट हैं । इन दोनों को मिलाकर 36889 करोड़ रुपये बनते हैं जोकि लगभग 28 प्रतिशत बनता है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पहले का लिया गया कर्जा तो पे कर दिया गया तो दोबारा से कर्जा क्यों बढ़ गया?

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, कुछ तो कर्जा बढ़ेगा।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, जो कर्जा बचा हुआ है उसमें से तो उसको रि–पे करना ही पड़ेगा । मैं माननीय सदस्य का प्रश्न समझ नहीं पाया हूं । मेरे कहने का मतलब यही है कि जो कर्जा बचा हुआ है उस कर्जे को पहले पे करना ही पड़ेगा।

वर्ष 2019–2020 के लिए बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2019–20 के लिए बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा ।

पिछली प्रथानुसार और सदन का समय बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्ज एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जायेंगी ।

कि राजस्व खर्च के लिए 78,70,01,000/-से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **1–विधान सभा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 160,53,02,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **2–राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 313,42,01,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **3–सामान्य प्रशासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1431,07,12,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **4–राजस्व** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 222,71,01,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **5–आबकारी व कराधान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 10584,69,21,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **6–वित्त** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 52,30,11,000/- से तथा पूंजीगत खर्च के लिए 409,28,01,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **7–आयोजना तथा सांख्यिकी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1145,32,76,000/- से तथा पूंजीगत खर्च के लिए 4008,63,52,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **8–भवन तथा सड़कें** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 13941,97,51,000/- से तथा पूंजीगत खर्च के लिए 100,00,01,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **9–शिक्षा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 482,72,00,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **10–तकनीकी शिक्षा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 382,94,02,000/- से तथा पूंजीगत खर्च के लिए 50,00,01,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **11–खेलकूद तथा युवा कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में

वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी ।

कि राजस्व खर्च के लिए 38,42,00,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **12–कला एवं संस्कृति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 4392,73,37,000/- से तथा पूंजीगत खर्च के लिए 474,36,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **13–स्वास्थ्य** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 583,02,01,000/- से तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1300,00,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **14–नगर विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेगीं।

कि राजस्व खर्च के लिए 4021,68,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **15–स्थानीय शासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेगीं।

कि राजस्व खर्च के लिए 54,58,01,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1,00,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **16–श्रम** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेगीं।

कि राजस्व खर्च के लिए 360,20,27,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **17–रोजगार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 519,12,42,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 75,93,27,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **18–औद्योगिक प्रशिक्षण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 508,80,70,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 7,60,21,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **19–अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 6663,29,96,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 18,92,01,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **20–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1352,87,70,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 144,10,01,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये

जो मांग संख्या **21—महिला तथा बाल विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 242,02,00,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **22—भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 430,83,57,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिये 13596,40,49,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या —**23—खाद्य एवं पूर्ति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी ।

कि राजस्व खर्च के लिए 1724,65,03,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1549,93,74,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **24—सिंचाई** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 325,06,01,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 15,01,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **25—उद्योग** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 130,15,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **26—खान एवं भू—विज्ञान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 2721,80,28,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **27—कृषि** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 1006,48,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 20,00,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **28—पशुपालन तथा डेरी विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 73,25,99,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **29—मछली पालन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 505,63,95,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **30—वन तथा वन्य प्राणी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 13,09,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **31—परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 4898,60,02,000/- से तथा पूंजीगत खर्च के लिए 300,00,02,000/- अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **32—ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए राजस्व खर्च के लिए 332,00,49,000/- से तथा पूंजीगत खर्च के लिए 154,90,01,000/- अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **33—सहकारिता** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 2387,01,60,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 297,11,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **34—परिवहन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 9,12,01,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 39,40,01,000/-से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **35—पर्यटन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 4663,39,01,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 410,00,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **36—गृह** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 175,63,91,000 /- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **37—निर्वाचन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 2136,73,46,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1470,58,26,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **38—लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 186,10,01,000/- से तथा पूंजीगत खर्च के लिए 50,00,01,000/- अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **39—सूचना तथा प्रचार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 7366,92,49,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 5857,69,04,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **40—ऊर्जा तथा विद्युत** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 152,74,51,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **41—इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 870,31,62,000 /- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **42—न्याय प्रशासन** के अधीन

व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव करेंगे कि राजस्व खर्च के लिए 277,27,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **43–कारागार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 39,18,45,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1,50,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **44–मुद्रण तथा लेखन सामग्री** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि पूंजीगत खर्च के लिए 1407,27,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **45–राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री करण सिंह दलाल, विधायक ने डिमांड्ज नम्बर 3, 14, 24, 31 व 40 पर तथा श्री कुलदीप शर्मा, विधायक ने डिमांड्ज नम्बर 13, 27, 34 व 40 पर कटौती प्रस्ताव दिए हैं । माननीय सदस्यगण, किसी भी डिमांड पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड का नंबर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं ।

डिमांड नम्बर 3

1. श्री करण सिंह दलाल

डिमांड नम्बर 13

1. श्री कुलदीप शर्मा

डिमांड नम्बर 14

1. श्री करण सिंह दलाल

डिमांड नम्बर 24

1. श्री करण सिंह दलाल

डिमांड नम्बर 27

1. श्री कुलदीप शर्मा

डिमांड नम्बर 31

1. श्री करण सिंह दलाल

डिमांड नम्बर 34

1. श्री कुलदीप शर्मा

डिमांड नम्बर 40

1. श्री करण सिंह दलाल
2. श्री कुलदीप शर्मा

यह सब कटौती प्रस्ताव पढ़े हुए तथा पेश किए हुए समझे जाएंगे लेकिन ये कटौती प्रस्ताव सदन में मतदान के लिए उस समय रखे जाएंगे जब विभाग की डिमांड सदन में मतदान के लिए रखी जाएंगी ।

अब मैं श्री करण सिंह दलाल को बोलने की अनुमति देता हूं ।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कईं डिमांड्स के ऊपर कट मोशन दिये है, मैं डिमांड नम्बर 3 पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोलना चाहूंगा। जितने जिला मुख्यालय या सब डिवीजन लैवल पर या कहीं भी जो सरकारी भवन बने हुए हैं, उन भवनों को बनाने का काम पी.डब्ल्यू.डी. करता है । सरकारी भवन में बिजली मुहैया कराना, पानी की उचित व्यवस्था कराना, पेंट कराना और उसका रखरखाव कराना आदि कार्य अलग–अलग डिपार्टमेंट्स के अंडर आते हैं । इसका नतीजा यह है कि जितने भी सरकारी भवन डिस्क्ट्रिट हैड क्वार्टर या कहीं भी बने हुए हैं, इन डिपार्टमेंट्स में आपसी अंतर कलह की वजह से जैसे ही वे सरकारी भवन बनते हैं तो सरकार का बहुत पैसा लगता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि उन सरकारी भवनों की मरम्मत करने या देखभाल करने के लिए एक डिपार्टमैंट की जिम्मेवारी नहीं होती है इसलिए उनके ऊपर कोई जिम्मेवार अधिकारी नहीं है जो सभी को मैनेज कर सके । अध्यक्ष महोदय, सरकारी भवनों का बहुत बुरा हाल होता जा रहा है । उसके बारे में सरकार को कोई न कोई पॉलिसी बनानी चाहिए । डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पलवल जिले में एन.एच.–2 का सिक्स लेन का काम चल रहा है, उसको साढ़े चार साल हो चुके हैं, अभी तक पलवल शहर में पूल का निर्माण नहीं हो पाया है तो इसके रास्ते में गांव भगोला और पृथला पड़ते हैं वहां इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं और वाहनों की आवाजाही बहुत अधिक होने के कारण जाम की स्थिति बन जाती है। जो कम्पनी एन.एच.–2 सड़क बनाने जा रही है, अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है। इस रोड को जो कम्पनी बना रही है उसने बिना सड़क के काम को कम्पलीट किये पृथला गांव के

पास टोल लगाने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। अगर वहां पर यह टोल बैरियर लग जाता है तो सड़क का काम पूरा न होने की वजह से वहां पर हर वक्त ट्रैफिक जाम लगा रहेगा इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि उस कांट्रैक्टर के साथ सरकार को यह बात करनी चाहिए कि जब तक उस रोड पर आने वाले सभी गांवों के ऊपर फ्लाई ओवर नहीं बनते हैं और दूसरी सभी रूकावटों को भी दूर नहीं किया जाता है तब तक वहां उस रोड पर टोल कलैक्शन का काम शुरू नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष जी, मेरा आर्म लाईसैंस के बारे में मैं यह कहना है कि डिप्टी कमिश्नर नये आर्म लाईसैंस तो बनाते ही नहीं है अपितु जिनको अपना आर्म लाईसैंस रिन्यू करवाना होता है उसको भी दर–दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। खेतों में रहने वाले लोगों को या जिनको आर्म लाईसैंस की वजह से नौकरी मिली हुई है उनके आर्म लाईसैंस को रिन्यू करने का कोई न कोई सैट कानून होना चाहिए जिससे अगर कोई एप्लीकैंट अपना आर्म लाईसैंस रिन्यू करवाने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाता है तो within a stipulated time उनके आर्म लाईसैंस को रिन्यू करवाने की दरख्वास्त को मंजूर करके उनके आर्म लाईसैंस का रिन्युअल होना चाहिए। अध्यक्ष जी, प्रदेश में नये आर्म लाईसैंस बनाने में रिश्वत का बहुत ही ज्यादा बोलबाला है। आर्म लाईसैंस को बनाने में बहुत बड़े–बड़े घोटाले हो रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आर्म लाईसैंस को बनाने और रिन्यू करने की प्रक्रिया को न्यायसंगत बनाना चाहिए और इस मामले को सरकार से गम्भीरता के विचार करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे प्रदेश के नौजवानों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। स्पीकर सर, इसी तरह से मैंने पॉवर डिपार्टमैंट से रिलेटिड भी कट मोशन दिया है। मेरा कैप्टन अभिमन्यु जी से भी मेरा निवेदन है कि बजट स्पीच में इन्होंने जो ट्यूबवैल्ज़ हैं उनका जिक्र किया है कि हरियाणा के अंदर साढ़े 6 लाख के करीब ट्यूबवैल्ज हैं। हमारे पड़ोस में पंजाब के अंदर 13 लाख ट्यूबवैल्ज़ हैं। पंजाब में ट्यूबवैल्ज के लिए बिजली पूरी तरह से मुफ्त है वहां पर भी सात हज़ार करोड़ रूपये का घाटा है और हरियाणा में तो 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से किसान बिजली का बिल देता है यहां पर 6 लाख ट्यूबवैल्ज का 60 हजार करोड़ रूपये का घाटा दर्शाया गया है। मुझे लगता है कि यह आंकड़ों में कोई गड़बड़ी है या फिर बिजली विभाग में कोई बड़ा घोटाला हो रहा है। अध्यक्ष जी, बिजली विभाग में जिन किसानों ने तत्काल स्कीम में 52 हजार एप्लीकेशंज़ लगाई थी जब से यह सरकार बनी हैं इन 52 हजार ट्यूबवैल

कनैक्शंज़ में से अभी भी 35 हजार ट्यूबवैल कनैक्शन अभी भी पैंडिंग हैं। हरियाणा प्रदेश के जो लोग इण्डस्ट्रियल कनैक्शन के लिए दरख्वास्त लगाते हैं उनको इण्डस्ट्रियल कनैक्शन नहीं मिलते। इसी प्रकार से पॉवर की सप्लाई में भी बहुत बड़ी समस्या है। पॉवर की सप्लाई न शहरों में है और न ही गांवों में सही है क्योंकि उसमें बार–बार ट्रिपिंग होती रहती है। मेरे विचार में इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक पुलिस के अधिकारी को, जो पुलिस का महकमा नहीं चला सका उसको बिजली का महकमा चलाने के लिए दे रखा है। सरेआम टैण्डरिंग में, मीटर परचेजिंग और पॉवर परचेज़ में वहां पर लूट मची रहती है। मेरा यह कहना है कि सरकार को इस विषय को गम्भीरता से लेना चाहिए। इसी प्रकार से मैंने एनवॉयरनमैंट के बारे में भी यहां पर निवेदन किया हुआ है कि एनवॉयरनमैंट में किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए तमाम जिला प्रशासन गांवों के धक्के खाता रहता था ताकि कोई किसान पराली न जला दे। उस समय कुल मिलाकर आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिये गये थे और लोगों के मन में पराली जलाने के नाम पर एक डर बिठा दिया गया था। स्पीकर सर, मेरा यह कहना है कि प्रत्येक शहर में नाजायज़ कारखाने चल रहे हैं लेकिन इन नाजायज़ कारखानों से होने वाले प्रदूषण पर सम्बंधित विभाग द्वारा कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि वहां से रिश्वत मिलती है। हर शहर के अंदर लगातार मोटर साईकिल्ज़ और कारें चलती रहती हैं जिनसे निरंतर धुआं निकलता रहता है उन पर रोकथाम लगाने की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। कुल मिलाकर हर शहर की एनवॉयरनमैंट के मामले में बहुत बुरी हालत है जिसके चलते अब हरियाणा प्रदेश किसी के भी रहने के लायक जगह नहीं रह गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार को कोई न कोई कानून बनाकर पर्यावरण को ठीक करना चाहिए। ऐसे ही मैंने इरीगेशन के बारे में निवेदन किया है। हमारे पलवल से यमुना कैनाल और आगरा कैनाल निकलती है। मेरे क्षेत्र में पानी के ट्यूबवैल्ज़ लगाकर मेवात तक के लोगों को वहां से पानी दिया जा रहा है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि हमारे क्षेत्र का अण्डर ग्राउंड वॉटर लैवल बड़ी तेजी के साथ नीचे जा रहा है। जब तक यमुना नदी के ऊपर बैराज नहीं बनेगा तब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान होने वाला नहीं है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी का इलैक्शन मैनीफैस्टो देखें तो उसमें यह लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वहां पर बैराज बनाये जायेंगे। स्पीकर सर, जहां

हमारा पलवल जिला समाप्त होता है और उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला शुरू होता है वहां यमुना नदी के ऊपर दो बैराज बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के इलैक्शन मैनीफैस्टो में किये गये वायदे को पूरा करने के लिए हमारे जिले के अंदर यमुना नदी पर एक भी बैराज बनाने का सरकार द्वारा इस बजट में भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अगर वहां पर बैराज नहीं बनाये जायेंगे तो हमारे क्षेत्र का अण्डर ग्राउण्ड वॉटर लैवल ऐसे ही तेजी से नीचे गिरता रहेगा और आने वाले दिनों में वहां पर लोगों को पीने तक को पानी नहीं मिलेगा। अध्यक्ष जी, इस बारे में मैंने ये कट–मोशन आपको दिये हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इन सभी बातों पर गम्भीरतापूर्वक गौर करेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विभिन्न डिमाण्ड्ज़ तथा कटौती प्रस्तावों को सदन में वोटिंग के लिए रखा जाता है।

मांग संख्या 1 एवं 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

> कि राजस्व खर्च के लिए 78,70,01,000/– से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या 1–विधान सभा के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेगी।
>
> कि राजस्व खर्च के लिए 160,53,02,000/– से अनधिक राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या–2 राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय पांच मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय पांच मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2019–2020 के लिए बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

21:00 बजे

मांग संख्या 3

श्री अध्यक्षः अब मैं मांग संख्या–3 पर कटौती प्रस्ताव नं. 1 जो कि श्री करण सिंह दलाल, विधायक द्वारा दिया गया है, को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि सामान्य प्रशासन के बारे में **मांग संख्या–3** की **राजस्व खर्च के लिए राशि 313,42,01,000/– रुपये** में 50 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 1 अस्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि **राजस्व खर्च के लिए 313,42,01,000/– रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या–3– सामान्य प्रशासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के अनुभाग के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या–4 से 12

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि राजस्व खर्च के लिए 1431,07,12,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **4–राजस्व** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 222,71,01,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **5–आबकारी व कराधान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 10584,69,21,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **6–वित्त** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 52,30,11,000/- से तथा पूंजीगत खर्च के लिए 409,28,01,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **7–आयोजना तथा सांख्यिकी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1145,32,76,000/- से तथा पूंजीगत खर्च के लिए 4008,63,52,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **8–भवन तथा सड़कें** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 13941,97,51,000/- से तथा पूंजीगत खर्च के लिए 100,00,01,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **9—शिक्षा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 482,72,00,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **10—तकनीकी शिक्षा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 382,94,02,000/- से तथा पूंजीगत खर्च के लिए 50,00,01,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **11—खेलकूद तथा युवा कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी ।

कि राजस्व खर्च के लिए 38,42,00,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **12—कला एवं संस्कृति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या 13

श्री अध्यक्षः अब मैं मांग संख्या—13 पर कटौती प्रस्ताव नं. 2 जो कि श्री कुलदीप शर्मा, विधायक द्वारा दिया गया है, को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है —

कि स्वास्थ्य के बारे में **मांग संख्या—13** की **राजस्व खर्च के लिए राशि 4392,73,37,000/— रुपये** में 1/— रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 2 अस्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि राजस्व खर्च के लिए 4392,73,37,000/- से तथा पूंजीगत खर्च के लिए 474,36,01,000/- रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या—13 स्वास्थ्य** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के अनुभाग के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या 14

श्री अध्यक्षः अब मैं मांग संख्या—14 पर कटौती प्रस्ताव नं. 3 जो कि श्री करण सिंह दलाल, विधायक द्वारा दिया गया है को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि शहरी विकास के बारे में **मांग संख्या–14** की **राजस्व खर्च के लिए राशि 583,02,01,000/– रुपये** में 50/– रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 3 अस्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि **राजस्व खर्च के लिए** 583,02,01,000/- से तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1300,00,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या–14 नगर विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के अनुभाग के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या 15 से 23

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि राजस्व खर्च के लिए 4021,68,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **15–स्थानीय शासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेगीं।

कि राजस्व खर्च के लिए 54,58,01,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1,00,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **16–श्रम** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेगीं।

कि राजस्व खर्च के लिए 360,20,27,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **17–रोजगार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 519,12,42,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 75,93,27,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **18–औद्योगिक प्रशिक्षण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 508,80,70,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 7,60,21,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **19–अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 6663,29,96,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 18,92,01,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **20–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1352,87,70,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 144,10,01,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **21—महिला तथा बाल विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 242,02,00,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **22—भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 430,83,57,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिये 13596,40,49,000/- से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या —**23—खाद्य एवं पूर्ति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगी ।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या 24

श्री अध्यक्षः अब मैं मांग संख्या—24 पर कटौती प्रस्ताव नं. 4 जो कि श्री करण सिंह दलाल, विधायक द्वारा दिया गया है, को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है —

कि सिंचाई के बारे में **मांग संख्या—24** की **राजस्व खर्च के लिए राशि 1724,65,03,000/— रुपये** में 500/— रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 4 अस्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि राजस्व खर्च के लिए 1724,65,03,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1549,93,74,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या—24 सिंचाई** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के अनुभाग के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या 25 से 26

श्री अध्यक्षः प्रश्न है —

कि राजस्व खर्च के लिए 325,06,01,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 15,01,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **25—उद्योग** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 130,15,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **26–खान एवं भू–विज्ञान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या 27

श्री अध्यक्षः अब मैं मांग संख्या–27 पर कटौती प्रस्ताव नं. 5 जो कि श्री कुलदीप शर्मा, विधायक द्वारा दिया गया है, को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि कृषि के बारे में **मांग संख्या–27** की **राजस्व खर्च के लिए राशि** 2721,80,28,000/- **रुपये** में 1/– रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 4 अस्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि राजस्व खर्च के लिए 2721,80,28,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या–27 कृषि** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के अनुभाग के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या 28 से 30

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि राजस्व खर्च के लिए 1006,48,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 20,00,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **28–पशुपालन तथा डेरी विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 73,25,99,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **29–मछली पालन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 505,63,95,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **30–वन तथा वन्य प्राणी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या 31

श्री अध्यक्षः अब मैं मांग संख्या–31 पर कटौती प्रस्ताव नं. 6 जो कि श्री करण सिंह दलाल, विधायक द्वारा दिया गया है, को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण के बारे में **मांग संख्या–31** की **राजस्व खर्च के लिए राशि 13,09,01,000/- रुपये** में 10/– रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 4 अस्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि राजस्व खर्च के लिए 13,09,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या–29 परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के अनुभाग के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या–32 एवं 33

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि राजस्व खर्च के लिए 4898,60,02,000/- से तथा पूंजीगत खर्च के लिए 300,00,02,000/- अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **32–ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए राजस्व खर्च के लिए 332,00,49,000/- से तथा पूंजीगत खर्च के लिए 154,90,01,000/- अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **33–सहकारिता** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय पांच मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ।

आवाजें : जी हां ।

श्री अध्यक्ष :ठीक है, हाऊस का समय पांच मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

वर्ष 2019–2020 के लिए बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

मांग संख्या–34

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 34 पर कटौती प्रस्ताव नं. 7 जो कि श्री कुलदीप शर्मा, विधायक द्वारा दिया गया है, को सदन के मतदान के लिए रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि परिवहन में मांग संख्या 34 की राजस्व खर्च के लिए राशि **2387,01,60,000/- रुपये** में 1 रुपये की कमी की जाए ।

(कटौती प्रस्ताव नं. 7 अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि राजस्व खर्च के लिए 2387,01,60,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 297,11,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **34–परिवहन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

मांग संख्या–35 से 39

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि राजस्व खर्च के लिए 9,12,01,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 39,40,01,000/-से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **35–पर्यटन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 4663,39,01,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 410,00,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **36–गृह** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 175,63,91,000 /- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **37–निर्वाचन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 2136,73,46,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1470,58,26,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **38–लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 186,10,01,000/- से तथा पूंजीगत खर्च के लिए 50,00,01,000/- अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **39–सूचना तथा प्रचार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

मांग संख्या–40

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 40 पर कटौती प्रस्ताव नं. 8 और 9 जो कि श्री करण सिंह दलाल, विधायक और श्री कुलदीप शर्मा, विधायक द्वारा दिये गये हैं, को सदन के मतदान के लिए रखता हूं ।

(i)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि **ऊर्जा तथा विद्युत** में मांग संख्या 40 की राजस्व खर्च के लिए राशि **7366,92,49,000/- रुपये** में 25/– रुपये की कमी की जाए ।

(कटौती प्रस्ताव नं. 8 अस्वीकृत हुआ।)

(ii)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि **ऊर्जा तथा विद्युत** में मांग संख्या 40 की राजस्व खर्च के लिए राशि **7366,92,49,000/- रुपये** में 1/–रुपये की कमी की जाए ।

(कटौती प्रस्ताव नं. 9 अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि राजस्व खर्च के लिए 7366,92,49,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 5857,69,04,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **40–ऊर्जा तथा विद्युत** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

मांग संख्या–41 से 45

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि राजस्व खर्च के लिए 152,74,51,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **41–इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 870,31,62,000 /- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **42–न्याय प्रशासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019–20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 277,27,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **43—कारागार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि राजस्व खर्च के लिए 39,18,45,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1,50,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **44—मुद्रण तथा लेखन सामग्री** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि पूंजीगत खर्च के लिए 1407,27,01,000/- से अनधिक राशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाये जो मांग संख्या **45—राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2019—20 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन बुधवार, दिनांक 27 फरवरी,. 2019, प्रातः 10:00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

09.07 बजे **(तत्पश्चात सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2019 प्रातः 10:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)**